

आर्थिक विकास का केंसाय सिद्धान्त

The Keynesian Theory of Economic Development

आर्थिक विकास का केन्सीय सिद्धान्त

Keynsian Theory of Economic Development

मूल लेखक :

कैनेथ के० कुरीहारा

अनुवादक :

श्री लाल मोहर राय



सत्यमेव जयते

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, की मानक ग्रंथों की
प्रकाशन योजना के अंतर्गत प्रकाशित

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय,
भारत सरकार

1969

© भारत सरकार
प्रथम संस्करण, वर्ष 1969

प्रस्तुत पुस्तक सर्व श्री जार्ज एलिन और अनविन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित कैनेथ के० कुरीहारा की अग्रणी पुस्तक *Keynsian Theory of Economic Development* के सन् 1961 में प्रकाशित संस्करण का हिन्दी अनुवाद है तथा इस पुस्तक का अनुवाद और पुनरीक्षण भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की मानक ग्रंथों की प्रकाशन योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के शतप्रतिशत अनुदान से हुआ है ।

मूल्य : रु० 4.10 पैसे



Price : Rs. 4.10 Paise

प्रधान प्रकाशन अधिकारी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा राकेश प्रेस, दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

प्रस्तावना

हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि इनमें उच्चकोटि के प्रामाणिक ग्रंथ अधिक-से-अधिक संख्या में तैयार किए जाएँ। भारत सरकार ने यह कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के हाथ में सौंपा है और उसने इसे बड़े पैमाने पर करने की योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा है तथा मौलिक ग्रंथ भी लिखाए जा रहे हैं। यह काम अधिकतर राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा प्रकाशकों की सहायता से प्रारंभ किया गया है। कुछ अनुवाद और प्रकाशन-कार्य आयोग स्वयं अपने अधीन भी करवा रहा है। प्रसिद्ध विद्वान और अध्यापक हमें इस योजना में सहयोग दे रहे हैं। अनूदित और नए साहित्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शब्दावली का ही प्रयोग किया जा रहा है ताकि भारत की सभी शिक्षा-संस्थाओं में एक ही पारिभाषित शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके।

आर्थिक विकास का केन्सीय सिद्धान्त नामक पुस्तक हिंदी वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इसके मूल लेखक कैनेथ के० कुरीहारा और अनुवादक श्री लाल मोहर राय हैं। आशा है कि भारत सरकार द्वारा मानक ग्रंथों के प्रकाशन संबंधी इस प्रयास का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जायगा।

वावू राम सक्सेना

अध्यक्ष

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

नई दिल्ली

मार्च, 1969

प्राक्कथन

इस पुस्तक का उद्देश्य सामान्य रूप से आर्थिक विकास एवं विशेष रूप से अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास की तकनीकी सम्भावनाओं एवं सीमाओं का स्पष्टीकरण है। इस विचार-वस्तु को तीव्र बनाने के लिए, इस पुस्तक में आद्योपात्त हमने स्वेच्छया अल्प-विकसित एवं विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की विकास-सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का तुलनात्मक विवेचन किया है। प्रस्तुत सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में, परिचालन की दृष्टि से, आर्थिक विकास के महत्त्वपूर्ण उपकरणों की व्याख्या करना हमारी प्रधान अभिरुचि रही है। तदनुसार, हमने उन माध्य परिवर्तियों के बीच के उन सम्बन्धों को चुना है, जिन पर प्रति-व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि मृदु रूप से निर्भर करती है और ऐसी मान्यताओं के आधार पर विश्लेषण के योग्य सरल और उपादेय परिणाम निकल सकता है। इसके लिए, विभिन्न अध्यायों को, जो यद्यपि अपने-आप में अपूर्ण हैं, इस रूप में नियोजित किया है कि ये समुक्त रूप से एक सैद्धान्तिक समग्रता की स्थापना कर सकें और अल्प-विकसित देशों के औद्योगीकरण-सम्बन्धी कार्यक्रम की पूरी योजना के निर्माण में सहायक हो सकें।

अभिस्वीकृति के तौर पर इस पुस्तक के शीर्षक में व्यवस्त केन्सीय ढाँचे के उल्लेख के प्रति हम अपने पूर्व-स्नेह को कई आधार पर न्यायोचित ठहरा सकते हैं। प्रथमतः, और समसामयिक रूप में यह पुस्तक आ० एफ० हेरोड तथा श्रीमती जोन रॉबिन्सन का, जिन्होंने, जैसा कि केन्स के पारगत शिष्यों से कोई भी आशा कर सकता है, केन्स के अल्पकालीन सिद्धान्त को दीर्घकालिक तथा गत्यात्मक बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत अधिक ऋणी है। यह पुस्तक विशेष रूप से हेरोड के विकास-सम्बन्धी विश्लेषण के लिए मार्ग तैयार करने वाले उपकरणों तथा अल्प-विकसित देशों में केन्सीय गत्यात्मकता के सम्भावित प्रयोगों के सम्बन्ध में श्रीमती जोन रॉबिन्सन के चुनौतीपूर्ण सुझाव के वगैरनहीं लिखी गयी होती,* किन्तु जैसा कि पाठक

* श्रीमती रॉबिन्सन का सुझाव इनके "मि० हेरोड्स डायनेमिक्स" इकानामिक जनरल (मार्च, 1949) में पाया जाएगा। श्रीमती रॉबिन्सन की नयी पुस्तक "दि एकमुलेशन ऑफ कैपिटल" हमें प्राप्त होने के पूर्व इस पुस्तक का बड़ा भाग तैयार हो चुका था। फिर भी इनकी नयी पुस्तक के सम्बन्ध में मेरी विलम्बित

आगे चल कर देखेंगे, हमें इनकी रचनाओं में प्रयुक्त विश्लेषण के विशिष्ट उपकरणों से असहमति प्रकट करने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं रही है। यद्यपि यह पुस्तक श्री हैरोड तथा श्रीमती रॉबिन्सन की केन्सीयोत्तर भावना से लिखी गई है। तथापि इसके शीर्षक में 'केन्सीयन्त्र' शब्द का प्रयोग इसे अन्य पुस्तकों से विशिष्ट बनाने के लिए किया गया है, जो स्पष्ट रूप से नव संस्थापकीय, "मार्क्सियन" या "ग्रुम्पीटेरियन" है।

द्वितीयतः, अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास के प्रति केन्स के तकनीकी, बहुराष्ट्रीय निर्दलीय रुख द्वारा प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त उसकी दूर दृष्टि के प्रति यह रचना अपनी प्रारम्भिक अवधारणा तथा आधारभूत प्रेरणा के लिए आभारनत है। यह एक अपूर्व दूरदृष्टि है, जो पुनर्निर्माण तथा विकास के निर्मित अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के सामान्य सिद्धान्तों में, जिनका केन्स वौद्धिक शिल्पी माना जाता था, स्थायी रूप से समाविष्ट है। तृतीयतः, फलमूलक विश्लेषण और नीति के लक्ष्य के रूप में आर्थिक विकास के लिए एक ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता जान पड़ती है, जो "केन्सीय सक्रियावाद" के अनुरूप हो, जिसे ए० सी० पीगू ने एक ऐसे आदर्श-निर्माण की संज्ञा दी है, जो पूर्वानुमानों की सहायता एवं नीति-सम्बन्धी मार्ग-निर्देशन के लिए सांख्यिकीय माप के हेतु ग्रहणशील तथ्यों के साथ निकटता रखता। चतुर्थतः, केन्स के नाम से सम्बद्ध राष्ट्रीय आय-विश्लेषण और राष्ट्रीय आर्थिक राजकौशल (statesmanship) ने परम्पराओं से बहुत अधिक अपसरण के वगैर अस्थायी समर्थ मांग की समस्या को मुख्यतः समाधान योग्य बना दिया है। इससे प्रत्येक मिश्रित राजकीय-सह-निजी अर्थ-व्यवस्था अब विश्वासपूर्वक तकनीकी सीमाओं के अन्तर्गत, किन्तु अस्थायित्व के द्वारा विस्थिति होने की अनिवार्यता के भय के वगैर प्रगति के लक्ष्य की दर को प्राप्त करने तथा उसे स्थिर बनाये रखने की दीर्घकालीन समस्या का समाधान निकाल सकती है।

अन्ततः, सामान्य सिद्धान्त (जेनरल थियरी) के अन्तिम अध्याय में वर्णित केन्स का सामाजिक दर्शन आर्थिक विकास के उस प्रतिफल, जो मानव मूल्यों के प्रति चेतनता से ओत-प्रोत, द्रुतगति से औद्योगिक विकास के लिए अत्यधिक उत्साह पर सुदृढ़ रूप से आधारित है, के मार्ग दर्शन के हेतु अपरिहार्य प्रकाश-गृह के रूप में जान पड़ता है। यह रूप एक ऐसे विश्वव्यापी आर्थिक विकास का प्रतिरूप है, जिसे केन्स ने द्वितीय युद्ध के बाद स्थापित होने वाले राष्ट्रों के नये प्रजातन्त्र के लिए सोचा था।

कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी स्वयं हमारे चिन्तन को यदि प्रभावित नहीं

प्रतिक्रिया इस पुस्तक के चौथे अध्याय में प्राप्त होगी। हैरोड की सुप्रसिद्ध पुस्तक "टुवार्ड्स ए डायनेमिक इकॉनॉमिक्स" के सम्बन्ध में चर्चा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।

किया है, तो उत्तेजित अवश्य किया है, जैसा कि पाठक इस पुस्तक के आरम्भिक अध्याय में वर्णित पूर्वाधिकारियों तथा अन्त में दी गई सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची से अनुमान लगा सकते हैं। फिर भी, हम कुछ व्यक्तियों के प्रति, जो केन्स के विचारों के विस्तार तथा उनके अमल में लाए जाने के हाल के हमारे प्रयास में व्यक्तिगत रूप से सहायक रहे हैं, विशेष तौर से सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं। हम कोलम्बिया-विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलियम भाइकरे की तकनीकी व्योरे पर सतर्क एवं उपयोगी आलोचनाओं के लिए पूर्ववत् बहुत अधिक ऋणी हैं। रजर-विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ब्रोडस माइकेल ने अलेग्जेन्डर हैमिल्टन के नेतृत्व में अमेरिका के प्रारम्भिक विकास की शिक्षा-प्रद गाथाओं द्वारा हमारी कल्पना को प्रज्वलित किया है। जबकि प्रोफेसर रायट अलेग्जेन्डर ने सिद्धान्तों के सभी स्तरों पर लैटिन अमेरिका की विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था के आनुभविक आँकड़े हमारे लिए प्रस्तुत किये हैं। इओआ स्टेट कॉलेज के प्रोफेसर गरहार्ड टिटनर ने बहुत सारी तकनीकी बातों की आलोचना से मुझे लाभान्वित किया है। कोयटा विश्वविद्यालय के आर्थिक विकास-अनुसन्धान-केन्द्र तथा ओसाका विश्वविद्यालय के सामाजिक एवं आर्थिक अनुसन्धान संस्थान के क्रमशः प्रो० हिडाओ ओया तथा सिन्ची इचीमूरा ने जापान की औद्योगिक प्रगति के अपने आत्मीय ज्ञान के आधार पर हमें बहुमूल्य सुझाव दिया है। सदा की तरह, ग्रिनेल कॉलेज के प्रेसिडेंट हार्वर्ड व्रोवेन ने मुझे उचित प्रोत्साहन प्रदान किया है। मेरी पत्नी, 'के' ने उस प्रकार की सहायता एवं सहानुभूति दी है, जिसकी आवश्यकता हर-एक लेखक को गम्भीर रचनाओं के विक्षुब्ध श्रम में बहुत अधिक होती है।

इन सभी मित्रों एवं सहयोगियों के हम बहुत अनुगृहीत हैं, किन्तु फिर भी, पाठकों द्वारा इस पुस्तक में पाये जाने वाले किसी भी अवगुण के लिए इनमें से किसी को भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अपने लेखों को समग्र अथवा आंशिक रूप में पुनः उद्धृत करने की अनुमति के लिए निम्नलिखित पत्रिकाओं के सम्पादकों के प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं : 'दि इंडियन जनरल ऑफ इकॉनामिक्स,' 'दि इंडियन इकॉनामिक जर्नल,' 'दि मेट्रोकोनामिका,' 'दि फाइनान्सेज पब्लिशर्स' (नीदरलैंड्स), 'दि इकॉनामिक स्टडीज क्वार्टर्ली' (जापान) तथा 'दि इकॉनामिक चौकली' (भारत)।

विषय-सूची

प्राक्कथन	पृष्ठ
1. संस्थापक एवं संस्थापकोत्तर पूर्वाधिकारी	1
संस्थापक अन्तर्दृष्टि एवं अग्रदृष्टि	1
संस्थापकोत्तर सिद्धान्त	6
2. अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की संरचना	14
अल्प-आर्थिक विकास के सूचक	14
विकास के संरचनात्मक निर्धारक तत्त्व	22
3. विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम गति	29
जनसंख्या की वृद्धि एवं जीवन-मान	29
अपेक्षित पूँजी-संचय	38
4. पूँजी-संचय एवं उत्पादन-सामर्थ्य	42
क्षमता-निर्माण की प्रक्रिया	42
हैरोड-डोमर मॉडल पर टिप्पणी	49
रॉबिन्सन मॉडल पर टिप्पणी	60
5. आर्थिक-विकास में टेक्नोलॉजिकल भूमिका	68
श्रम की उत्पादकता पर टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रभाव	69
श्रम बचाने एवं श्रम का प्रयोग करने वाले तकनीकों पर प्रभाव	74
क्षमता-वृद्धि पर टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रभाव	76
6. अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में दुहरी बेरोजगारी	87
केन्सीय बेरोजगारी की चक्रीय वृद्धि	89
ग्रैर-केन्सीय बेरोजगारी की दीर्घकालिक वृद्धि	95
छिपी हुई बेरोजगारी पर अनुलेख	104
7. आर्थिक विकास में पुनर्वितरणात्मक भूमिका	108
आय का पुनर्वितरण एवं बचत-अनुपात	110

8. आर्थिक विकास में मौद्रिक भूमिका	...	121
साख, ब्याज एवं विकास	...	122
स्फीति एवं विकास	...	130
9. आर्थिक विकास में वित्तीय भूमिका	...	141
अधिकतम विकास के लिए वित्तीय क्रियाएँ	...	141
स्थायी विकास के लिए वित्तीय क्रियाएँ	...	150
10. विदेशी व्यापार एवं आर्थिक विकास	...	158
विदेशी व्यापार एवं माँग में वृद्धि	...	159
सन्तुलित विकास के लिए प्राचलीय क्रियाएँ	...	164
11. केन्सीयोत्तर विकास-सिद्धान्तों पर उपसंहार	..	175
राज्य के विकासात्मक कार्य	...	175
सन्तुलन विकास की प्रकृति एवं यन्त्र	...	179
परिशिष्ट—संयुक्त राष्ट्र एवं आर्थिक विकास	...	186

अध्याय 1

संस्थापक एवं संस्थापकोत्तर पूर्वाधिकारी

अर्थशास्त्र के सिद्धान्त की अन्य शाखाओं की तरह आर्थिक विकास के आधुनिक सिद्धान्त का भी अपना एक अनन्य इतिहास है, जो एक साथ ही वर्तमान विकास के सिद्धान्त-निर्माण का अनुदर्शी तथा अति यथार्थवादी आदर्श-निर्माण का अग्रदर्शी है। इस क्षेत्र-विशेष में आर्थिक विचारधारा के आत्मनिष्ठ इतिहास से विभिन्न परिस्थितियों में आर्थिक विकास के वस्तु-निष्ठ इतिहास का एक समीचीन एवं समानपूर्ण नैकट्य है। अपेक्षाकृत एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए इस प्रारम्भिक अध्याय में ऐतिहासिक दृष्टि से विपमजातीय, किन्तु मूलतः समजातीय मानव-समुदायों के आर्थिक विकास की प्रकृति एवं कारणों के सम्बन्ध में संस्थापक एवं संस्थापकोत्तर विचारधाराओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। आर्थिक विकास के विशिष्ट क्षेत्र में समकालीन विचारधारा एवं कार्यक्रम-निर्धारण पर संस्थापक एवं संस्थापकोत्तर प्रभावों को इंगित करने के लिए पूर्वाधिकारियों का निम्नविवृत रूप में चुनाव किया गया है।

संस्थापक अंतर्दृष्टि एवं अग्रदृष्टि

आदम स्मिथ (1723-1790)

यह केवल संयोग की बात नहीं है कि आदम स्मिथ, जो न केवल ग्रेट-ब्रिटेन जैसे पहले से ही सर्वाधिक उन्नत औद्योगिक राष्ट्र में संस्थापक-सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे, अपितु आर्थिक प्रगति की सामान्य प्रकृति एवं पूँजीवादी विकास के विशिष्ट कारणों की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे। इनमें पहले की सामान्यता दूसरे की विशिष्टता से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि समसामयिक विकासवादी सिद्धान्त के प्रतिपादक आर्थिक प्रगति के सैद्धांतिक लक्ष्यार्थों का स्वागत या तिरस्कार करने की अपेक्षा, इसकी प्राविधिक शर्तों की परिपूर्ति में अधिक रुचि रखते हैं। इस सम्बन्ध में आदम स्मिथ की प्रधान त्रुटि यह थी कि वे सब समयों तथा स्थानों के लिए संगत स्थायी तत्वों तथा उन तत्वों के बीच, जो सीमित 'वैयक्तिक पूँजीवाद' पर लागू हो सकते हैं, स्पष्टरूप से विभेद नहीं कर सके।

अतएव, उनकी अवंध-नीति, अधिकतम प्रतियोगिता, मुक्त व्यापार, वैयक्तिक तथा सार्वजनिक हितों में सामंजस्य लाने वाला उपक्रमी तथा वैयक्तिक एवं राष्ट्रीय सद्गुण के रूप में मितव्ययिता, आधुनिक सैद्धांतिकों के लिए विशुद्ध पूँजीवाद के मार्ग

पर आर्थिक विकास के उचित निर्देश-संयंत्र के रूप में कार्य करती है। फिर भी आदम स्मिथ के 'वैलथ आफ नेशनस' को किसी प्रकार की आर्थिक व्यवस्था में सम्बद्ध किये वगैर समसामयिक समाजों के आर्थिक विकास के लिए अनुपयुक्त बतलाना भूल होगी। क्योंकि अन्य बातों के साथ-साथ इस ग्रंथ में इस सामान्य प्रस्ताव की भी चर्चा की गई है कि राष्ट्रीय सम्पत्ति में अभिवृद्धि निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है

(क) प्राविधिक श्रम-विभाजन से आवद्ध श्रम की उत्पादन-क्षमता, तथा (ख) सांस्थानिक तौर पर निर्धारित मितव्यय से आवद्ध पूँजी-संचय। इस प्रस्ताव की व्यापक मान्यता को बोर्ड चुनौती नहीं दे सकता। फिर भी राष्ट्रीय सम्पत्ति की स्वचालित एवं अवरोध वृद्धि को अनुक्रमबद्ध करने वाली तकनीकी प्रगति और पूँजी-संचय जिस अदृश्य शक्ति द्वारा सुनिश्चित होता है, उस पर आदम स्मिथ की निर्भरता के सम्बन्ध में अधिकांश व्यक्तित्व सदेह व्यक्त कर सकते हैं। आदम स्मिथ का यह प्रस्ताव केन्स के इस अनुदर्शन की प्रत्याशा है कि पूर्व-पूँजीवादी युग में प्रगति की दर की धीमी गति इन दो अवरोधक कारणों का परिणाम थी : (क) प्रमुख प्राविधिक उन्नति की अनुपस्थिति तथा (ख) पूँजी-संचय का अभाव। इन प्रकार आदम-स्मिथ को राष्ट्रों के औद्योगीकरण में पूँजी की मात्रा एवं गुण के निर्णायक महत्व पर पुरोगामी जोर देने का श्रेय दिया जा सकता है।

थॉमस राबर्ट माल्थस (1766-1835)

आदम स्मिथ की तरह, किन्तु डेविड रिकार्डों (जिनका सम्बन्ध मुख्यतः एक ही हुई निपज के वितरण में था) के प्रतिकूल, केम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों में अग्रगण्य राबर्ट माल्थस का ध्यान निपज के परिमाण एवं सम्पत्ति में वृद्धि के तात्कालिक कारणों की ओर पहले से ही स्थिर हो चुका था। फिर भी अनियमित गति (आधुनिक भाषा में चक्रीय विकास) से सम्बद्ध आर्थिक विकास की प्राविधिक सम्भावना के अव-लोकन में माल्थस का स्मिथ में मतभेद था। मतभेद इस बात पर था कि अब और कहीं वृद्धि के संचय, जिस पर आर्थिक प्रगति मुख्य रूप से निर्भर करती है, को इतनी तीव्र गति से बढ़ाया जाय, जिससे कि उपभोग्य माग में कमी हो जाय और उत्पादन-सम्बन्धी सामान्य घरेलू क्षीण हो जाय। संक्षेप में वैसे समाज, जिसकी समर्थ माग का आचरण 'से' के बाजार नियम के अनुकूल नहीं होता, सम्पत्ति के अस्थिर एवं अशांत वृद्धि के सम्बन्ध में माल्थस का ऐसा ही विचार है। यह विचार माल्थस की पुस्तक 'प्रिंसिपल्स ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी' में व्यक्त किया गया है। सामान्यतः इस विचार की जानकारी मुख्य रूप से केन्स के प्रयत्नों में ही हो पाई।¹

1. (क) देखें जे० एम० केन्स, 'एसेज इन परसुएशन, रूपोर्ट हाउट डेविस, लंदन, 1952 पृ० 360।

(ख) देखें, 'एसेज इन ब्रायप्रफी' केन्स द्वारा वर्णित माल्थस की आकर्षक एवं प्रभाव-शाली जीवनी, होराइन प्रेम, न्यूयार्क, 1951 पृ० सं० 81-124।

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से माल्थस की एक अधिक आकर्षक अन्य रचना 'ऐन ऐसे ओन दि प्रिन्सिपल्स ऑफ पापुलेशन एज इट एफेक्ट्स दि फ्यूचर इम्प्रूवमेन्ट आफ सोसाइटी' है। इस पुस्तक में माल्थस ने अत्यन्त आश्चर्य-चकित कर देने वाला यह विचार प्रस्तुत किया कि वैसी परिस्थितियों में, जहाँ जन-संख्या की वृद्धि अनियंत्रित तथा पूँजी का संचय अवंध नीति से होता है, वहाँ पूँजी अथवा जीवन-निर्वाह के साधनों की अपेक्षा जनसंख्या में अधिक दर से वृद्धि होती है। यहाँ माल्थस का विचार मार्क्स के 'औद्योगिक आरक्षित सेना' के सिद्धान्त (संरचनात्मक अपूर्ण रोजगारी) का पूर्वानुमान है; क्योंकि मार्क्स का यह विचार बिना किसी तात्पर्य का नहीं है। वस्तुतः, जैसा कि केन्स ने बतलाया है,¹ यह विचार माल्थस के इस निजी सिद्धान्त से निकटतम सादृश्य रखता है, जिसके अनुसार पूँजीवादी समाज में समर्थ माँग निपज का साथ देने में असफल हो सकती है। फिर भी, मार्क्स के ठीक विपरीत माल्थस का यह विचार था कि निबंध-नीति पर आधृत पूँजी-निर्माण की व्यवस्था को समाप्त करने के बजाय जन्म-दर का युक्तिपूर्ण नियंत्रण जनाधिक्य की तथाकथित समस्या का उचित निदान है। केन्स के अनुसार माल्थस पहला अर्थशास्त्री था, जिसने, दीर्घकालीन आर्थिक विश्लेषण के लिए इस बात को (केन्स की भाषा में) 'जोरदार महत्त्व' दिया था कि प्रदत्त आधार के बदले जनसंख्या के गत्यात्मक प्रतिपादन को एक परिवर्तनशील आधार माना जाय। इस प्रकार का प्रतिपादन जनाधिक्य से पीड़ित अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण है।

फ्रेडरिक लिस्ट (1789-1846)

अपने समय की औद्योगिक दृष्टि से अविकसित जर्मनी का प्रतिनिधित्व करते हुए, फ्रेडरिक लिस्ट सामान्य रूप से आर्थिक राष्ट्रीयता तथा विशिष्ट रूप से संरक्षण-वाद के आधार पर औद्योगीकरण का प्रधान समर्थक बन गया। आज भी उसके आर्थिक-विकास के सिद्धान्त को आधुनिक अल्पविकसित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों, जो राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हुए भी आर्थिक दृष्टि से विकसित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों के प्रभुत्व में हैं, का प्रबल समर्थन प्राप्त है।²

अपनी पुस्तक 'दास नेशनल सिस्टम दर पोलिटिशेन ओकानामी' (Das National System der politischen Okonomie) में लिस्ट ने आर्थिक विकास के सिद्धान्त में एक नये तत्व का समावेश किया। उसने देशी शिशु-उद्योगों के विकास को विशिष्ट रूप से प्रोत्साहन देने के लिए तब तक संरक्षणात्मक 'टैरिफ' प्रदान करने

1. केन्स, वहीँ, 107-108।

2. आधुनिक अर्थ-व्यवस्थाओं पर लिस्ट के प्रभाव के लिए देखें 'नाइचेल्स डे विडा बाई देसारेलो-इकानोमिको' (आर्थिक विकास पर एक परिसंवाद) मेक्सिको-विश्वविद्यालय के नेशनल स्कूल आफ इकानॉमिक्स में 1953।

की नीति को सैद्धांतिक औचित्य प्रदान किया, जब तक कि ये तुलनात्मक लाभ के आधार पर विदेशी उद्योगों की प्रतियोगिता का सामना न कर सकें। लिस्ट के सरक्षणवाद के आधार पर औद्योगीकरण के सिद्धान्त ने, उसके बौद्धिक शिषु, हेनरी सी० केरे¹ के माध्यम से अमेरिका के निर्माणकारी उद्योगों के आश्रित विकास में पुरोगामी महत्व का कार्य किया।

यद्यपि लिस्ट ने संरक्षित उद्योगों के आत्मघाती भीमात उद्योग बनने के खतरे के विरुद्ध कोई मुद्दब सूझा की व्यवस्था नहीं की, फिर भी उसने नये राष्ट्रों के आर्थिक विकास में निर्णायक प्रेरणात्मक शक्ति के रूप में राष्ट्रीयता के तन्त्र की ओर ध्यान आकृष्ट किया। यह एक ऐसा तत्त्व है, जिसकी अवहेलना आदम-स्मिथ तथा मुल्क व्यापार के अन्य समर्थकों ने की थी और जिन्होंने विश्वव्यापी पूर्ण रोजगारी और पूर्ण विकास के अस्तित्व को मौन रूप में स्वीकार कर लिया था। अपूर्ण विकास एवं मुल्क व्यापार की असंगतता-सम्बन्धी अपनी मौलिक अन्तर्दृष्टि के कारण लिस्ट का अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के इतिहास में उसी प्रकार अनन्य स्थान है, जिस प्रकार अपूर्ण रोजगार एवं मुल्क व्यापार की असंगतता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के कारण केन्स का। सरक्षण की विशेष कार्यान्विति सम्बन्धी प्राविधिक श्रुतियों को बड़ा-चढ़ाकर उस स्तर तक नहीं ले जाना चाहिए, जहाँ लिस्ट का व्यापक योगदान ही गुम हो जाय।

कार्ल मार्क्स (1818-1883)

आर्थिक विकास के सिद्धान्त के क्षेत्र में मार्क्स की ये तीन महत्वपूर्ण देन हैं; यथा व्यापक रूप में इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत करना, अपेक्षाकृत सङ्कुचित रूप में पूँजीवादी विकास की प्रेरणात्मक शक्तियों की व्याख्या करना तथा आयोजित विकास-रूपी एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करना। जैसा कि एक लेखक का कहना है कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास के हेतु अंकलित सिद्धान्त के प्रतिपादन-सम्बन्धी कार्ल मार्क्स के प्रयास की महत्वाकांक्षा उन सभी वस्तुओं से बड़ी-चड़ी थी, जिनके लिए सस्थापक अर्थशास्त्रियों ने उद्योग किया था।²

अपनी पुस्तक 'क्रिटिक ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी' के प्राक्कथन में मार्क्स ने ऐतिहासिक विकास के भौतिक अवधारण की रूप-रेखा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार

1. मेरे सहयोगी प्रो० ब्रोदस मार्टिनेल ने मुझे यह सूचना दी कि लिस्ट हेनरी केरे के पिता मैथु केरे के घनिष्ठ मित्र थे। मैथु केरे ने संरचनात्मक 'टैरिफ' के द्वारा अमेरिका के औद्योगीकरण में लिस्ट, जो उस समय अमेरिका आये थे, का बौद्धिक समर्थन प्राप्त किया।
2. देखें, टी० हेवलेमो का 'ए स्टडी इन दि थियरी आफ इकॉनामिक इवोल्यूशन', नार्थ हालैंड पब्लिशिंग कम्पनी, अमस्टरडम, 1954, पृ० 12।

आर्थिक संस्थाएँ सामाजिक विकास का परिणाम होते हुए भी स्वयं सामाजिक विकास की गति को प्रभावित करने में सक्षम हैं। शायद इसी विचारधारा से शुम्पीटर को आर्थिक विश्लेषण के लिए ऐतिहासिक घटनाओं एवं सामाजिक संस्थाओं के वर्तमान समष्टि की जगह अंतर्जनित परिवर्तनों के रूप में व्याख्या की प्रेरणा मिली थी। सामान्यतः यही दृष्टिकोण व्यापक रूप से समकालीन रचनाओं के अंतर-अनुशासनीय उपागमों में पाया जाता है।¹ अपनी प्रमुख कृति 'कैपिटल' में मार्क्स ने इस बात की व्याख्या की है कि पूँजीवादी विकास की विक्षुब्ध प्रक्रिया इन तत्त्वों पर निर्भर करती है : (क) मजदूरों के उपभोग के व्यय पर मुनाफाखोरों की वचतें, (ख) मुनाफे के लिए प्रतियोगिता से प्रेरित, किन्तु अपूर्ण उपभोग तथा अत्यधिक विनियोग के परिणामस्वरूप विनियोग की सुविधाओं में ह्रास से अवरोधित नयी पूँजी में उस वचत का विनियोग, तथा (ग) श्रमिकों की समाजशास्त्रीय आधार पर निर्धारित संख्या एवं प्रविधि द्वारा निर्धारित उत्पादकता।² पूँजीवादी विकास का यह मार्क्सवादी सिद्धान्त कई आधुनिक दीर्घकालीन सिद्धान्तों का पूर्वानुमान करता है, जैसे केन्स एवं हेन्सन के स्थिरता के सिद्धान्त³, डोमर एवं हैरोड का गत्यात्मक सिद्धान्त⁴, शुम्पीटर केलेकी,

1. मार्क्स के रीति-विधान की व्याख्या को शुम्पीटर द्वारा मौल रूप से मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में देखें—'कैपिटलिज्म, सोसलिज्म एंड डेमोक्रेसी, हारपर एंड ब्रदर्स न्यूयार्क, 1942 तथा 'टेन ग्रेड इकनामिस्ट्स: फ्रॉम मार्क्स टू केन्स' आक्सफोर्ड, न्यूयार्क, 1954।
2. जैसा कि हम शिकागो-विश्वविद्यालय के "इकानामिक डेवलपमेंट एंड कलचरल चेंजेज" के पृष्ठों में पाते हैं।
3. आधुनिक मार्क्सवादी व्याख्या के लिए देखें पी० स्वीजी का 'दि थियरी ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट', आक्सफोर्ड, न्यूयार्क, 1944।
4. देखें जे० एम० केन्स का 'सम इकानामिक कन्सीक्युनेशज ऑफ ए डिकलाइनिंग पापुलेशन इन्फोर्निक्स रिव्यू', अप्रैल, 1937, ए० एच० हेन्सन का इकानामिक प्रोग्रेस एंड डिकलाइनिंग पोपुलेशन ग्रोथ, 'अमेरिकन इकानामिक रिव्यू' मार्च, 1939।
5. देखें आर० एफ० हैरोड का 'टवाइस ए डाइनिमिक इकानामिक्स' मैकमिलन, लंदन, 1948, इ० डी० डोमर 'इक्सेपैन्शन एंड इम्प्लायमेंट', अमेरिकन इकानामिक रिव्यू मार्च, 1947।

कालडोर एवं गोडविन का चक्रीय विकास का सिद्धान्त¹, तथा श्रीमती जॉन रोविन्सन का संरचनात्मक अपूर्ण रोजगार का सिद्धांत²।

किन्तु आश्चर्य की बात है कि आयोजित विकास के सम्बन्ध में मार्क्स द्वारा उसकी गौण रचनाओं में व्यक्त किये गए विचारों के विकास का प्रभाव ही सोवियत रूस तथा चीन की मुख्य भूमि जैसे देशों के वास्तविक आर्थिक विकास पर अत्यधिक पड़ा है। आयोजित विकास के सम्बन्ध में मार्क्स के विचार उन पिछड़े देशों को भी अधिक जँचते हैं, जो अत्यधिक राष्ट्रीय प्रयास तथा विकसित राष्ट्रों से अनावश्यक विलगाव के जोखिम पर तीव्र गति से औद्योगीकरण चाहते हैं।³ अब यह देखना है कि भावी पीढ़ी अपेक्षाकृत किस भावना से कर्मोन्मत्त सवक ग्रहण करती है—मार्क्स की उस भावना से, जिसके अनुसार आयोजित विकास⁴ के हेतु उत्पादन के साधनों पर राजकीय स्वामित्व को एक इतिहास-प्रसिद्ध अनिवार्य शर्त माना जाता है अथवा केन्स की उस भावना से, जिसके अनुसार इन साधनों पर राजकीय नियंत्रण को आर्थिक दृष्टि से वांछित माना जाता है।⁵

संस्थापकोत्तर सिद्धान्त

जॉन मेनार्ड केन्स (1883—1946)

जो केन्स का नाम केवल अल्पकाल के समय में उसके इस प्रमुख कथन कि 'दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं' से याद करते हैं, उन्हें दीर्घकाल के सम्बन्ध

1. जे० ए० शुम्पीटर, *ब्यूजिनेस साइकिल्स*, मैग्रू-हिल न्यूयार्क 1933, एम० कैले की, 'थियरी ऑफ इकानामिक डायनमिक्स' राइनहार्ट, न्यूयार्क 1951 (विशेषतः छठा खंड), एन० कैलडोर 'दि रिलेशन ऑफ इकानामिक ग्रोथ एंड साइकलिकल फ्लक्चुएशन' इकानामिक जरनल, मार्च, 1954, आर० ए० गोडविन, 'ए मोडल ऑफ साइकलिकल ग्रोथ', 'दि ब्यूजिनेस साइकिल इन दि पोस्ट-वार वर्ल्ड' इ० लववर्ग द्वारा संपादित, मैकमिलन लंदन, 1955।
2. देखें इनके *केल्कुलेटेड इकानामिक पेपर्स*, केसी, न्यूयार्क 1951 में 'भावसं एंड केन्स' तथा इनका 'एन एसे इन मार्क्सियन इकानामिक्स' लंदन 1942।
3. देखें, एम० वोनफेबनर का 'इकानामिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल चेंज', लंदन, 1942 'दि अपील ऑफ कन्फिर्मेशन इन इकानामिक डेवलपमेंट'।
4. मार्क्स के इन परिकल्पित विचारों तथा उसके निश्चित आर्थिक सिद्धान्तों के सारांश के लिए देखें ए० रोल का 'ए हिस्ट्री ऑफ इकानामिक थॉट' (तृतीय संस्करण) का छठा अध्याय पेरनटिश हाल, न्यूयार्क, 1956।
5. इनके स्वामित्व की तुलना में नियंत्रण की अभिरुचि के कारणों के लिए 'जनरल थियरी' की पृष्ठ-संख्या 378-81 देखें।

उसकी देन को जानकर थोड़ा-बहुत आश्चर्य हो सकता है। निश्चय ही, केन्स की सर्वाधिक प्रमुख सैद्धांतिक देन अल्पकालीन आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्र में ही है। किन्तु जैसा कि उसकी विभिन्न रचनाओं के पाठक जानते हैं, उसका 'अल्पकाल' भी इतना छोटा नहीं था कि उसे 'दीर्घकाल' में जाने के लिए किसी विशेष प्रकाश की आवश्यकता पड़ती। साथ ही, केन्स की अंतर्दृष्टि एवं सिद्धान्त अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से, विशेषतः उनसे, जो सत्तावादी प्रणाली की जगह गणतंत्रवादी प्रणाली से अपना विकास करना चाहती हैं, सामान्यतः माने जाने की अपेक्षा अधिक सम्बद्ध हैं।¹ अतः, आर्थिक विकास के सिद्धान्त के सम्बन्ध में केन्स की क्या देन है? इसका कम-से-कम निम्नलिखित उत्तर है :

केन्स की व्यापक अंतर्दृष्टियों से हम प्रारम्भ करें। अपने 'इकानामिक पोसिबिलिटिज ऑफ आवर ग्रैंड चिल्ड्रेन' (1930) शीर्षक लेख में केन्स ने यह सुझाव दिया था कि भविष्य में आर्थिक गति की प्रगति निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगी : (क) जनसंख्या को नियंत्रित करने की हमारी शक्ति, (ख) युद्ध एवं नागरिक मतभेदों को दूर करने का हमारा निश्चय, (ग) विज्ञान से सम्बद्ध सभी बातों को विज्ञान के जिम्मे सुपुर्द करने की हमारी इच्छा, तथा (घ) हमारे उत्पादन एवं उपभोग के बीच की सीमा के द्वारा निर्धारित संचय की गति।² इसमें हम आर्थिक प्रगति की मौलिक शक्तों की व्यापक रूप-रेखा पाते हैं, जिसमें एक ओर संस्थापक विचारों के पांडित्य तथा दूसरी ओर समसामयिक लेखकों के जटिल विकास-प्रतिमानों का पूरा-पूरा समावेश है। ऐसी व्यापक अंतःप्रज्ञा अंतर्दृष्टि को क्रियात्मक महत्व देने के कार्य का भार केन्सोत्तर अर्थशास्त्रियों के लिए छोड़ दिया गया। किन्तु जैसा कि हम शीघ्र ही देखेंगे, स्वयं केन्स ने आर्थिक प्रगति की निर्धारित दर से सम्बद्ध मापनीय एवं परीक्षणीय प्राक्कल्पना की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य आरम्भ किया था।

केन्स ने पूँजीवादी विकास का कोई क्रमबद्ध विश्लेषण नहीं किया, किन्तु अपनी पुस्तक 'जेनरल थियरी' में कई छिट-फुट तथा विषयांतरिक टिप्पणी की, जिनकी तुलना मार्क्स के पूर्ववर्णित विचारों एवं शूम्पीटर के अनुवर्णित सिद्धान्तों से करना बहुत ही रोचक होगा। पूँजीवाद के भविष्य की संभावनाओं के सम्बन्ध में यदि मार्क्स मंदी का भविष्यवक्ता था, तो केन्स को तेजी का भविष्यवक्ता कहा जा सकता है।

1. अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं पर केन्स के सुस्पष्ट प्रभावों की व्याख्या के लिए देखें, जयपुर के दिसम्बर, 1953 ई० के इण्डियन इकानामिक एसोसिएशन का 'केन्सोनियन इकानामिक्स इन रिलेशन टू अंडरडेवलपड कौन्ट्रीज'। साथ ही, केन्स की 10वीं वरसी के उपलक्ष में प्रकाशित जुलाई 1956 ई० का 'इण्डियन जरनल ऑफ इकानामिक्स' भी देखें।

2. देखें इनका 'इसेज इन परसुएशन' पृष्ठ 373।

क्योंकि केन्स ने पूँजीवादी व्यवस्था को तत्त्वतः एक ऐसी व्यवस्था माना है, जिसमें ऐसे सुधार किये जा सकते हैं, ऐसी तरक्की लाई जा सकती है, जिससे यह मानव-प्रगति के आर्थिक आनन्द के उस गतव्य स्थान की ओर जाने में बाधक न होकर सहायक हो सके, जहाँ धन का संचय कोई विशेष सामाजिक महत्त्व नहीं रखता तथा आध्यात्मिक एवं कलात्मक उन्नति-सम्बन्धी प्रयत्न निर्विरोध गति पा सकता है। इसके ठीक विपरीत मार्क्स (और शुम्पीटर भी) पूँजीवाद को सारभूत रूप में एक ऐसी रचना मानता है, जो अनुमानतः आत्मनाश का बीज रखता हुआ क्षयग्रस्त होने के लिए और अपने अस्तित्व से रहित होने के लिए वृद्धिशील होता है। फिर भी, केन्स के 'स्थिरता के सिद्धान्त' में मार्क्स के 'विघटन के सिद्धान्त', प्रतिबल-प्राप्त चिरकालिक अपूर्ण उपभोग, अनि उत्पादन, मुनाफे की घटती हुई दीर्घकालिक दर जैसे अतृप्त तत्त्वों को आधुनिक अभिव्यक्ति दी।¹ किन्तु, इनमें प्रधान व्यावहारिक अंतर यह है कि केन्स ने आयोजित राजकीय क्रिया द्वारा अवैधनीतिक पूँजीवाद के समोधन में इसके निदान की खोज की, जबकि मार्क्स ने यह कहकर कि इससे अनिवार्यतः एक निरपवाद रूप से सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के बदले केवल पूँजीवादी वर्ग को ही लाभ होता है, किसी अथवा सभी प्रकार की राजकीय क्रियाओं को दुष्टता के साथ अस्वीकार किया।

केन्स के अपेक्षाकृत अधिक प्राविधिक पक्ष की ओर ध्यान देने पर हम प्रथमतः एक सर्वोपरि समर्थ माँग के सिद्धान्त को पाते हैं, जिसके वगैर हैरोड के सिद्धान्त का उद्भव सम्भव ही नहीं था। क्योंकि स्तर के रूप में यह केन्स के वृद्धि-विनियोग सन्तुलन की स्थैतिक दशा से, जैसा कि हिक्स ने बतलाया, अनुपात के रूप में हैरोड के वृद्धि-विनियोग सन्तुलन की गत्यात्मक दशा और फलतः, जैसा कि अगले अध्यायों में व्याख्या की जायगी, हैरोड के 'बाछित विकास-दर' तक जाने की ओर पहला तर्कसंगत कदम है। हैरोड का मूल गत्यात्मक लेख² दोनो कारणों से ध्यानाकर्षक है, प्रथमतः तो हैरोड को इतनी अधिक कल्पना एक पूर्व दृष्टि प्राप्त थी कि ऐसे समय में, जबकि सभी समसामयिक लेखक अल्पकालीन विचारों में ही तल्लीन थे, वह अपना ध्यान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन विचारों की ओर लगा सका। द्वितीय 'इकानामिक जनरल' के संपादक के रूप में केन्स ने स्पष्टतया उदारतापूर्वक एवं बीद्धिक

1. तुलना कीजिए, 'पोस्ट-केन्सीयन इकानामिक्स' (के० कुरीहारा द्वारा संपादित), रजर-विश्वविद्यालय प्रेस एवं एलेन एंड अनविन, 1954 में प्रकाशित, एस० सुह (S Jsuru) का लेख 'केन्स वरसेज मार्क्स . दि मेथोडोलौजी ऑफ एप्रोपेट्स'।
2. देखें, ई, 1949 ई० के इकानामिका में प्रकाशित इनका 'मि० हैरोड्स डायनमिक थियरी'।
3. देखें, मार्च, 1939 के इकानामिक जनरल में इनका निबंध 'एन एसे इन डायनमिक थियरी'।

क्षमता का परिचय देते हुए अपने शिष्य के लेख को प्रकाशित कर दिया, जिसमें वचत की माँग के ह्रासमान पहलू, जिस पर केन्स स्वयं जोर देते थे, के विरुद्ध क्षमताकारक पहलुओं पर जोर दिया गया था। हैरोड के विकास-सम्बन्धी आदर्श की ही तरह, डोमर ने भी केन्स के गुणक सिद्धान्त (विनियोग की माँग अथवा आय-प्रभाव) एवं उत्पादकता के संस्थापक सिद्धान्त (विनियोग के सिगमा-प्रभाव) के संश्लेषण का प्रयास किया।¹

पूर्ति की दी हुई दशाओं में (विशेषतः पूँजी स्थायी स्टॉक के साथ), जब एक बार उत्पादन का स्तर प्रभावकारी माँग के द्वारा निर्धारित होता है तो केन्स के अल्पकालीन सिद्धान्त की ही तरह दूसरा तार्किक प्रश्न यह होता है : यदि पूँजी के स्टॉक में वृद्धि से पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन हो जाय तो उस निपज का क्या होगा ? गत्यात्मक अर्थशास्त्र में इस प्रकार का प्रश्न होता है तथा उसका जवाब भी दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार श्रीमती जॉन रॉविन्सन ने प्रासंगिक ढँग से कहा है कि यह इस विरोधाभास की व्याख्या करता है कि केन्स की 'जनरल थियरी' का रूप स्थैतिक होते हुए भी इसने गत्यात्मक समस्याओं के विश्लेषण के लिए मार्ग तैयार किया है।² इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीमती रॉविन्सन³ के साथ-साथ नस्के⁴ ने गत्यात्मक अर्थशास्त्र को अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की दिशा में मोड़ दिया। दोनों ने ही विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए विनियोग-सम्बन्धी माँग एवं पूँजी-निर्माण के कारणात्मक महत्त्व पर जोर दिया। अब भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पूँजी में अभिवृद्धि, जैसा कि संस्थापक अर्थशास्त्रियों का विचार था, उपभोग में कमी के बगैर नहीं हो सकती अथवा जैसा कि केन्स ने कहा है, उपभोग में साथ-साथ वृद्धि के बगैर असम्भव है, अथवा जैसा कि नस्के⁵ का विचार है उपभोग में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के भी सम्भव है।

केन्स का राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी विश्लेषण विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने का न्यूनतम आधार है। साथ ही यह वचत, उपभोग, विनियोग, रोजगार तथा परि-

1. देखें डोमर-का वहीं।
2. द्रष्टव्य 'दि रेट ऑफ इंटररेस्ट एंड अदर एसेज' लंदन, 1952 के प्राक्कथन में।
3. आर० नस्के, प्रोब्लेम्स ऑफ कैपिटल फारमेशन इन अंडरडेवलप्ड कौन्ट्रीज' ब्लेकवेल, ओक्सफोर्ड, 1953।
4. जे० रॉविन्सन-का मार्च, 1949 के 'इकानामिक जरनल में मि० होरोड्स डायनामिक्स' तथा 'दि रेट ऑफ इंटररेस्ट' इत्यादि।
5. नस्के के विचारों की विस्तारपूर्वक व्याख्या सम्भाव्य वचत के रूप में छिपी हुई बेरोज़गारी के सम्बन्ध में की जाएगी। नस्के के 'संतुलित विकास' के सिद्धान्त के व्यापक मूल्यांकन के लिए 11वां अध्याय देखें।

चालन की दृष्टि से अधिक विकास के महत्वपूर्ण अन्य परिवर्तियों के अनुमान का प्राविधिक आधार है। यहाँ इस साधारण बात की चर्चा केवल इसलिए की गई है कि कभी-कभी व्यवहार में मनुष्य इसकी अपेक्षा करते हैं तथा यह जानने की कोशिश भी नहीं करते कि राष्ट्रीय आय की गणना के सैद्धांतिक आधार का उद्गम क्या है ?

वास्तव में, कोई भी व्यक्ति परिचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तरीके से आर्थिक विकास की चर्चा केन्स के 'जनरल थियरी' में उद्धृत मात्रा एवं फलनीय सम्बन्ध की चर्चा किये बिना नहीं कर सकता। किन्तु, जैसा कि हैरोड ने कहा है दीर्घ-कालीन विश्लेषण में इन परिवर्तियों को जनसंख्या, प्रविधि तथा साधन जैसी मौलिक शर्तों से पूर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही, केन्स की राष्ट्रीय आय का विश्लेषण इस बात की सतत याद दिलाता है कि बिना किसी सिद्धान्त अथवा स्वीकार्य प्राक्कल्पना के, जिससे कि राष्ट्रीय आय के अवयवों (उपभोग एवं विनियोग) की प्रवृत्ति की सार्थक व्याख्या में सुगमता हो और विशेषतः जिससे प्राविधिक सीमाओं के अन्दर वास्तविक अर्द्ध-विकसित देशों के सफल औद्योगीकरण को निर्देश मिल सके, किसी सांख्यिकीय सामग्री का सग्रह एवं माप-सम्बन्धी प्रविधि की सूक्ष्मता बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ करती।

केन्स की अन्तिम महत्वपूर्ण देन पुनर्निर्माण एवं विकासार्थ, विश्व-बैंक की स्थापना के विचारों से सम्बद्ध है। हैरोड ने केन्स के जीवन-वृत्तान्त में इसकी बड़े ही रोचक ढंग से व्याख्या की है।¹ यहाँ केन्स ने मार्क्स एवं उसके अनुयायियों के इस विचार का कि आर्थिक क्षेत्र में विकसित पूँजीवादी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विपत्ति का आधार पर स्थायी रूप से पिछड़े राष्ट्रों का शोषण करते हैं,² पूरी तरह से खंडन किया है। वास्तव में, केन्स अन्तर्राष्ट्रीय समागीकरण को विश्व-व्यापी समृद्धि एवं स्थायी विश्व-शांति का साधन मानता था। वह विश्व के सपन्न सदस्य-राष्ट्रों की वृद्धि की संभावनाओं को विपन्न राष्ट्रों की विकास-सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए विश्व-बैंक को एक प्रधान साधन समझता था। इस सम्बन्ध में बैंक के ऋण की विस्तृत कार्यवाही नहीं, जिसमें समय-समय पर सुधार एवं परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है, बल्कि पुनर्निर्माण एवं विकास के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विश्व-बैंक का विचार ही मौलिक एवं महत्वपूर्ण दोनों है। इस विचार का श्रेय केन्स की साहसिक कल्पना एवं वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीयता को है। सामान्य रूप से विभिन्न

1. देखें, इनका 'वि लाइफ आफ जॉन मेनार्ड केन्स' हरकार्ट, ब्रेस एवं कम्पनी, न्यूयार्क, 1951।

2. देखें, सितम्बर 1952 के 'सोशल रिसर्च' में ई० हेमन का 'मार्क्सिज्म एंड अंडर-डेवलप्ड कंट्रीज'।

राष्ट्रों के भविष्य के आचरण पर तथा विशिष्ट रूप से अल्प-विकसित राष्ट्रों के भावी आर्थिक विकास पर इसके महत्त्वपूर्ण प्रभाव की आशा की जाती है।¹

जोसेफ ए० शुम्पीटर (1883-1950)

शुम्पीटर पहला आधुनिक अर्थशास्त्री था, जिसने आर्थिक विकास को आर्थिक विक्षेपण के एक विशिष्ट क्षेत्र का रूप दिया। ऐसा उसने 1911 ई० में जर्मन भाषा में प्रकाशित तत्कालीन बहुत कम प्रसारित पुस्तक 'दि थियरी आफ इकनामिक डेवलपमेंट' में किया। २३ वर्षों के बाद इस पुस्तक के अंग्रेजी-संस्करण के प्रकाशन का भी बहुत ही कम प्रभाव पड़ा; क्योंकि उस समय मंदी एवं बड़े पैमाने पर बेरोजगारी जैसी गम्भीर अल्पकालीन समस्याओं में उलझे रहने के कारण विश्व को दीर्घकालीन समस्याओं की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देने का अवसर नहीं था। केवल वर्तमान युद्धोत्तरकालीन पुनर्निर्माण एवं विकास, जो चक्रीय समस्याओं में ह्रास के कारण² ही सम्भव हुआ है, के समय में अर्थशास्त्रियों ने शुम्पीटर के आर्थिक विकास के सिद्धान्त की ओर नये दृष्टिकोण से देखना आरम्भ किया है। किन्तु शुम्पीटर के सिद्धान्त³ के सैद्धांतिक एवं संस्थागत अधिस्वरों ने इसके प्राविधिक महत्त्व को कम तथा इसकी व्यावहारिक प्रयोज्यता को सीमित बना दिया है।

शुम्पीटर के अनुसार साहसी (नयी रीति चलाने वाला), नवीन क्रिया एवं साख की अस्थिर अन्तःक्रियाओं के परिणामस्वरूप पूँजीवाद का विकास भटके से होता है। अतः, अपने सफल निष्पत्तियों जैसे सामूहिक उत्पादन, सामूहिक शिक्षा एवं बृहत् व्यापार तथा इसके आवश्यक सहगामियों—जैसे राजकीय नियमन, वौद्धिक रोप तथा श्रमिक संघवाद के परिणामस्वरूप यह निश्चय ही समाजवाद के किसी-न किसी रूप के समक्ष अपने को अर्पित कर देगा। यहाँ शुम्पीटर मार्क्स के पूँजीवाद के अवश्यभावी विघटन की धारणा से सहमत है।⁴ यद्यपि शुम्पीटर इसके लिए पूँजीवाद की सफलता को उत्तरदायी मानते हैं, मार्क्स इसके लिए इसकी असफलता को उत्तरदायी ठहराते हैं। जो भी हो, ऐतिहासिक आर्थिक विकास के संस्थागत वास्तविक व्याख्यात्मक

1. देखें, यूनाइटेड नेशन्स का न्यूयार्क, 1951 में प्रकाशित 'मेयर्स फॉर दि इकनामिक डेवलपमेंट आफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज'। साथ ही, इस पुस्तक का परिशिष्ट भी देखें।
2. इस ह्रास के कुछ कारणों के लिए देखें, पूर्व उद्धृत 'दि व्यूजीनेस साईकिल इन दि पोस्ट वार वर्ल्ड'।
3. विशेषतः, जैसा कि उसके बाद पुस्तक 'कैपिटलिज्म, सोसलिज्म एवं डेमोक्रेसी' में विस्तृत किया गया है।
4. मई, 1950 ई० के 'अमेरिकन इकॉनामिक रिव्यू' में शुम्पीटर का अन्तिम संदेश देखें।

परिवर्त्ती के रूप में साहसी, नवीन क्रिया एवं साख के वर्णात्मक महत्त्व को कम ही लोग अस्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि निजी उपक्रम एवं जोखिम उठाने का अभाव, नवीन क्रिया में पटुता की अनुपस्थिति तथा बैंकिंग की सुविधाओं एवं पूँजी बाजार की आदिम अवस्था आज भी अल्प-विकसित बाजार सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्थाओं की सामान्य सस्थागत विशेषताएँ हैं।

किन्तु आज की मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के युग में शुम्पीटर द्वारा केवल निजी उद्यमकर्त्ता के रूप में नवीन क्रियाकारक की व्याख्या को निर्विवाद रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।¹ किन्तु जहाँ तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, इससे भी अधिक विवादास्पद उसकी नवीन क्रिया-सम्बन्धी अत्यधिक आशावादी धारणा है। यदि नवीन क्रिया उत्पादन की मुधरी हुई प्रविधि का रूप धारण करती है, तो इससे पूँजी के वर्तमान कोप में बिना किसी परिवर्त्तन के ही धर्म की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि हो सकती है। धर्म की उत्पादन-क्षमता में इस प्रकार की वृद्धि वा पूँजी-विपन्न अर्थ-व्यवस्थाओं में निश्चय ही स्वागत होगा। किन्तु यदि पूँजी-विपन्न अर्थ-व्यवस्था की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में पूँजी के दिये हुए कोण की तुलना में धर्म की कम आवश्यकता वाली प्रविधियों को अपनाने में बेरोजगारी की समस्या में भी वृद्धि होगी। किन्तु, इसके विपरीत यदि नवीन क्रिया विस्तारित मयत्र एवं उपकरण का रूप धारण करती है, तो इसका लाभ यह होता है कि इससे उत्पादन की प्रविधि में बिना किसी आवश्यक परिवर्त्तन के ही धर्म की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि होती है। किन्तु तब संभव है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में नये मयत्र एवं उपकरण-सम्बन्धी नवीन क्रिया-निवेश के लिए पर्याप्त मात्रा में वचन नहीं हो। और पुनः चूँकि नवीन क्रिया-निवेश लाभ की निजी प्रत्याशा तथा पूँजी प्रयोग की प्राविधिक स्थिति पर निर्भर करता है, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए इस प्रकार का निवेश तीव्र आर्थिक विकास के लिए पूँजी-संचय का विश्वस्त साधन नहीं भी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि लाभ की विविधता एवं प्रविधि की गत्यात्मकता सदा इस प्रकार की नहीं होती, जो अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में वांछित मात्रा में नवीन क्रिया-निवेश को प्रोत्साहित करे।²

निजी साख के महत्त्व पर शुम्पीटर द्वारा दिया गया जोर पूँजीवाद के विकास में बैंक-साख एवं निगम ऋण-इविवटी, वित्त-व्यवस्था के ऐतिहासिक महत्त्व को उचित रूप में प्रतिबिम्बित करता है। फिर भी, यह केवल इस प्रकार के मीट्रिक साधनों

1. देखें, डब्लू. एं. लीवीस की एलेन एंड अनवीन, लंदन, 1955 द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'दि थियरी आफ इकानामिक प्रोग्रेस'।
2. देखें, एं. जोशिदा की 'शुम्पेटेरियन सिस्टम एवं मोनोपली' तथा जून, 1957 के 'इकानामिक स्टडीज क्वार्टली' में प्रकाशित के शिवयामा का 'मोनोपली एंड इकानामिक डेवलपमेंट'।

(यानी उत्पादन में से उपभोग घटाने पर प्राप्त वास्तविक वचत) के वास्तविक आधार को दुर्वोध ही नहीं बनाता, वरन् राजकीय साख, घाटे की वित्त-व्यवस्था, वजट की वचतें तथा सरकार के अन्य राजकोपीय कार्यों को भी पृथक् कर देता है। साथ ही, यह कहना कि बैंकिंग की सुविधाओं में विकास से औद्योगीकरण में सहायता मिलती है, स्वयं सिद्ध ही है। क्योंकि इसका तात्पर्य केवल संस्थापकों के इस विचार को दुहराना है कि मुद्रा एवं बैंकिंग-सम्बन्धी संस्थाएँ वस्तु-विनिमय-व्यवस्था से विनिमय व्यवस्था के संक्रमण में शीघ्रतापूर्वक पहुँचती हैं। वास्तव में, विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने में इस बात का सुझाव—कि किस प्रकार राजकोपीय एवं मौद्रिक नीति से निपज में वृद्धि की दर में वृद्धि होगी अथवा किस प्रकार एक दिये हुए दर पर निपज में वृद्धि के स्थायित्व को प्रोत्साहित किया जा सकता है, अधिक लाभदायक होगा।

इसके बावजूद, आर्थिक विचारधारा के इतिहास में शुम्पीटर का नाम प्रविधि की गत्यात्मकता पर, दोनों सामान्य आर्थिक विकास के एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण एवं विणिष्ट रूप से चक्रीय विकास की प्रमुख व्याख्या के रूप में अन्य अर्थ-शास्त्रियों की अपेक्षा अधिक जोर देने के कारण स्मरणीय होगा। संस्थानिक कारणों पर अधिक जोर देने का कारण, शुम्पीटर के आर्थिक विकास का सिद्धान्त, उसके अभिप्राय के विरुद्ध, उन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को अधिक आकर्षक लगेगा, जो परम्परा से अलग होने के लिए उग्र रूप में तैयार हैं।

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की संरचना

किसी भी आचरण-सम्बन्धी विश्लेषण के लिए सर्वप्रथम संरचनात्मक विश्लेषण अनिवार्य है। सभी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में सर्वनिष्ठ मौलिक समस्याओं का गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की संरचनात्मक विशेषताओं तथा इसके निर्धारक तत्त्वों का विवेचन अनिवार्य है। किन्तु इस सम्बन्ध में हम केवल उन्हीं विशेषताओं तथा निर्धारक तत्त्वों का वर्णन करेंगे, जो परिचालन की दृष्टि से अति मार्थक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इस पर्यवेक्षण-सम्बन्धी अध्याय में विचार-वस्तु को तोरण करने के लिए हम अल्प-विकसित एवं विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की विषमताओं की तुलना करने चलेंगे।

अल्प आर्थिक विकास के सूचक

प्रति व्यक्ति न्यून वास्तविक आय

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को चित्रित करने के लिए चाहे जितने भी अन्य सूचकों की चर्चा की जाय, शायद एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचक प्रति-व्यक्ति न्यून वास्तविक आय है। 'प्रति-व्यक्ति' विशेषक वाक्यांश एक अन्यथा अनादर्शी सूचक में कल्याण का अंश जोड़ देता है, क्योंकि इससे शीघ्र ही यह स्पष्ट हो जाता है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था एक ऐसे समुदाय का प्रतिनिधित्व भी करती है, जिसकी भौतिक समृद्धि प्रति-व्यक्ति उपभोग के रूप में सदियों से प्रगतिहीन रही है। माथ ही यह इस बात की ओर भी संकेत करता है कि कोई अर्थ-व्यवस्था अनिवार्यतः केवल इसलिए अल्प-विकसित नहीं हो सकती कि उसकी प्रजनन की प्रवृत्ति उसकी उत्पादन-क्षमता से अधिक बलवती है, वरन् सम्भवतः इसलिए भी कि उसकी उत्पादन-क्षमता प्रजनन की प्रवृत्ति की अपेक्षा अधिक कमजोर है। अतः, एवं, 'प्रति-व्यक्ति' विशेषक अल्प-जनसंख्या वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के साथ-साथ जनाधिक्य वाली अधिक सामान्य स्थिति को भी सम्भाल सकता है।¹ जहाँ

1. 'प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय' को $y = Y/P$ के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें y औसत आय, Y , वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं P जनसंख्या का आकार है। अतएव प्रति-व्यक्ति राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास की अपेक्षा आर्थिक प्रगति का अच्छा माप है। यह विभेद इसलिए महत्वपूर्ण है कि ऐसी स्थिति में जबकि जनसंख्या में वृद्धि उपज में वृद्धि से अधिक होती है, जिसमें कि प्रति-व्यक्ति स्थिति पहले से भी खराब है, कोई आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती है।

तक उपर्युक्त सूचक में सन्निहित 'वास्तविक राष्ट्रीय आय,¹ का प्रश्न है, इससे निपज के भौतिक परिमाण एवं उसके मौद्रिक मूल्य के बीच जो अन्तर है, उसे जानने में सहायता मिलती है। उत्पादित एवं उपभुक्त भौतिक पदार्थों के रूप में उत्पादकता एवं कल्याण का वास्तविक माप उत्पादन का भौतिक परिमाण होता है, न कि उसका मौद्रिक मूल्य। साथ ही वास्तविक आय की धारणा हमें मौद्रिक लाभदायकता को भौतिक उत्पादकता का प्रतिनिधि मान लेने की निकटदर्शी भूल से बचाती है। यह एक ऐसी भूल है, जिससे अनुमानतः उत्पादक साधनों का भारी अपनिर्देशन हो सकता है, जो दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए संभवतः अहितकर है।

अपर्याप्त प्राकृतिक साधन

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था का एक अन्य परिचालन-सम्बन्धी सूचक जनसंख्या² के आकार के अनुरूप अपर्याप्त प्राकृतिक साधन है। यह अपुनरुत्पादनीय एवं क्षयशील भौतिक सम्पत्ति, विशेषतः प्रति संतुलन टेक्नोलॉजी की अनुपस्थिति में इतना अधिक महत्त्वपूर्ण एवं मानव कल्याणकारी जान पड़ता है कि संस्थापक अर्थशास्त्रियों ने भूमि को, पुनरुत्पादनीय पूँजी और थम के समकक्ष, उत्पादन के एक पृथक् साधन का रूप दिया था। इन संस्थापक अर्थशास्त्रियों में कुछ तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में सम्पूर्ण भूमि की लोचहीनता से इतना अधिक प्रभावित हुए कि वे इस शोक-पूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचे कि क्रमागत उत्पत्ति-ह्रास-नियम की निरंतर क्रियाशीलता से जीवन-मान अवनत रहेगा। यद्यपि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से विकसित अर्थ-व्यवस्थाएं विशालकाय उत्पादन की मितव्ययिताओं से अत्यधिक लाभान्वित अवश्य हुई हैं, किन्तु टेक्नोलॉजी की दृष्टि से पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्थाएँ, जिनकी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है तथा जिनमें प्राकृतिक साधनों का अभाव है, अभी तक विभिन्न ढंग से क्रमागत उत्पत्ति-ह्रास-नियम के निर्मम परिचालन के प्रभाव में रहे हैं।

अपवादस्वरूप कुछ देशों को छोड़कर वास्तविक रूप में अधिकांश अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को जनाधिक्य की समस्या का सामना करना पड़ता है;

1. वास्तविक राष्ट्रीय आय को $Y_r = Y_m/P(t)$ के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें Y_m मौद्रिक आय तथा t समय में $P(t)$ औसत मूल्य (चुने हुए आधार-काल की तुलना में) हैं। दीर्घकालीन विश्लेषण के लिए वास्तविक आय का आचरण ही महत्त्वपूर्ण है।
2. देखें, डब्लू० एस० एण्ड ई० एस० वायट्स्की, वर्ल्ड पापुलेशन एण्ड प्रोडक्शन, ट्वेन्टीयेथ सेन्चुरी फंड, न्यूयार्क, 1953।

क्योंकि इनमें मुख्य प्राकृतिक साधनों¹ (जैसे कृष्य-भूमि, कोयला, तेल तथा लोहे का भण्डार एवं वन) का प्रति-व्यक्ति औसत परिमाण इतना कम रहता है कि इससे इनके ठोस औद्योगीकरण एवं 'अपेक्षाधिक जनसंख्या' की समस्या के समाधान में कोई सहायता नहीं मिलती। किन्तु इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई देश प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधनों के होते हुए भी इन्हे विकसित करने के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी तथा पूँजी के अभाव में साधन-विहीन देश की ही तरह निर्धन होगा। फिर भी प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता स्वयं टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रगति की एक अनुकूलतम शर्त है। इस प्रकार विचार करने से, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था से सम्भवतः जनाधिक्य वाले राष्ट्र का भी केवल इसलिए बोध हो सकता है कि आज की अल्प-विकसित, विशेषतः टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई, अर्थ-व्यवस्थाओं में प्राकृतिक साधनों का अभाव माल्यम की चेतावनी के उपदेशात्मक महत्त्व पर जोर देता है।

अपर्याप्त पूँजीगत साधन

स्थूल पूँजी की अपर्याप्तता अल्प-विकसित देशों की एक ऐसी प्रमुख विशेषता है कि कभी-कभी इन्हे केवल 'पूँजी-विपन्न' अर्थ-व्यवस्था की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, आर्थिक विकास में पूँजी का योगदान इतना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कुछ लेखक अन्य तथ्यों² पर बहुत कम ध्यान देने हैं। चूँकि किसी निश्चित समय में वर्तमान स्थूल पूँजी का कोष विगत वचत एवं विनियोग का परिणाम होता है, अतएव यह कहा जा सकता है कि अपेक्षाकृत अल्प पूँजी के कोषवाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था निम्न वचत एवं निम्न विनियोग वाले समुदाय का भी प्रति-निधित्व करती है। इस निम्न वचत एवं निम्न विनियोग वाली स्थिति के लिए

1. किसी अर्थ-व्यवस्था में कृषि-योग्य भूमि के अतिरिक्त अन्य साधनों की जितनी ही अधिक प्रचुरता रहती है, वह उतना ही अधिक घरेलू निर्माण उद्योगों के विकास द्वारा खाद्य-पदार्थों के बदले अन्य वस्तुओं का निर्यात कर माल्यम के जनाधिक्य की समस्या के समाधान के योग्य होता है। ग्रेट-ब्रिटेन पहले ऐसा ही करता था और मुख्य चीन आजकल ऐसा ही करने का प्रयास कर रहा है। किन्तु, यदि किसी देश में घटती हुई जनसंख्या की तुलना में कृषि-योग्य भूमि एवं अन्य प्राकृतिक साधन दोनों का अभाव है, उसके लिए माल्यम द्वारा वर्णित समस्या और भी गंभीर हो जाती है। अत्यधिक औद्योगिक राष्ट्र होते हुए भी जापान के साथ यही बात पाई जाती है। यदि प्राकृतिक साधनों का अभाव नहीं होता, तो जापान पश्चिमी अर्थ-व्यवस्थाओं से सम्भवतः कम विकसित नहीं होता।
2. उदाहरण के लिए देखें, आर० नवर्से की पुस्तक 'प्रोब्लेम्स ऑफ कैपिटल फारमेशन इन अंडरडेवलप्ड कॉन्ट्रीज'।

निम्न पारिवारिक आय, मितव्ययी मध्यम वर्ग की स्वल्पता, पूँजी-वाजार एवं वचत वाली अन्य संस्थाओं का दोषपूर्ण संगठन, सम्पन्न वर्ग द्वारा प्रदर्शन, उपभोग तथा वचत की आदत को प्रभावित करने वाले अन्य तथ्यों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूँजी की अपर्याप्त पूर्ति के माप के रूप में अल्प वचत सभी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की एक सर्वनिष्ठ समस्या है। किन्तु पूँजी की माँग (विनियोग के पूर्व) केवल अल्प-विकसित अर्थव्यवस्थाओं की ही समस्या नहीं है।

यदि यह मान लिया जाय कि समाज में जितनी वचत होती है, ठीक उतनी ही रकम का विनियोग होता है, तो समाज की पूँजी का स्टाक बढ़ रहा है, स्थायी है अथवा ह्रासमान है, इस आधार पर आर्थिक विकास के तीन प्रतिरूप बतलाये जा सकते हैं।¹ इस प्रकार यदि समाज अपने शुद्ध उत्पादन से कम का उपभोग करता है, जिससे पूँजी के वर्तमान कोष अथवा शुद्ध विनियोग² में वृद्धि हो रही हो तो इसे प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था की संज्ञा दी जा सकती है। पुनः यदि समाज अपने शुद्ध उत्पादन का पूरा-पूरा उपभोग करता है, जिससे शुद्ध विनियोग शून्य के बराबर होता है, तो इसे स्थैतिक अर्थ-व्यवस्था कहा जा सकता है। अंततः, यदि समाज अपने शुद्ध उत्पादन से भी अधिक का उपभोग करता है जिससे शुद्ध विनियोग ऋणात्मक होता है, यानी प्रतिस्थापन के बगैर ही पूँजी के कोष में कमी आ रही हो तो इसे ह्रास-मान अर्थ-व्यवस्था कहा जा सकता है। अतएव, यदि किसी देश के पास पूँजी का सतत-प्रवाही कोष अल्प मात्रा में हो तो इससे तीव्र आर्थिक विकास के विरुद्ध परिकल्पना विरचित होती है।

1. इन प्रतिरूपों को प्रतीकात्मक रूप में निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है—

प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था : $(dy/dt) > 0$ कारण कि $(dk/dt) > 0, (y > c, s=1 > 0)$ ।

स्थैतिक अर्थ-व्यवस्था : $(dy/dt) = 0$ कारण कि $(dk/dt) = 0, (y = c, s=1=0)$ ।

ह्रासमान अर्थ-व्यवस्था : $(dy/dt) < 0$ कारण कि $(dk/dt) < 0, (y < c, s=1 < 0)$ ।

यहाँ पर y विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति, k वास्तविक पूँजी, c उपभोग, s वचत, l विशुद्ध विनियोग तथा t समय है।

2. एस० कुजेन्ट्स के अनुसार वर्तमान समय में अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में शुद्ध विनियोग की दर राष्ट्रीय उत्पत्ति के 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक तथा विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में 10 से 15 प्रतिशत तक होती है। (देखें, मार्च, 1955 ई० के 'अमेरिकन इकानॉमिक रिव्यू' में इनका 'इकानॉमिक ग्रोथ एण्ड इनकम इन इक्विलिटी')।

टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी पिछड़ापन

औसत उत्पादन व्यय अथवा उत्पादन से सम्बद्ध श्रम या पूँजी के ऊँचे अनुपात के रूप में मापने पर पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी की स्थिति में एक और भी परिचालन-सम्बन्धी सूचक अवलोकित हो सकता है। साधारणतः टेक्नोलॉजी की दृष्टि से अग्रवर्ती अर्थ-व्यवस्थाओं की अपेक्षा टेक्नोलॉजी की दृष्टि से मंद पड़ी हुई अर्थ-व्यवस्थाओं में उत्पादन की संपूर्ण श्रुद्ध लागत (यानी एक निश्चित मात्रा में उत्पादन के लिए पूँजी, श्रम एवं अन्य साधनों का आगत) अधिक होती है। इसी वास्तविक अर्थ में उत्पादन के मौद्रिक व्यय में सम्मिलित अल्प-मौद्रिक मजदूरी के वावजूद, बड़े पैमाने पर उत्पादन की मितव्ययिता के परिणामस्वरूप एक अग्रवर्ती अर्थ-व्यवस्था अल्प लागत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है।

साथ ही टेक्नोलॉजी की दृष्टि से पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था में साधनों का मूल्य (मजदूरी, व्याज इत्यादि) स्थायी दिया हुआ होने पर, सम्भवतः नियमित तथा औसत रूप से उच्च श्रम-निपज अनुपात तथा उच्च पूँजी-निपज अनुपात पाये जाते हैं। इससे बहुधा श्रम एवं पूँजी दोनों की अल्प-उत्पादकता का बोध होता है। टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी पिछड़ापन अकुशल एवं अप्रशिक्षित श्रमिकों के रूप में परिलक्षित होता है। अतएव, पूँजीगत साधनों के एक दिये हुए कोष के साथ तकनीक की दृष्टि से अपेक्षाकृत प्रशिक्षित श्रमिकों की तुलना में निपज की प्रति इकाई पर अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। अतः टेक्नोलॉजी की दृष्टि से पिछड़ापन के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के श्रम-निपज अनुपात में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। टेक्नोलॉजी की पिछड़ी हुई स्थिति के परिणामस्वरूप ही एक निश्चित मात्रा में राष्ट्रीय निपज के उत्पादन में अधिक पूँजीगत साधनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि अपर्याप्त तकनीकी ज्ञान के परिणामस्वरूप श्रम की उत्पादन क्षमता Y/N में पूँजी एवं श्रम के अनुपात K/N की अपेक्षा कम अनुपात में वृद्धि होती है, तो पूँजी-निपज अनुपात में $K/Y = (KN)/(YN)$ के माध्यम से वृद्धि होगी।¹ टेक्नोलॉजिकल पिछड़ापन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के पूँजी-निपज अनुपात को बढ़ाने में कम-से-कम एक महत्वपूर्ण कारण है। इस प्रवृत्ति के प्रत्यावर्तन में स्रोतपूर्ण साधनों के मूल्य पर किम हद तक निर्भर किया जा सकता है, अभी तक वर्णनाधीन है।

संरचनात्मक अपूर्ण रोज़गार

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की एक अन्य विशेषता संरचनात्मक अपूर्ण

1. विस्तृत विवेचन के लिए इस पुस्तक का पाँचवाँ अध्याय देखें।
2. विवादास्पद अंशों के लिए पाँचवें अध्याय के उपखंड नीति 'प्राचल के रूप पूँजी-निपज अनुपात' देखें।

रोजगार है। इस प्रकार की बेरोजगारी समर्थ मांग के पर्याप्त रहने पर भी पूंजीगत साधनों के पूर्ण उपयोग के बावजूद इनकी अपर्याप्तता के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ उपलब्ध श्रम (जनसंख्या में वृद्धि द्वारा शासित वर्तमान श्रम-संख्या), नियुक्त श्रम (श्रम-संख्या का वह भाग जो पूंजी के दिए हुए कोप पर, समर्थ मांग में परिवर्तन के अनुसार वास्तव में निगुक्त है) तथा अपेक्षित श्रम (श्रम का अधिकतम संभाव्य परिमाण जो समर्थ मांग के दिये हुए आकार के आधार पर वर्तमान उपकरणों के पूर्णरूपेण उपयोग करने पर रोजगार में लगाया जा सकता है और जो पूंजीगत साधनों एवं पूंजी की उत्पादन-क्षमता में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तनशील है) में अन्तर करना लाभदायक होगा। अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में नियमित तथा औसत रूप से अपेक्षित श्रम की अपेक्षा उपलब्ध श्रम का आधिक्य रहता है और इन दोनों का अन्तर संरचनात्मक अपूर्ण रोजगार का माप है।

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में संरचनात्मक अपूर्ण रोजगार की विद्यमानता मुख्यतः बढ़ती हुई श्रम-संख्या की तुलना में पूंजी के दीर्घकालिक अभाव का परिणाम है। इसके विपरीत, विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी मुख्यतः दी हुई जनसंख्या एवं पूंजी के कोप दोनों की तुलना में समर्थ मांग में चक्रीय कमी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। सरसरी तौर पर निम्नलिखित उदाहरण लाभदायक हो सकता है। जैसा कि पहले प्रासंगिक ढंग से इसे परिभाषित किया गया है : मान लें कि N = उपलब्ध श्रम, N_e = नियुक्त श्रम एवं N_r = अपेक्षित श्रम हैं। अब मोटे तौर पर बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण सम्भव है— (क) किसी देश में सम्पूर्ण बेरोजगारी = $N - N_e$; (ख) किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में संरचनात्मक अपूर्ण रोजगार = $N - N_r$; तथा (ग) किसी विकसित अर्थ-व्यवस्था में चक्रीय बेरोजगारी = $N_r - N_e$ । तो भी जैसा कि आगे के एक अध्याय में वर्णन किया गया है, एक वास्तविक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में एक ही समय सम्भवतः दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जा सकती है। अपेक्षित श्रम की तुलना में उपलब्ध श्रम के आधिक्य का तात्पर्य यह है कि पूंजी का वर्तमान कोप, पूर्ण रूप से प्रयुक्त होने पर भी सम्पूर्ण उपलब्ध श्रम को उत्पादक रोजगार में लगाने के लिए अपर्याप्त है। दूसरी ओर नियुक्त श्रम (N_e) की तुलना अपेक्षित श्रम (N_r) के आधिक्य का तात्पर्य यह है कि उपलब्ध श्रम का वास्तविक नियुक्त अंश पूंजी के वर्तमान कोप के पूर्ण रूप से प्रयुक्त होने पर (जबकि समर्थ मांग पर्याप्त है) जितने नियुक्त श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, उससे कम है। इन विभिन्न प्रकार की बेरोजगारियों के विस्तृत एवं गत्यात्मक विश्लेषण को अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की दुहरी बेरोजगारी के अध्ययन (छठे अध्याय) तक के लिए स्थगित करना पड़ेगा।

श्राय की अत्यधिक असमानता

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था का दूसरा परिचालन-सम्बन्धी चिह्न अत्यधिक

मात्रा में आय की असमानता है। इसे लॉरेंज वक्र के अर्थ में समता की पूर्ण रेखा से विचलन के रूप में मापा जा सकता है। एक प्रारूपिक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए लॉरेंज वक्र को एक प्रारूपिक विकसित अर्थ-व्यवस्था के वक्र की तुलना में 45° की रेखा के बहुत दूर पृथक् रहने की आशा की जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकसित देशों की तुलना में अल्पविकसित देशों में न्यूनतम आय वाली 10 प्रतिशत जनसंख्या की आय कुल आय के 10 प्रतिशत से बहुत कम होती है। यह इस सामान्य विचार कि अधिकांश अल्प-विकसित देशों में सम्पन्नता एवं विपन्नता के बीच बहुत विस्तृत खाई पाई जाती है, से बहुत कुछ मिलता-जुलता है, जिससे इनमें मध्यम वर्ग वस्तुतः पाया ही नहीं जाता। निश्चय ही अपवादस्वरूप कुछ हालतों में राजनीतिक सिद्धान्त अथवा मानवतावादी दर्शन के परिणामस्वरूप आय की अत्यधिक असमानता को रहने नहीं दिया जाता है। किन्तु इन अपवादों से इस मौलिक तथ्य कि विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की अपेक्षा समग्र रूप से अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं तथा किसी अर्थ-व्यवस्था के औद्योगिक परिपक्वता¹ की अपेक्षा औद्योगीकरण की प्रक्रिया की स्थिति में आय की असमानता अधिक पाई जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके दो सामान्य कारणों का यहाँ उल्लेख किया जा सकता है।

प्रथमतः, औद्योगीकरण की स्थिति में अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ, अनिच्छा-पूर्वक ही सही, पूँजी-संग्रह² की गति को तीव्र बनाने के लिए उच्च मात्रा में आय की विपन्नता को बनाये रखने के प्रबल आर्थिक दबाव के अंतर्गत रहती हैं। निर्धन व्यक्तियों की अपेक्षा धनवानों की सीमांत वचत की प्रवृत्ति साधारणतया अधिक होती है। अतएव, जिस समाज में औसत पारिवारिक आय से बहुत उच्च या बहुत निम्न आय वाले परिवारों का अनुपात जितना ही अधिक होगा, उसकी सीमांत वचत की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी और इसलिए पूँजी की पूर्ति भी अधिक होगी। अब आय में अत्यधिक असमानता आर्थिक विकास में वास्तव में सहायक होती है या नहीं यह दूसरी बात है। द्वितीय, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में वास्तविक आय का स्तर तथा इसमें वृद्धि की दर इतनी निम्न होती है कि इन प्रगतिशील करारोपण, सामाजिक बीमा, श्रमिक सघवाद, सामूहिक शिक्षा, बड़े पैमाने पर उत्पादन, एकाधिकार-विरोधी अधिनियम और व्यावसायिक गतिशीलता जैसी समकारी शक्तियों को

1. कुछ पूर्वकालिक तथा वर्तमान अनुभववाधित आंकड़ों के लिए एस० कुन्नेट्स की पूर्व उद्धृत पुस्तक 'इकानामिक प्रोब एण्ड इनकम इन इव्यूलिटी' देखें।
2. यह दबाव उन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में नहीं पाया जाता, जिनमें स्वयं सरकार वचत करने वाले मुख्य अभिकरण के रूप में कार्य करती है तथा उन अर्थ-व्यवस्थाओं में जो मुक्त रूप में तथा जो सुगमतापूर्वक विदेशी पूँजी प्राप्त कर सकती हैं, कम मात्रा में पाया जाता है।

बड़े एवं वृद्धिशील पैमाने पर विकसित करने के लिए आवश्यक आर्थिक आधार का अभाव रहता है। क्योंकि जब तक स्वयं राष्ट्रीय आय के आकार में वृद्धि नहीं की जाएगी, तब तक किसी विशेष आय वर्ग के हिस्से को केवल दूसरे वर्ग की आय को कम करके ही बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार समकारी शक्तियों के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए स्थान रह जाता है।

बाह्य ऋणग्रस्तता

विदेशी व्यापार सम्बन्धोंवाली विवृत व्यवस्था समझी जाने वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की अंतिम विशेषता उसकी दीर्घकालीन ऋणी की स्थिति है। किसी भी देश की निरन्तर बाह्य ऋणग्रस्तता मूलतः उस देश की प्रवल आयात-सम्बन्धी आवश्यकताओं की तुलना में दुर्बल निर्यात-क्षमता को परिलक्षित करती है। अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की दीर्घकालीन ऋण की स्थिति की व्याख्या निम्नांकित रूप में की जा सकती है— $B = P + M - E$ । जिसमें B शुद्ध विदेशी उधार, P पूँजीगत खाते में शुद्ध विदेशी भुगतान, M वास्तविक आयात तथा E वास्तविक निर्यात हैं। यह समीकरण यह बतलाता है कि आयात में वृद्धि अथवा निर्यात में कमी के परिणाम स्वरूप शुद्ध विदेशी उधार में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। इससे यह भी स्पष्ट है कि शुद्ध विदेशी भुगतान में वृद्धि होने से और भी उधार लेने की आवश्यकता पड़ेगी, जब तक कि इस प्रकार की वृद्धि निर्यात में समवृद्धि अथवा आयात में समह्रास के द्वारा विस्थित न हो जाय। इस प्रकार विचार करने पर यह कोई संयोग की बात नहीं जान पड़ती कि इस समय की अधिकांश विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को अपने औद्योगीकरण की प्रक्रिया में तथाकथित ऋणी की स्थिति से गुजरना पड़ा हो। इस दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका भी प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक एक ऋणी राष्ट्र था।

यदि भूत में कोई अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था दीर्घकालिक ऋणी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती थी, तो क्या ऐसा कोई कारण है, जिससे कि भविष्य में भी वह ऐसे राष्ट्र का ही प्रतिनिधित्व करती रहे। प्रयोग के तौर पर इसके कई उत्तर दिये जा सकते हैं। एक बात विल्कुल स्पष्ट है कि अधिकांश अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ टेक्नोलॉजी की दृष्टि से उन्नत अर्थ-व्यवस्थाओं से इतनी पिछड़ी होती है कि उन्हें विश्व-बाजार में प्रतियोगिता के चलते क्षति उठानी पड़ती है। फलतः वे अपने को आयात-आधिक्य के लिए सुग्राही बना लेती हैं, जिससे उन्हें विदेशों से निरन्तर उधार लेना पड़ता है। इसका दूसरा उत्तर यह है कि आजकल की अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ बाह्य भुगतान की अल्पकालीन समस्या की अपेक्षा विदेशी आधार के दीर्घकालीन आशय अथवा अपने आर्थिक विकास के सम्बन्ध में अधिक चिंतित रहती हैं और स्वर्ण के विक्रय अथवा विदेशी अनुदान के द्वारा निर्यात से अधिक आयात का वित्त-प्रबंधन अधिक-से-अधिक अल्पकाल में ही सम्भव है। दीर्घकाल में अधिकांश अल्प-

विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए यह सम्भव नहीं है। अतः आज यह सर्वत्र स्वीकार किया जाता है कि अल्प-विकसित देशों में आर्थिक विकास को अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के मुक्त प्रवाह के नयों पर नहीं छोड़कर उन्हें पुनर्निर्माण तथा विकास-सम्बन्धी विषयों के एक अन्य सस्याओं, जिनका उद्देश्य उधार शर्तों के तत्कालीन आधार पर दीर्घ-कालीन विकास-सम्बन्धी ऋण देना है, द्वारा आयोजित तरीके से सहायता देनी चाहिए। इस प्रकार के आयोजित बहुराष्ट्रीय ऋण के लेन-देन का लाभ यह है कि इससे पूँजी-सम्पन्न राष्ट्रों को साम्राज्यवादी के विशेष नाम से सम्बोधित हुए बगैर विदेशी ऋण देने का प्रोत्साहन मिलता है तथा पूँजी-विपन्न राष्ट्रों का परम्परागत राजनीतिक बंधनों के भय से मुक्त होकर तथा अत्यधिक राष्ट्रीय भित्तिबध्नीता की आवश्यकता के बगैर ही विदेशों से उधार लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

उपर्युक्त रूपरेखा द्वारा एक प्रारूपिक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के प्रारूपिक विकसित अर्थ-व्यवस्था में विभेद करने के लिए कुछ लाभदायक अभिलक्षणों का पता लग जाता है, यद्यपि कि इनमें से कुछ वास्तविक रूप में अविकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ दोनों की बीच की सीमा रेखा पर अवस्थित होती हैं।

विकास के सरचनात्मक निर्धारक तत्व

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की मापनीय अभिव्यक्तियों को देख लेने के पश्चात् अब हम इन अभिव्यक्तियों के अद्यस्थ कारणात्मक तत्वों का एक आम ढाँचा तैयार कर सकते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य किसी भी आधुनिक समाज में आर्थिक विकास के प्रतिरूप तथा गति को प्रभावित करने वाले कुछ तत्कालीन कारणों की सामान्य प्रकृति एवं महत्व के सम्बन्ध में प्रारम्भिक पर्यवेक्षण करना है। जिन आधार-भूत निर्धारक तत्वों की यहाँ पर व्याख्या की जायेगी, वे विकसित तथा अल्प-विकसित दोनों प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं में, यद्यपि स्पष्टतः अधिक या कम बल के साथ, लागू होते हैं।

श्रम-संख्या

एक 'संवृत' व्यवस्था समझी जाने वाली किसी भी अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक आय मूलतः श्रम-संख्या, पूँजी के कोष तथा टेक्नोलॉजिकल प्रगति के तत्कालीन सम्बन्ध पर निर्भर करती है। पूँजी के कोष तथा टेक्नोलॉजी की स्थिति को दिया हुआ मानकर हम आर्थिक विकास में श्रम के महत्व पर अपना ध्यान दे सकते हैं। इसे मोदाहरण स्पष्ट करने के लिए मान लिया जाय कि $Y =$ राष्ट्रीय निपज, $N =$ श्रम संख्या और $H =$ श्रम की औसत उत्पादकता है। तो हम निम्नांकित तुल्याक प्राप्त होते हैं —

$$(1) \text{ राष्ट्रीय निपज : } Y = H \cdot N$$

$$(2) \text{ श्रम-संख्या : } N = Y/H$$

$$(3) \text{ श्रम की उत्पादन-क्षमता : } H = Y/N$$

यहां Y पूर्ण रोजगार से संभाव्य निपज, N पूर्ण नियुक्ति रहने पर श्रम की संख्या तथा H टेक्नोलॉजी द्वारा निर्धारित कुल निपज एवं कुल श्रम¹ का अनुपात है।

उपर्युक्त तुल्यांकों से स्पष्ट है कि यदि स्थिर श्रम की उत्पादन-क्षमता की तुलना में नियुक्त श्रम-संख्या में वृद्धि हो अथवा यदि स्थिर श्रम-संख्या की तुलना में श्रम की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि हो, तो राष्ट्रीय निपज में वृद्धि हो सकती है। यदि श्रम एवं निपज का अनुपात प्राविधिक दृष्टि से निश्चित हो, तो हमें श्रम-संख्या में वृद्धि के साथ-साथ निपज में वृद्धि का सहजतम उदाहरण मिलता है। किन्तु श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, खाने वालों की संख्या में वृद्धि कर जटिल स्थिति उत्पन्न कर देती है। क्योंकि यदि सम्पूर्ण जनसंख्या (केवल श्रमिकों संख्या ही नहीं) में सम्पूर्ण निपज से तीव्र गति से वृद्धि होती है, तो श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के चलते कुल निपज में वृद्धि के परिणामस्वरूप भी प्रति-व्यक्ति वास्तविक आय के रूप में आर्थिक प्रगति नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि आर्थिक प्रगति के लिए उपज में वृद्धि के साथ-साथ श्रमिकों की उत्पादन-क्षमता (H) में भी वृद्धि अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में मुख्य बात यह है कि यदि संस्कृति द्वारा निर्धारित (जैसे काम एवं अवकाश के बीच चुनाव) कुल जनसंख्या का वह अंश, जो कार्य करने के लिए तत्पर तथा इच्छुक है, दिया हुआ है तो राष्ट्रीय निपज में वृद्धि की गति अन्य बातों के साथ-साथ नियुक्त श्रम की मात्रा एवं गुण, यानी उत्पादन-क्षमता पर निर्भर करती है।

वास्तविक पूंजी का कोष

आर्थिक विकास का दूसरा महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व वास्तविक पूंजी की उपलब्ध मात्रा है। वर्तमान संदर्भ में 'पूंजी' शब्द से उन मानव-कृत उत्पादन के भौतिक

1. उदाहरण के लिए, मान लिया कि $Y=40$ मिलियन डालर (स्थिर मूल्य पर) $N=40$ मिलियन श्रमिक एवं प्रति वर्ष प्रति श्रम की इकाई कुल मनुष्य घंटे 2000 (प्रति वर्ष 50 सप्ताह और प्रति सप्ताह 40 घंटे की मान्यता पर)। तब $Y/N=40,000/40 \times 2,000=4/8=0.5$ / यदि प्रति सप्ताह औसत काम के घंटे 40 से अधिक थे तो प्रति मनुष्य घंटे (H) निपज 0.5 से भी कम होगा। साथ ही, वास्तविक बेरोजगारी N के मूल्य कमी ला देगी और इस प्रकार Y के मूल्य में भी जब तक कि H में वृद्धि द्वारा उसकी विस्थिति नहीं हो जाती।

साधनों का बोध होता है, जो साधारणतः भौतिक उपभोग¹ से शुद्ध उत्पादन के अधिक हो जाने के फलस्वरूप, यानी घनात्मक वास्तविक बचत एवं निर्बल निवेश के परिणामस्वरूप समुपस्थित होने है। राष्ट्रों के औद्योगीकरण में पूँजी-संचय का ऐतिहासिक दृष्टि से अपूर्वतया इतना निर्णयात्मक स्थान रहा है कि इसने यदि इनकी सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था को नहीं, तो कम-से-कम इनकी उत्पादन-प्रणाली को 'पूँजी-वादी' या 'चक्रदार' नाम से विख्यात कर दिया है। पूँजी के कोप-परिवर्तन के प्रभाव के पृथक्करण के लिए, श्रम की पूर्ति को स्थिर मान लेना सुविधाजनक होगा।

अब निम्नलिखित सम्बन्धों पर विचार करना सम्भव होता है.—

(4) राष्ट्रीय निपज : $Y = fK$

(5) पूँजी का कोप : $K = Y/f$

(6) पूँजी की उत्पादिता $f = Y/K$

यहाँ पर K वास्तविक पूँजी तथा f पूँजी औसत उत्पादिता है। (4) से (6) तक उपर्युक्त सम्बन्ध वास्तविक पूँजी या पूँजी की उत्पादिता अथवा दोनों में वृद्धि के परिणामस्वरूप निपज में वृद्धि की सैद्धान्तिक सम्भावना को स्पष्ट करते हैं। यदि पूँजी की उत्पादिता (f) को प्राविधिक रूप से दिया हुआ मान लिया जाय, तो निपज में वृद्धि का एक तरीका पूँजी के वास्तविक कोप में वृद्धि है।² अब स्वाभाविक प्रश्न यह होता है कि कबो किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में पूँजी के कोप में 5 प्रतिशत की दर से तथा किसी विकसित अर्थ-व्यवस्था में 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि होती है। इस प्रश्न का सर्वोत्तम तरीके से जवाब बचत की प्रवृत्ति, जो पूँजी की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करती है तथा विनियोग की प्रवृत्ति जो पूँजी की माँग का प्रतिनिधित्व करती है, के सदर्भ में पृथक्-पृथक् रूप से दिया जा सकता है। पूँजी की माँग एवं पूर्ति के आम निर्धारक तत्त्व सर्वज्ञान है, किन्तु विशेषतः अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में ऐच्छिक बचत की न्यूनता को संपूरित करने में बलात् बचत (उदाहरण के लिए बजट के आधिक्य, विनिधान की प्राथमिकता, मितव्ययिता-नियतन, अनिवार्य

1. कुछ लोग शुद्ध विनियोग की धारणा को विस्तृत बनाने के लिए इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं सफाई के कार्यक्रम द्वारा श्रमिकों की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि, निरक्षरता को कम करने के लिए शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार तथा प्राविधिक प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि पर व्यय को भी रखना उचित समझते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ट्वेंटियेथ सेनचुरी फंड द्वारा 1955 ई० में प्रकाशित एन० एस० बुचानन एवं एच० एस० एलिस की पुस्तक एप्रोचेज टू इकानामिक डवलप-मेंट। किन्तु हम लोगों के अर्थ में इस प्रकार के व्यय से प्रत्यक्ष रूप में पूँजी-संचय नहीं होता।

वचत-पत्र-कार्यक्रम, अंतःप्रशासनीय उधार तथा विदेशी विनिमय नियंत्रण) के द्वारा तथा निजी निवेश को पूरित करने में सरकारी निवेश की संभावनाओं को स्वीकार करना चाहिए।

टेक्नोलॉजिकल अग्रवृत्तिता

टेक्नोलॉजी अंतिम आंतरिक निर्धारक तत्त्व है, जिसकी व्याख्या इस प्रारंभिक पर्यवेक्षण में की जायगी। व्यावहारिक अर्थपूर्ण ढंग से टेक्नोलॉजी की व्याख्या करने के लिए इसकी अभिव्यक्ति श्रम-निपज अनुपात तथा पूँजी-निपज अनुपात जैसे कुछ प्राविधिक प्राचलों के रूप में सुविधाजनक होगी। इन दोनों गुणकों में से किसी में ह्रास का तात्पर्य आर्थिक क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल प्रगति होगा; क्योंकि श्रम-निपज अनुपात अथवा पूँजी-निपज अनुपात में ह्रास से श्रम अथवा पूँजी की औसत उत्पादकता में वृद्धि का बोध होता है। इसे (3) तथा (6) समीकरणों के पुनःसूत्रीकरण के द्वारा निम्नांकित प्रकार से दिखलाया जा सकता है :—

$$(7) (1/H) = (N/Y) \quad (\text{श्रम-निपज अनुपात})$$

$$(8) 1/f = (K/Y) \quad (\text{पूँजी निपज अनुपात})$$

अन्य बातों के समान रहने पर, श्रम-निपज अनुपात में ह्रास (श्रम की उत्पादकता में वृद्धि) अथवा पूँजी-निपज अनुपात में ह्रास (पूँजी की उत्पादकता में वृद्धि) के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय निपज में वृद्धि होती है। अब इस अवसर पर एक दिलचस्प प्रश्न यह होता है कि किन शक्तियों के परिणामस्वरूप निम्नतर श्रम-निपज अनुपात तथा पूँजी-निपज अनुपात से श्रम एवं पूँजी की उच्चतर उत्पादकता का बोध होता है? विशुद्ध टेक्नोलॉजिकल शब्दों में इस प्रश्न का जवाब देना अधिक आकर्षक जान पड़ता है, किन्तु मानवीय प्रयोजनों, बाजारगत दशाएँ, आयोजित क्रियाएँ तथा अन्य अन्योन्याश्रयी शक्तियों को ध्यान में रखते हुए इस आकर्षण का संवरण अनिवार्य हो जाता है। तदनुसार, श्रम-निपज अनुपात में दीर्घकालिक ह्रास के लिए अत्यधिक श्रम-विभाजन, श्रम के बदले अन्य साधनों के प्रतिस्थापन के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सुविधा, श्रम वचाने के साधनों का अधिकाधिक अंगीकरण मजदूरी की उच्च गति, जनसंख्या की मन्द वृद्धि आदि शक्तियों के सम्मिश्रण को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जहाँ तक पूँजी-निपज अनुपात में दीर्घकालिक ह्रास को प्रभावित करने वाली टेक्नोलॉजिकल तथा अन्य शक्तियों का सम्बन्ध है, पूँजी वचाने वाले अन्वेषण तथा नवीन क्रियाएँ, पूँजी की अधिक टिकाऊपन वाली संरचना, ऊँची दीर्घकालीन व्याज की दर, अधिक पूँजी प्रधान से कम पूँजी प्रधान उद्योगों की ओर संरचनात्मक-स्थानान्तरण तथा अन्य उत्पादक साधनों के बदले पूँजी के प्रतिस्थापन की दीर्घकालीन लोच विशेष रूप से उल्लेखनीय है। टेक्नोलॉजिकल प्राचलों में ये दीर्घकालिक परिवर्तन या तो, जैसा कि मार्क्स और शुम्पीटर का विचार

है, प्रधानतया स्वतंत्र प्रकृति के हो सकते हैं, या जैसा कि परम्परागत विश्लेषण से स्पष्ट है, मुख्यतः अभिप्रेरित प्रकृति (बाजारगत दशाओं, जिनमें सापेक्ष साधनों के मूल्य भी सम्मिलित हैं) के हो सकते हैं।

बाह्य निर्धारक Xv

आंतरिक विकास के दो आधारभूत मौलिक निर्धारक तत्त्व किसी राष्ट्र के निर्यात की क्षमता तथा पूँजी के आयात-सम्बन्धी उसकी योग्यता एवं इच्छा हैं। इनमें पहला निर्धारक दीर्घकाल में निर्णायक होता है, क्योंकि लगातार आयात आधिकार्य (यानी राष्ट्रीय निपज में शुद्ध योग) के भुगतान की योग्यता अततांगत्वा किसी राष्ट्र की उस क्षमता पर निर्भर करती है, जिसके कारण वह प्रतियोगात्मक लाभदायक व्यय से दूसरे राष्ट्रों द्वारा अपेक्षित वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं निर्यात कर सकता है। दूसरा निर्धारक किसी राष्ट्र के औद्योगीकरण की प्रारम्भिक स्थिति में, जबकि आवश्यक आयात के भुगतान के लिए उसकी निर्यात की क्षमता तकनीकी दृष्टि से सीमित होती है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। 91758

K9

आधुनिक विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि विदेशी व्यापार के परिवर्तनों का घरेलू आय एवं घरेलू उत्पादकता पर विरोधात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि निर्यात का घरेलू आय पर स्फीतिक, किन्तु घरेलू उत्पादकता पर अवस्फीतिक प्रभाव पड़ता है जबकि आयात का घरेलू आय पर अवस्फीतिक तथा घरेलू उत्पादकता पर स्फीतिक प्रभाव पड़ता है। अतएव, विशेषतः ऐसी स्थिति में, जब हम स्फीति एवं असंतुलन के बगैर स्थायी विकास को प्राप्त करने एवं बनाये रखने की सम्भावनाओं में अभिर्हचि रखते हैं, तब हमें विदेशी व्यापार के दोनों, गुणक एवं उत्पादकता प्रभाव, की जाँच करना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की विस्तारपूर्वक जाँच आगे चलकर की जाएगी। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जहाँ तक अल्प-विनसित अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है, यदि अर्थ-व्यवस्था को बगैर निरन्तर मुद्रास्फीति एवं असंतुलन की हलचल के दीर्घकालिक विकास की ओर अग्रसर होना है, तो विदेशी व्यापार का गुणक-प्रभाव उसके उत्पादकता प्रभाव का अवश्य ही अतिक्रमण करेगा। आधुनिक विश्लेषण से हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि पूर्ण रोजगार सम्बन्धी-संस्थापक मान्यता को अवश्य छोड़ देना चाहिए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण रोजगार एवं अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में सन्तुलन की प्रक्रिया को समझाने के लिए आय, न कि मूल्य-यंत्र, का अध्ययन अनिवार्य है। इसका तात्पर्य यह है कि आधुनिक परिस्थितियों में व्यापार की शर्तों एवं मूल्य लोच की परम्परावादी पूर्वधारणा की जगह आयात की सीमांत प्रवृत्ति, निर्यात-आय अनुपात, आयात-आय अनुपात, निर्यात-प्रधान तथा आयात-प्रधान घरेलू उद्योगों की उत्पादकता तथा अन्य गैर-मूल्य-सम्बन्धी कारणों से अधिकाधिक विश्लेषण पर जोर दिया जाएगा।

विदेशी ऋण का, चाहे यह प्रतिकूल-भुगतान-संतुलन का परिणाम हो अथवा पूँजी के स्वतःप्रेरित आयात का, दीर्घकालिक महत्त्व इस बात में है कि ऋणी देश ऋण के रूप में प्राप्त रकम का उत्पादक तरीके से प्रयोग करें, जिससे कि उसकी घरेलू वास्तविक आय में उसके ऋण के वास्तविक दायित्व से अधिक वृद्धि हो। राष्ट्र अपने आयात के आधिक्य को इस प्रकार पूरा कर सकते हैं या नहीं, यह केवल उनके आयात की प्रवृत्ति पर नहीं, बल्कि अन्य राष्ट्रों के विदेशों को उधार देने की इच्छा पर निर्भर करता है। किन्तु ऋणी राष्ट्र इस प्रकार अपने उत्पादक साधनों को विकसित करने में सफल हो जाते हैं, तो जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त के इतिहास से स्पष्ट है, वे अंततः घाटेवाला एवं ऋणी राष्ट्र नहीं रहकर आधिक्य वाला एवं ऋणदाता राष्ट्र बन जाएँगे। जहाँ तक अधिकांश अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था वाले राष्ट्रों का सम्बन्ध है, अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के प्रवाह से वे ऋणदाता एवं उधार देने वाले राष्ट्रों के रूप में नहीं, बल्कि ऋणी एवं उधार लेने वाले राष्ट्र के रूप में ही लाभान्वित होंगे।

दूसरी ओर विदेशी उधारदान का दीर्घकालीन महत्त्व विदेशी अर्जक परिसंपत्ति के ब्यूह बनाने की सम्भावना में है, जिससे इनके शुद्ध अर्जक से अंततः आयात-आधिक्य की प्राप्ति की जा सके। इस सम्भावना को एक विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था के ऋणदाता की स्थिति $L = E - M + R$ के रूप में व्यक्त करके स्पष्ट किया जा सकता है। इसके L शुद्ध विदेशी उधारदान, R पूँजी खाते में शुद्ध विदेशी प्राप्तियाँ और E तथा M पहले की ही तरह क्रमशः वास्तविक निर्यात तथा आयात हैं। यह समीकरण यह बतलाता है कि यदि शुद्ध विदेशी प्राप्तियाँ बहुत कम हैं, जैसा कि विदेशी उधारदान की प्रारंभिक स्थिति में संभवतः होता है, तो विदेशी उधारदानों में वृद्धि के लिए निर्यात-आधिक्य की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा मौलिक रास्ता नहीं है। यदि विदेशी उधारदान में इस प्रकार वृद्धि हो जाती है, तो ऋणदाता राष्ट्र, आगे या पीछे, पूँजी-खाते में विदेशों से अधिक रकम अर्जन करेगा (यानी R में वृद्धि होगी)। पुनः जैसा कि उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट है, यदि पूँजीगत खाते में शुद्ध विदेशी प्राप्तियाँ विदेशों में प्रचलित उधारदान से अधिक है, यानी $R > L$ हैं, तो आयात निर्यात से अधिक हो सकता है, यानी $M > E$ । इस सम्बन्ध में यह कल्पना करना कोई कठिन काम नहीं है कि यदि ग्रेट ब्रिटेन प्रथम युद्ध के पूर्व तक विश्व का महान् ऋणदाता राष्ट्र नहीं होता, तो उसके औद्योगिक विकास का स्वरूप संभवतः कुछ दूसरा ही होता। यदि ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्र, जिन्होंने द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप अपनी विदेशी सम्पूर्ण अथवा अधिकांश अर्जक सम्पत्ति को खो दिया है, इस प्रकार की विदेशी सम्पत्ति को पुनः संचित करना चाहते हैं, तो उनके लिए लगातार निर्यात-आधिक्य प्राप्त करना एवं उसे बनाये रखना तथा व्यापाराधिक्य के बराबर अथवा कम रकम विदेशों में उधार देना अधिकाधिक मात्रा में आवश्यक होगा। इसके

परिणामस्वरूप प्रचलित उधारदान के अतिरिक्त पूँजीगत खाते में जो विदेशी प्राप्तियाँ होंगी, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर आयात-आधिव्यय को पूरा करने में प्रयोग किया जा सकता है ।

इस रूपरेखा के बाद, अब हम लोग अधिक उचित रीति से, गम्भीरतापूर्वक एवं व्यवहृत रूप में अधिक महत्वपूर्ण तरीके से आर्थिक विकास की प्रकृति एवं प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे ।

अध्याय 3

विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम गति

विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने के लिए, सर्वप्रथम निर्देश के किसी केन्द्रीय मानक, यानी निर्देश के सामान्य आधार के रूप में आर्थिक विकास के किसी आदर्श अभिसूचक की आवश्यकता होती है। अतएव, इस अध्याय में विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम गति की धारणा एवं निर्धारण की गवेषणा की जायगी। विकास की दर के इस लक्ष्य को एक बार स्पष्ट रूप से परिभाषित और निश्चित कर लेने के बाद इसे केवल परिष्कृत एवं कार्यान्वित करना ही रह जाता है। इस अध्याय में विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम गति की व्याख्या स्पष्टतः निम्नलिखित संदर्भ में की जायगी—(क) जीवन-मान एवं जनसंख्या की वृद्धि में सम्बन्ध, तथा (ख) बढ़ती हुई जनसंख्या की आर्थिक आवश्यकताओं एवं विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था की टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी सम्भावनाओं के बावजूद प्रगति की आदर्श गति को प्राप्त करने तथा बनाये रखने के लिए आवश्यक पूँजी-संचय की गति।

जनसंख्या की वृद्धि एवं जीवन-मान

किसी भी अर्थ-व्यवस्था में जनसंख्या एक ही साथ उपयोगिता-संतुष्टि का अंतिम विषय तथा उपयोगिता-निर्माण की एक मौलिक शर्त है। जनसंख्या की यह दुहरी विशेषता उपभोक्ता एवं उत्पादक के रूप में आर्थिक मनुष्य के दुहरे कार्य में निहित है। उपभोग करने वाली जनता के रूप में जनसंख्या उच्चतम जीवन-मान की आकांक्षा रखती है। कार्यकारी शक्ति के रूप में जनसंख्या इच्छित उच्च जीवन-मान को प्राप्त करने के लिए उसका आर्थिक आधार प्रस्तुत करती है। अतएव, उपभोक्ता के कल्याण एवं श्रम की उत्पादकता दोनों के दृष्टिकोण से जनसंख्या की वृद्धि एवं जीवन-मान के सम्बन्ध का विश्लेषण अनिवार्य है।

नियोजनीय जनसंख्या

पहले इस वृहत् प्रश्न, कि क्यों समय एवं स्थान के साथ-साथ (क) जनसंख्या की वृद्धि की दर, तथा (ख) दी हुई कुल जनसंख्या एवं नियोजनीय जनसंख्या के अनुपात में अंतर पाया जाता है, के कारणों की व्याख्या से प्रारंभ किया जाए। जनसंख्या के आकार में 'प्राकृतिक वृद्धि' (आप्रवास और उत्प्रवास को छोड़कर) जन्म-दर के मृत्यु-दर से अधिक होने पर निर्भर करती है। ये उपर्युक्त दरें स्वयं आर्थिक तथा

गैर-आर्थिक कारणों के सम्मिश्रण से प्रभावित होती है। जन्म-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्वों में जनसंख्या-विशेषज्ञ साधारणतः निम्नलिखित का उल्लेख करते हैं। विवाह की औसत आयु, प्रसूति-विद्या की स्थिति, सतति-निग्रह का ज्ञान एवं प्रयोग, गुप्त तथा प्रकट गर्भपात, सरकार द्वारा पारिवारिक सहायता, पारिवारिक बहुजननता, प्रति-व्यक्ति वास्तविक आय, पारिवारिक आय पर करो का बोझ एवं बच्चों के लिए भविष्य में आर्थिक अवसर। जहाँ तक मृत्यु-दर का प्रश्न है, यह निम्नलिखित तत्त्वों से प्रभावित होती है—जनसंख्या के घनत्व की मात्रा (स्वायत्त साधनों की तुलना में जनसंख्या), चिकित्सा-विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य-विज्ञान की स्थिति, युद्धों की आवृत्ति (अन्तर्राष्ट्रीय तथा गृह-युद्ध), प्राकृतिक आपदाएँ, महामारी, अकाल और स्वास्थ्य-बीमा की पद्धति।

यद्यपि जनांकिकीय निर्धारक अनेक हैं, तथापि अर्थशास्त्र की दृष्टि से जनसंख्या में वृद्धि की अर्थपूर्ण व्याख्या इस सरल मान्यता में पाई जा सकती है कि जनसंख्या में वृद्धि की दर निम्नलिखित रूप लेती है —

$$\frac{\Delta P}{P} = B \left(\frac{P}{K} \right) - D \left(\frac{P}{C} \right), \quad (1)$$

जिसमें $\Delta P/P$ जनसंख्या में वृद्धि की दर है, B जन्म की दर, D मृत्यु की दर, K/P प्रति-व्यक्ति पूँजी का कोप, C/P प्रति-व्यक्ति उपभोग के साधन, $B (P/K)$ प्रजनन की क्षमता जो इस मान्यता पर आधारित है कि जन्म-दर में प्रति-व्यक्ति पूँजी के कोप के ठीक विपरीत परिवर्तन होता है। (पूँजीगत साधनों तथा पूँजीगत उत्पादों की मात्रा जितनी ही अधिक होगी, उतना ही अधिक एक औसत परिवार का भुकाव 'बच्चे के बजाय एक नई मोटर' को पसंद करने की ओर होगा) और $D (P/C)$ जनसंख्या का घनत्व है, जो इस मान्यता पर आधारित है कि मृत्यु-दर में प्रति-व्यक्ति उपभोग के साधनों के ठीक विपरीत परिवर्तन होता है।

अब इस प्रश्न पर विचार किया जाय कि कुल जनसंख्या का एक निश्चित भाग क्यों मरदा कार्य करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक रहता है? इसका उत्तर विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कारकों का उल्लेख किया जा सकता है। समुदाय का श्रम एवं विश्राम के बीच चयन, पारिवारिक एवं शैक्षणिक व्यवस्थाएँ, सामाजिक स्तरण, सम्पत्ति-सम्बन्ध, बच्चों एवं स्त्रियों के श्रम पर वैधानिक प्रतिबंध, कार्य करने के लिए प्रोत्साहन, उत्तराधिकार, एवं मृत्यु-दर और जलवायु-सम्बन्धी स्थिति। इन्हीं कारकों के परिणामस्वरूप किसी एक अर्थ-व्यवस्था में श्रम-शक्ति कुल जनसंख्या का सामान्यतः आधी तो किसी दूसरी में एक-तिहाई हो सकती है। साधारणतः जो अर्थ-व्यवस्था जितनी ही अधिक औद्योगिकृत होनी है, वहाँ की श्रम-शक्ति कुल जनसंख्या के अनुपात में उतनी ही कम

होती है। क्योंकि एक अत्यधिक औद्योगीकृत समाज एक कम औद्योगीकृत समाज की अपेक्षा एक बड़े अवकाश-प्राप्त वर्ग के मरण-पोषण में समर्थ होता है।

सरलता के लिए इन सभी अद्यःस्थ प्रभावों को एक गुणक के रूप में लिया जाय जो श्रम एवं विश्राम के बीच समाज के चुनाव का मापन करता हो। इस प्रकार का गुणक नियोजनीय श्रम-शक्ति को कुल जनसंख्या से सम्बद्ध करता है। यदि समाज का श्रम एवं विश्राम के बीच चुनाव नियोजनीय श्रम-शक्ति (N) एवं कुल जनसंख्या (P) के बीच एक स्थायी अनुपात (α) निश्चित करता है, तो $N/P = \alpha =$ स्थायी होता है। इस सम्बन्ध से श्रम-संख्या की वृद्धि की निम्नलिखित दर प्राप्ति होती है—

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{\alpha \Delta P}{N} = \frac{\alpha \Delta P}{\Delta P} = \frac{\Delta P}{P} \quad (2)$$

समीकरण (2) के द्वारा निर्धारित श्रम-संख्या में वृद्धि की दर ही विकास की श्रेष्ठतम सामाजिक गति-रूपी भवन के निर्माण के विश्लेषणात्मक कार्य करती है। यदि जनसंख्या का आकार समीकरण (1) में बतलाये गये तरीके से निर्धारित होता हो, तथा समीकरण (2) के अनुसार श्रम-शक्ति एवं कुल जनसंख्या का अनुपात स्थायी हो, तो श्रम-संख्या के आकार में जनसंख्या में वृद्धि की दर के अनुसार ही वृद्धि होगी। जनसंख्या द्वारा आकांक्षित जीवन-मान नामक एक और विश्लेषणात्मक आधार है। अब इस दूसरे आधार की व्याख्या की जाय।

प्राप्य जीवन-स्तर

जीवन-स्तर साधारणतः प्रति-व्यक्ति वास्तविक आय से मापा जाता है, किन्तु यहाँ इसकी व्याख्या एक सीमित अर्थ में की जा सकती है। चूँकि अन्तिम विश्लेषण में, प्रति-व्यक्ति वास्तविक आय श्रम की औसत उत्पादकता पर निर्भर करती है, अतः जीवन-स्तर से प्रति-परिवार के 'कमासुत' की वास्तविक आय का बोध होता है। श्रम की उत्पादकता का यह दुहरा कार्य इस बात को दुहराने से कि श्रम की उत्पादकता ($H = Y/N$) श्रम की औसत आय का भी प्रतिनिधित्व करती है, से सुगमतापूर्वक स्पष्ट हो जाता है। इन दोनों की वास्तविक अनुरूपता किसी मूर्त समाज की सांस्थानिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक स्थान तथा समय में श्रम की औसत उत्पादकता 'कमासुत' की उच्च अथवा निम्न जीवन-स्तर की चरम तकनीकी औचित्य को निर्धारित करती है।

व्यवहारतः, उच्च जीवन-स्तर की आकांक्षा का तात्पर्य, उत्पादन के तरीकों में इस प्रकार की उन्नति की आकांक्षा करना है, जिससे श्रम की प्रति इकाई निपज, यानी श्रम की औसत उत्पादकता में वृद्धि हो। टैक्नोलॉजी की दृष्टि से एक पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था, मूलतः, अपने प्राच्यौगिक पिछड़ेपन को दूर कर ही यथार्थ रूप में उच्च जीवन-स्तर की आकांक्षा कर सकती है। मान लिया कि इस प्रकार की कोई

अर्थ-व्यवस्था अपनी प्राद्यौगिक प्रगति के द्वारा, श्रम की औसत उत्पत्ति में निम्न-लिखित दर से वृद्धि कर सकती है—

$$\frac{\Delta H}{H} = h \quad (3)$$

जिसमें H पूर्ण नियुक्त श्रम एवं निपज के अनुपात को स्पष्ट करता है। तब $h > 0$ का तात्पर्य बढ़ता हुआ जीवन-स्तर, $h < 0$ का घटता हुआ जीवन-स्तर तथा $h = 0$ का स्थायी जीवन-स्तर से है। जीवन-स्तर के ये तीनों ढाँचे उत्पादन में वृद्धि की दर एवं जनसंख्या में वृद्धि की दर में अन्तर पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार, प्राप्य जीवन-स्तर जनसंख्या एवं उत्पादकता पर निर्भर करता है। अब हम लोग 'विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम गति' की संकल्पना को सुलभाने की स्थिति में हैं।

सामाजिक श्रेष्ठतम गति की संकल्पना

पूर्ववर्ती विवरण को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आय में वृद्धि की दर को, जिसे सामाजिक दृष्टि से श्रेष्ठतम समझा जाता है, एक बढ़ती हुई जनसंख्या की पूर्ण रोजगार एवं बढ़ते हुए जीवन-स्तर की आत्मनिष्ठ इच्छा को प्रतिबिम्बित करने के बावजूद, कोकेजन (Cockaigne) के प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि वर्तमान सदर्भ में, विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम गति वर्तमान श्रम-संख्या की पूर्ण रोजगारी एवं श्रम की उत्पादकता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के अनुरूप निपज में वृद्धि की अधिकतम गति का निर्देश करती है। इस प्रकार की अधिकतम विकास की प्राप्ति एवं इसे बनाये रखना पूँजी-संचय के समान दर की विद्यमानता पर निर्भर करता है। इसके परिणामस्वरूप श्रम की पूर्ण रोजगारी की आकांक्षा एवं पूँजी के वृद्धि की आकांक्षा में एक प्रकार के सम्भावित संघर्ष का आभास होता है। इस प्रकार के आशय के सम्बन्ध में आगे चलकर व्याख्या की जायगी। इस बीच, प्रथम सन्निकट मान के रूप में "हम लोग विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम दर को नियोज्य श्रम-

1. मान लिया कि $Y = HN$, जिसमें Y शुद्ध राष्ट्रीय निपज, H श्रम की औसत उत्पादकता एवं N श्रम की संख्या है। इससे यह स्पष्ट होता है कि $\Delta Y = H \Delta N + N \Delta H$ । पुन $y = \Delta Y/Y$, $h = \Delta H/H$ तथा $n = \Delta N/N$ मानने पर निम्नलिखित प्राप्त होता है :—

$$Y (1+y) = H (1+h) N (1+n)$$

$$Y + yY = (H + hH) (N + nN)$$

$$= HN + HnN + hHN + hHnN$$

$$y = (nHN/Y) + (hHN/Y) + (hnNH/Y)$$

H संख्या में वृद्धि की दर एवं श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के योग के रूप में मान सकते हैं :

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta N}{N} + \frac{\Delta H}{H} \quad (4)$$

जिसमें $\Delta Y/Y$ निपज में वृद्धि की अधिकतम दर है, जो उपर्युक्त वर्णित जनसंख्या में वृद्धि एवं तकनीकी प्रगति के अनुरूप है। समीकरण (4) से यह स्पष्ट होता है कि प्रति इकाई निपज के नियुक्त श्रम की मात्रा को कम करने के लिए श्रम की उत्पादकता ($\Delta H/H$) की दर के ऊँची होने तथा उत्पादक रोजगार में खप जाने योग्य श्रम-संख्या ($\Delta N/N$) में वृद्धि की दर के ऊँची होने पर प्राप्य अधिकतम लक्ष्य की दर भी ऊँची होगी।

$G_m = \Delta Y/Y$, $n = \Delta N/N$ तथा $h = \Delta H/H$ मानकर समीकरण (4) में अंतर्ग्रस्त परिमाणों की सोदाहरण व्याख्या निम्नांकित प्रकार से की जा सकती है :

यदि $n=0.01$, $h=0.04$, तो $G_m=0.05$

(विकसित अर्थ-व्यवस्था)

यदि $n=0.015$, $h=0.02$, तो $G_m=0.035$

(मध्यवर्ती अर्थ-व्यवस्था)

यदि $n=0.02$, $h=0.005$, तो $G_m=0.025$

(अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था)

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कोई अर्थ-व्यवस्था श्रम की उत्पादकता में वृद्धि की दर (h) को अधिकाधिक बनाकर तथा श्रम-संख्या में वृद्धि की दर (n) को न्यूनतम बनाकर वास्तविक रूप में विकास की ऊँची दर को लक्ष्य के रूप में अपना सकती है। किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए इसका आशय यह है कि यदि इसकी श्रम-संख्या दो प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या की वृद्धि के अनुरूप, विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की तरह 5 प्रतिशत की वृद्धि की ऊँची दर को प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय श्रम की उत्पादकता में $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की जगह तीन प्रतिशत की वृद्धि है। इससे हम उत्पादन एवं जनसंख्या के सम्बन्ध पर पहुँचते हैं, जिसका अन्तर जीवन-स्तर को निर्धारित करता है।

उत्पादन बनाम जनसंख्या

समीकरण (4) से यह महत्वपूर्ण आशय स्पष्ट होता है कि प्रति 'कमासुत' के जीवन-स्तर Standard of living per "bread-winner" में दीर्घकालिक सुधार के

इसमें से अंतिम पद h n को उपेक्षित लघु प्राप्ति समझकर छोड़ने पर $y=n+h$ होता है, जो हम लोगों के विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम गति की धारणा $y=G_m$ का प्रतिनिधित्व करता है।

लिए भ्रम-सदृशता में वृद्धि की दर से निपज में अधिक वृद्धि अनिवार्य है। यह आशय निम्नलिखित परिवर्तित समीकरण से स्पष्ट हो जाता है :

$$\frac{\Delta H}{H} = \frac{\Delta Y}{Y} - \frac{\Delta N}{N} \quad (5)$$

जिसमें जैसा कि पहले बतलाया गया है, $\Delta H/H$ गत्यात्मक परिस्थिति में जीवन-स्तर का माप है। समीकरण (5) को जीवन-स्तर की तीनों प्रवृत्तियों के रूप में निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है -

यदि $Gm - n > 0$, तो $h > 0$ (बढ़ता हुआ जीवन-स्तर)

यदि $Gm - n = 0$, तो $h = 0$ (स्थायी जीवन-स्तर)

यदि $Gm - n < 0$, तो $h < 0$ (गिरता हुआ जीवन-स्तर)

इन उदाहरणों में यह स्पष्ट है कि जीवन-स्तर (प्रति परिवार पोषण करने वाले) में दीर्घकालिक सुधार निपज में वृद्धि की दर (Gm) को बढ़ाकर या जनसंख्या की वृद्धि की दर (n) को कम करके या दोनों के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही ये जनसंख्या की वृद्धि एवं उत्पादन में वृद्धि के सम्बन्ध में कुछ कठिन प्रश्नों को भी प्रस्तुत करते हैं जो दीर्घकालिक जीवन-स्तर को निर्धारित करते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि कोई अर्थ व्यवस्था $ht^{+1} > (Gm - n)^t$ के रूप में कालगत विषमता को तम्ह, घालू निपज एवं जनसंख्या की प्रवृत्तियों द्वारा निर्धारित जीवन-स्तर की अपेक्षा अधिक ऊँचे जीवन-स्तर की आकांक्षा करती है, तो इसे जनसंख्या की वृद्धि की दर को कम करने तथा उत्पादन में वृद्धि की दर को बढ़ाने के बीच चुनाव की व्यावहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।¹ इस सदर्भ में हमें

- 1 यो ही विश्व-जनसंख्या-सम्मेलन (इटली, अगस्त, 1954) में सम्भवतः आशावादी एवं निराशावादी विचार धाराओं के बीच ध्रुवात विरोध था। निराशावादी विचारधारा के लोग यह भयानक आशंका व्यक्त करते थे कि न्यूक्लीय विज्ञान की महान आशाओं के बावजूद विश्व की जनसंख्या में कदाचित् इसके साधनों से अधिक वृद्धि होगी। इसके विपरीत आशावादी विचारधारा के लोग केवल यह तर्क देते थे कि यदि आपके जूते आपको तंग कर रहे हैं, तो छोटे जूतों के उपयुक्त बनाने के लिए अपने अगूठों को काटने के मूर्खतापूर्ण उपाय के बावजूद, अपने बड़े पैरों के लिए बड़े जूते ही क्यों न खरीदे जाएँ ? [देखें, जापान, मार्च, 1955 ई० के रोरन केजू (Roron Keizain) (इकोनामिक स्टैंडिज क्वाटर्ली) में प्रकाशित एम० टाची एवं के० अकमासु का ए रिपोर्ट ऑन दि वर्ल्ड पोपुलेशन कानफ्रेंस।] निराशावादी विचारधारा के लिए देखें, मई, 1955 ई० के रिश्यू ऑफ इकानामिक्स एण्ड स्टेटिक्स में एच० एच० विलार्ड का 'सम नोट्स ऑन पोपुलेशन एवं लिविंग लेवल्स'।

जनाधिक्य की समस्या के निदान के सम्बन्ध में माल्थस एवं मार्क्स के बीच संस्थापक विवाद की बात याद आती है। केन्स ने भी इस मतभेद की ओर संकेत किया था।¹ माल्थस-मार्क्स-विवाद के सम्बन्ध में केन्स की पूर्ण उद्धृत टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए अधिक अनुभूतिपूर्ण तरीका यह जान पड़ता है कि जनसंख्या की समस्या पर, विशेषतः जीवन-स्तर के संकुचित अर्थ में, दो ओर से आक्रमण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इसके लिए अल्पकाल में उत्पादन में वृद्धि पर पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिए तथा जनसंख्या की वृद्धि की दर को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालीन प्रयास करना चाहिए।

हैरोड के विकास की प्राकृतिक दर

अब यहां हैरोड के विकास की प्राकृतिक दर की तुलना विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम गति से लाभदायक जान पड़ती है। हैरोड ने अपनी प्राकृतिक दर की परिभाषा इस प्रकार से दी है : “प्राकृतिक दर प्रगति की वह दर है, जिसे जनसंख्या की वृद्धि एवं टेक्नोलॉजिकल प्रगति सम्भव बनाती है तथा जो निपज की उस रेखा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके प्रत्येक बिन्दु पर सभी प्रकार के उत्पादकों को यह संतोष होता है कि वे श्रम एवं विश्राम के बीच उचित संतुलन स्थापित कर रहे हैं।”² इसके अतिरिक्त, वह अपने प्राकृतिक दर की धारणा से अनैच्छिक बेरोजगारी को अलग कर देते हैं जिससे प्राकृतिक दर से बढ़ने वाली अर्थ-व्यवस्था में सदा पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। अंततः, हैरोड यह सुझाव देते हैं कि दीर्घकाल में विकास की कोई भी दर प्राकृतिक दर से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसे ‘अधिकत साध्य’ विकास की दर की संज्ञा दी है।³

हैरोड ने एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था का विचार किया है जिसमें विकास की प्राकृतिक दर (यानी जनसंख्या की वृद्धि एवं टेक्नोलॉजिकल प्रगति के अनुरूप दर) में

1. केन्स एसेज इन वायग्राफी, पृ० 107-8।
2. डायनमिक इकानामिक्स, पृष्ठ 87
3. देखें इनकी “दो रेट आफ इंटरेस्ट” एवं अन्य, पृष्ठ 160। डब्लू० फेलनर इस महत्व को बिल्कुल भूल जाते हैं, जब वे इस बात की शिकायत करते हैं कि हैरोड के अर्थ में विकास की प्राकृतिक दर कोई निश्चित परिमाण नहीं है; क्योंकि विकास की कोई इस प्रकार की अनन्य दर नहीं है, जिसे प्राकृतिक कारण सम्भव बनाते हों। (देखें फेलनर का मैकमिलन, न्यूयार्क, 1951 ई० में प्रकाशित मनी, ट्रेड एण्ड इकानामिक ग्रोथ में ‘दि कैपिटल आउट-पुट रेशियो इन डायनमिक इकानामिक्स’। तथापि, फेलनर की आपत्ति हैरोड के प्राकृतिक दर की अस्पष्ट प्रकृति से है। यदि हैरोड ने अपने विकास के प्राकृतिक दर का निर्धारण स्पष्टतः अधिक निश्चित प्राकृतिक कारणों के सम्बन्ध में किया होता, तो इसकी अधिकांश अस्पष्ट प्रकृति दूर हो गई होती।

विकास की प्रमाणित दर से कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। विकास की प्रमाणित दर वह दर है, जो बचाने वालों की इच्छा एवं विनियोजताओं के लाभ के परियोजन के अनुरूप होती है और, तब वे इसके लिए निदान प्रस्तावित करते हैं। दूसरे शब्दों में वे एक ऐसी विकसित अर्थ-व्यवस्था का वर्णन करते हैं, जिसमें पूँजी-संग्रह जनसंख्या में वृद्धि की अपेक्षा अधिक बढ़ता है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार हैरोड के प्राकृतिक दर की धारणा विकसित पूँजीवादी की व्यवस्था की दीर्घकालिक अस्थिरता (विशेषतः अधोमुखी) के कारणों के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। "थ्रोमती रॉबिन्सन ने प्राकृतिक दर के प्रयोग को इस आधार पर चुनौती दी है कि हैरोड द्वारा अव्यञ्छित स्थिति के ठीक विपरीत अधिक/सार्वभौमिक स्थिति वह है, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि में पूँजी के संग्रह से अधिक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है"।¹

प्रयोग के प्रश्न के अतिरिक्त भी हैरोड के प्राकृतिक दर की धारणा स्वयं कई कारणों से सदिग्धात्मक है। प्रथमतः उनके अनुसार यह अशत जनसंख्या की वृद्धि पर निर्भर करती है जबकि श्रम एवं विभ्राम के बीच समुदाय के चुनाव की ओर उनका संकेत सम्पूर्ण जनसंख्या के बदले श्रमसंख्या का सुभाव देता है। इस पिछली स्थिति में भी हैरोड को श्रम-संख्या में वृद्धि का निर्धारण ऊपर दिये गये समीकरण (2) के आधार पर करना पड़ता है। दूसरा, हैरोड तकनीकी सुधारों की प्रकृति एवं प्रभाव, जिन पर उसकी प्राकृतिक दर अशत निर्भर करती है, को अनिर्दिष्ट ही छोड़ देते हैं। श्रम बचाने वाले आविष्कारों को मनमाने ढंग से पूँजी बचाने वाले तकनीकों² के समानार्थक रूप में परिभाषित कर, हैरोड एक स्थायी श्रम-निपज अनुपात एवं एक स्थायी पूँजी-निपज अनुपात का अनुद्धान करने हुए जान पड़ते हैं। इस प्रकार वे कहते हैं कि "भेरी धारणा यह नहीं है कि आविष्कार पूर्व परिभाषित अर्थ में प्रधानतः श्रम बचाने वाले होते हैं।"³ किन्तु, केवल उन्हीं आविष्कारों को, जो पूँजी

1. इस प्रकार, थ्रोमती रॉबिन्सन स्पष्टतः एक पूँजी-विपन्न विश्व को ध्यान में रखते हुए हैरोड के एक-पक्षीय प्रयोग की आलोचना करती है। इनके अनुसार "कोई भी समुदाय, जिसकी एकमात्र समस्या यह है कि उसके पास आवश्यकता के लिए सभी प्रकार से पर्याप्त पूँजी है, को वास्तव में अधिक चिन्ता नहीं करनी पड़ती। अतएव, हमें भी इनकी कठिनाइयों को याद कर कष्ट नहीं उठाना चाहिए।" (देखें इनकी 'वी रेट ऑफ इन्टरेस्ट, एव अन्य, पृष्ठ 161)। फिर भी थ्रोमती रॉबिन्सन हैरोड के प्राकृतिक दर की धारणा से असहमत नहीं होकर केवल इसके प्रयोग से असहमत है।
2. डायनामिक इकानामिक्स, पृष्ठ 26-7।
3. पूर्व उद्धृत, पृष्ठ 28।

प्रयोग करने वाले होते हैं, श्रम वचाने वाला समझना एक निरर्थक पुनरुक्ति है।¹ इसका कारण यह है कि हैरोड के श्रम वचाने वाले आविष्कारों की परिभाषा की आशय के ठीक विपरीत, निपज की प्रति-इकाई अधिक पूँजी के प्रयोग के वगैर भी निपज की प्रति-इकाई श्रम में कमी हो सकती है, या दूसरे शब्दों में, प्रति-इकाई श्रम के निपज में वृद्धि हो सकती है। इस विरोधी विचार का कारण यह है कि श्रम वचाने वाली तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप निपज में सदा वृद्धि होती है और इस प्रकार अपने हर (Y) में वृद्धि के द्वारा यह पूँजी-निपज अनुपात (K/Y) को घटा देता है। इस प्रकार हमें केवल पूँजी प्रयोग करने वाले तकनीक से ही श्रम-वचाने वाले तकनीक को उपस्थित नहीं करना चाहिए।

फिर भी, यदि पूँजी-निपज अनुपात में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के वावजूद श्रम-निपज अनुपात को तकनीक की दृष्टि से स्थायी माना जाय, जिससे कि $N/Y = B = \text{स्थिर}$ हो, तो निपज में श्रम-संख्या में वृद्धि की दर से ही वृद्धि होनी चाहिए यानी

$$G_n = \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta N/B}{N/B} = \frac{\Delta N}{N} = n. \quad (6)$$

इस प्रकार समीकरण (6) द्वारा दिया गया G_n बढ़ती हुई श्रम-संख्या को पूर्णतया नियुक्त रखने के लिए आवश्यक हैरोड के विकास की प्राकृतिक दर की धारणा के विल्कुल सन्निकट जान पड़ता है।

किन्तु यदि G_n हैरोड के प्राकृतिक दर के सन्निकट है तो यह हमारे अर्थ में 'सामाजिक श्रेष्ठतम दर' से कम है। क्योंकि, यद्यपि हैरोड की प्राकृतिक दर पूर्ण रोजगार की गारंटी प्रदान करती है, तथापि यह बढ़ते हुए दीर्घकालिक जीवन-स्तर (प्रति परिवार पोषण करने वाले के) को स्वीकार नहीं करती। जीवन-स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सुस्पष्ट परिवर्त्ती के निषेध का प्रधान कारण हैरोड की स्थायी श्रम-निपज अनुपात की मान्यता है। किन्तु यदि श्रम-निपज में दीर्घकाल में $H_t = H_0 (1 + h)t$, के अनुसार कमी होती है (यानी यदि श्रम की औसत उत्पादकता में वृद्धि हो रही है) तो अन्यथा-अवश्यंभावी तकनीक मूलक बेरोजगारी को दूर करने तथा जीवन-स्तर में दीर्घकालिक सुधार के लिए समीकरण (4) के अनुसार निपज में G_m की दर से वृद्धि अनिवार्य है। तकनीकी प्रगति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने वाली श्रम की उत्पादकता में वृद्धि की दर (h) की प्रस्तावना से हैरोड की प्राकृतिक दर हमारे सामाजिक श्रेष्ठतम गति की दर के समरूप हो जाती है। इससे

1. इस आलोचना के सम्बन्ध में देखें सन् 1954 ई० के ओसाका युनिवर्सिटी इंस्टी-च्यूट ऑफ सोशल एण्ड इकानामिक रिसर्च के 'स्टडिज इन ग्रोथ इकानामिक्स' (वाई० टाकता द्वारा संपादित) में वाई० टाकता का 'ए रिपलीकेशन ऑन ग्रोथ रेट्स'।

$G_n = G_m$ के हो जाता है। अस्पष्ट रूप में व्यक्त किए जाने के बावजूद हैरोड के विकास की प्राकृतिक दर की धारणा जनसंख्या एवं तकनीकी जैसे महत्वपूर्ण तत्वों के सम्बन्ध में अन्तर्दृष्टि प्रदान करने तथा उसके प्रामाणिक दर के साथ-साथ, वृद्धिशील अर्थ-व्यवस्था के दीर्घकालिक अस्थायित्व के सम्बन्ध में प्रकाश डालने के लिए महत्वपूर्ण है।

अपेक्षित पूँजी-सचय

यद्यपि विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम दर हमें जनसंख्या के पूर्णतः रोज़गार एवं अच्छे जीवन की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रगति की दिशा को बतलाती है, फिर भी यह स्वयं इस बात को स्पष्ट नहीं करती कि इस प्रकार की प्रगति वास्तव में प्राप्त की जा सकती है तथा इसे लगातार बनाये रखा जा सकता है अथवा नहीं। अब इस स्थान पर अपेक्षित पूँजी सचय के सम्बन्ध में विचार करना अनिवार्य है। यदि समीकरण (4) द्वारा व्यक्त विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम दर समाजशास्त्रीय एवं तकनीकी ढंग से दी हुई हो, तो पूँजी सचय की अपेक्षित दर को निर्धारित करना संभव एवं आवश्यक है। यह आवश्यक इसलिए है कि बढ़ती हुई धन-संख्या को सञ्चित करने तथा वृद्धिमान जीवन-स्तर को प्राप्त करने के लिए पूँजी के बढ़ते हुए कोष की आवश्यकता होती है। यह सम्भव इसलिए है कि अपेक्षित (मागी हुई) वास्तविक पूँजी की मात्रा का निपज से कुछ निश्चित सम्बन्ध होता है। यदि सामाजिक श्रेष्ठतम विकास के लिए आवश्यक पूँजी-सचय की दर निर्धारित हो जाती है, तो अगला तार्किक प्रश्न यह हो सकता है कि क्या इस दर¹ तथा वांछित उपभोग के संभावित त्याग पर जनसंख्या वृद्धि की पूर्ति करने के लिए योग्य एवं इच्छुक है अथवा नहीं।

अपेक्षित निवेश-अनुपात

सामाजिक श्रेष्ठतम विकास के लिए आवश्यक पूँजी में वृद्धि की दर को निर्धारित करने के लिए पहले पूँजी-निपज के अनुपात को स्पष्ट करना आवश्यक है। वास्तविक पूँजी के लिए K तथा निपज के लिए Y मानने पर एक निश्चित मात्रा में निपज के उत्पादन के लिए अपेक्षित वास्तविक पूँजी की मात्रा को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है $K = by$, जिसमें b पूँजी-निपज अनुपात है, जिसमें

1. अपने "डायनमिक इकानामिक्स" (पृ० 87) में हैरोड इसी प्रकार का प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न का उनका अपना उत्तर यह है कि निपज में वृद्धि की प्राकृतिक दर के अनुरूप विनियोग की दर बचाने वालों की इच्छाओं के अनुरूप हो भी सकती है अथवा नहीं भी। अतएव, वे $G_n Cr =$ अथवा s के लिखते हैं जिसमें G_n प्राकृतिक दर, Cr अपेक्षित पूँजी-निपज अनुपात तथा s बचत अनुपात हैं।

तकनीकी प्रगति एवं/अथवा सापेक्ष साधन मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप परिवर्तन होता है। उपर्युक्त सम्बन्ध से यह स्पष्ट होता है कि यदि सामाजिक श्रेष्ठतम निपज में ΔY से वृद्धि होती है तो पूँजी में भी निश्चय ही $\Delta K = b\Delta Y + Y\Delta b$ मात्रा के बराबर वृद्धि होगी। इसमें $Y\Delta b$ निपज के किसी भी स्तर और इस लिए अपेक्षित अतिरिक्त वास्तविक पूँजी की मात्रा पर परिवर्तनीय पूँजी-निपज अनुपात के सम्भावित प्रभाव को व्यक्त करता है। विकल्पतः हम यह भी कह सकते हैं कि सामाजिक श्रेष्ठतम निपज $\Delta Y = \Delta K/b + Y\Delta b/b$ मात्रा तक विस्तार-क्षम्य है। अतएव यदि किसी अर्थ-व्यवस्था को G_m की दर से, यानी सामाजिक श्रेष्ठतम दर से बढ़ना है, तो पूँजी में भी निश्चित रूप से G_m की दर से ही वृद्धि होनी चाहिए। क्योंकि $K = bY$ से तथा सरलता के लिए $Y\Delta b$ पद को छोड़ देने से निम्नलिखित प्राप्त होता है—

$$\frac{\Delta K}{K} = \frac{b\Delta K}{K} = \frac{b\Delta Y}{bY} = \frac{\Delta Y}{Y} = G_m, \quad (7)$$

जिसमें $\Delta K/K$ पूँजी में वृद्धि की अपेक्षित दर है, जो वचतकारों की अभिवृद्धि से सम्बद्ध नहीं भी हो सकती है।

समीकरण (7) के द्वारा दिये गये पूँजी में वृद्धि की अपेक्षित दर को सुपरिचित वचत एवं विनियोग सिद्धान्त के अनुरूप बनाने के लिए $\Delta K/K = Y$ मानकर उपर्युक्त दर को अपेक्षित विनियोग अनुपात के रूप में सुगमता-पूर्वक निम्न लिखित प्रकार से दिखलाया जा सकता है—

$$\frac{I^r}{Y} = \frac{\Delta K}{Y} = \frac{YK}{Y} = Yb = Gmb, \quad (8)$$

जिसमें I^r/Y अपेक्षित विनियोग अनुपात को व्यक्त करता है। यदि अपेक्षित विनियोग अनुपात समीकरण (8) के द्वारा दिया गया हो, तो जनसंख्या को निश्चय ही वास्तविक आय की इसी दर से वचत करनी चाहिये, यानी—

$$S^r = \frac{I^r}{Y} = Gmb, \quad (9)$$

जिसमें S^r अपेक्षित वचत-अनुपात को व्यक्त करता है। S^r को सामाजिक श्रेष्ठतम विकास के लिए आवश्यक वास्तविक पूँजी की पूर्ति का मापक मानकर समीकरण (7) से (9) के परिचालन-सम्बन्धी महत्व को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

यदि $G_m = 0.05$, $b = 3$, तो $S^r = 0.15$
(विकसित अर्थ-व्यवस्था)

यदि $G_m = 0.035$, $b = 3.5$, तो $S^r = 0.1225$
(मध्यवर्ती अर्थ-व्यवस्था)

यदि $G_m = 0.025$, $b = 4$, तो $S^r = 0.10$

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था

उपर्युक्त माँडलो में सामाजिक श्रेष्ठतम विकास की दर का अलग-अलग मूल्य, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, जनसंख्या एवं उत्पादकता में वृद्धि की दर में विभिन्नता की मान्यता के परिणामस्वरूप है। जहाँ तक पूँजी-निपज अनुपात के मूल्य में विभिन्नता का सम्बन्ध है, ये इस मान्यता पर आधारित हैं कि आर्थिक विकास की स्थिति जितनी ही उच्चतर होती है, निपज की प्रति-इकाई के लिए अपेक्षित पूँजी की मात्रा उतनी ही कम होती है, या वस्तुतः यों कहा जा सकता है कि पूँजी की ओर से उत्पादकता उतनी ही अधिक होती है। इन मान्यताओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम गति प्राप्त करने तथा बनाए रखने के लिए स्थायी तौर पर अपनी शुद्ध राष्ट्रीय निपज का 10 प्रतिशत बचाना पड़ेगा। इसी प्रकार एक विकसित अर्थ-व्यवस्था को स्थायी तौर पर 15 प्रतिशत तथा मध्यवर्ती अर्थ-व्यवस्था को स्थायी तौर पर 12.5 प्रतिशत बचाना पड़ेगा। अब स्वाभाविक प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक प्रकार की अर्थ-व्यवस्था वास्तव में अपेक्षित दर से बचाती है अथवा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग, विशेषतः एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में देंगे।

अपेक्षित बनाम वास्तविक बचत अनुपात

यदि अधिकांश आधुनिक अर्थ-व्यवस्थाएँ वास्तव में अपनी शुद्ध राष्ट्रीय निपज का 3 से 5 प्रतिशत तक बचा सकें तो, जैसा कि प्राप्य आँकड़ों से विदित होता है इनके लिए समीकरण (9) में दी हुई शर्तों को पूरा करना यथायतः बड़ा ही कठिन हो जायगा। मान लें कि किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में श्रम-संख्या में वृद्धि की दर 2 प्रतिशत तथा श्रम की उत्पादकता में वृद्धि की दर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत है। इससे उस अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य यथार्थ, निपज में $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत सामाजिक श्रेष्ठतम विकास की दर को प्राप्त करना तथा बनाये रखना हो सकता है, जैसा कि उपर्युक्त $G_m = 0.025$ के उदाहरण में दिया गया है। तब समीकरण (9) के अनुसार अपेक्षित बचत-अनुपात 10 प्रतिशत है। किन्तु यदि सम्बद्ध अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की सैथानिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि इस प्रकार की है कि यह केवल 5 प्रतिशत ही वास्तविक बचत कर सकती है, तो वहाँ बचत में $(s^* - s)$ के बराबर कमी होगी। इस में s वास्तविक बचत अनुपात को व्यक्त करता है। जब तक बचत में यह कमी किसी भी प्रकार पूरी नहीं की जाती, तब तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था पूँजी के अभाव में, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं एवं उत्पादकता के अनुरूप अपनी निपज में $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत वृद्धि की दर को दीर्घकाल में बनाये रखने को कौन कहे, प्राप्त करने में भी समर्थ नहीं हो सकती।

अपेक्षित श्रेष्ठतम विकास की तुलना में पूँजी के अभाव की समस्या से

पीड़ित अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के समक्ष दो विकल्प हैं—या तो ॥ अथवा और ॥ में अधोमुखी समयोजन द्वारा अपेक्षित निवेश के अनुपात में कमी या संस्थानिक एवं मनोवैज्ञानिक ग्रंथ में उचित परिवर्तन के द्वारा वास्तविक वचत-अनुपात में वृद्धि। इसके अतिरिक्त संभावनाएँ भी हैं। प्रथमतः, एक विदेशी व्यापारिक सम्बन्ध वाली विकृत अर्थ-व्यवस्था में पूँजी के आयात द्वारा अपेक्षित एवं वास्तविक वचत अनुपात के अन्तर को समाप्त करने की सैद्धांतिक संभावना सदा रहती है। द्वितीय, वचत-कर्त्ताओं की अभिवृत्ति का विचार किए वगैर, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था उद्योगों के संगठन में सुधार-जैसे साधनों की अत्यधिक गतिशीलता, उपकरणों के अत्यधिक मानकीकरण, निपज की अत्यधिक एकरूपता, एवं साधनों की अत्यधिक स्थाना-पन्नता के द्वारा पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि (पूँजी की पूर्ति की विपक्षता में) कर सकती है।¹

पूर्वोक्त विश्लेषण से विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम गति को प्राप्त करने तथा बनाये रखने की तकनीकी संभावनाओं एवं कठिनाइयों के सम्बन्ध में ज्ञान होता है। चूँकि, जनसंख्या तकनीक एवं पूँजी सभी अपने-अपने विकास के स्वतंत्र नियमों का अनुकरण करते हैं, इसलिए यह मानने का कोई भी कारण नहीं है कि विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम दर एवं अन्य विकास-दरें, संयोग से अथवा प्रयास के अतिरिक्त, सदा समान होती हैं। ऐसा होने पर इस बात की प्रबल सम्भावना रहती है कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में पूँजी के अभाव में थ्रम की उत्पादन-क्षमता बेकार हो जाती है तथा जीवन-स्तर मन्द पड़ जाता है।

1. वचत की पूर्ति से पृथक् पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता के विस्तारपूर्वक विवरण के लिए देखें, मेरी पुस्तक 'इण्ट्रोडक्शन टू केन्सीयन डायनमिक्स' एलेन एण्ड अनविन, लंदन एवं कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क 1956 ई०, पृ० 209।

पूँजी-संचय एवं उत्पादन-सामर्थ्य

किसी भी अर्थ-व्यवस्था में पूँजी-संचय औद्योगीकरण की कुंजी है ; क्योंकि पूँजी ही उत्पादन का एकमात्र ऐसा साधन है, जिसमें अनिश्चित प्रसारणीयता का गुण विद्यमान है। पूँजी का अनन्य गुण ही, औद्योगीकरण के लिए भूमि एवं श्रम की अपेक्षा, मुख्य रूप से पूँजी के प्रसार पर निर्भर करने का मूल प्रयोजन है। साथ ही, कोई भी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था पूँजी के संचय का विचार अर्थ-व्यवस्था की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के लिए, न कि समर्थ माँग उत्पन्न करने के लिए करती है। विशेषरूप से हम लोग निपज के विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम दर को वास्तविक रूप में प्राप्त करने एवं बनाये रखने के सम्बन्ध में पूँजी-संचय एवं उत्पादन क्षमता के तकनीकी सम्बन्ध पर विचार करेंगे। विचारणीय वस्तु को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए हम लोग हेरोड-डोमर मॉडल, जिसमें उत्पादन-सामर्थ्य एवं समर्थ माँग की परस्पर क्रिया निहित है तथा थ्रीमती जॉन रॉबिन्सन के पूँजी-संचय के सिद्धान्त का भी आलोचनात्मक तरीके से अवलोकन करेंगे।

क्षमता-निर्माण की प्रक्रिया

किसी भी अर्थ-व्यवस्था की सम्भावित उत्पादन-क्षमता टेक्नोलॉजी की दो हुई सीमाओं के अन्तर्गत, वहाँ पर उपलब्ध सभी उत्पादक साधनों के पूर्ण उपयोग से प्राप्त सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की सम्पूर्ण पूर्ति में निहित होती है। टेक्नोलॉजी में प्रगति तथा साधनों की खोज से यह बढ़ सकती है, किन्तु इन प्रभावों को पूँजी अथवा श्रम की उत्पादकता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। साथ ही, यदि श्रम को दिया हुआ मान लिया जाय, तो उत्पादन-क्षमता पर पूँजी की मात्रा एवं गुण के अनन्य फलन के रूप में विचार किया जा सकता है। ऐसा इस मान्यता पर किया जाता है कि श्रम का अभाव प्राप्त उत्पादक पूँजी के पूर्ण उपयोग में कोई बड़ी बाधा उपस्थित नहीं करता है। तब उत्पादन-क्षमता में वृद्धि (क) निवेश के अनुपात एवं (ख) निवेश की उत्पादकता के तकनीकी सम्बन्ध पर निर्भर करेगी। अब हमें देखना है कि उत्पादन-क्षमता में वृद्धि इन दोनों के बीच यथार्थतः क्यों और किस प्रकार निश्चित होती है।

पूँजी एवं क्षमता की वृद्धि

यदि समर्थ माँग का दिया हुआ स्तर इतना ऊँचा हो, जिससे कि वर्तमान वास्तविक पूँजी के पूर्ण प्रयोग को न्यायोचित करार दिया जा सके, तो शुद्ध निवेश (1), यानी वास्तविक पूँजी में वृद्धि ($1 = \Delta K$) का तात्पर्य निश्चित रूप से उत्पादन-सामर्थ्य में वृद्धि होगी :

$$\Delta Y' = \sigma \Delta K = \sigma 1, \quad (1)$$

जिसमें Y' उत्पादन क्षमता, K वास्तविक पूँजी एवं σ प्रचलित टेक्नोलॉजी की दर पर निवेश की उत्पादकता है।

निपज की वनावट एवं उद्योग का संगठन दिया हुआ रहने पर, शुद्ध निवेश एवं सामर्थ्य में निम्नांकित प्रकार का सम्बन्ध होता है :

$$\frac{1}{Y'} = \delta \quad (2)$$

जिसमें δ निवेश-अनुपात जिसका, मूल्य एक अर्थ-व्यवस्था से दूसरी अर्थ-व्यवस्था में तथा आर्थिक विकास के एक स्तर से दूसरे स्तर में अलग-अलग होता है। समीकरण (2) में व्यक्त निवेश-अनुपात—वचत-अनुपात जो वचत की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है, के ठीक विपरीत पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन के सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस अन्तर का महत्व थोड़ी देर बाद स्पष्ट किया जायगा।

समीकरण (1) तथा (2) से हमें उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की निम्नलिखित दर प्राप्त होती है :

$$\frac{\Delta Y'}{Y'} = \sigma \frac{1}{Y'} = \sigma \delta = GK, \quad (3)$$

जिसमें GK उस दर को बतलाता है, जिसमें शुद्ध निवेश के द्वारा यदि विनियोग-सम्बन्धी वस्तुओं के उद्योगों की पूर्ण क्षमता का प्रयोग किया जाय, तो उत्पादन-क्षमता का प्रसार किया जा सकता है। समीकरण (3) से यह स्पष्ट होता है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि की दर में निवेश-अनुपात (δ) तथा निवेश की क्षमता σ में वृद्धि के ठीक समान अनुपात में परिवर्तित होने की क्षमता है। यहाँ पर निवेश-अनुपात पूँजी के परिमाण तथा निवेश की उत्पादकता-पूँजी के गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। समीकरण (3) से यह भी प्रकट होता है कि पूँजी एवं निपज दोनों में समान दर से एवं घातीय ढंग से निम्नलिखित प्रकार से वृद्धि होती है :

$$Y'(t) = Y'oe^{\sigma \delta t}, \quad (4)$$

और

$$K(t) = Koe^{\delta t} \quad (5)$$

समीकरण (3) के परिचालन-सम्बन्धी महत्व को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है :

यदि $\delta = 0.05, \sigma = 0.2$, तो $Gk = 0.01$
(अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था)

यदि $\delta = 0.08, \sigma = 0.25$, तो $Gk = 0.02$
(मध्यवर्ती अर्थ-व्यवस्था)

यदि $\delta = 0.12, \sigma = 0.5$, तो $Gk = 0.06$
(विकसित अर्थ-व्यवस्था)

यहाँ σ के मूल्य का अनुपात तीनों प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए मान लिये गये पूँजी-निपज अनुपात के व्युत्क्रम से लगाया गया है। (अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए $K/Y = 5$, मध्यवर्ती अर्थ-व्यवस्था के लिए $K/Y = 4$ तथा विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए $K/Y = 2$ की मान्यता पर $\frac{1}{5} = 0.2$, $\frac{1}{4} =$

0.25 तथा $\frac{1}{2} = 0.5$)। δ के मूल्य का अनुमान इन विभिन्न प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं के बचत-अनुपात के यथासम्भव अनुरूप भी लगाया जाता है। उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की उत्पादन-क्षमता अधिक विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की अपेक्षा बहुत धीरे-धीरे बढ़ती है। इसका कारण δ , जो पूँजी के परिमाण को व्यक्त करता है, के साथ-ही-साथ σ , जो पूँजी के गुण को व्यक्त करता है, की न्यूनता है। अतः अब हमे उन ठोस कारणों की जांच करनी है, जिनके परिणामस्वरूप एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में निरन्तर निम्न-निवेश अनुपात तथा निवेश की निम्न उत्पादकता पाई जाती है।

निम्न निवेश-अनुपात

संस्थापक अर्थशास्त्रियों ने यह मान लिया था कि निपज की रचना इतनी समजातीय होती है तथा उद्योग का संगठन इतना समायोजित होता है कि जो कुछ भी उपभोग में नहीं आता, यानी बचा लिया जाता है, उसका उपयोग सदा पूँजीगत वस्तुओं में बिना किसी कठिनाई के किया जाता है। इस सरल मान्यता के आधार पर यह तर्क करना न्याय-संगत जान पड़ता है कि यदि कोई अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था अधिक मितव्ययी होने का प्रयास करे, तो वह पूँजी एवं क्षमता में विकास की गति को तीव्रतर बना सकती है। किन्तु तब हम इस असंगत कि कुछ अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में बचत की पर्याप्त उच्च औसत प्रवृत्ति के बावजूद इनमें पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता में कमी होती है, को समझने में किकर्तव्य-विमूढ़ हो जाते हैं। वास्तव में, बात यह नहीं है कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ

इतनी अमितव्यापी होती हैं कि ये वास्तविक आय के रूप में कुछ वचा ही नहीं पातीं, वरन् यह कि कुछ तकनीकी कठिनाइयों के चलते, जिन्हें संस्थापक अर्थ-शास्त्रियों ने अपनी मितव्ययिता के द्वारा प्रगति वाले तर्क में मान्यता के रूप में स्वीकार किया था, वचत की इच्छा के बावजूद उत्पादक उपकरणों में न तो ये विनियोग करती हैं और न कर ही सकती हैं।

उपर्युक्त असंगति के कारणों की व्याख्या के लिए संस्थापक मान्यताओं को समाप्त कर वास्तविक विश्व में निपज की विपमजातीय रचना तथा उद्योग की विपमायोजित संगठन को मान्यता प्रदान करना अनिवार्य है। एक बार ऐसा मान लेने पर, यह स्पष्ट हो जायगा कि वास्तविक आय के रूप में जो कुछ भी वचाया जाता है, वह सम्पूर्ण पूँजीगत माल के लिए उपयुक्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में गैर-उपभोग का आवश्यक रूप से यह आशय नहीं है कि इससे उस प्रकार के मानवीय एवं भौतिक साधनों की उपलब्ध होती है, जिसका प्रयोग शान्त रूप से सुगमता-पूर्वक पूँजीगत मालों के उत्पादन के लिए किया जा सकता हो। अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में इसका आशय यह है कि यदि वास्तविक आय के रूप में अधिक वचत के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कमर कसकर भी प्रयास किया जाय, तो भी उप-भोक्ता उद्योगों द्वारा मुक्त श्रम, उपकरणों तथा कच्चे पदार्थों की विशिष्टता के परिणामस्वरूप अधिक पूँजीगत मालों का उत्पादन सम्भव नहीं हो सकता। निपज की रचना जितनी ही विपमजातीय होती है, उत्पादक साधनों की यह विशिष्टता उतनी ही अधिक होती है; क्योंकि जब तक उपभोक्ता एवं टिकाऊ वस्तुएँ भौतिक रूप में अलगाने योग्य होती हैं, (जैसे गेहूँ एवं मशीन, अगर ये वस्तु सूची के रूप में अलगाने योग्य नहीं हैं), इनके उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन का साधन ऐसी विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं, जो साधारणतः पारस्परिक रूपांतरण की अवज्ञा करती है। इस प्रकार निपज की विपमांगीय रचना, जो एक आधुनिक आर्थिक समाज की प्रधान विशेषता है, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में निवेश अनुपात के वास्तविक वचत-अनुपात से कम होने की असंगत क्रिया की एक मौलिक व्याख्या है। उद्योग का विपमायोजित संगठन इसका एक दूसरा मौलिक कारण है। अब पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता में इस वाद वाली अड़चन पर विचार किया जाय।

एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के औद्योगिक संगठन में निम्नलिखित हठ-धामिताएँ एवं कठिनाइयाँ पाई जाती हैं : प्रथमतः, उपभोक्ता वस्तुओं तथा पूँजीगत वस्तुओं अथवा कृषि एवं उद्योग के बीच उत्पादक साधनों की सापेक्षिक अगतिशीलता पाई जाती है। साधनों की इस अगतिशीलता के लिए अप्रभावपूर्ण श्रम-विनिमय व्यवस्थाएँ, परिवहन एवं संचार की अकुशल सुविधाएँ और असंगठित पूँजी-बाजार आदि कारण उत्तरदायी हैं। द्वितीय, इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में बहुत सारे छोटे पैमाने के पूँजीगत वस्तुओं के उद्योग होते हैं, जिनमें अप्रचलित और प्रायः

आदिमकालीन सद्य एव उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जनाधिक्य में परिपूर्ण अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में सस्ते श्रम की उपलब्धि सुप्रवाही संयंत्रों एवं उपकरणों के स्थापन को हतोत्साहित करती है, यद्यपि इन की स्थापना का व्यय आंतरिक अथवा बाह्य साधनों से जुटाया जा सकता है। तृतीय, तीव्र घिसावट एवं अप्रचलन के परिणामस्वरूप पूँजी की अपरिमित वरबादी होती है। अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में पूँजी का टिकाऊपन साधारणतः इस प्रकार का होता है कि इनमें विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की तुलना में ऊँची दर से पुनर्स्थापन-व्यय की आवश्यकता पड़ती है। इसका कारण यह है कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में सद्य एवं उपकरण साधारणतया इतने पुराने और घिमे हुए सामानों से बने हुए होते हैं कि कुल नये विनियोग का अधिकांश पुनर्स्थापन पर ही खर्च किया जाता है, जिससे पूँजी के कोष में शुद्ध वृद्धि के लिए बहुत कम अथवा कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में गृहयुद्ध, प्राकृतिक आपदाएँ, बड़े-बड़े अग्निकांड तथा सग्रह की अपर्याप्त सुविधाओं के परिणाम अत्यधिक पूँजी की वरबादी एवं क्षति के कारण भी घिसाई की औसत दर (भौतिक अर्थ में) अधिक ऊँची होती है। इन्हीं कारणों से पूँजीगत माल के उत्पादन की क्षमता वचत की पूर्ति से कम हो सकती है, यानी $S < \delta$ इससे दूसरे प्रकार से यों कहा जा सकता है कि $S < \delta$ असमानता पूँजीगत मालों की पूर्ति की अपेक्षा माँग के आधिक्य को बतलाती है क्योंकि $\delta Y'$ पूँजीगत माल की माँग, $(1-\delta)Y'$ उपभोक्ता वस्तुओं की माँग, $S Y'$ पूँजीगत माल की पूर्ति तथा $(1-S)Y'$ उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति को बतलाने है। इससे यह सिद्ध होता है कि $(S-\delta)Y' = (1-\delta)Y' - (1-S)Y'$ के। यह इस बात को सूचित करता है कि विदेशी व्यापारिक सम्बन्ध वाली विकृत अर्थ-व्यवस्था पूँजीगत मालों में कमी को उपभोक्ता वस्तुओं की आंतरिक पूर्ति के आधिक्य $(1-S)Y' - (1-\delta)Y' > 0$ के बदले में इनके आयात के द्वारा पूरा किया जा सकता है। विदेशी व्यापार के अभाव में $\delta = S$ बनाने के लिए निपज की बनावट और या उद्योग की संरचना को समायोजित करना होगा। किन्तु निपज की बनावट और उद्योग की संरचना की अति अनुकूल मान्यता के आधार पर भी यदि $\delta = S$ के होता है, तो निवेश की निम्न उत्पादकता के परिणामस्वरूप पूँजी की वृद्धि की दर श्रेष्ठतम विकास के उद्देश्य से बहुत ही कम होगी। अब ऐसी परिस्थिति में हमें अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में निवेश की न्यून उत्पादकता पर विचार करना चाहिए।

निवेश की न्यून उत्पादकता

मोटे तौर पर, मन्द पूँजी-सग्रह एवं तकनीकी प्रगति निवेश की उच्च उत्पादकता को अवरोध करती है। अल्प एवं स्थायी पूँजी का कोष पूँजी एवं अन्य उत्पा-

दक साधनों की तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित नहीं करता है। वास्तव में, यह कुछ व्यंग्यात्मक प्रतीत होता है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए पूँजी के गुण में सुधार करना अनिवार्य होता है, किन्तु पूँजी की मात्रा में तीव्र गति से वृद्धि नहीं होने के कारण यह ऐसा शीघ्रतापूर्वक नहीं कर सकती, जबकि किसी विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए ऐसा आवश्यक नहीं होने पर भी पूँजी की मात्रा में सुगमता-पूर्वक वृद्धि के कारण अपनी पूँजी के गुण में तेजी से सुधार कर सकती है। विश्व के सम्पूर्ण अल्प-विकसित हिस्से में उत्पादन के चक्रदार तरीके का अपर्याप्त प्रसारण उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के लिए अपेक्षाकृत अधिक एवं उत्तम पूँजी की विद्यमानता के विरुद्ध एक प्रबल मान्यता है। हस्त-प्रचलित औजारों पर निर्भर करने वाली अर्थ-व्यवस्था एवं संचालित उपकरणों पर निर्भर करने वाली अर्थ-व्यवस्था (जैसे पैरों से चलने वाली द्विचक्रीय गाड़ी बनाम ट्रैक्टर) के बीच उत्पादन-क्षमता के अन्तर की कल्पना करना कठिन कार्य नहीं है। चक्रीयता का स्तर जितना ही ऊँचा होता है, उत्पादन के अन्य साधनों के साथ प्रयुक्त पूँजीगत साधनों की प्रकृति उतनी ही अधिक स्वचालित होने की होती है। अपर्याप्त चक्रीयता स्वयं उच्च व्याज संरचना अथवा उपभोग के निर्वाह-स्तर का परिणाम हो सकता है। ये दोनों, मार्शल के प्रचलित शब्दों में, प्रतीक्षा के द्वारा पूँजी के अधिकाधिक प्रयोग को निरुत्साहित करते हैं। अतएव तकनीकी पिछड़ापन एवं मन्द पूँजी-संग्रह अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में निवेश की उत्पादकता को न्यून बनाने वाले मौलिक कारण हैं।¹

डोमर ने कुछ अधिक विशिष्ट कारणों का सुभाव दिया है जिनमें से कुछ अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में लागू होते हैं।² वे नये संयंत्रों को लगाये गये प्रति डालर की उत्पादन-क्षमता (इनके संकेतन के अनुसार) से निवेश के संभावित सामाजिक औसत क्षमता के न्यून होने के लिए श्रम की कमी को एकमात्र सर्वाधिक प्रधान कारण मानते हैं। डोमर² स्पष्टतः एक ऐसी विकसित अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखते हैं जहाँ जनसंख्या की वृद्धि धीमी अथवा स्थायी है, जिससे कि निपज के सम्बन्ध में श्रम की पूर्ति इतनी लोचदार नहीं होती है कि श्रम के प्रभाव में पुराने संयंत्रों के उत्पादन में और कमी करनी पड़ती है और इस प्रकार यह नये संयंत्रों के उत्पादन में वृद्धि को खिसका देता है। किन्तु एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था, जो स्वभावतः वेकार श्रमिकों से परिपूर्ण होती है, के संदर्भ में हम उसके सर्वाधिक प्रधान कारण को सबसे कम महत्वपूर्ण कारण मान सकते हैं। डोमर के अन्य कारणों—जैसे वह स्थिति जिसमें नये संयंत्र प्रभावोत्पादक माँग के अभाव में पूर्ण क्षमता भर उत्पादन नहीं कर सकते और अन्तिम स्थिति जिसमें जहाँ पर बाजार के लिये नये

1. कुछ अधिक मार्मिक टिप्पणी के लिए जे० रॉबिन्सन के रेट आफ इन्टरेस्ट, एवं अन्य में नोट्स आन दि इकानामिक्स आफ टेक्निकल प्रोग्रेस देखें।
2. इ० डी० डोमर का पूर्व उद्धृत "इक्सपैन्सन"।

संयंत्रों की प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप पुराने संयंत्र अपना उत्पादन कम कर देते हैं, कुछ अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में लागू होते हुए पाये जाते हैं। किन्तु इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं को विशेषरूप से निजी उपक्रम के आधार पर विकसित करने वाली अर्थ-व्यवस्था के रूप में व्यवस्था करना अनिवार्य है क्योंकि उन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में जो बहुत एव वृद्धिशील सार्वजनिक निवेश को गुण्य के रूप में संधारण करती हैं, प्रभावोत्पादक माँग के अभाव के कारण नये संयंत्रों के पूर्ण क्षमता से कम बिन्दु पर कार्य करने की संभावना बहुत ही कम पाई जाती है।

इस बात को मानते हुए कि संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए निवेश की उत्पादकता (उनका कुल σ) पुराने संयंत्रों की निपज पर नये संयंत्रों के प्रतिकूल प्रभाव से घट जाती है, तो जहाँ तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, स्वयं नये संयंत्रों में विनियोग किये गये प्रति डॉलर की उत्पादन-क्षमता (उनका अलग-अलग δ) के व्यावहारिक महत्व को कम करना भूल होगी। क्योंकि, किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में लिए, पिरामिड के प्रकार के नये संयंत्रों के निर्माण, चाहे अल्पकाल में इनका आय-प्रभाव जो भी हो, का परित्याग औद्योगीकरण-सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए निर्णायक महत्व की बात है। वास्तव में, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में प्रेक्षित रूप में निम्न उत्पादन-क्षमता के कारणों की, स्वयं नये संयंत्रों की प्रकृति एवं भेद के विशेष उल्लेख के वगैर, पूर्णरूप से व्याख्या नहीं की जा सकती और निवेश अनुपात (δ) जितना ही छोटा होगा, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को उन संयंत्रों एवं उपकरणों, जो दीर्घकाल में उत्पादन-क्षमता (यानी $\sigma = \Delta Y/1$ में अंतर्निहित बनावट को) में प्रसार करते हैं, के चुनाव में उतनी ही अधिक मावधानी से काम लेना पड़ेगा।

पूँजी एवं उत्पादकता की आवश्यकता

किसी अर्थ-व्यवस्था के वांछित विकास अथवा स्थायित्व से सम्बद्ध किये वगैर, पूँजी के संग्रह अथवा संग्रह का कोई अर्थ नहीं होता। हैरोड एवं डोमर ने विकसित पूँजीवादी व्यवस्था के सदर्भ में पूँजी-असंग्रह एवं दीर्घकालिक स्थायित्व के सम्बन्ध पर उचित रूप से जोर दिया है। किन्तु जहाँ तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, पूँजी-संग्रह एवं निपज की सामाजिक श्रेष्ठतम वृद्धि के सम्बन्ध पर जोर देना चाहिए। निम्नांकित विश्लेषण के लिए, जैसा कि सभी अर्थ-व्यवस्थाओं में होता है, हम लोग एक ऐसी स्थिति की सकल्पना करेंगे, जिसमें पूँजी की वृद्धि की दर निपज की सामाजिक श्रेष्ठतम वृद्धि से कम है, यानी $Gk < Gm$ ।

$GK = Gm$ बनाने के लिए, निवेश-अनुपात (α) को बढ़ाना या निवेश की उत्पादकता (σ) को बढ़ाना या दोनों को बढ़ाना आवश्यक है। $Gk = Gm$ तथा $Gk = \alpha\sigma$ से $\alpha' = Gm/\sigma$ एवं $\alpha' = Gm/\alpha$ के रूप में श्रेष्ठतम निवेश-अनुपात एवं

निवेश की श्रेष्ठतम उत्पादकता प्राप्त होती है। इन वाद वाले रूपों के परिचालन-सम्बन्धी महत्व को निम्नांकित उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है :

$$\text{यदि } Gm = 0.05, \sigma = 0.2, \text{ तो } \alpha' = 0.25$$

(श्रेष्ठतम निवेश-अनुपात)

$$\text{यदि } Gm = 0.05, \alpha = 0.1, \text{ तो } \alpha = 0.50$$

(श्रेष्ठतम उत्पादकता-अनुपात)

इस प्रकार विकास-दर का अधिकतम लक्ष्य 5 प्रतिशत तथा वास्तविक निवेश-उत्पादकता अनुपात के 2 प्रतिशत दिया हुआ होने पर, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को अपने निवेश-अनुपात को 25 प्रतिशत के श्रेष्ठतम अंक तक बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार विकास की अधिकतम दर के समान रहने तथा वास्तविक निवेश अनुपात के 10 प्रतिशत दिया हुआ होने पर, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को अपने निवेश-अनुपात को 50 प्रतिशत के श्रेष्ठतम अंक तक बढ़ाना होगा, क्योंकि $Gk = Gm$ की विषमता इस बात का सूचक है कि वास्तविक निवेश-अनुपात एवं निवेश-उत्पादकता अनुपात अपेक्षित सामाजिक श्रेष्ठतम विकास से कम है। इसके अतिरिक्त (σ) अथवा α में वृद्धि का यथार्थवादी प्रयत्न बड़े (σ) अथवा α के विरुद्ध काम करने वाली शक्तियों, जिनकी व्याख्या हम लोग थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, को भी ध्यान में रखेगा।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक श्रेष्ठतम दर की वृद्धि के लिए एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को निम्नलिखित शतें पूरी करनी पड़ती हैं :

$$Gk = \sigma' \alpha' = Gm = n + h, \quad (6)$$

क्योंकि $Gk < Gm$ से स्पष्ट होता है कि पूँजी के अभाव के परिणामस्वरूप संरचनात्मक अपूर्ण रोजगार के बगैर बढ़ते हुए जीवन-स्तर के आधार पर प्रगति के आदर्श मार्ग को प्राप्त करने एवं उसे यथावत बनाये रखने के लिए अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में पूँजी में वृद्धि की दर बहुत ही कम है।

हैरोड-डोमर मॉडल पर टिप्पणी

हैरोड एवं डोमर¹ के विकास-सम्बन्धी मॉडल विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर तैयार किये गये हैं और इसलिए इनकी आलोचना मुख्यतः इन्हीं

1. हैरोड, डायनामिक इकानामिक्स; डोमर का पूर्व उद्धृत 'इक्सपेंशन एण्ड इम्प्लायमेंट'।

अर्थ-व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से की गई है।¹ किन्तु हम लोग इनके मॉडल का मूल्यांकन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट रूप से जानने के लिए करेंगे कि इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए कौनसी चीज प्रासंगिक है और कौनसी नहीं है।

हैरोड की प्रमाणित दर

अपनी प्राकृतिक दर, जिमकी चर्चा पहले की जा चुकी है, के अतिरिक्त हैरोड के निर्देश का एक और मापदण्ड विकास की 'प्रमाणित' दर है। इसे ये इस प्रकार परिभाषित करते हैं : "विकास की प्रमाणित दर प्रगति की वह व्यापक दर है, जो कार्यान्वित करने पर उद्यमकर्त्ताओं को इस मानसिक स्थिति में छोड़ती है कि वे समान प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं।"² हैरोड की प्रमाणित दर (G_w) की यथार्थ प्रवृत्ति को देखने के लिए निम्नलिखित रूपों में इसे जानना अनिवार्य है :

$$\frac{S}{Y_w} = s = \text{स्थिर} \quad (1')$$

$$\frac{\Delta K}{\Delta Y_w} = Cr = \text{स्थिर} \quad (2')$$

$$\Delta K = 1 = Cr \Delta Y_w = s Y_w, \quad (3')$$

$$G_w = \frac{\Delta Y_w}{Y_w} = \frac{s}{Cr}, \quad G_w Cr = s. \quad (4')$$

जो इस बात की ओर संकेत करता है कि

$$\frac{\Delta K}{K} = \frac{s Y_w}{K} = \frac{(s/Cr) K}{K} = \frac{s}{Cr} \quad (5')$$

यहाँ पर Y_w पूँजी के पूर्ण उपयोग से प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय निपज का प्रमाणित स्तर, K पूर्ण उपयोग की स्थिति में शुद्ध पूँजी का कोष, शुद्ध निवेश, s औसत बचत अनुपात और Cr पूँजी-निपज अनुपात का संतुलन मूल्य (औसत=कल्पित सीमात) या हैरोड के शब्दों में 'अपेक्षित पूँजी गुणक' है।

- I. फिर भी श्रीमती जे० रॉबिन्सन एवं आर० आइनर की आलोचनाओं में अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए बहुत सी शिक्षाप्रद चीजें हैं। (देखें जे० रॉबिन्सन का पूर्व उद्धृत मि० हैरोड्स डायनमिक्स एवं 'दि रेट आफ इन्टरेस्ट, इट्स'; आइनर का मार्च 1952 के अमेरिकन इकॉनामिक रिव्यू में प्रकाशित 'अंडर इम्प्लायमेंट-इक्विलिब्रियम रेट्स ऑफ ग्रोथ'।)

डायनमिक इकॉनामिक्स, पृष्ठ 82।

उपर्युक्त पद्धति से यह स्पष्ट होता है कि उद्यमकर्त्ता उतना विनियोग करते हैं, जितना समाज आय की पूर्ण-क्षमता के स्तर पर वचाने को तैयार होता है और यदि निपज में उसी दर से वृद्धि होती है, जिस दर से इस शुद्ध निवेश के परिणाम स्वरूप वास्तविक पूँजी में वृद्धि उसे होने देती है, तो सम्बन्धित अर्थ-व्यवस्था अपनी वास्तविक पूँजी का सदा पूर्ण उपयोग करती रहेगी और Gw की अपरिवर्त्ती दर से प्रगति करती रहेगी। जैसा कि समीकरण (5') में अंतर्भूत है, वचाने वालों की इच्छा के अनुरूप पूँजी में वृद्धि की अपेक्षित दर भी मालूम होती है। समीकरण (4') से यह स्पष्ट होता है कि हैरोड की प्रमाणित दर उत्पादन-क्षमता के उस संतुलित मूल्य की ओर संकेत करती है, जो वचत की पूर्ण क्षमता के प्रयोग के लिए पर्याप्त निवेश को प्रेरित करने के उद्देश्य से आवश्यक है, यानी जो अन्यथा अवश्यभावी बेकार अथवा अतिरिक्त क्षमता के परिणामस्वरूप ऋणात्मक शुद्ध निवेश को घटित होने से रोकती है। अब हम लोग Gw की दर से उन्नति करने वाली अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी हैरोड के मॉडल का मूल्यांकन, विशेषतः अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से करेंगे।

1. 'प्रमाणित' दर हैरोड द्वारा दिया गया इस मौलिक प्रश्न का उत्तर है कि विकसित पूँजीवादी व्यवस्था के स्थायी विकास को बनाये रखने के लिए कौन-कौन-सी आवश्यक शर्तें हैं। मार्स (एवं बाद में शुम्पीटर) ने भी इस प्रश्न को उठाया था तथा इसका उत्तर नैराश्यपूर्ण ढंग से दिया गया था। केन्स ने भी इसे पुनरु-जीवित किया था तथा इसका उत्तर आशावादी तरीके से देने का प्रयास किया था। केन्स की ही तरह हैरोड भी एक ऐसे विश्व की संकल्पना करता है, जिसमें वचाने की प्रवृत्ति निवेश की अभिप्रेरणा से अधिक होती है और इसलिए जिसमें चक्रीय अवस्फीति एवं दीर्घकालिक गतिरोध की निरन्तर प्रवृत्ति पाई जाती है। किन्तु केन्स के विपरीत हैरोड निम्नलिखित बातों पर जोर देता है (क) उत्पादन क्षमता के प्रभावोत्पादक माँग से अधिक हो जाने का खतरा, (ख) प्रेरित निवेश का प्रबल कार्य और विशेषतः (ग) प्रगतिशील संतुलन की अगतिशीलता। यहां याद रखने योग्य बात यह है कि केन्स का तात्पर्य एक दी हुई उत्पादन-क्षमता की तुलना में प्रभावोत्पादक माँग की अपर्याप्तता से था, जिसकी उत्पत्ति अपर्याप्त स्वतः प्रेरित निवेश की तुलना में वचत की उच्च सीमांत प्रवृत्ति (गुणक के माध्यम) से होती है। साथ ही, वचत एवं विनियोग की समानता से सम्बन्ध केन्स की संतुलन आय केवल स्थैतिक ही नहीं वरन् स्थिर भी है, जब कि हैरोड का संतुलन इस अर्थ में गत्यात्मक एवं अस्थिर दोनों हैं कि परिवर्त्तन की सकारात्मक अचल दर होते हुए भी, अव्यवस्थित हो जाने पर, इसमें स्वयं पूर्व अवस्था में पहुँचने की क्षमता नहीं होती।

इन विभिन्नताओं के बावजूद हैरोड के 'प्रमाणित' दर की धारणा केन्स के प्रभावोत्पादक माँग के सिद्धान्त पर पूर्णरूप-से आवृत्त है। वास्तव में, इसे केन्स के

अपर्याप्त प्रभावोत्पादक माँग एवं अनैच्छिक सामूहिक बेरोजगार के सदर्थ के बगैर समझा भी नहीं जा सकता। इस प्रकार हैरोड चक्रीय अवस्फीति की सम्भावना की परिकल्पना करते हैं, जो प्रभावोत्पादक माँग की 'जाच एवं वृद्धि' का प्रतिनिधित्व करने वाली विकास की दर (C) के अपेक्षित उत्पादन-क्षमता का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमाणित दर से निम्न होने के कारण उत्पन्न होती है। इसी प्रकार, वे दीर्घकालिक गतिरोध की सम्भावना की भी परिकल्पना करते हैं, जो 'प्रमाणित' दर के जनसंख्या एवं तकनीकी की वास्तविक प्रवृत्तियों के अनुरूप अधिकतम उत्पादन-क्षमता का प्रतिनिधित्व करने वाली स्वाभाविक दर (Gm) से अधिक होने की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होती है।¹ संक्षेप में, हैरोड की 'प्रमाणित' दर औद्योगीकरण-सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए पथदर्शक नहीं होकर चक्रीय-विरोधी एवं गतिरोध-विरोधी नीतियों को प्रकट करने के लिए विश्लेषण का अस्त्र है।

2 हैरोड की प्रमाणित दर, आवश्यक रूप से श्रम के पूर्ण रोजगार की प्रतिभूति (गारंटी) न प्रदान कर, पूँजी के पूर्ण उपयोग की प्रतिभूति प्रदान करती है। यदि वचत अनुपात एवं पूँजी-निपज-अनुपात स्वेच्छाचारितापूर्वक पूर्ण रोजगार सम्बन्धी आय से सम्बद्ध हो जाते हैं, तो भी जैसा कि पहले कहा जा चुका है,² प्रमाणित दर का तात्पर्य अपर्याप्त प्रभावोत्पादक माँग के परिणामस्वरूप केन्स की बेरोजगारी की समस्या से है। ठीक इसके विपरीत, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में जिस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, उसका निराकरण केवल प्रभावोत्पादक माँग में वृद्धि के द्वारा उस बिन्दु तक नहीं किया जा सकता है, जहाँ उपलब्ध पूँजी के पूर्ण उपयोग का औचित्य दीख पड़ता है। कोई भी दूसरा निष्कर्ष हैरोड के इस मौलिक विचार से कि 'केन्सीय रूप में यह (प्रमाणित दर) बढ़ती हुई अनैच्छिक बेरोजगारी की सम्भावना की सकल्पना करता है, से असंगत होगा।³ साथ ही, जैसा कि कुछ लेखकों ने प्रयास किया है,⁴ हैरोड (और डोमर के प्रतिरूप) की 'प्रमाणित' दर पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण क्षमता दोनों पर ध्यान रखने के लिए अलग उत्पादन-फलन (जिसमें श्रम

1. देखें, डापनमिक इकॉनामिक्स पृ० 91, साथ ही रजर्स यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 1955 में प्रकाशित (आर० ए० सोलो द्वारा संपादित) इकॉनामिक्स एण्ड दि पब्लिक इन्टरेस्ट में मेरा निवध ग्रोथ थियरी एण्ड दि प्रोब्लेम्स आफ इकॉनामिक स्टेबिलाइजेशन'।

2. हैरोड इस प्रकार की दर को 'विशिष्ट' प्रमाणित दर कहता है। (देखें, उनकी पूर्व उद्धृत पुस्तक 'एन एसे इन डॉयनमिक थियरी')।

3. डॉयनमिक इकॉनामिक्स, पृ० 87।

4. उदाहरण के लिए देखें, नवम्बर, 1953 ई० में क्वाटर्ली जरनल ऑफ इकॉनामिक्स में एच० फिलवीन का 'फुल केपेसिटी वर्सेज फुल इम्प्लायमेंट ग्रोथ'।

एवं पूँजी दोनों निवेश अंतर्निहित हों) की कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि, प्रमाणित दर के सहयोग से हैरोड की 'प्राकृतिक' दर ही इसे कर सकती है, यानी जब $Gw = Gn = G$ । यहाँ ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि Gw की दर से पूर्ण नियुक्त पूँजी की वृद्धि भी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की संरचनात्मक बेरोज़गारी को, जो बढ़ती हुई उत्पादकता के साथ जनसंख्या की वृद्धि से पूँजी-संग्रह के पीछे पड़ जाने की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होती है, दूर नहीं कर सकती। स्वतः-प्रेरित निवेश का वहिष्करण हैरोड की 'प्रमाणित' दर की धारणा को अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए विश्लेषणात्मक ढंग से अपर्याप्त बना देती है। हैरोड स्वतः-प्रेरित निवेश का वहिष्करण शायद वाञ्छरगत अर्थ-व्यवस्था के अस्थायित्व को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में आय के उच्चावचन पर आधृत लाभ की प्रत्याशा पर निवेश में मनमाने ढंग से विस्तार तथा संकुचन किया जाता है। इसीलिए, श्रीमती जान रॉबिन्सन ने स्वीकारात्मक ढंग से कहा है कि श्री हैरोड का मुख्य विषय यह है कि प्रमाणित दर को विशुद्ध अवैध-नीतिमय दशाओं में सामान्य रूप से नहीं प्राप्त किया जा सकता है।¹ दूसरी ओर जे० आर० हिक्स का यह विचार है कि 'प्रमाणित' दर से बढ़ती हुई अर्थ-व्यवस्था के लिए हैरोड के मॉडल में अत्यधिक अस्थायित्व है। अतएव, इनकी राय में स्थायित्व प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में स्वतःप्रेरित निवेश का प्रयोग आवश्यक है।²

3. जो भी हो, सम्बन्ध बात यह है कि हैरोड (और हिक्स भी) स्वतःप्रेरित निवेश को, वचत के केवल उस भाग को, जिसका केवल प्रेरित निवेश अवशोषण नहीं

1. देखें, इनकी दि रेट आफ इन्टरेस्ट, एटसेट्रा, पृष्ठ 160, n-1। यह चर्चा उन्होंने हैरोड के आशय के सम्बन्ध में टी०सी० शेलिंग के भ्रम के विरुद्ध हैरोड को वचाने के सिलसिले में की थी। (देखें दिसम्बर, 1947 के 'अमेरिकन इकानामिक रिव्यू' में शेलिंग का 'कैपिटल ग्रोथ एण्ड इक्यूलिब्रियम')। किन्तु हैरोड द्वारा अस्थायित्व की स्थिति, जो आवश्यक एवं पर्याप्त दोनों है, के स्पष्टीकरण से यह अंतिम भ्रम शायद दूर हो गया होता।
2. ट्रेड साइकिल, पृ० 60। यह देखना कठिन हो जाता है कि हिक्स की तरह के आत्म-समापन के सिद्धान्त पर आधृत स्वतः प्रेरित निवेश इतना समरूप कैसे हो सकता है कि स्थायित्व प्रदान करने वाले तत्व की तरह कार्य कर सकता है अथवा पूँजी के बड़े एवं वृद्धिशील स्टॉक के अस्थायित्व प्रदान करने के प्रभाव के कारण समरूप रह सकता है, जब तक कि हिक्स का स्वतःप्रेरित विविध स्टॉक से बाहर वाले प्रकार का भी प्रतिनिधित्व नहीं करता हो। हिक्स के व्यापार चक्र-सम्बन्धी विश्लेषण के इस अन्तिम अस्पष्ट विचार के सम्बन्ध में 1952-53 के खंड XX (1) संख्या 52 के 'रिव्यू आफ इकानामिक्स स्टडिज' में एच० रोज़ का निबंध 'डिमान्ड सप्लाय एंड प्राइस लेवल इन मैक्रो डायनमिक्स'।

करता हो, समतोलन करने के लिए माँग का एक साधन मानता है। स्वतः प्रेरित निवेश के सम्बन्ध में यह विचार हैरोड के सुधरे हुए निम्नांकित समीकरण में अंतर्भूत है : $GC = s \cdot k$, जिसमें G वास्तविक विकास की दर है, C भूल एवं सुधार पर आधृत पूँजी-निपज-अनुपात, s वास्तविक आय-स्तर एवं बचत का अनुपात तथा k आय के अंश के रूप में व्यक्त स्वतः प्रेरित निवेश है। हैरोड अपने प्रमाणित बचत निवेश समीकरण $GwCr = s$ में स्पष्ट परिवर्तों के रूप में स्वतः प्रेरित निवेश को अलग कर देता है, क्योंकि अंशतः वह त्वरक-सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से कार्य-क्षेत्र प्रदान करना चाहता है और अंशतः इसलिए कि वह केवल उसी प्रकार के स्वतः प्रेरित निवेश को ध्यान में रखता है, जो पूर्ति में वृद्धि किये बगैर ही माँग में वृद्धि करने हैं (उदाहरण के लिए शस्त्रीकरण)¹। उसके अनुसार दीर्घकाल में K अवश्य अदृश्य हो जायेगा क्योंकि दीर्घकाल में सम्पूर्ण पूँजीगत व्यय जिस कार्य में प्रयोग किया जाता है उसके लिए न्यायोचित ठहराया जाता है।²

4 हैरोड ने उस प्रकार के स्वतः प्रेरित निवेश को, जिसे केन्स अधिकाधिक आवश्यक समझते थे, स्वेच्छापूर्वक स्पष्ट कर दिया है। वह है मार्वाजिनिक निवेश, जो दीर्घकालिक विचारों को ध्यान में रखते हुए पूँजी की सीमात क्षमता को पता लगाने में राज्य की उत्कृष्ट क्षमता तथा सामान्य सामाजिक लाभों³ पर आधृत है। आज की अल्प-विकसित मिश्रित अर्थ-व्यवस्थाओं के विकास में इस प्रकार का निवेश बहुत अधिक ध्यावहारिक महत्त्व का है। वास्तव में, यह निश्चय ही कठिन ज्ञान पड़ता है कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ, जिनके पास निजी उपक्रम एवं निधि दोनों का अभाव रहता है, किस प्रकार दीर्घकालीन विचारों एवं सामान्य सामाजिक लोगों पर आधृत पर्याप्त सार्वजनिक निवेश, चाहें वह रूढ़ अर्थ में आराम-समापन वाला हो अथवा नहीं, के बगैर अपनी उत्पादन-क्षमता एवं साधनों को विकसित कर सकता है। साथ ही, इस प्रकार की कल्पना उचित ज्ञान पड़ती है कि विकास-जागहक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ अपने स्वतः प्रेरित निवेश, विशेषतः सार्वजनिक प्रकृति के निवेश का क्षमता-मूलक प्रकृति के दीर्घकालिक कार्यक्रम (जैसे राजपथ, बन्दरगाह, पुल, रेलवे, बाँध एवं प्राकृतिक साधनों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इनको उपयोग) में लगायेंगी। यद्यपि हैरोड के शस्त्रीकरण की तरह के स्वतः प्रेरित निवेश समाप्त हो सकते हैं, तथापि इस प्रकार के स्वतः प्रेरित निवेश दीर्घकाल में निश्चय ही समाप्त नहीं हो सकते। यदि स्वतः प्रेरित निवेश को आत्म-समापन एवं क्षमता-मूलक बनाया जा सके (अमेरिका की T. V. A. की तरह), तो कोई कारण नहीं कि

1. देखें डायनामिक इकॉनामिक्स पृ० 79, जिसमें वह युद्ध के सम्बन्ध में चर्चा करता है।
2. तर्जुम।
3. जनरल थियरी, पृ० 164।

इसे पूर्ण क्षमता निपज की वृद्धि की दर में, हम लोगों के Gk की तरह सम्मिलित नहीं किया जाय। इस प्रकार हैरोड का 'अपेक्षित पूँजी गुणक' (Cr) प्रेरित निवेश को केवल निपज से सम्बद्ध करता है, अतएव इसका अयोग्य स्टॉक उत्पन्न करने की प्रवृत्ति वाले स्वतःप्रेरित निवेश के साथ सम्बन्ध किसी भी उत्पादकता को स्पष्ट नहीं कर सकता। निम्न वचन-अनुपात (s), जो अति अनुकूल मान्यता पर भी पूँजीगत वस्तुओं की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है, वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि पूँजी-निपज अनुपात के (1/Cr) को निजी अथवा सार्वजनिक स्वतः प्रेरित उत्पादक निवेश को सम्मिलित कर ऊँचा रखा जाय।

डोमर की पूर्ण रोजगार-दर

अब हम डोमर के विकास-मॉडल पर विचार करेंगे। उसकी शुद्ध निवेश में वृद्धि की पूर्ण रोजगार-सम्बन्धी दर की धारणा के विस्तारीकरण द्वारा हम निम्नांकित प्रकार से प्रारम्भ करेंगे :—

$$Y^d = \frac{1}{\alpha}, \quad (1')$$

(प्रभावोत्पादक माँग का स्तर)

$$Y^s = \sigma K, \quad (2'')$$

(उत्पादक क्षमता का स्तर)

$$Y^d = Y^s \text{ अथवा } \frac{1}{\alpha} = \sigma K, \quad (3'')$$

(संतुलन की स्थिति)

$$\Delta Y^d = \frac{\Delta I}{\alpha} \quad (4'')$$

(माँग की वृद्धि)

$$\Delta Y^s = \sigma \Delta K = \sigma I, \quad (5'')$$

(क्षमता की वृद्धि)

$$\Delta Y^d = \Delta Y^s \text{ अथवा } \frac{\Delta I}{\alpha} = \sigma I, \quad (6'')$$

(संतुलन की स्थिति)

$$Y = \frac{\Delta I}{I} = \alpha \sigma \quad (7'')$$

(निवेश की वृद्धि दर)

जो इस बात की ओर संकेत किया करता है कि

$$\frac{\Delta Y^d}{Y^d} = \frac{\Delta I/\alpha}{Y^d} = \frac{\Delta I/\alpha}{1/\alpha} = \frac{\Delta I}{I} = \alpha \sigma \quad (8'')$$

(माँग की वृद्धि की दर)

यहाँ पर Y^* शुद्ध राष्ट्रीय आय का स्तरक अथवा पूर्ण रोजगार पर प्रभावोत्पादक माँग को दिखाता है, को Y^* उत्पादन-क्षमता का स्तर या पूर्ण रोजगार पर पूर्ति, I शुद्ध निवेश, K वास्तविक पूँजी, α बचाने की सीमात प्रवृत्ति और σ पूँजी अथवा शुद्ध निवेश की उत्पादकता है।

इस पद्धति से हमें यह ज्ञात होता है कि स्थायी α एवं स्थायी σ के दिया हुआ होने पर, यदि वृद्धि अर्थ-व्यवस्था में (4") द्वारा दिये गये माँग पक्ष एवं (5") द्वारा दिये गये पूर्ति पक्ष में इस प्रकार संतुलन स्थापित करना है कि (6") द्वारा वर्णित पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहे, तो शुद्ध निवेश में r (शुद्ध निवेश में वृद्धि की अपेक्षित दर) अथवा $\sigma\sigma$ की दर से वृद्धि करनी पड़ेगी। समीकरण (8") की तरह इससे यह भी संकेत मिलता है कि आय अथवा माँग में $\sigma\sigma$ की दर से अवश्य वृद्धि होनी चाहिए। संक्षेप में, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए अर्थ-व्यवस्था को समीकरण (3") द्वारा वर्णित शर्तों को अवश्य ही पूरा करना पड़ेगा। डोमर द्वारा जोर दिये गये "निवेश की दुहरी प्रकृति" को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। क्योंकि, केन्स के गुणक सिद्धान्त की तरह $\Delta I/I$ का भाज्य, समीकरण (4") के माध्यम से अतिरिक्त माँग का सृजन करता है, किन्तु डोमर की वृद्धिशील अर्थ-व्यवस्था के मॉडल की तरह इसका भाजक समीकरण (5") के माध्यम से अतिरिक्त क्षमता का सृजन करता है। समीकरण (1") में परिवर्त्ती केवल माँग के एक स्तर का सृजन कर सकता है जबकि समीकरण (5") में यही। परिवर्त्ती, उचित समय में पूँजी में वृद्धि (ΔK) का सृजन कर सकता है। यदि बढ़ती हुई पूँजी के स्टॉक वाली वृद्धि अर्थ-व्यवस्था लगातार पूर्ण-रोजगार को बनाये रखना चाहती है तो उसे वास्तविक पूँजी में इस वृद्धि (ΔK) के परिणामस्वरूप उत्पादन-क्षमता में वृद्धि (ΔY^*) को निवेश में वृद्धि (ΔI) के परिणामस्वरूप प्रभावोत्पादक माँग में समान वृद्धि (ΔY^d) के द्वारा बराबर करना होगा। अब हम लोग डोमर के मॉडल का मूल्यांकन विशेष रूप से अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के दृष्टिकोण से करेंगे।¹

1. डोमर ने जिस स्थिति पर विचार किया था, वह सारतः वही है, जिस पर हैरोड ने भी विचार किया था। उच्च बचत-अनुपात (α) एवं निवेश की उच्च उत्पादकता जो प्रायः शुद्ध रूप से हैरोड के पूँजी निपज अनुपात का अन्योन्य है, उस स्थिति की प्रमुख विशेषताएँ हैं। इस प्रकार यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें सिद्धांततः एक औसत रूप से प्रभावोत्पादक माँग में उत्पादन-क्षमता से कम-से-कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है यानी $Y^d < Y^*$ । स्थायी तौर पर $Y^d = Y^*$ के लिए, डोमर का

1. वैकल्पिक आलोचनाओं के लिए देखें आर० आइसनर का पूर्व उद्धृत, दिसम्बर, 1947 के अमेरिकन इकॉनामिक रिव्यू में 'कैपिटल इक्सपेंशन एंड इन्वोलुट्रियम', वार्ड० टाकता द्वारा संपादित स्टैटिज इन प्रोथ-इकॉनामी।

कहना है कि आय एवं क्षमता दोनों में एक समान दर से वृद्धि होनी चाहिए, यानी $\Delta Y^d = \Delta Y^s$ । सार रूप में यह वही विश्व है, जिसे केन्स ने 'प्रचुरता में निर्धनता' नामक विशेषता से विभूषित किया था। यह उस प्रकार का विश्व है जिस में प्रभावोत्पादक माँग की अपर्याप्तता का अनुभव होता है।¹ क्योंकि उच्च वचत-अनुपात अपर्याप्त माँग के चलते वास्तविक निर्धनता का सूचक है, जबकि निवेश की उच्च उत्पादकता पर्याप्त क्षमता के परिणामस्वरूप संभाव्य विपुलता का निर्देशक है। डोमर संस्थानिक एवं आनुभविक आधार पर उच्च α एवं उच्च σ की दृढ़ता को तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं और तब α एवं σ के प्रचलित मूल्यों के साथ शुद्ध निवेश की वृद्धि की दर ($\Delta I/I$) में तकनीकी अथवा राजकोपीय समायोजन का प्रस्ताव करते हैं। किन्तु अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में निम्न वचत अनुपात एवं निवेश की निम्न उत्पादकता की समस्या पाई जाती है, जिससे यह अवस्फीति के प्रवृत्ति के लिए खुली रहती है। ऐसी अर्थ-व्यवस्था के संभवतः अपने संस्थानिक एवं मनोवैज्ञानिक ग्रंथी को इस प्रकार से समायोजित करना पड़ता है, जिससे कि $\Delta I/I$ एवं $\sigma C\alpha = r/\sigma$, जिसमें $r = \Delta I/I$ के दिये हुये मूल्यों पर वचत-अनुपात में वृद्धि की जाय अथवा $\Delta I/I$ एवं α ($\sigma = r/\alpha$) के दिया हुआ रहने पर निवेश की उत्पादकता में वृद्धि के लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार किये जायें।

2. डोमर इस बात की संभावना पर विचार नहीं करते कि शुद्ध निवेश की वृद्धि की दर, जिसे ये पूर्ण रोजगार की एक आवश्यक शर्त मानते हैं, स्वयं दीर्घकाल में इस प्रकार के स्थायी प्रभावों को उत्पन्न कर सकती है, जिससे कि संतुलन की अपेक्षित स्थिति $y^d = y^s$ एवं $\Delta y^d = \Delta y^s$ दीर्घकाल तक नहीं बनाई रखी जा सकती है। एक उन्नत अर्थ-व्यवस्था में नवीन क्रिया के द्वारा निवेश-गुण्य (ΔI) को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास, जिसे डोमर अधिक अधिमान देते थे, शुद्ध निवेश की उत्पादकता (σ) को बढ़ा सकता है। किन्तु जब तक 'नवीन क्रिया-निवेश' मुख्यतः आय-उत्पादक प्रकृति का नहीं होता, तब तक साथ-ही-साथ क्षमता में वृद्धि किये वगैर यह आय में वृद्धि के अपेक्षित उद्देश्य को विफल बना देता है। इस प्रकार का आत्मघाती परिणाम एक जवरदस्त दीर्घकालीन संभावना है, क्योंकि नवीन क्रिया निवेश के नये अवसरों को प्रस्तुत करने और इस प्रकार नवीन क्रिया-संबंधी निवेश में वृद्धि (ΔI) के साथ-साथ, अतिरिक्त निपज को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक शुद्ध निवेश की रकम को घटा देता है। जहाँ तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है, उपर्युक्त आत्मघाती परिणाम ठीक उलटा हो जाता है; क्योंकि स्फीतिजनक माँग को कम करने के लिए नवीन क्रिया-निवेश में कमी के साथ-साथ निवेश की उत्पादकता में आत्मघाती कमी एवं इसीलिए उत्पादन-क्षमता में कमी हो सकती है।

1. जेनरल थियरी पृ० 30। किन्तु, डोमर का विश्व केन्स की तुलना में अधिक कष्टकारक है; क्योंकि पहली पूँजी के वृद्धिशील स्टाकवाली गतिशील व्यवस्था है।

इसके अधिक यदि नवीन क्रिया-निवेश में वृद्धि के प्रयत्नों के उपपरिणाम के रूप में निवेश की उत्पादकता बढ़ जाती है, तो समुदाय की मितव्ययिता सम्भवतः बढ़ जाएगी। इससे वचत-अनुपात में वृद्धि तथा आय में कमी होगी। यह भी एक प्रबल दीर्घकालीन सम्भावना है, क्योंकि निवेश की उत्पादकता एवं वचत अनुपात में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। अतएव, यह कोई आकस्मिक नहीं कि σ एवं σ' दोनों उन्नत अर्थ-व्यवस्थाओं में उच्च तथा अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में निम्न रहते हैं। अतएव, निवेश की उत्पादकता एवं वचत अनुपात (σ एवं σ') $\Delta I/I$ की दर से बढ़ते हुए शुद्ध निवेश की दीर्घकालीन गति से इस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं कि डोमर के समतुलन की स्थिति $Y^d = Y$ एवं $\Delta Y^d = \Delta Y$ डोमर द्वारा अपेक्षित कारणों से ही उलट सकते हैं।

3 अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से डोमर के मॉडल के विरुद्ध शायद सर्वाधिक गम्भीर आलोचना यह है कि उसकी निवेश की वृद्धि की अपेक्षा दर 'संरचनात्मक बेरोजगारी' की समस्या के समाधान में असफल रह जाती है। डोमर की 'अपेक्षित' वृद्धि की दर, केवल प्रभावोत्पादक माँग की अपर्याप्तता के कारण उत्पन्न 'केन्सीय बेरोजगारी' की समस्या या दूसरे शब्दों में, पूँजी के अपूर्ण प्रयोग का ही समाधान करती है, जबकि हैरोड 'अनैच्छिक बेरोजगारी' की मान्यता से प्रारम्भ करता है और तब $g_w = g_n$ शर्तों की पूर्ति के द्वारा पूर्ण रोजगार समतुलन को प्राप्त करने की सम्भावनाओं पर विचार करता है, डोमर पूर्ण रोजगार की स्थिति ($Y^d = Y$) की मान्यता से आरम्भ करता है और तब α की दर से आय एवं निवेश के विस्तार के द्वारा इस स्थिति को बनाये रखने की सम्भावना पर विचार करता है। हैरोड के g_w से अधिक डोमर का y दोनों पूर्ण क्षमता एवं पूर्ण रोजगार की प्रतिभूति (गारंटी) नहीं दे सकता है। क्योंकि, अधिकांश अल्प-विकसित देशों की तरह यदि श्रम-संख्या में पूँजी-संग्रह से अधिक वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो पूर्ण रोजगार के साथ प्रारम्भ करने वाली अर्थ-व्यवस्था को पूँजीगत उपकरणों के अभाव में आगे अथवा पीछे गैर-केन्सीय बेरोजगारी की अनुभूति होगी। ऐसा तभी होगा, जबकि यह नहीं मान लिया जाय कि उत्पादन के श्रम-गहन उपाय श्रम की उत्पादकता में किसी प्रकार की कमी लायें वगैर इसे टाल नहीं देते अथवा यह नहीं मान लिया जाय कि श्रम की प्रारम्भिक अधिकता वास्तविक भयदूरी की दर में इस प्रकार की कटौती करती है, जिससे कि पूँजी-संग्रह अत्यधिक लाभदायक हो जाय। यह एक खुला प्रश्न है कि क्या श्रम-गहन तकनीकों का प्रयोग, यद्यपि कि ये गैर-केन्सीयन बेरोजगार को कम करने में सहायक होते हैं, तथापि ये बड़े पैमाने की उत्पादन की मितव्ययिताओं के माध्यम से, जिसमें श्रम की तुलना में पूँजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, उत्पादकता में वृद्धि के दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक हो सकता है? यह भी एक खुला प्रश्न है कि क्या अधिक विकसित श्रम-सघ के अभाव में किसी भी अल्प-विकसित

अर्थ-व्यवस्था में श्रम वास्तविक मजदूरी की दर में संतुलनकारी कटौती को सहर्ष स्वीकार कर सकता है ? इस प्रकार शुद्ध-निवेश में α σ की दर में वृद्धि यद्यपि यह अनुपयुक्त क्षमता को उत्पन्न होने से रोकती है, बढ़ती हुई श्रम-संख्या को खपाने के लिए पर्याप्त मात्रा में तीव्र नहीं भी हो सकती है। अपने σ को जनसंख्या की वृद्धि एवं प्राविधिक प्रगति के अंतर्गत करने के बजाय, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की गैर-केन्सीयन बेरोजगारी तथा विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की केन्सीयन बेरोजगारी दोनों के विश्लेषण के लिए हैरोड की 'प्राकृतिक' दर की तरह डोमर को विकास की किसी अतिरिक्त दर को काम में लाना होगा। इस प्रकार, हैरोड के विकास की 'वारंटेड' दर की तरह डोमर के विकास की संतुलन दर पूँजी के पूर्ण नियोजन की प्रतिभूति (गारंटी) प्रदान करती है और जब तक श्रम-संख्या की वृद्धि की दर के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट मान्यता नहीं की जाती, तब तक यह आवश्यक रूप से श्रम के पूर्ण नियोजन की प्रतिभूति (गारंटी) नहीं प्रदान करता।

4. अंततः, तकनीक के सम्बन्ध में डोमर की अभिमति में बहुत-सी अपेक्षित बातों की कमी रह जाती है। समर्थ माँग की अपर्याप्तता के सम्बन्ध में चिन्तन-रत रहने के कारण, डोमर तकनीकी प्रगति को मुख्यतः निवेश के अवसर का स्रष्टा मानता है। जहाँ तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है, तकनीकी प्रगति की आकांक्षा, इस बात को ध्यान में रखे वगैर कि इससे समर्थ माँग में वृद्धि होती है अथवा नहीं, इसके उत्पादकता-प्रभाव (σ) के लिए की जाती है। इस सम्बन्ध में यह बतलाना अनिवार्य है कि केन्स, जैसा कि डोमर मान लेता है, पूँजी के उत्पादक गुणों पर अधिक जोर नहीं देता है। इसके लिए डोमर केन्स को ही उत्तरदायी ठहराता है।¹ अवकाश के स्रष्टा के रूप में तकनीकी प्रगति के लिये केन्स इतने अधिक उत्सुक थे कि वे इसके सहगामी 'तकनीकी बेरोजगारी' को 'कुसमंजन की अस्थायी स्थिति' समझकर ढाल देने के पक्ष में थे।² अवकाश के स्रष्टा के रूप में तकनीकी प्रगति के सम्बन्ध में केन्स की यह सुखद स्थिति, डोमर की तकनीकी से सम्बन्ध-निवेश की अत्यधिक ऊँची संभावित उत्पादकता (σ) के प्रति चेतावनी-सम्बन्धी स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। अतएव, जहाँ तक पूँजी के तकनीक की दृष्टि से सुधार-योग्य गुण (डोमर का उच्च σ) का सम्बन्ध है, केन्स द्वारा इस पर अधिक जोर देना उचित जान पड़ता है।

और न तो केन्स ने, जैसा कि डोमर मानते हैं, दीर्घकाल से पूँजी के बढ़ते हुए परिमाण के सम्बन्ध में कोई गंभीर चिन्ता ही व्यक्त की है। ठीक इसके विपरीत केन्स ने पूँजी के परिमाण [में उस हद तक वृद्धि संभव एवं वांछित बतलायी है, जहाँ पूँजी की 'सीमांत क्षमता शून्य हो जाती' है। अतएव, यहाँ पूँजीवाद का लगान

1. डोमर-पूर्व उद्धृत, पृ० 53।

2. केन्स का पूर्व उद्धृत 'इकोनामिक पोसिविलिटिज फॉर आवर ग्राउंड चिल्ड्रेन'।

उपजीवी पक्ष समाप्त हो जाता है।¹ पूँजी की घटती हुई सीमात-क्षमता के लिए केन्स की गम्भीर चिन्ता, जिसकी चर्चा डोमर ने की है, केवल आंतरिक परिस्थितियों में ही होती है, जहाँ पूँजी के सचय को अवध-नीति पर छोड़ दिया जाता है और जहाँ द्रव्य एवं ऋण पर दिये गये व्याज की दर, संस्थानिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से, पूँजी की घटती हुई सीमात क्षमता से सुगमतापूर्वक समायोजित करने के लिए घटने में असमर्थ सिद्ध होती है। अतएव, एक उचित तरीके से संचालित समाज की तरह, यदि पूँजी की मात्रा एवं व्याज की दर पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाय, तो पूँजी-सचय के बजाय तकनीक, अभिरूचि, जनसंख्या एवं संस्थाओं² में परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रगति की आशा करना केन्स सम्भव समझता था। किन्तु स्पष्ट है कि इस बात को बिना जाने डोमर केन्स के निष्कर्ष से करीब-करीब सहमत हो जाता है, जबकि वह तकनीकी प्रगति की अभिवृद्धि (० में वृद्धि) की वाछनीयता को इस शर्त पर प्रजापित करता है कि वैयक्तिक तवीन क्रिया-निवेश जिस अतिरिक्त बचत का प्रयोग नहीं कर सकता, उसका उपयोग अन्य तरीके से (जैसे सरकार के द्वारा) किया जाता है।

राबिन्सन के मॉडल पर टिप्पणी

जॉन राबिन्सन के पूँजी-सचय के सिद्धान्त³ का सार उनके इस केन्द्रीय प्रस्ताव में निहित है: 'यदि उद्यमकर्ताओं को लाभ नहीं होता, तो वे पूँजी-संग्रह नहीं कर सकते और यदि वे पूँजी-संग्रह नहीं करते, तो उन्हें लाभ नहीं होता।'⁴ आर्थिक विकास की मौलिक प्रकृति का विश्लेषण वह पूँजीवादी नियमों के अनुसार करना चाहती हैं। इस उद्देश्य से वे केवल पूँजी एवं धन को उत्पादन का साधन मानते हुए एवं सम्पूर्ण उत्पत्ति को उद्यमकर्ताओं एवं श्रमिकों के बीच वितरण करते हुए एक संवृत अबंध अर्थ-व्यवस्था के शाब्दिक मॉडल का निर्माण करती हैं। पहले हम लोग जे० राबिन्सन के आधारभूत मॉडल का विवेचन करेंगे और तब हैरोड-डोमर मॉडल के साथ इसके सम्बन्ध एवं केन्सीय विकास-सम्बन्धी अर्थशास्त्र में इसके स्थान को, विशेष रूप से अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से, स्पष्ट करेंगे।

आगे-आगे आने वाले विश्लेषण को सहज बनाने के लिए, उचित मान्यताओं के आधार पर राबिन्सन के संग्रह के सिद्धान्त को निर्दिष्ट आकार देना लाभदायक

1. 'जेनरल थियरी' पृ० 221, पृ० 376।

2. पूर्व उद्धृत पृ० 220-1।

3. देखें, इनकी पुस्तक 'दि एकुमुलेशन ऑफ कॅपिटल', इरविन, होम उड, 1956 (विशेषतः द्वितीय खंड, भाग I एवं II)।

4. पूर्व उद्धृत, पृ० 76।

जान पड़ता है। उसके मूल मॉडल में निम्नांकित सरल मान्यताएं अंतर्निहित हैं : (क) श्रमिक मजदूरी के रूप में प्राप्त अपनी सम्पूर्ण आय को उपभोग पर व्यय करते हैं, जबकि लाभ प्राप्त करने वाले लाभ से प्राप्त अपनी सम्पूर्ण आय को वचाते एवं विनियोग करते हैं और (ख) एक दी हुई निपज को उत्पन्न करने में पूँजी एवं श्रम एक निश्चित अनुपात में लगाये गये हैं। आगे चलकर वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, वे अपनी दूसरी मान्यता को कुछ शिथिल कर देती हैं। उनका सम्पूर्ण विवेचन घटनोत्तर रूप में संचालित होता है, किन्तु हम लोग इसकी व्याख्या आर्थिक सिद्धान्त के घटना-पूर्व रूप में भी कर सकते हैं।

वितरण-समीकरण जो जे० राविन्सन के विकास-सिद्धांत का केन्द्रीय-बिन्दु है, जो निम्नांकित प्रकार से दिखलाया जा सकता है :

$$pY = wN + \pi K, \quad (1'')$$

जिसमें Y शुद्ध राष्ट्रीय निपज, N रोजगार-प्राप्त श्रम का परिमाण, K उपर्युक्त पूँजी-गत उपकरणों का परिमाण, p निपज एवं पूँजीगत उपकरणों का औसत मूल्य, w मजदूरी की मौद्रिक दर और π वास्तविक पूँजी के वर्तमान स्टॉक के सामान्य प्रयोग के लिए आवश्यक कुल लाभ की दर (सूद की दर को सम्मिलित करते हुए) हैं। समीकरण (1'') के दोनों पक्षों को औसत मूल्य-सूचकांक p से विभाजित करने पर हमें वास्तविक अर्थ में निम्नलिखित वितरण समीकरण प्राप्त होता है :

$$Y = \frac{w}{p} N + \pi K, \quad (2''')$$

जिससे हम लोग लाभ की दर π प्राप्त कर सकते हैं। $Y/N = P$ एवं $K/N = \theta$ रखते हुए लाभ की दर को बताने के लिए समीकरण (2''') का निम्नांकित रूप में पुनर्विन्यास किया जा सकता है :

$$\pi = \frac{Y - \frac{w}{p} N}{K} = \frac{\frac{Y}{N} - \frac{w}{p}}{\frac{K}{N}} = \frac{P - \frac{w}{p}}{\theta} \quad (3''')$$

जिससे यह स्पष्ट होता है कि लाभ की दर श्रम की उत्पादकता (P), वास्तविक मजदूरी की दर (w/p) एवं पूँजी-श्रम अनुपात (θ) तकनीकी सम्बन्ध पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में, लाभ की दर को पूँजी के शुद्ध प्रतिफल की दर ($P - w/p$) के साथ प्रत्यक्ष रीति से तथा पूँजी की तीव्रता के गुणक (θ) के साथ प्रतिलोमतः परिवर्तित होने के योग्य है।

यह मान लिया जाता है कि उद्यमकर्त्ता लाभ को अधिकतम बनाने की निम्नांकित दशा की पूर्ति करते हैं :

$$d \left(\frac{P - \frac{w}{p}}{0} \right) \frac{1}{0} = 0 \quad (4'')$$

उत्पादन फलन के रहने पर :

$$Y = F(N, K), \quad \lambda_v \quad (5'')$$

जिस K/N को स्थिर मान लिया जाता है (थोड़े समय के लिए) और जहाँ Y को K एवं N से सम्बन्धित सजातीयता का सम्बन्ध मान लिया जाता है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल के रूप में आगे चलकर हम लोग इस उत्पादन फलन की परिवर्तनीयता पर विचार करेंगे। समीकरण (5'') वितरण-समीकरण (1'') का उत्पादन-प्रतिरूप है। व्ययपक्ष की ओर से, सतुलन की स्थिति में, शुद्ध वास्तविक राष्ट्रीय आय, वास्तविक उपभोग व्यय (C) एवं शुद्ध वास्तविक निवेश (I) के बराबर अवश्य होगा :

$$Y = C + I; S = I, \quad 1 < g \quad (6'')$$

जो वास्तव में केन्सी का प्रचलित आय-व्यय अथवा वृद्धि-निवेश-समीकरण है। यहाँ उपभोग (C) एवं वृद्धि (S) राष्ट्रीय आय से लिये गये हैं, अतएव इन्हें रॉबिन्सन की मान्यताओं से संगत रूप में इस प्रकार में परिवर्तित करना आवश्यक है :

$$C = C_n = \frac{w}{p} N, \quad (7'')$$

एवं

$$S = S_k = \pi K, \quad (8'')$$

यहाँ C_n मजदूरी के रूप में प्राप्त आय में से उपभोग व्यय है और S_k लाभ के रूप में प्राप्त आय में से वृद्धि है। जहाँ तक शुद्ध निवेश का सम्बन्ध है इसे केवल वास्तविक पूँजी में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है :

$$I = \Delta K \quad (9'')$$

समीकरण (8'') एवं (9'') को ध्यान में रखते हुए हम लोग समीकरण (6'') के द्वारा व्यक्त निवेश-सम्बन्ध निम्नांकित प्रकार से पुनः लिख सकते हैं :

$$\Delta K = \pi K, \quad (10'')$$

जिसमें तथा समीकरण (3'') को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को पूँजी में वृद्धि की निम्नलिखित दर प्राप्त होती है

$$\frac{\Delta K}{K} = \frac{\pi K}{K} = \pi = \frac{P - \frac{w}{p}}{p} \quad (11'')$$

समीकरण (11'') द्वारा दी गयी पूँजी में वृद्धि की दर वह दर है, जिसे जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उद्यमकर्ता पूँजीवादी खेल के नियमों का अनुकरण कर प्राप्त

करते हैं। समीकरण (11'') यह बतलाता है यदि पूँजी का शुद्ध प्रतिफल ($P-w/p$) श्रम-निपज अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ता है, तो पूँजी में वृद्धि की दर वृद्धि-क्षम्य होगी। रिकार्डों के शब्दों में, इसका तात्पर्य यह है कि जब तकनीकी स्थिति पूर्ववत् रहती है (हम लोगों के उदाहरण में P एवं θ स्थिर रहते हैं) तो वास्तविक मजदूरी की दर ह्रास से पूँजी का संचय प्रबल तथा वास्तविक मजदूरी की दर में वृद्धि से कमजोर होता है। अतः, ऐसा जान पड़ता है कि जॉन राविन्सन ने हम लोगों को केन्स के माध्यम से, पुनः डेविड रिकार्डों के आर्थिक-विकास के सिद्धान्त पर वापस ला दिया है। इस सम्बन्ध में आगे हम कुछ कहेंगे।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि राविन्सनीयन विचारधारा में पूँजी में वृद्धि की दर उन बातों पर निर्भर करती है, जो लाभ की दर (π) का निर्धारण करती है। यहाँ 'अन्य बातों' से शायद वास्तविक मजदूरी की दर (w/p) श्रम की उत्पादकता (P) तथा पूँजी-श्रम अनुपात (θ) के तकनीकी सम्बन्ध का बोध होता है।

अब जॉन राविन्सन के श्रम के पूर्ण रोजगार एवं पूँजी के पूर्ण उपयोग के स्वर्णयुगीय संतुलन की धारणा पर विचार किया जाए। इस संतुलन के लिए आवश्यक एक आधारभूत शर्त को इस प्रकार से देख सकते हैं। पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण प्रयोग की स्थिति में $K/N = \theta$ को स्थायी मानते हुए पूर्ण नियुक्त श्रम की मात्रा में वृद्धि $\Delta N = \Delta K/\theta$ के द्वारा दी जा सकती है। इस अति सम्बन्ध से हमें पूर्ण नियुक्त श्रम में वृद्धि की दर प्राप्त होती है :

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{\Delta K/\theta}{N} = \frac{\Delta K/\theta}{K/\theta} = \frac{\Delta K}{K}, \quad (12'')$$

जिससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्ण नियुक्त श्रम में पूँजी में वृद्धि की दर के समान ही वृद्धि होती है। साथ ही, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जब पूँजी-श्रम-अनुपात (θ) स्थायी रहता है, तब पूँजी में भी इतनी तेजी से वृद्धि होनी चाहिए, जितनी तेजी से श्रम की संख्या में वृद्धि होती है। निपज के सम्बन्ध में श्रम की पूर्ति के पूर्ण-तथा लोचदार होने पर, समीकरण (12'') पूँजी एवं श्रम दोनों की पूर्ण नियुक्ति के स्वर्णयुगीय संतुलन को स्पष्ट करता है।

तब जॉन राविन्सन यह प्रश्न उठाती हैं कि यदि किसी कारणवश अर्थ-व्यवस्था इस स्वर्णयुगीय संतुलन से विचलित हो जाय, तो इसे ठीक करने के लिए क्या इसके पास कोई संतुलनकारी यंत्र उपलब्ध है? मान लिया कि अर्थ-व्यवस्था ने विपम मार्ग ग्रहण कर लिया है तथा इसका विपमता निम्नांकित प्रकार से स्पष्ट होती है :

$$\frac{\Delta K}{N} > \frac{\Delta N}{K},$$

यानी अधिकांश अल्पविकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की तरह श्रम संख्या पूँजी-संचय से अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में अर्थ-व्यवस्था पुनः स्वर्ण-युगीय सतुलन की स्थिति में आ सकती है अथवा नहीं, यह जॉन रॉबिन्सन के अनुसार लाभ-मजदूरी सम्बन्ध के आचरण पर निर्भर करता है। उपर्युक्त विपमता में अतिरिक्त, प्रगतिशील पूर्ण रोजगारी सन्निहित श्रम के आधिक्य द्वारा सतुलनकारी यंत्र के निर्माण से दूर हो जा सकती है। किन्तु, यह एक बहुत बड़ी 'यदि' है; क्योंकि लाभ-मजदूरी-सम्बन्ध सतुलनकारी तरीके का आचरण रख सकता है अथवा नहीं भी। वास्तव में, यह बाजार की परिस्थितियों (प्रगतियोगात्मक एवं एकाधिकारी), मजदूरी के जीवन-निर्वाह दर की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, एवं स्वतन्त्र तकनीकी संभावनाओं पर निर्भर करता है। तकनीक की दो हुई स्थिति में, श्रम के उपर्युक्त आधिक्य से शीघ्र अथवा बाद में नकद मजदूरी की दर (w) में कमी होती है। यदि सामान्य मूल्य (p) स्थायी रहे, जैसा कि एकाधिकार-प्रधान अर्थ-व्यवस्था में होता है, तो नकद मजदूरी की दर में इस कमी से वास्तविक मजदूरी की दर (w/p) में भी कमी होगी। इस प्रकार यदि वास्तविक मजदूरी की दर घट जाय, तो जैसा कि समीकरण तब (11'') से स्पष्ट है, पूँजी की वृद्धि की दर में लाभ की दर पर वास्तविक मजदूरी में कमी के बढ़ते हुए प्रभाव के माध्यम से वृद्धि हो सकती है। सम्भव है कि पूँजी में वृद्धि की दर बढ़ कर श्रम संख्या में वृद्धि की स्थायी दर के बराबर हो जाय, जिससे कि $\Delta K/K = \Delta N/N$ हो जाय। दूसरी ओर, मजदूरी के जीवन-निर्वाह स्तर के अंतराक्षेप अथवा सामान्य मूल्य में नकद मजदूरी के अनुपात में ही कमी के कारण वास्तविक मजदूरी की दर में ह्रास हो जाय (जैसा कि दीर्घकाल में प्रतियोगात्मक बाजार में होता है) तो सन्निहित श्रम का आधिक्य सतुलनकारी यंत्र का निर्माण नहीं कर सकता तथा प्रगतिशील अपूर्ण रोजगारी दूर नहीं हो सकती। यह अंतिम सम्भावना हैरोड की अनिश्चित स्थिरता की धारणा से मिलती-जुलती है। हैरोड की यह धारणा तकनीकी गुणांकों की स्थिरता एवं साधनों की सापेक्ष मूल्य-गतियों की मान्यता पर आधृत है।

इसका ठीक विलोम पूँजी-संचय के श्रम-संख्या से अधिक तेजी के साथ बढ़ने की स्थिति, जैसा कि अधिकांश विकसित देशों में सत्य होता है। फिर भी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की तुलना में विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के स्वर्णयुगीय सतुलन के पथ पर लौटने की सम्भावना अधिक है। इसके कारण जे० शुम्पीटर के आर्थिक विकास के सिद्धान्त के पाठकों (जॉन रॉबिन्सन को सम्मिलित करते हुए) के लिए बिल्कुल स्पष्ट हैं। क्योंकि, यद्यपि वास्तविक मजदूरी की दर अनम्य थी, फिर भी श्रम की उत्पादकता (p) अथवा पूँजी श्रम अनुपात (0) में परिवर्तन इस प्रकार हो सकता है, जिससे लाभ की दर में वृद्धि हो और जिसके परिणामस्वरूप $\Delta K/K$ में वृद्धि की दर में भी सतुलनकारी तरीके से वृद्धि (अथवा कमी) हो। समी-

करण (11''') से यह स्पष्ट है। यहीं जॉन रॉबिन्सन अपने आधारभूत मॉडल से भी आगे चली जाती हैं, तथा रिकार्डों की अपेक्षा शुम्पीटर से अधिक समीप हो जाती हैं। यहीं हमें समीकरण (5''') द्वारा अभिव्यक्त उत्पादन-फलन पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। यदि श्रम की उत्पादकता ($Y/N=p$) में उसी पूँजी-श्रम-अनुपात ($K/N=0$) के लिए वृद्धि हो जाय अथवा यदि पहले के उसी मूल्य के लिए वाद के अनुपात में कमी हो जाय, तो सम्पूर्ण उत्पादन-फलन ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। तकनीकी गुणांकों में उन परिवर्तनों को बाजारगत परिस्थितियों से स्वतंत्र समझना शुम्पीटर की भावना के अनुरूप है। इसी भावना से जॉन रॉबिन्सन भी तकनीकी परिवर्तनों पर विचार करती हैं। समीकरण (11''') यह बतलाता है कि किसी स्थायी पूँजी-श्रम अनुपात ($0=0$) के लिए यदि श्रम की उत्पादकता (P) में वास्तविक मजदूरी की दर की अपेक्षा अधिक तेजी में वृद्धि होती है, तो पूँजी की वृद्धि की दर में भी वृद्धि होगी। साथ ही, यदि पूँजी-श्रम अनुपात (0) में W/p एवं p , में सहगामी परिवर्तनों के बगैर कमी हो जाय तो भी पूँजी में वृद्धि की दर में और अधिक वृद्धि हो सकती है। पूँजी की गहनता के गुणांक में कमी के साथ-साथ दी हुई वास्तविक मजदूरी की दर की तुलना में श्रम की उत्पादकता में अधिक कमी होने पर कठिनाई उपस्थित हो सकती है। इसका संभावित परिणाम यह होगा कि पूँजी में वृद्धि की दर में वृद्धि के बजाय कमी होगी, उत्पादन की कम पूँजी वाली अथवा चक्रदार तरीके का प्रतिनिधित्व करती है, जो अन्यथा श्रम की उत्पादकता तथा वास्तविक मजदूरी में वृद्धि कर सकती है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि समान अनुपात ही इस प्रकार देखने से, समीकरण (11''') के सम्बन्ध में वर्णित 'रिकार्डों का प्रभाव', परिवर्त्ती टेक्नोलॉजिकल प्राचलों से युक्त अधिक सामान्य स्थिति की एक विशिष्ट स्थिति है।

हैरोड तथा डोमर के साथ जॉन रॉबिन्सन के मॉडल को निम्नांकित प्रकार से देखा जा सकता है : समीकरण (2''') को ध्यान में रखकर तथा पुनर्व्यवस्थित करते हुए, समीकरण (3''') को पुनः इस प्रकार से लिखा जा सकता है :

$$n = \frac{Y - \frac{w}{p}N}{K} = \frac{Y}{K} \left(\frac{Y - \frac{w}{p}N}{Y} \right), \quad (13''')$$

जो यह बतलाता है कि लाभ की दर के पूँजी की उत्पादकता ($\gamma/K=\sigma$) के अनुपातिक होने के लिए राष्ट्रीय आय $[Y - (W/p)N]/Y$ में लाभ के हिस्से के गुणा होता है। चूँकि $S = \pi K$ और $[Y - (w/p)N]/Y = \pi K/Y = S/Y = S$ और चूँकि $b = I/c$, अतएव

$$\frac{\Delta K}{K} = \pi = cS, I/c \text{ (डोमर) अथवा } = \frac{s}{b} \text{ (हैरोड)} \quad (14''')$$

इस प्रकार जॉन रॉबिन्सन का मॉडल सारतः हैरोड तथा डोमर के मॉडलों के ही समान है। फिर भी, इनमें महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि जॉन रॉबिन्सन पूँजी-संचय को स्पष्टतः लाभ-मजदूरी सम्बन्ध (π एवं w/p) तथा श्रम की उत्पादकता (p) पर आधारित मानती है। इस तरह, ये अपने सिद्धान्त को वास्तविक बाजारगत अर्थ-व्यवस्था के बिल्कुल समीप ला देती है। इसके विपरीत, मुख्यतः केन्स के तरीके से, हैरोड तथा डोमर पूँजी-संचय को वचत-अनुपात (अथवा इसके व्युत्क्रम) पर आधारित मानते हैं जो पूँजीवाद अथवा समाजवादी सभी अर्थ-व्यवस्थाओं में लागू होता है। साथ ही, यह महत्वहीन नहीं है कि जॉन रॉबिन्सन पूँजी संचय के प्रश्न पर मुख्यतः श्रम के दृष्टिकोण से तथा हैरोड एवं डोमर पूँजी के दृष्टिकोण से विचार करते हैं। इस प्रकार अब जॉन रॉबिन्सन 'पूँजीवाद खेल के नियमों' के द्वारा पूँजी-संचय की चर्चा करती है, तो उनके कथन का यही तात्पर्य जान पड़ता है कि पूँजी के मूल्य (प्रायः शुद्ध रूप से आय की दर) एवं श्रम की उत्पादकता की तुलना में श्रम के मूल्य में (वास्तविक मजदूरी की दर) में कमी के बगैर व्यक्तिवादी, पूँजीवाद सार-भूत रूप में विकसित नहीं कर सकता। यह उसके कहने का तरीका हो सकता है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को विशुद्ध रूप में पूँजीवादी खेल के नियमों का अनुकरण करना उचित नहीं होगा। इनके लिए स्वतंत्र निवेश (जिम्में शुम्पीटर की तरह के नवीन क्रियात्मक निवेश भी शामिल होंगे) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय एवं मौद्रिक नीतियों से युक्त केन्स की मिश्रित राजकीय एवं निजी अर्थ-व्यवस्था के तकनीक को अपनाना अधिक उचित होगा।

केन्सोत्तर विकास अर्थशास्त्र में जॉन रॉबिन्सन की प्रधान देन यह जान पड़ती है कि उन्होंने सस्थापक मूल्य एवं वितरण सिद्धान्त तथा केन्स के आधुनिक वचत एवं निवेश-सिद्धान्त को एक सलग्न प्रणाली में समाकलित कर दिया है। किन्तु, जहाँ तक नीति के प्रयोग का सम्बन्ध है, यह उनका प्रधान दोष भी जान पड़ता है। क्योंकि, हैरोड एवं डोमर के मॉडलों की भाँति वित्तीय एवं मौद्रिक नीति प्राचलो को प्रस्तुत करने के लिए जॉन रॉबिन्सन का मॉडल तब तक सुधार के योग्य नहीं है, जब तक कि श्रम की उत्पादकता, मजदूरी की दर, लाभ की दर तथा पूँजी-श्रम अनुपात को पूर्णतया आयोजित अर्थ-व्यवस्था की तरह व्यावहारिक नीति का उद्देश्य नहीं समझा जाय। साधनों के सापेक्ष मूल्य के प्राचलीय कार्य के द्वारा आय के पुनर्वितरण (लाभ एवं मजदूरी के बीच) को लाने तथा इस प्रकार पूँजी-संचय को जनसंख्या की वृद्धि से ममायोजित होने देने के बजाय, कोई भी व्यक्ति वित्तीय नीतियों के द्वारा आय के पुनर्वितरण अथवा जनसंख्या में वृद्धि को पूँजी में दी हुई वृद्धि के साथ ममायोजित करना अधिक पसन्द कर सकता है। फिर भी, जॉन रॉबिन्सन का सिद्धान्त विशुद्ध पूँजीवादी खेल के नियमों के अनुसार पूँजी-संचय की मौलिक प्रवृत्ति के सम्बन्ध में

हमारी जानकारी को और तीव्र बनाता है। अंततोगत्वा, जॉन रॉबिन्सन के संतुलन-कारी यंत्र के गुणकारी होने अथवा नहीं होने की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि इनका विकास-सम्बन्धी मॉडल, यद्यपि स्थायी संतुलन का साधन प्रस्तुत करने योग्य है, तथापि इस सारभूत रूप में, हैरोड एवं डोमर की अवैध नीति वाली अर्थ-व्यवस्था के मॉडलों की तरह ही अस्थायित्व है।

अध्याय ७

आर्थिक विकास में टेक्नोलॉजिकल भूमिका

आर्थिक प्रगति के लिए पूंजी-संचय के ठीक बाद टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रगति कारणात्मक महत्त्व की है। आदमस्मिथ ने राष्ट्रों की सम्पत्ति में अभिवृद्धि के आधार के रूप में विशेषज्ञता पर जोर दिया था। मार्क्स ने टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रगति को पूंजीवादी विकास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना था। बाम बर्क (Bohm-Bawerk) ने उत्पादन के चक्रदार तरीकों को औद्योगीकरण के समरूप बतलाया था। शुम्पीटर ने ऐतिहासिक विकास की सम्पूर्ण प्रतिक्रिया की व्याख्या 'नवीन क्रिया' के रूप में की थी। केन्स ने भविष्य में एक ऐसी अर्द्ध-स्थायी स्थिति की भविष्यवाणी की थी, जिसमें परिवर्तन तथा प्रगति केवल तकनीक, रुचि, जनसंख्या एवं संस्थाओं में परिवर्तन के ही परिणामस्वरूप होंगे। इन सभी अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक एवं सामाजिक विकास में टेक्नोलॉजी-संबन्धी प्रगति के कारणात्मक महत्त्व पर अतर्दृष्टि की विभिन्न मात्रा के साथ जोर दिया था। हैरोड और डोमर से प्रारम्भ करने पर हम देखते हैं कि आर्थिक विकास में महत्त्व का सांकेतिक स्थानान्तरण टेक्नोलॉजिकल भूमिका के अधिक व्यावहारिक उपचार की ओर हो गया है। फिर भी, ये लोग टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी स्थायी प्रचालन, जो विभिन्न समय एवं स्थानों के विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने के लिये विश्लेषणात्मक दृष्टि से असुविधाजनक होते हैं, को आधार मानकर, 'तटस्थ टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी अग्रवर्तिता' की अभिधारणा करते हैं। जॉन रॉबिन्सन ने अपने उत्तेजक, 'नोट्स ऑफ दि इकनामिक्स ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस' में विकास-विश्लेषण के टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी अधिक लचीले प्राचलन को बतलाया है; क्योंकि विभिन्न अनुपातों को रखने के आशय पर भी विचार करना अधिक शिक्षाप्रद होगा।¹ तथापि ये तथा आर्थिक विकास के अन्य लेखकगण मुख्यतः टेक्नोलॉजी के माँग-पक्ष के साथ अभिरुचि रखते हैं और उसकी उत्पादकता-पक्ष के साथ

इनका सम्बन्ध-मात्र प्रसंगवश रहता है।¹ ऐसा इसलिए है कि ये टेक्नोलॉजी की दृष्टि से पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्थाओं की विकास-सम्बन्धी समस्याओं से सम्बद्ध न होकर विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की स्थायित्व की समस्या में पहले से व्यक्त हैं।

वर्तमान अध्याय का उद्देश्य अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं पर गैर-तटस्थ टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रभावों का विश्लेषण तथा साथ ही, अंतर्गत टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी नम्य प्राचलों पर इसके विभिन्न प्रभावों को स्पष्ट करना है।

श्रम की उत्पादकता पर टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रभाव

सर्वप्रथम शुद्ध राष्ट्रीय निपज पर श्रम वचाने एवं श्रम प्रयोग करने के तकनीक के प्रभावों का विश्लेषण किया जाएगा। इन्हें अपनाये जाने के विशेष कारणों पर बाद में विचार किया जायगा। इसके लिए हम गैर-श्रम उत्पादक साधनों, मजदूरी दर-सहित साधनों के सापेक्ष मूल्य एवं जनसंख्या की वृद्धि तथा समर्थ माँग की दशाओं को दिया हुआ मान लेंगे। इन मान्यताओं के आधार पर निपज को श्रम की मात्रा एवं उत्पादकता का एक अद्वितीय कार्य (फंक्शन) माना जा सकता है। इनमें से श्रम की उत्पादकता टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी परिवर्तनों को परिलक्षित करती है।

मूल सम्बन्ध

उपर्युक्त मान्यताओं के आधार पर, निपज में निम्नलिखित के बराबर वृद्धि होगी :

$$\Delta Y = p \Delta N \quad (1)$$

जिसमें Y पूर्णरोजगार से निस्सरित संभाव्य निपज है, N पूर्ण रोजगार की स्थिति में श्रम की मात्रा तथा p टेक्नोलॉजी की प्रचलित स्थिति के द्वारा निर्धारित श्रम की औसत एवं सीमांत उत्पादकता है। यह वही श्रम की उत्पादकता है, जिसे दिखलाया जाएगा कि यह श्रम वचाने तथा श्रम के प्रयोग करने सम्बन्धी तकनीकों की अनुक्रिया अनुरूप कालान्तर में बदलती रहती है। यहां केवल इतना ही कहना

1. माँग-सम्बन्धी पहलू से पूर्वग्राह्यता के आदर्श उदाहरण के लिए देखें—जे० ड्युसेनबरी (J. Duesenberry) का मई, 1956 ई० में “अमेरिकन इकॉनामिक रिव्यू” में “इनोवेशन एंड ग्रोथ”। इस प्रकार की पूर्व-ग्राह्यता की आलोचना के लिए एच० आर० वोवेन का दिसम्बर, 1954 के “अमेरिकन इकॉनामिक रिव्यू” में प्रकाशित “टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड एग्रीगेट डिमांड” देखें। दूसरी ओर, जापानी अर्थशास्त्रियों की टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी व्याख्या, जैसे वार्ड० ताकटा द्वारा संपादित “स्टडीज़ इन ग्रोथ इकॉनामिक्स” में अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए बहुत सी शिक्षाप्रद बातें मिलती हैं।

पर्याप्त है कि, नियमित तथा औसत रूप में, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से विकसित अर्थ-व्यवस्था में p उच्च तथा टेक्नोलॉजी की दृष्टि से पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था में p निम्न होती है।

अब पूर्ण नियुक्त श्रम-संख्या में वृद्धि एवं पूर्ण रोजगार-निपज के अनुपात को v के समरूप करने पर निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त होता है :

$$\frac{\Delta N}{Y} = v \quad (2)$$

समीकरण (2) में दिया गया अनुपात जनसंख्या की वृद्धि को बतलाता है तथा जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही इसकी गति में भी परिवर्तन होता है। यह प्रकल्पना की जा सकती है कि जनाधिक्य वाली अर्थ-व्यवस्था में v बड़ा तथा कम आबादी वाली अर्थ-व्यवस्था में v छोटा होता है।

(1) और (2) से हमें पूर्णरोजगार-निपज में वृद्धि की निम्नलिखित दर प्राप्त होती है :

$$\frac{\Delta Y}{Y} = pv, \quad (3)$$

जो यह स्पष्ट करता है कि पूर्ण रोजगार निपज में pv की दर से वृद्धि होती है। और pv की दर टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रगति और जनसंख्या की वृद्धि पर निर्भर करती है।

चूँकि, श्रम की उत्पादकता श्रम-निपज अनुपात का उलटा भी है, $p=1/a$ (जहाँ $a=N/Y=\Delta N/\Delta Y$), हम लोग पूर्ण-रोजगार में वृद्धि की दर को वैकल्पिक रूप में निम्नलिखित प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं :—

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{1}{a} \cdot v = \frac{v}{a}, \quad (4)$$

जो अब यह दिखलाता है कि जब अतिरिक्त श्रम-संख्या एवं पूर्ण रोजगार-निपज का अनुपात अपरिवर्तित रहता है, तो पूर्ण रोजगार-निपज की वृद्धि की दर में श्रम-निपज अनुपात (a) में परिवर्तन के ठीक विपरीत परिवर्तन होता है।

टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी परिवर्तनों के प्रभावों को पृथक् करने के लिए हम लोग यह मान लेते हैं कि पूर्ण नियुक्त श्रम की संख्या एवं निपज का अनुपात कालान्तर में स्थायी रहता है, यानी समय का अपरिवर्ती फलन होता है :

$$v = \bar{v}l = \bar{v}. \quad (5)$$

तो भी जैसा कि हम लोग देखेंगे, टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी परिवर्तनों की प्रचलित प्रकृति एवं दिशा के प्रत्युत्तर में श्रम-निपज अनुपात परिवर्तनाश्रित होता है।

श्रम-वचाने के तकनीकों का प्रभाव

साधनों का सापेक्ष मूल्य दिया हुआ रहने पर, हम लोग उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में श्रम वचाने अथवा श्रम लगाने वाली टेक्नोलॉजी के प्रयोग को स्वतन्त्र रूप से दिया हुआ, यानी उन्हें बाजारगत परिस्थितियों से स्वतंत्र मान सकते हैं। फिर भी हम लोग आगे चलकर श्रम-वचाने अथवा श्रम-उपयोग करने वाले तकनीकों को अपनाने के आर्थिक एवं टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी कारणों की खोज करेंगे। श्रम-वचाने वाले तकनीक की प्रकृति को इस प्रकार से देखा जा सकता है : यदि श्रम-निपज अनुपात श्रम-पूँजी अनुपात एवं निपज-पूँजी अनुपात का परिणाम है, यानी $N/\gamma = (N/K)/(\gamma/K)$, और यदि पूँजी की उत्पादकता (γ/K) को स्थायी माना जाय, तो दी हुई पूँजी की तुलना में श्रम की मात्रा में कोई कमी से (निम्न N/K) श्रम-निपज अनुपात में कमी (निम्न N/γ) होगी। अतएव, एक दिये हुए उत्पादन फलन में प्रति इकाई पूँजी के श्रम की मात्रा के घटाने के लिए सभी अन्वेषण एवं नवीन क्रिया को श्रम वचाने का साधन समझा जा सकता है।

यह मानते हुए कि N/K एवं इसके परिणामस्वरूप N/γ में अपरिवर्त्ती ह्रास को रोकने के लिए कोई वावा-जनक अथवा खिसकाने वाली शक्ति नहीं, हम लोग कालान्तर में श्रम-निपज अनुपात $(a = N/Y)$ को ga की स्थायी दर से घटने दे सकते हैं :

$$a = at = \frac{ao}{(I + ga)^t} \quad (6)$$

जिसमें at समय के फलन के रूप में गत्यात्मक श्रम-निपज अनुपात है, ao उस अनुपात का प्रारम्भिक मूल्य है और ga उस अनुपात के ह्रास की स्थायी दर है। समीकरण (6) में निम्नलिखित अनुक्रम अंतर्निहित है :

$$\begin{aligned} ao &= e, \\ a_1 &= ao/(I + ga) = e/(I + ga), \\ a_2 &= a_1/(I + ga) = e/(I + ga)^2, \\ a_3 &= a_2/(I + ga) = e/(I + ga)^3, \end{aligned}$$

इत्यादि, इत्यादि।

(5) एवं (6) को ध्यान में रखते हुए एवं $\Delta\gamma/\gamma$ को Gn से निर्दिष्ट करते हुए समीकरण (4) को पुनः सूत्र के रूप में निम्नांकित प्रकार से वर्णन किया जा सकता है :

$$Gn = \frac{\bar{p}}{ao/(I + ga)t}, \quad (7)$$

जो यह बतलाता है कि कालान्तर में जैसे-जैसे श्रम-निपज अनुपात घटता है, वैसे-वैसे पूर्ण रोजगार-निपज की वृद्धि की दर विपरीततः बढ़ने में सक्षम होती है। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त श्रम एवं निपज का स्थायी अनुपात ($v = \bar{v}$) दिये रहने पर श्रम की बढ़ती हुई उत्पादकता ($pl = w/I/at$) के प्रभावस्वरूप Gn में वृद्धि होती है।

श्रम-उपयोग के तकनीकी का प्रभाव

दूसरी ओर, मान लें कि श्रम-उपयोग करने वाले तकनीकी को इस प्रकार अपनाया जाता है कि कालान्तर में श्रम-निपज अनुपात में ga की स्थायी दर से घातीय सम्बन्ध के अनुसार वृद्धि होती है।

$$a = at = ao (1 + ga)^t, \quad (8)$$

जिसमें ga अब श्रम-निपज अनुपात में वृद्धि की स्थायी दर को स्पष्ट करता है। समीकरण (8) पृथक् गतियों को बतलाता है जो निम्नांकित प्रकार से परिभाषित किये जाते हैं :

$$ao = e,$$

$$a_1 = ao (1 + ga) = e (1 + ga),$$

$$a_2 = a_1 (1 + ga) = e (1 + ga)^2,$$

$$a_3 = a_2 (1 + ga) = e (1 + ga)^3,$$

इत्यादि, इत्यादि।

(5) एवं (8) को ध्यान में रखते हुए समीकरण (4) को पुनः इस प्रकार से लिखा जा सकता है :

$$Gn = \frac{v}{ao (1 + ga)t}, \quad (9)$$

जो यह बतलाता है कि स्थायी v के दिये रहने पर कालान्तर में श्रम-निपज अनुपात में जैसे-जैसे वृद्धि होती है, वैसे-वैसे पूर्ण रोजगार निपज की अवधि की दर विपरीततः घटने में सक्षम है। दूसरे प्रकार से इसे यों कहा जा सकता है कि जब अतिरिक्त श्रम एवं निपज का अनुपात स्थायी रहता है, तो घटती हुई उत्पादकता के परिणामस्वरूप Gn में ह्रास होता है।

नीति प्राचल के रूप में श्रम-निपज अनुपात

यदि हम लोग उस गौरव-पूर्ण स्थिति को अपनाते हैं, जिसे टी० हेबलो¹ ने एक स्थान पर अपनाया है कि टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्राचल वस्तुतः रासायनिक सूत्रों तथा यांत्रिकी के नियमों की अपेक्षा मानवीय पसंद तथा आचरण से अधिक सम्बद्ध है

1. देखें, इनकी पुस्तक 'ए स्टडी इन दि थियरी आफ इकानामिक इवोल्यूशन' पृ० 49।

तो श्रम-निपज को आयोजित हेर-फेर किया जा सकने वाला नीति-प्राचल समझना अधिक लाभदायक है। अब प्रश्न यह है कि श्रम-निपज अनुपात या निपज-श्रम अनुपात को एक ऐसा दिया हुआ तकनीकी आधार जिससे अन्य सभी का अनुकूलन किया जा सके, मानने के वर्तमान श्रम-निपज अनुपात को Gn तथा v के किसी स्वीकृत मान के ही अनुकूल क्यों न किया जाय ? इस प्रश्न का आशय यह सुझाव देना होगा कि तकनीकी प्राचलों को नीति-गत विषय की तरह समझा जा सकता है। चूंकि केवल संयोग के अतिरिक्त वास्तविक श्रम-निपज अनुपात (a') को सदा अपेक्षित या संतुलित (a) के समान होने के पक्ष में कोई परिकल्पना नहीं है, अतएव यथासंभव $a' = a$ के बराबर रखना आवश्यक एवं वांछनीय हो जाता है। तीसरे समीकरण से Gn एवं v के स्वीकृत स्तर के अनुरूप श्रम-निपज अनुपात का अपेक्षित मान मिलता—

$$a = \frac{v}{Gn}, \quad P = \frac{Gn}{v} \quad (10)$$

यहाँ पर a एवं p क्रमशः अपेक्षित श्रम-निपज अनुपात एवं श्रम की उत्पादकता हैं। समीकरण (10) से यह स्पष्ट है कि श्रम-निपज अनुपात को पूर्ण रोजगार निपज तथा अतिरिक्त श्रम एवं निपज के एक दिये हुए आधार के अनुपात के किसी प्रकार के अनुकूलन के लिए तकनीकी परिवर्तनों की प्रकृति एवं दिशा में निश्चित रूप से विचार पूर्वक परिवर्तन करना होगा। दूसरे शब्दों में, यह $a' \neq a$ की विषमता पर विचार करता है।

मान लिया कि औद्योगीकरण की और उन्मुख अर्थ-व्यवस्था की भाँति दिये हुए v की तुलना में एक ऊँचे Gn को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो समीकरण (10) के अनुसार अपेक्षित श्रम-निपज अनुपात में ह्रास अवश्य होगा। इस का आशय यह है कि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम वचाने वाले उपायों का प्रयोग करना चाहिए। यदि तकनीक की प्रचलित स्थिति के परिणामस्वरूप वास्तव में वृहत् श्रम-निपज अनुपात (a') प्राप्त होता है, तो Gn में उपर्युक्त परिवर्तन से तकनीक में इस प्रकार की उन्नति की आवश्यकता होती है, जिससे वास्तविक श्रम-निपज अनुपात कम होकर अपेक्षित अंक (a) के स्तर तक हो जाय। यह अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की एक विशेष स्थिति हो सकती है। फिर भी, अन्य दिये हुए आधार v में वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रम वचाने वाले तकनीकों की जगह श्रम-प्रयोग करने वाले तकनीकों की आवश्यकता की संभावना का अनुमोदन किये वगैर श्रम वचाने वाले उपायों के उपयोग की सिफारिश नहीं की जा सकती। अब मान लिया कि एक जनाधिक्य वाली अर्थ-व्यवस्था की भाँति, एक दिये हुए gn की तुलना में उच्च v स्वीकार्य समझा जाता है। तब इसके परिणामस्वरूप समीकरण

(10) के अनुसार, अपेक्षित श्रम-निपज अनुपात v में उपर्युक्त परिवर्तन के पूर्व की अपेक्षा अधिक है। इस सम्बन्ध में नीति का आश्रय यह है कि जब तक निपज में वृद्धि की निम्न दर को स्वीकार नहीं किया जाता है, श्रम प्रयोग करने वाले तकनीकों को प्रोत्साहित करना चाहिये। किन्तु तब श्रम प्रयोग करने वाले तकनीकों को अपनाने से श्रम की उत्पादन-क्षमता में कमी आ जाती है। अतएव, एक-जनाधिक्य वाली अर्थ-व्यवस्था में, तीव्र तकनीकी प्रगति की प्रक्रिया में श्रम की उत्पादकता को बढ़ाने की इच्छा तथा गंभीर बेरोजगारी को टालने की इच्छा में सम्भावित संघर्ष पाया जाता है।¹ तो भी, यहाँ ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि श्रम-निपज अनुपात को सदा एक दिया हुआ आधार मानने के बजाय, इसे किसी भी तकनीक की दृष्टि से नग्न अर्थ-व्यवस्था में विचारपूर्ण परिवर्तन के योग्य सम्भावित नीति प्राचल समझना चाहिए। यह हमें श्रम बचाने तथा श्रम को प्रयोग करने वाले तकनीक को अपनाने के लिए प्रभावित करने वाले कतिपय कारणों के सर्वेक्षण की ओर ले जाता है।

श्रम बचाने एवं श्रम का प्रयोग करने वाले तकनीकों पर प्रभाव

श्रम-निपज अनुपात में परिवर्तन की गति, यानी g_a जिसे हम लोग स्वतंत्र रूप से दिया हुआ मान लेते हैं, का ठीक-ठीक निर्धारण कठिन है। फिर भी, श्रम बचाने तथा श्रम का प्रयोग करने वाले तकनीकों के चयन के प्रमुख कारणों की निम्नलिखित रूप-रेखा के द्वारा g_a के निर्णायकों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

किसी बाजारगत अर्थ-व्यवस्था द्वारा श्रम बचाने के उपायों को अपनाने का सर्वाधिक स्पष्ट कारण यह है कि इनके परिणामस्वरूप श्रम की प्रति-इकाई उत्पादन

1. जापान का एक अर्थशास्त्री इस बात की व्याख्या इस प्रकार करता है : वस्तुतः उत्पादकता में वृद्धि का ताव उत्पादन की प्रक्रिया में अधिक-से-अधिक अतिरिक्त जनसंख्या को खपाने की आवश्यकता से कम-से-कम अस्थायी तौर पर अवमंदित हो जाएगा। जहाँ तक नियुक्त साधनों के अनुपात का सम्बन्ध है, यद्यपि आधुनिक तकनीक को पूर्णतः लोचदार नहीं माना जा सकता, फिर भी जापान में शायद श्रम की उत्पादकता की जगह श्रम-गहन उपायों को अपनाने के कुछ उदाहरण मिल सकते हैं। (देखें, एच. किडगुरा लॉरेंस प्रोजेक्शन ऑफ़ दि जैपनीज इकानामी—'ए क्रिटिकल इमैल्युशन, काइक्लोस, IX (2), 1956 किन्तु, जैसा कि जॉन रॉबिन्सन ने बतलाया है 'यदि वस्तुओं तथा पूंजीगत मालों की समर्य मांग प्रति-व्यक्ति निपज में वृद्धि के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ती है, तो श्रम-बचाने वाली नवीन क्रियाओं को अपनाने से तकनीक-मूलक बेरोजगारी नहीं होती।

लागत में साधारणतया कमी होती है। अतएव, अन्य बातों के यथावत् रहने पर, औसत मजदूरी की दर जितनी ही उच्च होगी, श्रम बचाने के उपायों को पता लगाने तथा अपनाने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। संयुक्तराष्ट्र का 'स्वचालन' की ओर झुकाव इसका अच्छा उदाहरण है, किन्तु वहाँ पर श्रम-संगठनों का 'उच्च मजदूरी-आन्दोलन' ही इसका एकमात्र प्रेरक कारण नहीं है। किन्तु, वहाँ एक अवाजारगत अर्थ-व्यवस्था में सम्भवतः श्रम की प्रति-इकाई वास्तविक आय में वृद्धि अथवा मानवीय नित्यक्रम (वास्तविक लागत) में कमी की सम्भावना पर अधिक जोर दिया जाता है। श्रम बचाने के उपायों को अपनाने का दूसरा संभावित कारण श्रम-विनिमय की प्रभावयुक्त व्यवस्था के अभाव में वर्तमान श्रम की अत्यधिक अगतिशीलता हो सकता है। इस प्रकार की बड़ी एवं वृद्धिशील जनसंख्यावाली अर्थ-व्यवस्थाओं द्वारा भी श्रम बचाने वाले तकनीकों की प्रगति को प्रोत्साहित करने के कारणों की व्याख्या मुख्यतः इस आधार पर की जा सकती है कि संभावित प्राप्य श्रम-शक्ति सदा उचित समय एवं स्थान में नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं रहती। श्रम-बचाने वाले उपायों को अपनाने का एक दूसरा संभावित कारण यह भी हो सकता है कि पूर्ण रोज़गार की तेज़ी अल्प रोज़गार की मंदी से बढ़ जाती है, जिससे श्रम बचाने वाले अन्वेषणों एवं नवीन क्रियाओं को अपनाना, विशेषतः जनसंख्या में मंद वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रम की पर्याप्त मात्रा में बेलोचदार पूर्ति वाली अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए अनिवार्य एवं लाभदायक हो जाता है। विवृत अर्थ-व्यवस्थाओं में श्रम बचाने वाले तकनीकों के प्रयोग का एक संभावित कारण इनका श्रम बचानेवाले उपायों के अत्यधिक जानकारी अर्थ-व्यवस्थाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस प्रकार के तकनीक को अपनाना उसे आयात करने तथा तकनीक की दृष्टि से विकसित देशों की नकल करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अतएव, एक विवृत अर्थ-व्यवस्था में श्रम बचाने के उपायों को अपनाने की दिशा तीव्र गति से बढ़ सकती है। 'मेजी रेस्टोरेशन' के बाद का जापान इसका एक अच्छा ऐतिहासिक उदाहरण है। साधारणतया, श्रम बचाने वाले उपायों से अस्थायी बेरोज़गारी (इस सम्बन्ध में तकनीक मूलक बेरोज़गारी) के रूप में अल्पकालीन हानि की तुलना में अत्यधिक उत्पादकता के रूप में इससे दीर्घकालीन लाभ के सम्बन्ध में जितनी ही अधिक जानकारी होगी, श्रम बचाने वाले आधारों पर नवीन क्रियाकरण की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक तीव्र होगी।

जहाँ तक श्रम बचाने वाले उपायों के संभावित कारणों का सम्बन्ध है, इन्हें पता लगाना प्रवीणता के इस युग में और भी कठिन कार्य है। श्रम बचाने वाले तकनीक को अपनाने की क्लासिक स्थिति का निर्माण तकनीक-मूलक बेरोज़गारी के सर्वज्ञात भय से किया जाता है। किन्तु रोज़गार के लिए श्रम-प्रयोग करने वाले तकनीकों को स्थायी रूप से अपनाने का सुभाव बहुत कम लोग देंगे; क्योंकि उत्पादन-क्षमता का परित्याग किये बगैर बेरोज़गारी को दूर करने के वैकल्पिक उपाय एवं साधन (यानी

अल्पकाल में समर्थ माँग में वृद्धि एवं दीर्घकाल में वास्तविक पूँजी के संचय के द्वारा) उपलब्ध है। इसका एक प्रबल कारण यह जान पड़ता है कि उत्पादक, विशेषतः जनाधिक्य वाली अर्थ-व्यवस्थाओं में, ऐसा सोचते हैं कि उत्पादन के श्रम बचाने वाले तकनीकों में उपलब्ध श्रम की निम्न उत्पादन-क्षमता की क्षति-पूर्ति मुख्यतः निम्न श्रम-व्यय के द्वारा हो जायगी। इसी विश्वास पर कार्य करते हुए उत्पादक श्रम-व्यय करने वाले तकनीकों की तुलना में श्रम-प्रयोग करने वाले तकनीकों को अधिकाधिक मात्रा में अपना सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए श्रम-निपज अनुपात में वृद्धि हो जाती है। इसका एक दूसरा कारण यह भी दिया जा सकता है कि साहसियों के बीच तीव्र प्रतियोगिता के अभाव में वे निम्न तकनीकी योग्यता वाले उपकरणों को अपनाकर भी सन्तुष्ट हो जाते हैं। किन्तु, यह उन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के साथ लागू नहीं होता जिन्हें भीषण विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और इस प्रतियोगिता का सामना करने तथा विकास के कार्यों के लिए आवश्यक विदेशी विनिमय प्राप्त करने के उद्देश्य से श्रम बचाने वाले तकनीकों को नहीं अपनाकर श्रम-प्रयोग करने वाले तकनीकों को अपनाने का एक प्रधान कारण उच्च तकनीकी वाले सुप्रवाही उपकरणों को लगाने के लिए कोष (अतः वास्तविक बचत) का सामान्य अभाव जान पड़ता है। साथ (यानी मौद्रिक पूँजी) के कार्य (फ़ंक्शन) के रूप में कंप्यूटर का नवीन क्रिया का सिद्धान्त यहाँ प्रासंगिक जान पड़ता है। सामान्य अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्रम-प्रयोग-सम्बन्धी तकनीकी प्रगति सर्वत्र श्रम की बढ़ती हुई उत्पादकता की प्रभावशाली प्रवृत्ति की सीमा निर्धारित करती है।

क्षमता-वृद्धि पर टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रभाव

विकल्पित श्रम को दिया हुआ मानकर, हम लोग क्षमता-निपज की वृद्धि पर टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी आघातों की जाँच-पड़ताल करें। इसके लिए पूँजी की पूर्ति के व्याज की लोच को शून्य के बराबर मान लेना सुविधाजनक होगा, किन्तु पूँजी-निपज अनुपात के स्थायित्व की सामान्य कल्पना का परित्याग अनिवार्य है। इसके बदले में हम ग्रँर-तटस्थ टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रगति के सूचक के रूप में लोचपूर्ण पूँजी-निपज अनुपात के आधार पर कार्य करने का प्रस्ताव रखते हैं। औपचारिक विश्लेषण के बाद, हम विभिन्न परिस्थितियों में पूँजी-निपज अनुपात को प्रभावित करने वाली प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे।

मूल सम्बन्ध

श्रम की उत्पादकता की ही तरह, हम पूर्ण-क्षमता-निपज में वृद्धि की दर के आधारभूत निर्धारण के विश्लेषण से प्रारम्भ करते हैं। वास्तविक पूँजी में वृद्धि के

परिणामस्वरूप निपज में पूर्ववर्णित मान्यताओं के अनुसार निम्नांकित के बराबर परिमाण में वृद्धि होती है।

$$\Delta Y' = \sigma \Delta K, \quad (1')$$

जिसमें Y' पूर्ण-क्षमता से प्राप्त सम्भावित शुद्ध राष्ट्रीय निपज, या केवल पूर्ण क्षमता निपज है, K पूर्ण नियुक्ति क्री स्थिति में वास्तविक पूँजी की मात्रा, और δ सम्बन्धित पूँजी की औसत एवं सीमांत उत्पादकता (सीमान्त उत्पादकता की स्थिति में यह शुद्ध निवेश की औसत उत्पादकता को सूचित करता है; क्योंकि $\Delta K = I$) हैं।

पुनः, हम यह मानते हैं कि शुद्ध निवेश एवं उपज में एक निश्चित सम्बन्ध है :

$$\delta = \frac{\Delta K}{Y} = \frac{I}{Y'}, \quad (2')$$

जिसमें δ बढ़ती हुई पूँजी एवं निपज का अनुपात अथवा जैसा कि पहले कहा गया था 'पूँजीगत वस्तुओं को उत्पन्न करने की क्षमता' है। जैसा कि पहले अध्याय में वर्णित किया गया था, अति अनुकूल मान्यता के आधार पर $\delta = s$ (जहाँ पर s बचत का अनुपात है) होता है। इसी प्रकार की मान्यता के आधार पर हैरोड के मॉडल s स्पष्ट परिवर्तों के रूप में दीख पड़ता है। निवेश अनुपात (δ) के लिए स्थायी रहना कोई आवश्यक नहीं है, किन्तु यह साधारणतया अर्थ-व्यवस्थाओं में उच्च तथा अल्प-विकसित में निम्न होता है।

(1') एवं (2') समीकरणों से पूर्ण-क्षमता निपज में वृद्धि की दर प्राप्त होती है :

$$\frac{\Delta Y'}{Y'} = \sigma \delta \quad (3')$$

जो यह बतलाता है कि पूर्ण क्षमता निपज में वृद्धि की दर पूँजी की उत्पादकता (σ) \times निवेश-अनुपात (δ) के प्रत्यक्ष अनुपात में होती है।

चूँकि पूँजी की उत्पादकता पूँजी-निपज अनुपात के विपरीत है, $\sigma = I/b = K/Y = \Delta K / \Delta Y$, समीकरण (3') को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है :

$$\frac{\Delta y'}{y'} = \frac{I}{b} \delta = \frac{\delta}{b}, \quad (4')$$

जो यह बतलाता है कि δ के स्थायी दिया हुआ होने पर, पूर्ण-क्षमता निपज में वृद्धि की दर में पूँजी-निपज अनुपात (b) के ठीक विपरीत अनुपात में परिवर्तन होता है।

स्पष्ट रूप में टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी आघात को उपस्थित करने के लिए हम लोग विशेष रूप से यह मानते हैं कि निवेश अनुपात अचर रूप से समय का फलन है :

$$\delta = \delta_1 = \bar{\delta} \quad (5')$$

इतना तो आवृत्ति-सम्बन्ध, किन्तु तैयारी अभी करनी है। अब उत्पादन क्षमता पर पूँजी बचाने तथा पूँजी उपयोग करने वाले तकनीकों के सम्भावित प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा।

पूँजी बचाने के तकनीको का प्रभाव

मान लिया कि पूँजी बचाने के तकनीक प्रयोग में है। यदि इस प्रकार के तकनीको को g_b की स्थायी दर पर अपनाया जाता है, तो पूँजी-निपज अनुपात में घातीय ह्रास होगा

$$b = b_1 = \frac{b_0}{(1+g_b)} \quad (6')$$

जिसमें b_1 गत्यात्मक पूँजी-निपज अनुपात, b_0 इस अनुपात का प्रारम्भिक मान तथा g_b इस अनुपात में ह्रास की दर है। समीकरण (6') वस्तुतः पूँजी की वृद्धिशील उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि $\sigma_1 = 1/b^1$ है। यह निम्नांकित अधोगामी गतियों को सूचित करता है

$$\begin{aligned} b_0 &= a, \\ b_1 &= b_0/(1+g_b) = c/(1+g_b), \\ b_2 &= b_1/(1+g_b) = c/(1+g_b)^2, \\ b_3 &= b_2/(1+g_b) = c/(1+g_b)^3, \end{aligned}$$

इत्यादि, इत्यादि।

समीकरण (5') एवं (6') को (4') में प्रतिस्थापित करने तथा $\Delta Y'/Y'$ को G_k से निदिष्ट करते हुए निम्नांकित प्राप्त होता है :—

$$G_k = \frac{\delta}{b_0/(1+g_b)} \quad (7')$$

जो यह बतलाता है कि निवेश-अनुपात (g) के स्थायी रहने पर, पूर्ण-क्षमता निपज-अनुपात में वृद्धि की दर पूँजी-निपज अनुपात में दिये हुए समय में कमी के ठीक विपरीत अनुपात में बढ़ती है।

पूँजी-उपयोग के तकनीको का प्रभाव

अब हम इसकी विपरीत स्थिति की व्याख्या करेंगे जहाँ मुख्य प्रवृत्ति उत्पादन के पूँजी-उपयोग वाले तकनीको को अपनाने की होती है। इसके कारणों को

अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। यदि पूँजी निपज अनुपात में gb की स्थायी दर से वृद्धि होती है, तो हमें उस अनुपात के चक्रवृद्धि व्याज की वृद्धि प्राप्त होती है :

$$b = b_t = b_0(I + gb)^t, \quad (8')$$

जिस में gb , इस बार, पूँजी-निपज अनुपात की वृद्धि की स्थायी दर को बतलाता है। पहले की ही तरह समीकरण (8') को प्रवर्धित किया जा सकता है :

$$\begin{aligned} b_0 &= c, \\ b_1 &= b_0(I + gb) = c(I + gb), \\ b_2 &= b_1(I + gb) = c(I + gb)^2, \\ b_3 &= b_2(I + gb) = c(I + gb)^3, \end{aligned}$$

इत्यादि, इत्यादि।

(5') एवं (8') समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, समीकरण (4') को परिवर्तित रूप में निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है :

$$G_k = \frac{\delta}{b_0(I + gb)^k}, \quad (9')$$

यह समीकरण यह बतलाता है कि यदि निवेश अनुपात स्थायी रहे, तो पूर्ण-क्षमता निपज में वृद्धि की दर में बढ़ते हुए पूँजी-निपज अनुपात के ठीक विपरीत ह्रास होता है। दूसरे शब्दों में, पूँजी की ह्रासमान उत्पादकता से G_k में दीर्घकालिक कमी उत्पन्न होती है।

नीति-प्राचल के रूप : पूँजी-निपज अनुपात

श्रम-निपज अनुपात ही की तरह, पुनः संभावित नीति-प्राचल के रूप में पूँजी-निपज अनुपात पर विचार करना भी लाभदायक होगा। समीकरण (9') से G_k एवं δ के दिये हुए मान के अनुरूप अपेक्षित पूँजी-निपज अनुपात प्राप्त होता है :

$$b = \frac{\delta}{G_k}, \quad \sigma = \frac{G_k}{\delta}, \quad (10')$$

जिसमें b एवं σ क्रमशः अपेक्षित पूँजी-निपज अनुपात एवं पूँजी की उत्पादकता हैं। चूँकि अवंध नीति के अंतर्गत पूँजी-निपज अनुपात के वास्तविक मूल्य (b') के इसके अपेक्षित अथवा संतुलित मूल्य (b) से विचलित होने की सम्भावना रहती है, अतएव G_k एवं δ का कोई दिया हुआ स्वीकार्य मूल्य होने पर, $b' = b$ करने के उद्देश्य से, टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रगति की प्रकृति एवं दिशा को प्रभावित करना सार्वजनिक नीति के लिए आवश्यक हो जाता है।

उदाहरण के लिए, यदि एक दिये α की तुलना में उच्च G_k आवश्यक एवं वांछनीय होता है, तो समीकरण (10') के अनुसार अपेक्षित पूँजी-निपज अनुपात में अवश्य ह्रास होगा। यदि टेक्नोलॉजी की प्रचलित स्थिति उच्च वास्तविक पूँजी-निपज अनुपात को स्थापित करने वाली है, तो उपर्युक्त उदाहरण में उच्च G_k की इच्छित वस्तु के रूप में स्वीकार करने के लिए वर्तमान पूँजी-निपज अनुपात को G_k एवं α के स्वीकार्य मूल्य, यानी b अनुपात के सतुलन मूल्य के समरूप जान-बूझकर करना होगा। फिर पूँजी-निपज अनुपात में कमी, यद्यपि क्षमता-निपज में विकास की ऊँची दर को सूचित करती है, तो भी इसमें कुछ प्रत्ययात्मक एवं व्यावहारिक कठिनाइयाँ अन्तर्गस्त हैं।

उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) के एक अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि एक जनसंख्या में वृद्धि की उच्च दर एवं निम्न वृद्धि दर वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए अपने निवेश-कार्यक्रम में भारी उद्योगों, जैसे पूँजी-गहन योजनाओं की तुलना में कृषि जैसी शीघ्र फल देने वाली योजनाओं को प्रधानता देना अधिक उत्तम होगा।¹ कोई इसे केवल दृढ़तापूर्वक यह कहकर टाल सकता है कि भारी उद्योगों का कोई आधारभूत विकल्प नहीं है, जैसा एन० कालडोर ने किया था, किन्तु फिर भी गड़बड़ी रह ही जाती² है जो सिद्धांत-ठोस नीति के लिए हानिकारक होती है। इस शीघ्र-फल देने वाली योजनाओं को शायद इसलिए श्रेष्ठ समझा जाता है कि ये शीघ्रता के दृष्टिकोण से स्वतः ही अपेक्षाकृत निम्न पूँजी-निपज अनुपात देती हैं।³ निश्चय ही यह प्रस्ताव पूँजी-विपन्न, जनाधिक्य वाले एवं अल्पविकसित देशों के लिए आकर्षक जान पड़ता है, किन्तु किसी भी प्रकार यह उतना स्पष्ट नहीं होता कि शीघ्र फल देने वाली एवं थम-प्रधान योजनाओं की ओर निवेश कार्यक्रम को लगाने का परिणाम निम्न पूँजी-निपज अनुपात होता है। हम अपने सदेह को निम्न प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं।

1. यू० एन० इकॉनॉमिक बुलेटिन फॉर एशिया एंड दि फॉर ईस्ट, नवम्बर, 1955, विशेषतः 'प्रोब्लेम्स एंड टेक्निक्स ऑफ इकॉनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू इ० सी० ए० एफ० ई० कोन्ट्रोज'।
2. दिसम्बर, 1956 ई० में न्यूयार्क में मेट्रोपॉलिटन इकॉनॉमिक एसोशियेशन की एक बैठक में, 'इकॉनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू सेकंड फाइव ईयर प्लान' नामक भाषण में।
3. यू० एन० पूर्व उद्धृत।

मान लिया कि K वास्तविक पूँजी, N नियुक्त करने योग्य श्रम, γ निपज, K/N पूँजी-श्रम अनुपात, K/γ पूँजी-निपज अनुपात, एवं γ/N श्रम की उत्पादकता हैं। पुनः मान लिया कि K/N पूँजी की गहनता की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे उच्च K/N को 'पूँजी-प्रधान' उद्योग अथवा योजना एवं निम्न K/N को 'श्रम प्रधान' उद्योग अथवा योजना से सम्बद्ध किया जा सकता है। यह प्रस्ताव कि एक निम्न-पूँजी-गहन योजना का परिणाम निम्न पूँजी-निपज अनुपात होता है, केवल तभी सत्य होगा जबकि श्रम की उत्पादकता को पूँजी की तीव्रता से स्वतन्त्र मान लिया जाए। किन्तु, इस अन्तिम मान्यता की स्वीकृति संदेहात्मक जान पड़ती है; क्योंकि अवलोकन एवं अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि श्रम की उत्पादकता में औद्योगीकरण में 'पूँजी-गहन' की मात्रा के अनुसार अधिक या कम परिवर्तन होता है। इसे हम लोग पूँजी-निपज अनुपात एवं अन्य टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्राचलों के निम्न सम्बन्ध के संदर्भ में स्पष्ट कर सकते हैं :

$$\frac{K}{\gamma} = \frac{K/N}{\gamma/N} \quad (11')$$

जो यह बतलाता है कि पूँजी-निपज अनुपात पूँजी-श्रम अनुपात का प्रत्यक्ष तथा श्रम की उत्पादकता का परोक्ष तरीके से अनुरूप है। समीकरण (11') से यह स्पष्ट है कि यदि $(K/N)/(\gamma/N)$ अनुपात के भाजक को इसके भाज्य में ह्रास से अप्रभावित मान लिया जाय, तो पूँजी-निपज अनुपात को श्रम-प्रधान उपायों या नवीन क्रिया से समतुल्य समझा जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि श्रम की उत्पादन क्षमता (γ/N) में पूँजी की तीव्रता के गुणक (K/N) से कम अनुपात में वृद्धि के परिणाम-स्वरूप उच्च पूँजी-निपज अनुपात प्राप्त हो सकेगा। अतएव, इस बात की सैद्धान्तिक सम्भावना है कि 'पूँजी-प्रधान' औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप, न कि बावजूद, पूँजी-निपज अनुपात में ह्रास होगा।¹ इस प्रकार विश्लेषण अनुपात

1. इस सम्भावना को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित संख्या-सचक उदाहरण पर विचार करना लाभदायक जान पड़ता है :—

अपनाये गए तकनीक का प्रकार	(1) चक्रदार की स्थिति	(2) श्रम की उत्पादकता	(3) पूँजी-निपज अनुपात	(4) वचत अनुपात	(5) विकास-दर
	(K/N)	(γ/N)	(K/γ)	(S/γ)	$(\Delta \gamma/\gamma)$
प्रारम्भिक	50/100	10/100	5	0.05	0.01
पूँजी-प्रधान	100/100	25/100	4	0.05	0.0125
श्रम-प्रधान	25/100	4/100	6.25	0.05	0.008

$$(3) = (1)/(2); (5) = (4)/(3)$$

मे ह्रास होगा।' इस प्रकार विश्लेषण एवं नीति, दोनों की दृष्टि से पूँजी-धन-अनुपात (K/N) एवं धन की उत्पादकता (Y/N) को केवल परतन्त्र परिवर्ती (K/Y) के सम्बन्ध में स्वतन्त्र परिवर्ती ही नहीं, वरन् एक दूसरे के सम्बन्ध में अन्योन्याश्रित परिवर्ती समझना महत्वपूर्ण है।

यह उदाहरण इस सम्भावना को स्पष्ट करता है कि न्यून पूँजी अनुपात वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था भी पूँजी-प्रधान तकनीक को अपना कर अथवा पूँजी-प्रधान औद्योगीकरण को प्रोत्साहित कर (द्वितीय पक्ति की तरह) उच्च विकास दर ($\Delta Y/Y$) प्राप्त कर सकती है।

पाठक उपर्युक्त उदाहरण, जो ३ मार्च, 1957 ई० के 'इकॉनामिक वीकली' (भारत) में प्रकाशित हमारे 'टेबनीक्स फॉर मैक्सिमम ग्रोथ एण्ड एम्प्लायमेंट' के एक अंश के रूप में छपा था, के प्रति श्रीमती जोन रॉबिन्सन तथा श्री ए० के० सेन एवं एस० साधी की प्रतिक्रिया में दिलचस्पी ले सकते हैं। अन्य स्थानों में श्रीमती रॉबिन्सन की प्रतिक्रिया तकनीक के चुनाव के सम्बन्ध में वाद-विवाद की सघात-प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। साथ ही, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त उदाहरण से श्रीमती रॉबिन्सन तथा अन्य कहां सहमत तथा कहां असहमत होते हैं।

'इकॉनामिक वीकली' (अप्रैल 27, 1957) के अपनी टिप्पणी में श्रीमती जोन रॉबिन्सन कहती है। 'वे (श्री के० के० कुरीहारा) तीन तकनीक दिखलाते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 100 व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं। इनमें सर्वाधिक पूँजी-गहन तकनीक निवेश की 100 इकाई (अधिक स्पष्ट रूप से, पूँजी) से निपज की 25 इकाई उत्पन्न करता है। दूसरे निपज की 10 इकाई के लिए 50 इकाई निवेश तथा अन्तिम निपज की 4 इकाई के लिए 25 इकाई निवेश चाहता है। इनमें से पहला तकनीक (हम लोगो के सक्षय-मूलक उदाहरण में दूसरी पक्ति प्रत्येक दृष्टिकोण से अन्य दो से श्रेष्ठ है। इस प्रकार का तर्क, उदाहरण के लिए अम्बर चरखा के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है, जिसका एक सूत कातने वाले कारखाने की तुलना में दोनो प्रति व्यक्ति तथा प्रति इकाई निवेश से कम उत्पादन होता है, किन्तु इसका दो प्रकार के करघों के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनमें से पहले प्रकार का करघा कम यन्त्रीकृत होने के कारण प्रति-व्यक्ति कम, किन्तु निवेश की प्रति इकाई अधिक एवं दूसरा अधिक यन्त्रीकृत होने के कारण निवेश की प्रति इकाई अधिक, किन्तु प्रति-व्यक्ति कम उत्पादन करता है।'

श्री ए० के० सेन अपने 'मैन, मशीन एण्ड ग्रोथ' (30 मार्च, 1957 के 'इकॉनामिक वीकली' में) में कहते हैं, 'प्रो० कुरिहारा का यह प्रस्ताव बिल्कुल

पूँजी वचाने एवं पूँजी प्रयोग करने वाले तकनीकों पर प्रभाव

पूँजी-निपज अनुपात (g_b) में परिवर्तन की दर को प्रभावित करने वाली प्रवृत्तियों¹ का चित्रण करना कठिन होते हुए भी संभव है। किन्तु, यहाँ पर आगे हम लोग

ठीक है कि पूँजी की गहनता के अल्पीकरण से पूँजी-निपज अनुपात अल्प नहीं होता। यदि (Y/N) में (K/N) के अनुपात से अधिक वृद्धि हो, तो सम्भव है कि उच्च पूँजी-श्रम अनुपात से निम्न पूँजी-निपज अनुपात की प्राप्ति हो। यह वास्तव में तथ्य का प्रश्न है तथा (K/N) एवं (K/Y) के बीच सम्बन्ध का दो में से एक तरफ सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। प्रो० कुरिहारा श्रम की उत्पादकता (Y/N) को पूँजी की गहनता (K/N) से स्वतन्त्र मानने की कल्पना करते हुए वचत-अनुपात (S/Y) को इससे स्वतन्त्र मानते हैं (तीनों स्थिति में 0.05)। किन्तु, वचत-अनुपात निश्चय ही मजदूरी के विल तथा निपज के अनुपात पर निर्भर करता है, जो स्वयं श्रम की उत्पादकता (Y/N) पर आश्रित है।

एस० साची अपने “प्रो० कुरिहारा ऑन चायस आफ टेक्नीक्स” (इकॉनामिक वीकली, मार्च, 1957 में) में कहते हैं, “जैसा कि अन्य लोगों ने इसके पूर्व किया है”; प्रो० कुरिहारा दृढ़ता से इस सिद्धान्त (कि श्रम की प्रचुरता के परिणाम-स्वरूप अल्प-विकसित देशों को श्रम-प्रधान उद्योगों का विकास करना चाहिए) का खण्डन करते हैं, जैसा कि अन्य कई व्यक्तियों ने पहले किया है। ऐसी स्थिति में (उपर्युक्त संख्या-मूलक उदाहरण के संदर्भ में) चुनाव का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। यदि पूँजी-प्रधान निवेश की पद्धति को नहीं चुना जाय, तो यह केवल अज्ञानता-मात्र होगी। किन्तु, जब एक प्रकार की निवेश-पद्धति, दूसरी की तुलना में, प्रारम्भ में विकास की निम्न दर तथा बाद में उच्च दर प्रदान करती है, तभी चुनाव की वास्तविक समस्या उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में किस पद्धति को चुना जाय, यह आर्थिक विश्लेषण के बजाय राजनीतिक विचारों पर निर्भर करता है।

सैद्धान्तिक स्तर पर देखें—डब्लू० फेलनर का पूर्व उद्धृत “दि कैपिटल आउटपुट रेशियो इन डायनमिक इकॉनामिक्स” जे० राविन्सन का पूर्व उद्धृत ‘नोट्स ऑन दि इकॉनामिक्स ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस’; वाई० टाकटा का पूर्व उद्धृत; एस० सुर का अप्रैल 1956 ई० के इकॉनामिक रिव्यू में प्रकाशित “ए नोट ऑन कैपिटल आउटपुट रेशियोज़”। आनुभविक आधार पर देखें—जून 1953 के “हारवर्ड इकॉनामिक रिसर्च प्रोजेक्ट”, एंस्टिटेयूट ऑफ दि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इन्डस्ट्रीज़, 1947; डी० क्रीमर का कैपिटल एंड आउटपुट ट्रेंड्स इन मैनफैक्चरिंग इन्डस्ट्रीज़ 1880-1948 (नेशनल बुरो आफ इकॉनामिक रिसर्च का 41वां कदाचित्क पेपर, 1947), एम० शिनोरा का अक्टूबर, 1956 के इकॉनामिक रिव्यू में प्रकाशित ‘दि डिफरेंस आफ कैपिटल आउटपुट रेशियोज़ एंमॉग

केवल उन प्रभावों का वर्णन करेंगे, जो पूँजी प्रयोग करने वाले तकनीकों को अपनाना अव्यवहार्य करना अनिवार्य बनाने हैं और इस प्रकार पूँजी-निपज अनुपात को बढ़ाने हैं। इसके विपरीत वाले प्रभावों को पाठकों के अनुमान के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि, यहाँ हम लोग मुख्यतः इस बात से सम्बद्ध हैं कि स्थायी निवेश अथवा वचन अनुपात के दिये हुए रहने पर आर्थिक विकास को सीमित करने वाले कारण के रूप में हमें उच्च पूँजी-निपज अनुपात को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए।

आगे की व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में अनावश्यक उच्च पूँजी-निपज अनुपात का एक मौलिक कारण पूँजी-गहनता की निम्न मात्रा है, जो दिये हुए श्रम की तुलना में पूँजी से प्राप्त निपज को अधिक अनुपात में घटा देता है। दूसरे शब्दों में, श्रम की तुलना में पूँजी की मितव्ययिता (कम चमत्कार) के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप एक दी हुई निपज को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक पूँजी की मात्रा में विरोधाभासी तरीके से वृद्धि होती है। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, यह विरोधाभास इस सम्भावना का परिणाम है कि श्रम की प्रति इकाई पूँजी (K/N) में ह्रास पूँजी-निपज अनुपात (K/Y) को घटाने के बजाय बढ़ा सकता है, यदि, जैसा कि समीकरण (11') से स्पष्ट है, श्रम की प्रति इकाई पूँजी में यह ह्रास श्रम की उत्पादकता में अनुपात से अधिक कमी उत्पन्न करता है। जोन रॉबिन्सन इसके लिए एक दूसरा कारण बतलाती हैं जो इस प्रकार है: "जहाँ साहसी एक दूसरे में पूँजीगत मान घरीदते हैं, मजदूरी-दर की तुलना में पूँजीगत वस्तुओं के मूल्य में कमी से पूँजी-प्रयोग के तकनीकों को अपनाने में प्रोत्साहन मिलता है।" यह उन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए विशेष महत्त्व का होता है, जो मुख्यतः आयात किए गए उपकरणों तथा कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती हैं तथा जिनमें बड़े समाकलित उद्योगों का अभाव रहता है, जिनके लिए साधनों के मूल्य से बहुत कम अन्तर होना है, और पूँजीगत वस्तुओं के मूल्य में अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के अनुकूल ह्रास होगा। ऐसा केवल इसलिये नहीं कि पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादकों एवं निर्यातकों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिযোগिता से इनके मूल्य में कमी होगी, वरन् इसलिए भी कि जनसंख्या में आंतरिक वृद्धि मजदूरी की औसत दर पर अधोमुखी दबाव डालती है। यही परम्परागत विश्लेषण प्रासंगिक हो जाता है। पूँजी-श्रम अनुपात को आश्रित परिवर्तों के रूप में निम्न तरीके पर विचारें।

इन्डस्ट्रीज'; वाई० ओकजेकी का मार्च, 1957 के 'इकॉनॉमिक स्टडीज क्वाटर्लीज' में 'ऑन दि कैपिटल को-एफिशियन्ट इन अडर-डेवलप्ड कंट्रीज विथ स्पेशल रेफरेंस टू दि केसेज आफ इण्डिया एंड जापान'।

देखें उनकी पुस्तक दि रेट ऑफ इंटरेस्ट, एटसेट्रा, पृष्ठ 52-3।

$$\frac{K}{N} = f\left(\frac{P_k}{P_n}\right), \quad (12')$$

जिसमें P_k पूंजी का औसत मूल्य (कुछ परिभाषा के आधार पर) और P_n श्रम का औसत मूल्य (मौद्रिक मजदूरी की दर) हैं। तब श्रम के रूप पूंजी में प्रति-स्थापन की लोच को निम्नलिखित सामान्य रूप में व्यक्त किया जा सकता है :

$$e = \frac{P_k/P_n}{K/N} \cdot \frac{d(K/N)}{d(P_k/P_n)} = \frac{d(K/N)}{d(P_k/P_n)} \bigg/ \frac{K/N}{P_k/P_n} \Rightarrow 1, \quad (13')$$

इसमें e लोच गुणक को सूचित करता है, जो इस सुविधा की मात्रा को मापता है, जिससे साधनों के सापेक्ष मूल्य में परिवर्तन के प्रतिवचन में श्रम के बदले पूंजी का प्रतिस्थापन किया जा सकता है। यदि श्रम की उत्पादकता को स्थिर मान लिया जाय, तो समीकरण (11') के योग से समीकरण (12') एवं (13') यह सूचित करते हैं कि $e = 1$ स्थायी पूंजी-निपज अनुपात, $e > 1$ वर्णनाधीन उच्च पूंजी-निपज अनुपात तथा $e < 1$ निम्न पूंजी-निपज अनुपात के लिए उत्तरदायी हैं। जहाँ तक स्वयं साधनों के मूल्य में परिवर्तन का सम्बन्ध है, ये पूंजी एवं श्रम के सापेक्ष अभाव, पूंजी एवं श्रम बाजार के संगठन, संगठित पूंजी एवं श्रम की शक्तियों की तुलनात्मक सौदा-शक्ति तथा संभवतः उत्पादक साधनों के बीच दी हुई राष्ट्रीय आय के वितरण के सम्बन्ध में सार्वजनिक नीति पर निर्भर करता है।

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में साधारणतया उच्च पूंजी-निपज अनुपात का एक अन्य संभावित कारण औद्योगीकरण की प्रारम्भिक स्थिति में टिकाऊ विकास पूंजी—जैसे इस्पात, बिजली, जहाज-निर्माण तथा अन्य पूंजी-उपयोग-सम्बन्धी कार्यों की संरचनात्मक आवश्यकता है। इसका परिणाम यह होता है कि नयी अर्थ-व्यवस्थाओं में पूंजी-उपयोग की तकनीकी प्रगति की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा अंशतः इसलिए होता है कि ये अर्थ-व्यवस्थाएँ अभी तक परिपक्व स्थिति तक नहीं पहुँच पाई हैं, जहाँ पर वैज्ञानिक प्रवृद्ध (प्रवृद्ध एवं व्यवस्था-सम्बन्धी) एवं अन्य पूंजी बचाने वाली प्रगति तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है। साथ ही, कृषि-क्षेत्र में व्यापक उन्नति के लिए भी, जैसा कि तीव्र गति से उन्नति करने वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है, स्पष्टतया प्रति इकाई कृषि-निपज के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है।

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में पूंजी-निपज अनुपात की प्रवृत्ति के इतना उच्च होने का एक अन्य प्रधान कारण व्याज की उच्च दर है। यह कुछ विरोधाभासी जान पड़ सकता है, क्योंकि सामान्य ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि उच्च व्याज की दर

उत्पादन की प्रक्रिया में पूँजी के प्रयोग को हतोत्साहित करता है और इस प्रकार पूँजी-निपज अनुपात को कम करने का प्रयास करता है। किन्तु पुनर्विचार करने पर यह दिखावटी विरोधाभास समाप्त हो जाएगा। ब्याज की उच्च दर में श्रम की तुलना में पूँजी के प्रयोग को हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है (निम्न K/N) ; क्योंकि यह वर्तमान परिस्थिति के पूँजीगत मूल्य को नयी परिसंपत्ति के सम्भावित पूर्ति मूल्य की तुलना में कम कर देती है और इस प्रकार पहले की अपेक्षा बाद वाली परिसंपत्ति को अधिक मूल्यवान् एवं कम आकर्षक बना देती है। केन्स की प्रचलित शब्दावली में, इसका अर्थ यह है कि पूँजी की सीमांत क्षमता (शुद्ध लाभ की दर) बाजार की ब्याज दर से निम्न है जिससे यह स्टॉक, ऋण-पत्र एवं अन्य वर्तमान परिसंपत्ति में वित्तीय निवेश की तुलना में टिकाऊ उपकरणों में वास्तविक निवेश को हतोत्साहित करता है। मुद्दम बात यह है कि यदि ब्याज की प्रचलित उच्च दर से उत्पादन का चक्रदार तरीका हतोत्साहित होता है (यानी K/N निम्न होता है) तो पूँजी की तुलना में निपज में संभवतः अधिक अनुपात में ह्रास होगा, जिससे समीकरण (11') के अनुसार पूँजी-निपज अनुपात बढ़ जाएगा। इस प्रकार ब्याज की निरन्तर उँची दर की संभावना में कम पूँजी-प्रधान (या अधिक श्रम-प्रधान) तकनीकों को प्रोत्साहित करने तथा मजदूरी एवं शुद्ध लाभ की दी हुई स्थायी दर होने पर निपज पर बाद वाले घटते हुए दबाव के कारण उच्च पूँजी-निपज अनुपात के निर्माण की प्रवृत्ति पाई जाती है।

अतः एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में निपज की बतावट तथा नये उद्योगों के आकार एवं स्थिति का भी उच्च पूँजी-निपज अनुपात पर कुछ प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हस्त-निर्मित वस्तुओं की तुलना में यंत्र-निर्मित वस्तुओं को अधिक पसंद किया जाता है, तो निपज में बनावट में इस प्रकार परिवर्तन होगा, जिससे प्रति इकाई निपज से अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही, यदि नये यंत्र तथा उद्यमों के आकार में वृद्धि होती है, किन्तु ये कच्चे पदार्थों के साधनों (जो अधिकांशतः विदेशों में पाये जाते हैं) से बहुत दूर स्थित हों, तो अतिरिक्त वास्तविक निपज की तुलना में पूँजीगत लागत में वृद्धि होगी, जिसके साथ संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए पूँजी-निपज अनुपात में वृद्धि होगी।

अध्याय 6

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में दोहरी बेरोज़गारी

केन्स के रोज़गार के सामान्य सिद्धान्त में व्यापकता का अभाव है; क्योंकि यह उस प्रकार की बेरोज़गारी पर विचार नहीं करता, जो पूर्ण प्रयोग के बाद भी वास्तविक पूँजी के अभाव के कारण वर्तमान रहती है, यानी जो पूँजी के वर्तमान कोप के पूर्ण प्रयोग के लिए समर्थ माँग की पर्याप्तता के बाद भी पाई जाती है। उसका रोज़गार का सिद्धान्त अल्पकालीन स्थिति में लागू होता है, जिसमें पूँजी-संचय, जनसंख्या की वृद्धि, तकनीकी प्रगति तथा पूर्ति की अन्य आधारभूत शक्तें दी हुई मान ली जाती हैं और इसलिए उस रोज़गार की मात्रा अनन्य रूप से समर्थ माँग के स्तर द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार, केन्स का सिद्धान्त केवल समर्थ माँग को स्थायी बनाने अथवा बढ़ाने के उद्देश्य से पिरामिड-निर्माण की तरह अनुत्पादक रोज़गार की नीति को युक्तिसंगत ठहराने में प्रयुक्त होने का खतरा मोल लेता है।

इसी केन्सीय पृष्ठभूमि में हैरोड रोज़गार के स्थायित्व पर विचार करने में उत्पादकता के दीर्घकालीन महत्त्व पर जोर देते हैं। इनके अनुसार 'सतत विकास की दर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बातों पर ध्यान दिये वगैर अल्पकाल में पूर्ण रोज़गार प्राप्त करना अदूरदर्शिता है।'¹ केन्स के रोज़गार के अल्पकालीन सिद्धान्त तथा मार्क्स के रोज़गार के दीर्घकालीन सिद्धान्त के बीच लुप्त कड़ी प्रदान करने का श्रेय हैरोड को दिया जाता है। क्योंकि, जैसा कि जोन राँबिन्सन का कहना है कि 'यद्यपि कि उनका यह विल्कुल विचार नहीं है, तथापि हैरोड हमें मार्क्स के श्रम की आरक्षित सेना की ओर ले जाते हैं, जो पूँजी-संचय की दर की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि एवं कमी के अनुसार बढ़ती अथवा घटती है।'² इस अन्तिम प्रकार को इन्होंने 'केन्सीय बेरोज़गारी' के विपरीत "मार्क्सियन बेरोज़गारी" का नाम दिया है।³ जोन राँबिन्सन ने

1. आर० एफ० हैरोड, डायनमिक इकॉनामिक्स, पृ० 74।

2. जे० राँबिन्सन, मि० हैरोड्स डायनमिक्स, पूर्व उद्धृत।

3. पूर्व उद्धृत।

यह भी सुभाव दिया है कि "माविसयन बेरोजगारी उस प्रकार की बेरोजगारी है, जो प्रारंभ के पिछड़े हुए एवं जनाधिक्यवाले देशों तथा युद्ध-विनष्ट अर्थ-व्यवस्थाओं में जहाँ केवल काम करने के लिए साधनों एवं सामानों के अभाव में बेरोजगारी पाई जाती है, वर्तमान रहती है।"¹

इस प्रकार केन्स का रोजगार सिद्धान्त, विचनन का वह केन्द्रीय बिन्दु प्रदान करता है, जहाँ से रिकार्डों के स्वतः पूर्ण रोजगार ('थ' ल से के नियम')² विश्व की आलोचना की जा सकती है तथा माल्यस एवं मार्क्स के जनाधिक्य वाले विश्व और थम की आरक्षित सेना³ की धारणा पर विचार किया जा सकता है। साथ ही, केन्स के बेरोज-

1. देखें 'क्लेवटेड इकॉनामिक पेपर्स' में इनका निबन्ध 'मार्क्स एन्ड केन्स' पृ० 133-145।
2. केन्स के रोजगार के सिद्धान्त को पिकासोन्मुख एवं उन्नतशील अर्थ-व्यवस्था के लिए लागू करने के प्रयास के लिए देखें, हैरोड का 'डायनमिक इकॉनामिक्स'; डोमर का पूर्व उद्धृत 'एक्सपेन्शन एंड एम्प्लायमेंट'; जोन रॉबिन्सन का 'द रेट ऑफ इन्टरेस्ट एटसेस्ट्रा', विशेषतः तृतीय अध्याय 'दि जेनरलाइजेशन ऑफ द जेनरल थियरी', एम० कालेकी का 'राईनहर्ट', न्यूयार्क 1954 का 'थियरी ऑफ इकॉनामिक डायनामिक्स', विशेषतः छठा भाग, बी० हिगीन्स का जून 1950 के 'इकॉनामिक जर्नल' में 'द थियरी ऑफ इन्वैजिग अन्डर इम्प्लायमेंट'; आर० आइनर का पूर्व उद्धृत 'अन्डर इम्प्लायमेंट रेट्स ऑफ ग्रोथ', डी० हैम्बर्ग का अगस्त 1952 ई० के 'क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकॉनामिक्स' में 'फुल कॅपेसिटी वॉर्ल्ड फुल एम्प्लायमेंट ग्रोथ'; एच० पिलवीन का 'फुल कॅपेसिटी वॉर्ल्ड फुल एम्प्लायमेंट ग्रोथ' एच० पिलवीन का 'फुल कॅपेसिटी वॉर्ल्ड फुल एम्प्लायमेंट ग्रोथ' 'उसी स्थान में नवम्बर 1953 ई० (हैरोड एवं डोमर की टिप्पणी के साथ)।
3. अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से सम्बद्ध निम्नलिखित है—जोन रॉबिन्सन का अक्टूबर, 1955 का इकॉनामिक रिव्यू (जापान) में प्रकाशित 'ए थियरी ऑफ लॉन्ग-रन डेवलपमेंट' तथा 23 जून, 1956 ई० के इकॉनामिक थोकली (भारत) में प्रकाशित 'द वायस ऑफ टेक्नीक'; आर० नक्वे, प्रोग्रेस ऑफ कॅपिटल फॉरमेशन इन अन्डरडेवलप्ड इकॉनामिक्स; ए० एन्ड डी आई० एम० नवारेटे का 1953 के न० 3 इन्टरनेशनल इकॉनामिक पेपर्स में 'अन्डर एम्प्लायमेंट इन अन्डरडेवलप्ड इकॉनामिक्स; स्टडीज इन ग्रोथ इकॉनामिक्स (वाई० ताकता द्वारा सम्पादित) में एम० मोरिथिमा का 'फुल एम्प्लायमेंट पॉलिमी इन ए ग्रोइंग इकॉनामी' तथा एस० फूजीता का 'ग्रोथ थियरी एन्ड सुपरप्लस पापुलेशन'; 4 अगस्त, 1956 के इकॉनामिक थोकली में डि० थोप का 'टेक्नीक ऑफ प्रोडक्शन

गार के सिद्धान्त को अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए विल्कुल अप्रयोज्य कहकर टाल देना गलत होगा। ऐसा केवल इसलिए नहीं होगा कि अल्पकाल मिलकर केन्स के उस दीर्घकाल का सर्जन करते हैं, जिसमें 'हम सभी मर जाते हैं', वरन् मूलतः इसलिए कि मुख्य रूप से निजी व्यवसाय पर संचालित अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ समर्थ माँग की चक्रीय अभाव की सम्भावनाओं से मुक्त नहीं हो सकतीं दीर्घकालीन गैर-केन्सीयन बेरोज़गारी के साथ-साथ अल्पकालीन केन्सीयन बेरोज़गारी की उपस्थिति से अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की पूर्ण रोज़गार-सम्बन्धी नीति बहुत ही जटिल हो जाती है; क्योंकि पहले को दूर करने के लिए अल्पकालीन उपाय आवश्यक रूप से बादवाले दीर्घकालीन उपायों को दूर करने के लिए अनुरूप नहीं होते।

वर्तमान अध्याय का सम्बन्ध व्यापकतया अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में बेरोज़गारी की दुहरी प्रकृति से है। इसका सम्बन्ध अधिक विशिष्ट रूप से (क) केन्सीयन बेरोज़गारी की चक्रीय वृद्धि तथा (ख) गैर-केन्सीयन बेरोज़गारी की दीर्घकालीन वृद्धि से है। दोनों हालतों में पूर्ण एवं उत्पादक रोज़गार के लिए प्राचलीय कार्यक्रम पर भी विचार किया जायगा। छिपी हुई बेरोज़गारी के सम्बन्ध में भी पश्च-लेख के रूप में कुछ टिप्पणी की जाएगी।

केन्सीयन बेरोज़गारी की चक्रीय वृद्धि

पूँजीवादी प्रकृतिवालो अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था अपने विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम की अल्पकालीन परिधि (उदाहरण के लिए पाँच वर्ष) के अन्तर्गत केन्स द्वारा वर्णित चक्रीय बेरोज़गारी का अनुभव करती है। क्योंकि, इसकी समर्थ माँग यद्यपि यह दीर्घकाल में उत्पादन-क्षमता से बढ़ जाती है, तथापि अल्पकाल में उत्पादन-क्षमता से कम पड़ सकती है। इस प्रकार की सम्भावना ऐसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में, जिनकी नियति-सम्बन्धी आय तथा निजी निवेश-परिमाणात्मक रूप में इनकी कुल समर्थ माँग का प्रधान साधन होते हैं—विशेष रूप से पाई जाती है। केन्स के बेरोज़गारी-सम्बन्धी विश्लेषण की संवद्धता एवं अल्पविकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में केन्स की पूर्ण रोज़गार-सम्बन्धी नीति की विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए हम पहले बड़ी संख्या में अनैच्छिक बेरोज़गारी में चक्रीय वृद्धि के वर्णन से प्रारम्भ करेंगे।

श्रम की पूर्ति

यदि जनसंख्या, तकनीक एवं साधनों के मूल्यों को दिया हुआ मान लिया जाय,

एन्ड एम्प्लायमेन्ट इन एन अन्डरडेवलप्ड इकॉनामी; अगस्त, 25, 1956 के उसी में ए० के० दास गुप्ता का 'डिसगाइज्ड अनइम्प्लायमेन्ट एन्ड इकॉनामिक डेवलपमेन्ट, के० के० कुरीहारा का पूर्व उद्धृत 'थ्रय एनेलेसिस् एन्ड द प्रोब्लम ऑफ कैपिटल एकमुलेशन इन अन्डरडेवलप्ड कन्ट्रीज'।

तो इस प्रकार की मान्यता सम्भव होगी कि सदा इतनी मात्रा में श्रम वर्तमान रहता है, जिससे कि पूँजी के वर्तमान कोष को पूर्ण रूप से प्रयुक्त किया जा सके। हमारे शब्दों में, हम यह मानते हैं कि श्रम की पूर्ति में उसी दर से वृद्धि होती है, जिस दर से पूँजी के वर्तमान कोष को पूर्ण रूप से एवं सतत प्रयोग के लिए श्रम की आवश्यकता पड़ती है। जब हम लोग सरचनात्मक बेरोजगारी की प्रकृति एवं उद्भव का अध्ययन प्रारम्भ करेंगे, तो यह मान्यता समाप्त हो जायगी। यथार्थता के लिए हम मानते हैं कि निम्नलिखित शर्तें सदा पूरी होती हैं—

$$N = Nr, \quad \Delta N = \Delta Nr, \quad (1)$$

जिनमें N उपलब्ध श्रम की मात्रा है, जो जनसंख्या की वृद्धि के द्वारा शासित होती है तथा Nr पूँजी के वर्तमान कोष को पूर्ण रूप से प्रयोग करने के लिए अपेक्षित श्रम की मात्रा है। (1) द्वारा दी गई शर्तें यदि पूरी हो जायें, तो वे इस बात का विश्वास दिलाती हैं कि श्रम का अभाव पूँजी के पूर्ण प्रयोग में कभी रुकावट नहीं उत्पन्न कर सकता। वे इस बात की ओर भी संकेत करती हैं कि यदि पूँजी का वर्तमान कोष पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं होता है, यानी यदि बेकार अथवा अधिक क्षमता वर्तमान है, तो यह समर्थ माँग की अपर्याप्तता के कारण है। इस प्रकार यदि मान लिया जाय कि श्रम की पूर्ति अपने को श्रम की किसी भी माँग के अनुरूप बना लेती है, तो केन्सीयन बेरोजगारी की उपस्थिति की व्याख्या माँग की परिस्थितियों के सन्दर्भ में की जा सकती है। यहाँ अपेक्षित श्रम की माँग एवं वास्तविक श्रम की माँग में स्पष्ट रूप से अन्तर करना अनिवार्य है। इनमें पहले प्रकार की माँग पर पहले विचार कर लिया जाय।

अपेक्षित श्रम की माँग

यदि समर्थ माँग (सम्पूर्ण निपज के लिए) को इतना अधिक मान लिया जाय, जो पूँजी के वर्तमान कोष के पूर्ण प्रयोग को आवश्यक बना देती है, तो उस पूर्ण प्रयोग के लिए आवश्यक श्रम की मात्रा निम्नांकित रूप से दी जाती है :

$$Nr = \beta K, \quad (2)$$

जिसमें K पूर्ण प्रयोग के बाद वास्तविक पूँजी की मात्रा है तथा β टेक्नोलॉजी की वर्तमान स्थिति द्वारा दी हुई श्रम की गहनता का गुणांक (पूर्ववर्णित पूँजी-श्रम अनुपात का व्युत्क्रम) है। समीकरण (2) पूँजी के वर्तमान कोष के पूर्ण प्रयोग से उपलब्ध बेरोजगार की अधिकतम सम्भाव्य मात्रा को बतलाता है।

हम जानते हैं कि पूँजी एवं निपज निम्न रूप से सम्बद्ध है :

$$K = bY', \quad (3)$$

जिसमें Y' पूर्ण क्षमता-निपज तथा b औसत तथा सीमान्त पूँजी निपज

अनुपात हैं। हम लोग यह भी जानते हैं कि शुद्ध निवेश (1) अतिरिक्त पूंजी (ΔK) के बराबर है और साम्य की स्थिति में वचत के बराबर होता है, यानी

$$I = \Delta K = sY', \quad (4)$$

जिसमें s पूर्ण क्षमता निपज पर वचत की औसत क्षमता है।

(3) एवं (4) से पूर्ण नियुक्त पूंजी में वृद्धि प्राप्त होती है :

$$\Delta K = \frac{s}{b} K, \quad (5)$$

जिससे पूर्ण नियुक्त पूंजी में वृद्धि की दर प्राप्त होती है (यानी, इस समीकरण के दोनों पक्षों को K से भाग देने पर)

$$\frac{\Delta K}{K} = \frac{s}{b}, \quad (6)$$

समीकरण (2) एवं (6) को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपेक्षित, श्रम में वृद्धि की दर को निम्नांकित प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं :

$$\frac{\Delta Nr}{Nr} = \frac{\beta \Delta K}{Nr} = \frac{\beta \Delta K}{\beta K} = \frac{\Delta K}{K} = \frac{s}{b} \quad (7)$$

जो यह बतलाता है कि अपेक्षित श्रम की मात्रा में पूर्ण नियुक्त पूंजी में वृद्धि की दर के बराबर दर, यानी s/b की दर से वृद्धि हो सकती है। यदि s/b स्थायी है, तो समीकरण (7) पूर्ण क्षमता वृद्धि के अनुरूप प्रगतिशील पूर्ण रोज़गार के एक स्थायी क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। किन्तु, वास्तविक रोज़गार पूर्ण रोज़गार के इस स्थायी क्रम पर होगा या नहीं, यह श्रम की पूर्ति की लोच, जिसे हम लोग वर्तमान समय में अनन्त मानते हैं, पर निर्भर नहीं करके, समर्थ माँग, जिसे हम लोग दिया हुआ मानते हैं, के आचरण पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर हमें वास्तविक श्रम की माँग के निर्धारण को देखना चाहिए।

वास्तविक श्रम की माँग

श्रम को सज्जित करने के लिए वास्तविक पूंजी के कोप के दिया हुआ होने पर, वास्तविक नियुक्त श्रम की मात्रा समर्थ माँग का फलन है, यानी—

$$Ne = \epsilon Y^o, \quad (8)$$

जिसमें Ne वास्तविक राष्ट्रीय आय या समर्थ माँग की अनुक्रिया में माँगी जाने वाली वास्तविक श्रम की मात्रा है, Y^o वास्तविक राष्ट्रीय आय या समर्थ माँग के स्तर तथा ϵ समर्थ माँग की तुलना में नियुक्त श्रम का टेक्नोलॉजी द्वारा दिया गया अनुपात है।

केन्स के गुणक सिद्धान्त से हम लोग यह जानने हैं कि समर्थ माँग निम्नांकित मात्रा से परिवर्तित हो सकता है :

$$\Delta Y^o = \frac{I}{s'} \Delta I, \quad (9)$$

जिसमें ΔI वार्षिक शब्दों में अपूर्वानुमेय निजी निवेश एवं पूर्ववर्णित विदेशी ऋण को सम्मिलित करते हुए स्वतन्त्र निवेश गुणक तथा s' बचत की सीमात प्रवृत्ति है। यहाँ पर I/s' गुणक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ बचत की सीमान्त प्रवृत्ति (s') समीकरण (4)-(7) में पाई जाने वाली बचत की औसत प्रवृत्ति (s) की तरह स्थायी नहीं है।

यदि हम लोग अतिरिक्त निवेश को निश्चित रूप से समर्थ माँग से सम्बद्ध मानते हैं, तो हमें निम्नांकित प्राप्त हो सकता है—

$$v = \frac{\Delta I}{Y^o}, \quad (10)$$

जिसमें v समर्थ माँग एवं वृद्धिशील निवेश का अनुपात है और उतना ही अस्थायी हो सकता है जितना कि स्वतन्त्र निवेश को प्रभावित करने वाले तत्त्व परिवर्तनीय हैं (सार्वजनिक निवेश को छोड़कर)।

समीकरण (9) एवं (10) से समर्थ माँग में वृद्धि की निम्नांकित दर प्राप्त होती है :

$$\frac{\Delta Y^o}{Y^o} = \frac{I}{s'} v = \frac{v}{s'}, \quad (11)$$

जो दर चक्रीयता उतना ही परिवर्तनीय है, जितना कि उसके निर्धारक (s' , v) अस्थायी है।

समीकरण (9) एवं (11) को ध्यान में रखते हुए वास्तविक थम में वृद्धि की दर को निम्नांकित तरीके से लिखा जा सकता है :

$$\frac{\Delta Ne}{Ne} = \frac{\epsilon \Delta Y^o}{Ne} = \frac{\epsilon \Delta Y^o}{\epsilon Y^o} = \frac{\Delta Y^o}{Y^o} = \frac{v}{s'}, \quad (12)$$

जो यह बतलाता है कि मांगी हुई वास्तविक थम की माँग v/s' की दर से बढ़ सकती है, यानी यदि वास्तविक थम एवं समर्थ माँग का अनुपात (ϵ) स्थायी हो, तो यह माँग में वृद्धि की दर से ही बढ़ेगी।

केन्सीयन बेरोज़गारी की वृद्धि

पूर्ववर्ती विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि केन्स के अर्थ में पूर्ण रोज़गार को बनाये रखने के लिए आवश्यक शर्तें निम्नांकित के द्वारा व्यक्त की जाती हैं—

$$\frac{\Delta K}{K} = \frac{\Delta Y^o}{Y^o}, \quad \frac{s}{d} = \frac{v}{s'}, \quad (13)$$

किन्तु यदि निजी निवेश अथवा निर्यात से प्राप्त आय (v के द्वारा व्यक्त) में अस्थायी ह्रास के कारण पूँजी का आधिक्य, अथवा समर्थ माँग की कमी उत्पन्न हो जाती है, तो अपेक्षित श्रम एवं माँगे जाने वाले वास्तविक श्रम में असंगति उत्पन्न होगी। क्योंकि, जैसा पहले वर्णन किया जा चुका है, चक्रीय बेरोज़गारी की माप पूँजी की वर्तमान कोप के पूर्ण प्रयोग से प्राप्त पूर्ण रोज़गार एवं वास्तविक रोज़गार, जिसे समर्थ माँग का वर्तमान स्तर सम्भव बनाता है। से होती है, अतएव, वर्तमान गतिशील सन्दर्भ में केन्सीयन बेरोज़गारी को निम्नांकित रूप में व्यक्त किया जा सकता है :

$$\frac{\Delta U^o}{U^o} = \frac{\Delta Nr}{Nr} - \frac{\Delta N^e}{N^e} = \frac{s}{b} - \frac{v}{s'}, \quad (14)$$

जिसमें $\frac{\Delta U^o}{U^o}$ माँग (सम्पूर्ण निपज के लिए) में वृद्धि की दर से पूँजी की वृद्धि की दर में आधिक्य के परिणामस्वरूप केन्सीयन बेरोज़गारी में वृद्धि की दर है और जिसमें सिरनामा c संलग्न बेरोज़गारी की समस्या की चक्रीय प्रकृति को व्यक्त करता है। समीकरण (14) के द्वारा व्यक्त केन्सीयन बेरोज़गारी की वृद्धि पूर्ण क्षमता की वृद्धि के अनुरूप प्रगतिशील पूर्ण रोज़गार की स्थिर रेखा से चक्रीय विचलन (निम्नगामी) की मात्रा को मापता है। यह विकसित अथवा अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में पूँजीवाद के चक्रीय विकास को स्पष्ट करता है। फिर भी, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में, जो समीकरण (13) में दिये हुए सन्तुलन की शर्तों की पूर्ति का प्रयास करती है, ऐसे तरीकों, जो संरचनात्मक बेरोज़गारी की अधिक गम्भीर एवं मौलिक समस्या के समाधान के दीर्घकालीन उद्देश्यों को समाप्त कर दें, को नहीं अपनाये जाने के लिए कठोर दबाव पड़ता है। इस अपवाद को ध्यान में रखकर अब हम लोग मध्यम एवं दीर्घकालीन पूर्ण एवं उत्पादक रोज़गार के लिए परिचालन-सम्बन्धी सम्भावनाओं की संक्षेप में खोज करें।

केन्सीयन बेरोज़गारी को दूर करने के लिए प्राचलीय संक्रिया

वचत की, सीमान्त क्षमता (s') को, पूर्व निश्चित वचत की आदतों को व्यक्त करने वाले स्थायी प्राचल मानते हुए केन्स ने स्वतन्त्र निवेश (v द्वारा व्यक्त) को परिवर्ती नीति-प्राचल माना है। किन्तु, वर्तमान सन्दर्भ में नीति के कुशल प्रयोग के क्षेत्र के विस्तार के लिए हम v एवं s' दोनों को परिवर्ती नीति-प्राचल मानेंगे। साथ ही,

केन्सीयन बेरोजगारी से पीड़ित अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए उपलब्ध वैकल्पिक मार्ग को देखने के लिए v एवं s' को अलग-अलग करना अनिवार्य है।

अतिरिक्त स्वतन्त्र निवेश एवं समर्थ माँग के अनुपात को हम लोग निम्नांकित प्रकार से अलग-अलग कर सकते हैं—

$$v = \frac{\Delta I_p + \Delta I_g + \Delta E}{Y^o} = \frac{\Delta I_p}{Y^o} + \frac{\Delta I_g}{Y^o} + \frac{\Delta E}{Y^o} = v_p + v_g + v_e \quad (15)$$

जिसमें I_p आन्तरिक निजी निवेश, I_g सरकारी निवेश, E निर्यात-सम्बन्धी आय, तथा v_p , v_g एवं v_e क्रमशः $\Delta I_p/Y^o$, $\Delta I_g/Y^o$, तथा $\Delta E/Y^o$ को सूचित करते हैं। समीकरण (15) तीन निवेश नीति-प्राचल प्रदान करता है, जिससे हम लोग गुणक की प्रक्रिया के लीवर पक्ष की क्रिया का संचालन कर सकते हैं।

इस प्रकार, वचत की सीमान्त प्रवृत्ति को भी निम्न प्रकार से पृथक् किया जा सकता है :

$$s' = \frac{\Delta S_p + \Delta S_g + \Delta M}{\Delta Y^o} = \frac{\Delta S_p}{\Delta Y^o} + \frac{\Delta S_g}{\Delta Y^o} + \frac{\Delta M}{\Delta Y^o} = s'_p + s'_g + m, \quad (16)$$

जिसमें S_p निजी बचत, S_g राजकीय बचत (यानी बजट का आधिक्य), M आयात-सम्बन्धी व्यय, s'_p निजी बचत की सीमान्त क्षमता, s'_g राजकीय बचत की सीमान्त क्षमता एवं M आयात की सीमान्त क्षमता है। समीकरण (16) गुणक प्रक्रिया के क्षरण-पक्ष की क्रिया-संचालन के लिए तीन बचत-प्राचल देता है।

(15) एवं (16) को ध्यान में रखते हुए समीकरण (11) को निम्नांकित प्रकार से पुनः लिखा जा सकता है—

$$\frac{\Delta Y^o}{Y^o} = \frac{v}{s'} = \frac{v_p + v_g + v_e}{s'_p + s'_g + m} \quad (17)$$

केन्सीयन बेरोजगारी को दूर करने लिए यह दीर्घकालीन आवश्यकता कि s/b की स्वामी दर पर पूँजी की वृद्धि को मध्यम एवं दीर्घकालीन उपायों के द्वारा निविघ्न छोड़ देना चाहिए, यहाँ सम्भावित प्राचलीय प्रक्रिया पर कुछ प्रतिबन्ध लगा देती है। सर्वप्रथम तो सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए वचत की सीमान्त क्षमता (s') को केवल स्थायी तौर पर गुणक को बढ़ाने के लिए घटाया नहीं जा सकता; क्योंकि s' में कमी से s आत्मघाती ह्रास हो सकता है और इसीलिए पूर्ण नियुक्त पूँजी में वृद्धि की दर में भी कमी हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि s' के अवयवों को इस प्रकार जोड़-मोड़ करना चाहिए, जिससे सम्पूर्ण s' स्थिर रहे तथा वास्तविक भार लीवर-पक्ष

पर पड़े। यदि s' को स्थिर रहना है, तो निजी वचत की सीमान्त-क्षमता $(s'p)$, राजकीय वचत की सीमान्त क्षमता $(s'o)$ एवं आयात की सीमान्त क्षमता (m) प्रत्येक को दूसरे में वृद्धि की मात्रा के बराबर से कम करना होगा। अब s' के विभिन्न अवयवों में किसको कम किया जाय, यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसका निर्णय दीर्घकालीन उत्पादन-क्षमता में न्यूनतम क्षति को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा।

जहाँ तक लीवर-पक्ष का सम्बन्ध है, उपर्युक्त आवश्यकता का तात्पर्य यह है कि v के किसी भी अवयव की उत्पादकता एवं इसके आय-उत्पादक प्रभाव को निश्चित रूप से ध्यान में रखना होगा। अतएव, समर्थ माँग एवं अतिरिक्त निवेश के कुल अनुपात में v_p , v_o एवं v_e के उत्पादकता-प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इनमें एक साथ वृद्धि के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, पिरामिड-निर्माण के प्रकार के निवेश को प्रत्येक परिस्थिति में अवश्य ही ढालना होगा। अन्यथा शुद्ध निवेश की उत्पादकता में कमी के परिणामस्वरूप पूँजी-निपज अनुपात (b) में वृद्धि होगी, जिससे पूँजी की वृद्धि को अविकल रखने का दीर्घकालीन उद्देश्य विफल हो जायगा। किन्तु, व्यावहारिक नीति के रूप में v_e प्राचल सुगमतापूर्वक आन्तरिक नीति-निर्धारण में सहायक नहीं होता; क्योंकि यह प्रधानतः विदेशों की आयात की क्षमता पर निर्भर करता है। v_p एवं v_o को दिया जानेवाले सापेक्षभार का निर्धारण b के दीर्घकालीन के प्रतिरूप (यानी इसके व्युत्क्रम σ) एवं जिस हद्द तक अवन्ध नीति को काम योग्य समझा जाता है, सन्दर्भ में किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की अपेक्षा अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में केन्सीयन बेरोजगारी को समाप्त करना अधिक कठिन है। इसका कारण यह है कि विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में पहले से ही पूँजी की वृद्धि की उच्च दर होती है, जिसके परिणामस्वरूप यह अपनी वचत की सीमान्त क्षमता को कम कर सकती है, अथवा अनुत्पादक, किन्तु रोजगार बढ़ानेवाली योजनाओं में निवेश की क्षमता को बढ़ा सकती है। फिर भी उपर्युक्त पृथक्करण-सम्बन्धी विश्लेषण, उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के दीर्घकालीन उद्देश्य में किसी प्रकार की क्षति पहुँचाये बगैर, मध्यम एवं दीर्घकाल में केन्सीयन बेरोजगारी को दूर करने की सम्भावनाओं को बतलाता है।

गैर-केन्सीय बेरोजगारी की दीर्घकालिक वृद्धि

समर्थ माँग के चक्रीय कुव्यवहार के परिणामस्वरूप केन्सीयन बेरोजगारी से बहुत अधिक गम्भीर गैर-केन्सीय तरीके की बेरोजगारी है, जो एक विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था को अल्प-विकसित एवं जनाधिक्यवाली संरचना में निहित है। यह मुख्यतः अनुत्पादक पेशों के रूप में व्यक्त होती है तथा इसे 'छिपी हुई बेरोजगारी' कहा जाता है। यह उसी प्रकार की बेरोजगारी है, जिसे हैरोड के विकास की स्वाभाविक एवं प्रामाणित दरों की सन्निधिलक्षित करती है तथा जिसे जोन रॉबिन्सन

ने 'माक्सियन बेरोजगारी' की सज्ञा दी है। किन्तु, फिर भी, हम लोग इसे 'गैर-केन्सीयन बेरोजगारी' अथवा 'सरचनात्मक बेरोजगारी' कहना अधिक सुबोध समझते हैं। क्योंकि, मार्क्स की 'आरक्षित श्रम-सेना' सम्भव है कि हैरोड एव जोन रॉबिन्सन द्वारा स्वयं¹ वर्णित समान मौलिक परिवर्तनों का परिणाम हो, फिर भी यह ऐतिहासिक तथ्य कि लाभ की दर की तुलना में मजदूरी की दर पर अत्यधिक श्रम-सख्या का घटता हुआ दबाव पूँजी के तीव्र संचयन² को प्रोत्साहित करता है, की आलंकारिक अभिव्यक्ति जान पड़ती है। इससे ऐसा स्पष्ट होता है कि मार्क्स 'आरक्षित श्रम-सेना' को पूँजीवादी विकास की आवश्यक शर्त मानता था, यद्यपि वह सन्निहित श्रम के 'शोषण' पर रोष प्रकट करता था। इसके विपरीत हमारी मौलिक स्थिति यह है कि उत्पादक मानव शक्ति की प्रत्यक्ष बरबादी तथा भारी उद्योगों के बढ़ते सीमान्त कृषि, कुटीर-उद्योग एवं छिपी हुई बेरोजगारी के अन्य धक्कासट्टों को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप गैर-केन्सीयक तरीके की बेरोजगारी के औद्योगीकरण के मार्ग में एक आधारभूत रुकावट है।

इस सामान्य पृष्ठभूमि के साथ, अब हम अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में गैर-केन्सीय बेरोजगारी की प्रकृति एवं उद्भव की जाँच करेंगे। हम उपलब्ध श्रम की पूर्ति, जिसे पिछले खंड में हमने दिया हुआ मान लिया था, के विश्लेषण से प्रारम्भ करेंगे।

1. देखें, इनका पूर्व उद्धृत 'मार्क्स एवं केन्स'।
2. इस मान्यता पर कि लाभ-सम्बन्धी आय से बचाने की सीमांत प्रवृत्ति घनात्मक तथा मजदूरी-सम्बन्धी आय से बचाने की सीमान्त-प्रवृत्ति शून्य या ऋणात्मक है। मार्क्स की 'आरक्षित श्रम-सेना' के औपचारिक मॉडल के रूप में स्पष्ट अथवा अस्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादन के लिए देखें। एस्० सुरु, 'एसेज ऑन मार्क्सियन इकॉनामिक्स' (साईंस काउंसिल ऑफ ज़ापान इकॉनामिक सीरिज (नं० 8) टोकियो, 1956; एन० शिनोहरा, जुलाई, 1954 के 'इकॉनामिक रिव्यू' में 'इकॉनामिक प्रोग्रेस एन्ड प्राइस स्ट्रक्चर'। अनौपचारिक अवलोकन के लिए देखें, नॉफ, न्यू० या० 1948 में प्रकाशित 'दि न्यू इकॉनामिक्स' (एस० ई० हैरिस द्वारा सम्पादित में पी० स्वीजी का 'केन्स, द इकॉनामिस्ट', विशेष रूप से पृ० 107, जहाँ वे लिखते हैं कि 'केन्स बेरोजगारी को पूँजीवादी यन्त्र में एक तकनीकी दोष का लक्षण मानते हैं, जबकि मार्क्स इसे एक अपरिहार्य साधन समझते हैं, जिसके द्वारा पूँजीवादी श्रम-बाजार पर अपना नियन्त्रण कायम करते हैं।' दूसरी ओर जोन रॉबिन्सन इसलिए मार्क्स की आलोचना करती है कि उसने बचाने के सम्बन्ध में निर्णय एवं निवेश के सम्बन्ध में निर्णय के बीच बिलगाव के परिणाम-स्वरूप बेरोजगारी की सम्भावना, जिस पर केन्स ने जोर दिया है, की उपेक्षा की है। (देखें इनका पूर्व उद्धृत 'मार्क्स एवं केन्स'।)

श्रम की पूर्ति

साधनों के सापेक्ष मूल्य एवं समाज का कार्य तथा विश्राम के बीच चुनाव के दिया हुआ होने पर, श्रम की पूर्ति में निम्नांकित मात्रा से वृद्धि होते हुए माना जा सकता है :

$$\Delta N = \alpha \Delta P, \quad (18)$$

जिसमें N पहले की तरह पूर्ति की गई श्रम की मात्रा, P सम्पूर्ण जनसंख्या का आकार तथा α समाज के कार्य तथा विश्राम के अधिमान पर आधारित कार्य की औसत एवं सीमांत प्रवृत्ति हैं ।

इसके बाद हम लोग बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उपलब्ध श्रम के बीच एक निश्चित सम्बन्ध की उपस्थिति मान सकते हैं, यानी—

$$\lambda = \frac{\Delta P}{N}, \quad (19)$$

जिसमें λ को जन्म एवं मृत्यु की प्रचलित दरों तथा सम्भवतः उत्प्रवास की नीति द्वारा स्वतंत्र रूप से पूर्व-निर्धारित माना जा सकता है । बाद में, वर्णित कारणों के चलते यह माना जा सकता है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में उच्च λ होता है ।

समीकरण (18) एवं (19) से हमें श्रम की संख्या में वृद्धि की निम्नलिखित दर प्राप्त होती है :

$$\frac{\Delta N}{N} = \alpha \lambda, \quad (20)$$

जो संरचनात्मक अल्प-बेरोज़गारी की समस्या के पूर्ति-पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है । समीकरण (20) यह बतलाता है कि उपलब्ध श्रम में वृद्धि की दर कार्य की क्षमता (α) में अतिरिक्त जनसंख्या एवं उपलब्ध श्रम के अनुपात (λ) के अनुक्रमानुपाती है । दूसरे शब्दों में, एक वृद्धिशील अर्थ-व्यवस्था में श्रम की पूर्ति सांस्कृतिक रूप से दिये गए प्राचल (α) एवं जनांकिकीय रूप से दिये गये प्राचल (λ) का फलन है ।

पूर्ति-पक्ष में मौलिक कठिनाई यह है कि अधिकांश अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में उपलब्ध श्रम की वृद्धि की दर ($\Delta N/N$) बहुत ऊँची होती है । इसके दो कारण हैं; प्रथमतः, इनकी कुछ जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को कार्य करने के लिए इच्छुक रहने (उच्च α) के अतिरिक्त कोई दूसरा मौलिक विकल्प नहीं होता और द्वितीयतः, इनकी जनांकिकीय संरचना साधारणतया इस प्रकार की होती है जो बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उपलब्ध श्रम का उच्च अनुपात (उच्च λ) प्रदान करती है । सम्भरित श्रम में वृद्धि की यह आनुषंगिक उच्च दर संरचनात्मक बेरोज़गारी अथवा नहीं, यह अभियाचित श्रम की वृद्धि की प्रचलित दर पर निर्भर है । पुनः एक बार हम लोग माँगपक्ष को देखें ।

श्रम की माँग

जहाँ तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, श्रम की माँग के सम्बन्ध में निम्नलिखित दो आधारभूत कठिनाइयों का अनुभव होता है: (क) पूर्ण नियुक्त पूँजी की मद वृद्धि, तथा (ख) औद्योगीकरण की प्रक्रिया प्रति-इकाई निपज के माँग जाने वाले श्रम की मात्रा पर टेक्नोलॉजिकल प्रगति का घटता हुआ प्रभाव।

यदि बढ़ती हुई श्रम-शक्ति को पूर्ण एवं उत्पादक तरीके से रोज़गार प्रदान करना है, तो पूँजी में भी उपलब्ध श्रम में वृद्धि की दर से वृद्धि होनी चाहिए। किन्तु, सभी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में पूँजी में वृद्धि की दर निम्न होती है। ऐसा केवल इनके निम्न वचन अनुपात (s') के कारण ही नहीं, बल्कि इसलिए भी होता है कि पूर्ववर्णित कारणों से इनकी पूँजी-निपज का अनुपात (b) उच्च होता है। तदनुसार, जैसा कि समीकरण (7) से स्पष्ट होता है, अपेक्षित श्रम में वृद्धि की दर भी निम्न होनी चाहिए। पूँजी में वृद्धि की निम्न दर स्वयं अपने आप में एक बड़ा अशुभ लक्षण है, किन्तु अपेक्षित श्रम की तीव्र वृद्धि पर एक दूसरा दबाव भी है। अब हम यह देखें कि ऐसा किस प्रकार से होता है।

समीकरण (7) यह लक्षित करता है कि उत्पादन-क्षमता में भी निश्चित रूप से उसी दर में वृद्धि होनी चाहिए, जिस दर में अपेक्षित श्रम में वृद्धि हो रही है। क्योंकि, अपेक्षित श्रम एवं क्षमता-निपज के दिये हुए स्थायी अनुपात $N_r/Y = a$, से उत्पादन-क्षमता में $\Delta Y' = \Delta N/a$ से वृद्धि होगी। अतएव हमें उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की निम्न दर प्राप्त होती है।

$$\frac{\Delta Y'}{Y'} = \frac{\Delta N_r/a}{Y'} = \frac{\Delta N_r/a}{N/a} = \frac{\Delta N_r}{N_r} = \frac{s}{b}, \quad (21)$$

जो यह बतलाता है कि उत्पादन-क्षमता एवं पूर्ण नियुक्त पूँजी में निश्चित रूप में s/b की दर से वृद्धि होगी।

किन्तु, यदि श्रम की उत्पादकता में टेक्नोलॉजिकल प्रगति के प्रभाव के अन्दर वृद्धि होती है, तो जैसा कि पिछले अध्याय में बतलाया गया है, श्रम-निपज अनुपात में समय के क्रमानुसार कमी होगी। ऐसा होने पर किसी भी समय अपेक्षित श्रम की मात्रा, यदि श्रम-निपज अनुपात में कमी नहीं होगी, तो उससे कम होगी, यानी —

$$N_r(t) = \frac{a^0}{(1+g_a)^t} Y'_0, \quad (22)$$

जिसमें Y'_0 , t पर क्षमता निपज का प्रारम्भिक मूल्य है तथा g_a पूर्व की तरह श्रम-निपज अनुपात में ह्रास की दर है।

अतः (21) एवं (22) को ध्यान में रखने से समीकरण (7) में तरीके से संशोधन करना अनिवार्य होता है :

$$\frac{\Delta N_r}{N_r} = \frac{I + \frac{s}{b}}{I + g_a} - I, \quad (23)$$

जो यह बतलाता है कि यदि पूंजी एवं निपज में s/b की दर से वृद्धि होती है, जबकि श्रम-निपज अनुपात में g_a की दर से ह्रास हो रहा है, तो अपेक्षित श्रम में वृद्धि की दर $(I + \Delta N_r N_r)$ बराबर होगी $(I + s/b)/(I + g_a)$ । इस प्रकार, समीकरण (23) दीर्घकालीन टेक्नोलॉजिकल बेरोजगारी को सूचित करता है जो तटस्थ टेक्नोलॉजी की स्थिति में संरचनात्मक अल्प-रोजगारी की सहज अवस्था को उलभनपूर्ण बना देता है। यह पूर्ण रोजगार की साम्यावस्था की एक मौलिक आधारभूत शर्त को भी सूचित करता है। इसकी व्याख्या हाल ही में जाएगी।

गैर-केन्सीयन बेरोजगारी की वृद्धि

यदि ऊपर वर्णित कारणों से उपलब्ध श्रम में वृद्धि की दर अपेक्षित श्रम में वृद्धि की दर से अधिक हो जाती है, तो निम्नांकित असमता प्राप्त होती है :

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{\Delta P}{P} > \frac{\Delta N_r}{N_r} = \frac{\Delta K}{K},$$

जिस असमता से संरचनात्मक अल्प-रोजगार में वृद्धि की निम्नांकित दर प्राप्त होती है :

$$\frac{\Delta U^s}{U^s} = \frac{\Delta N}{N} - \frac{\Delta N_r}{N_r} = \alpha \lambda - \frac{s}{b}, \quad (24)$$

जहाँ $\Delta U^s/U^s$ गैर-केन्सीय बेरोजगारी की दर है। इसमें अपर अंकित s सन्निहित बेरोजगारी की दीर्घकालीन प्रकृति को सूचित करता है। समीकरण (24) यह सूचित करता है कि संरचनात्मक अल्प-रोजगारी के परिमाण में समय के क्रम से घातीय रूप में निम्न प्रकार से वृद्धि होगी :

$$U^s(t) = e(\alpha \lambda - s/b)^t U_0 \quad (25)$$

समीकरण (24) एवं (25) छिपी हुई बेरोजगारी की निरंतर विद्यमानता को सूचित करते हैं; क्योंकि पूँजीगत साधनों के अभाव में स्थायी रूप से बेरोजगार होने वाले लोगों में से अधिकांश बाद में जीवन-निर्वाह के लिए कृषि, हस्तशिल्प मार्ग-विक्रय एवं घरेलू नौकरियों-जैसे अनुत्पादक पेशों में लग जाते हैं। इन सभी पेशों में काम करने के लिए कम अथवा कोई भी पूँजीगत साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतएव, छिपी हुई बेरोजगारी संरचनात्मक अल्प-बेरोजगारी का वह विशिष्ट रूप है, जो केवल अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में ही नहीं, वरन् विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के अविकसित क्षेत्रों (उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ दक्षिणी हिस्सों) में भी पाई जाती है।

अतएव, हम देखते हैं कि संरचनात्मक बेरोजगारी उस प्रकार की अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में उत्पन्न एवं स्थिर रह सकती है, जिसमें, यदि पूँजी के वर्तमान कोष के पूर्ण प्रयोग की स्थिति में रखने के लिए समर्थ माँग पर्याप्त मात्रा में उच्च हो तथा यदि टेक्नोलॉजिकल प्रगति तटस्थ हो, जिससे कि निपज की प्रति-इकाई आवश्यक श्रम की मात्रा में ह्रास नहीं होता हो, तो भी जिसकी श्रम की पूर्ति में श्रम की माँग से अधिक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए संरचनात्मक बेरोजगारी सामान्य रूप में आर्थिक विकास एवं विनिष्ट रूप में औद्योगीकरण के लिए एक कर्ष है; क्योंकि यह अनुत्पादक एवं अयोग्य उद्यमों का गैर-चप्रीय और गैर-सघर्षणात्मक बेरोजगारी के रूप में स्थायित्व प्रदान करती है।

गैर-केन्सीय प्रकार की सख्या बहुत बेरोजगारी को न्यून बनाने की क्रियात्मक सभावनाओं की व्याख्या के पूर्व, दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक निम्नांकित दो आधारभूत शर्तों को बतलाना लाभदायक होगा :

$$\frac{s}{b} = \alpha \lambda \quad (26)$$

जयकि टेक्नोलॉजी की तटस्थता की मान्यता पर श्रम की उत्पादकता स्थायी रहती है, तथा

$$\frac{s}{b} = \alpha \lambda + g\alpha \quad (27)$$

जबकि समय के क्रम में श्रम की उत्पादकता में श्रम-निपज अनुपात में कमी के लिए वृद्धि होती है। समीकरण (27) का दायीं पक्ष $(1 + \alpha\lambda) (1 + g\alpha) - 1$ के समन्वित है। यह वह दर है, जिस पर श्रम-निपज अनुपात में ह्रास के परिणामस्वरूप उत्पन्न दीर्घकालिक टेक्नोलॉजिकल बेरोजगारी को दूर करने के लिए पूँजी एवं क्षमता में वृद्धि अनिवार्य है।

गैर-केन्सीय बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्राचल-क्रिया

पूर्ववर्ती विवरण से यह स्पष्ट है कि गैर-केन्सीय तरीके की सामूहिक बेरोजगारी से पीड़ित अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को मुख्य रूप से पूँजी में वृद्धि की दर $(\Delta K/K)$ में वृद्धि करनी होगी या जनसंख्या में वृद्धि की दर $(\Delta P/P)$ में कमी करनी होगी या दोनों ही करने होंगे। विशेषतया संरचनात्मक अल्प-बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, या निश्चयात्मक आधार पर, पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार को दीर्घकालिक रूप में बनाये रखने के लिए, पूँजी एवं जनसंख्या की वृद्धि की दर को निर्धारित करने वाले संरचनात्मक प्राचलों के साथ उचित कार्रवाई अनिवार्य है। अब समीकरण (26) एवं (27) द्वारा दी गई साम्यावस्था की परिस्थितियों को ध्यान में ले हुए प्राचल-क्रियाओं पर विचार किया जाय।

अपेक्षित श्रम में वृद्धि की दर को बढ़ाने के लिए, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को वचत-अनुपात (s) में वृद्धि तथा पूँजी-निपज अनुपात (b) में कमी यानी $(\Delta P/P) > (\Delta K/K)$ की परिस्थिति उत्पन्न करनी होगी। ऐसा करने से कहना आसान है, विशेषतः जब और जिस स्थिति में उपभोग का स्तर पहले से ही इतना निम्न है कि s में कोई भी वृद्धि कठिन हो जाती है तथा टेक्नोलॉजी की स्थिति इतनी पिछड़ी है कि b में कमी (अथवा पूँजी की उत्पादकता में वृद्धि) भी कठिन हो जाती है। यहाँ हम श्रम की पूर्ण रोजगार की इच्छा एवं इसकी अधिक चालू-उपभोग की इच्छा के बीच एक प्रकार का द्वन्द्व पाते हैं। इस प्रकार का द्वन्द्व एक विकसित अर्थ-व्यवस्था में नहीं पाया जाता है, जिसमें अधिक वचत (अथवा निम्न उपभोग) ही केन्सीय वेरोजगारी का कारण होती है। अतएव, वचत-अनुपात को बढ़ाकर अपेक्षित श्रम की वृद्धि की दर में वृद्धि करने से अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में एक आर्थिक व्यवस्था, जो सामूहिक उपभोग की वेदी पर कुछ लोगों को अधिक वचाने की सुविधा देती हैं, उसके प्रति श्रमिकों में तिरस्कार की प्रवृत्ति उत्तेजित होती है। फिर भी, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था s में उन उपायों के द्वारा, जो पहले से ही निम्न उपभोग में और अधिक त्याग को आवश्यक नहीं बनाते (उदाहरण के लिए, वित्तीय एवं विदेशी व्यापार-सम्बन्धी नीतियाँ, जिनका आगे चलकर पृथक् रूप से विवरण किया जाएगा), जिस हद्द तक वृद्धि करती हैं, उस हद्द तक वह लौकिक रोप को जाग्रत करने एवं राजनीतिक साम्य को उलटे, वगैर पूँजी की वृद्धि की दर में वृद्धि कर सकती है और इसलिए अपेक्षित श्रम में वृद्धि की दर में भी वृद्धि कर सकती है।

जहाँ तक पूँजी-निपज अनुपात (b) में कमी का प्रश्न है, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को पूँजी वचाने वाले टेक्नोलॉजिकल सुधारों को अपना कर तथा यन्त्रों एवं साधनों के वेकार प्रयोग को दूर कर पूँजी की क्षमता में वृद्धि करनी होगी। आगे चलकर यह दिखलाया जायगा कि अधिक उत्पादक क्षेत्रों में पूँजी के पुनर्विभाजन से सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए पूँजी निपज अनुपात में कमी हो सकती है। मँहगी मुद्रा-नीति के द्वारा पूँजी-निपज अनुपात में कमी के प्रयास को आशाहीन एवं अनर्थक समझकर टाल देना चाहिए। क्योंकि, मँहगी मुद्रा-नीति के द्वारा पूँजी-निपज-अनुपात में जो भी कमी आती है, वह मजदूरी की मौद्रिक दर में सम्भावित वृद्धि (उदाहरण के लिए, श्रम-संघों के कार्यों द्वारा) अथवा पूँजीगत वस्तुओं के औसत मूल्य में सम्भावित ह्रास (उदाहरण के लिए, बाजार की प्रतियोगिता से), यानी साधना-मूल्यों में परिवर्तन द्वारा उत्पादन के पूँजी प्रयोग वाले तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने से बिलकुल समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, मँहगी मुद्रा-नीति विकासात्मक निवेश-सम्बन्धी क्रियाओं को प्रोत्साहित करने के दोर्घकालीन उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। पाठक टेक्नोलॉजी पर पिछले अध्याय में पूँजी-निपज अनुपात को कम करने के सम्बन्ध में अन्य सुझावों को देख सकते हैं।

दूसरी क्रियात्मक सभावना समीकरण (27) में श्रम-निपज अनुपात में कमी की दर (g_a) को कम करने की है। इसका तात्पर्य यह है कि दीर्घकालिक टेक्नोलॉजिकल बेरोजगारी की सभावना से ग्रस्त अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को सरचनात्मक अल्प रोजगारी में उस वृद्धि को, जो $\alpha\lambda$ को, की दर पर पूँजी-संचय के द्वारा उत्पादक रोजगार में नहीं खप सकती है, अन्य न्यूनतम बनाने के लिए श्रम बचाने वाले उपायों का प्रतिरोध करना होगा। यहाँ दो कठिनाइयाँ दृष्टिगोचर होती हैं। प्रथमतः तो जैसा कि पिछले अध्याय में देखा जा चुका है, श्रम बचाने वाले उपायों को अपनाने के प्रतिरोध से श्रम की उत्पादकता में इतनी कमी हो सकती है, जिससे कि $K/\gamma = (K/N)/\gamma/N$ के माध्यम से उच्च पूँजी-निपज अनुपात आवश्यक हो जाय। वास्तव में, यह आत्मघाती है; क्योंकि वचत-अनुपात के दिया हुआ होने पर, b के उच्च होने पर पूँजी में इतनी वृद्धि हो सकती है, जितना कि इसके निम्न होने पर। द्वितीयतः, श्रम की उत्पादकता की वृद्धि की दर में अन्तर्निहित ह्रास पूर्व वर्णित विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम दर की धारणा से असंबद्ध है; क्योंकि दीर्घकालिक रूप में बढ़ते हुए जीवन-स्तर को प्राप्त करने के लिए श्रम की उत्पादकता में ह्रास नहीं, बल्कि वृद्धि आवश्यक होती है। इन कठिनाइयों के सन्दर्भ में एक स्थायी धनात्मक g_a को दिया हुआ मानना ही सर्वाधिक उचित तरीका जान पड़ता है और तब पूँजी में वृद्धि की दर को $(\alpha\lambda + g_a)$ के अनुकूल बनाना चाहिए, जिससे श्रम की उत्पादकता के परित्याग तथा जीवन स्तर को निम्न बनाये वगैर ही दीर्घकालिक टेक्नोलॉजिकल बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है।

विकल्पतः, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था पूँजी में वृद्धि की दर को दिया हुआ मानकर जनमर्या की वृद्धि की दर में कमी के द्वारा उपलब्ध श्रम में वृद्धि की दर को कम करने का प्रयास कर सकती है। इसे और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए यह कहा जा सकता है कि $(\Delta P/P) > (\Delta K/K)$ की परिस्थितियों में, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को दोनों α तथा λ में निश्चित रूप से कमी करनी चाहिए। कार्य करने की क्षमता (σ) में कमी इस बात का संकेत करती है कि समाज को काम की जगह विश्राम को पसन्द करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि कुल जनसंख्या का एक छोटा भाग सदा कार्य करने के योग्य एवं तत्पर रहे। इसमें अनिवार्यतः साम्प्रतिक वरण सन्निहित है, जो आर्थिक दृष्टि से अपेक्षित हो सकता है, अथवा नहीं भी। यदि ऐसे व्यक्तियों को, जो कि श्रम-सेना के नियमित सदस्य नहीं हैं अथवा नहीं होना चाहते हैं (उदाहरणतः; स्कूल जाने अथवा अवकाश-प्राप्त उम्र के काम खोजने वालों, सरुदम्य उद्योगों में काम करने के लिए इच्छुक गृहणियाँ एवं माताएँ, विशेष रूप से विद्वान वैज्ञानिक एवं कलाकार, जिन्हें अपनी रोजी-रोटी के लिए काम करना पड़ता है और विलक्षण धनी व्यक्ति, जो टिन तरीके से अपनी जीविका प्राप्त करना चाहते हैं) श्रम-बाजार से स्थायी रूप

से अलग कर दिया जाय, तो अपेक्षित थ्रम या विकास की दर को बढ़ाने-सम्बन्धी दवाव में निश्चय ही बहुत कमी हो जाएगी। यदि श्रम की उत्पादिकता में स्थायी धनात्मक दर g_a में वृद्धि हो रही है, तो एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था एक बड़े अवकाश-प्राप्त वर्ग का भरण-पोषण कर सकती है और इस प्रकार α के अन्यथा अधिक मूल्य को कम कर सकती है। क्योंकि, बढ़ती हुई उत्पादिकता काम के कम घंटे तथा अधिक मजदूरी आन्दोलन को सम्भव बनाती है।

अन्ततः एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था संतति निग्रह तथा अन्य जनांकिकीय प्रयोगों के द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उपलब्ध श्रम के अनुपात λ को कम करने का प्रयास कर सकती है। किन्तु, जैसा कि जनसंख्या-सम्बन्धी विशेषज्ञों द्वारा सदा इस बात की चेतावनी दी जाती है, इस सम्बन्ध में कुछ सांस्थानिक कठिनाइयों का निश्चित रूप से सामना करना पड़ेगा। λ को कम करने के प्रयास में उत्प्रवास का प्रोत्साहन भी, यदि यह सम्भव है,¹ सम्मिलित है। किन्तु, जैसा कि हावेलमो का सुझाव है,² यदि यह मान लिया जाय कि जन्म-दर जानकारी के सूचकांक से प्रती-पानुपाती दर में परिवर्तित होता है, तो जनसंख्या में वृद्धि को नियन्त्रित करने के नकारात्मक उपाय से, व्यापक अर्थ में, टेक्नोलॉजिकल प्रगति को त्वरायित करने वाले धनात्मक प्रभाव की उत्पत्ति हो सकती है। साथ ही, जैसे-जैसे एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था निर्विरोध रूप से उस विन्दु की ओर अग्रसर होती है, जहाँ जनसंख्या की वृद्धि को संरचनात्मक वेरोजगारी में वृद्धि का कारण न समझकर निवेश की माँग को प्रोत्साहित करने वाले साधन के रूप में समझा जाता है, वैसे-वैसे बड़ी एवं वृद्धिशील जनसंख्या के पक्ष का तर्क कमजोर होने के बजाय दृढ़ होता जाता है।

1. उदाहरण के लिए, जापान यद्यपि औद्योगिक दृष्टि से विकसित है, तथापि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की तरह इसमें जनाधिक्य की स्थिति पाई जाती है। अतएव, यह अल्प-जनसंख्या वाली अर्थ-व्यवस्थाएं (जैसे, युद्धोत्तर काल में ब्राजील स्वीकार करने के लिए जितना तैयार रहती हैं, उतना उत्प्रवास को प्रोत्साहित करता है।
2. हावेलमो : 'ए स्टडी इन दि थियरी आफ इकॉनामिक इवोल्यूशन' (पृष्ठ 43)। हावेलमो इस मान्यता को विस्तृत नहीं करता, किन्तु उसने इस अवलोकनीय तथ्य को अपने ध्यान में रखा था कि अशिक्षित परिवारों की अपेक्षा शिक्षित परिवारों को संतति-निग्रह के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त है। तथापि, यह निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता है कि इस सूचना एवं व्यवहार में एकरूपता है। उदाहरण के लिए जापान में साक्षरता का प्रतिशत अधिक होने पर भी वहाँ खिलाने तथा रोजी देने के लिए बड़ी एवं वृद्धिशील जनसंख्या है। फिर भी, अधिक जानकारी के पक्ष का तर्क ठीक ही रह जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रगति पूँजी में गुणात्मक सुधार के द्वारा पूँजी-निपज-अनुपात को कम करती है।

छिपी हुई बेरोजगारी पर अनुसंधान*

रोजगारी पर अपनी विवेचना को समाप्त करने के पूर्व आर० नस्कॉ की जनाधिक्यवाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में बचत सम्भाव्य के रूप में कम विकास वाली बेरोजगारी पर विचार करना लाभदायक जान पड़ता है।¹ इस विचार के अनुसार, छिपी हुई बेरोजगारी की पूर्ण सामबन्दी उपभोग में कमी के बगैर शुद्ध-निवेश में वृद्धि कर सकती है। इसे नस्कॉ अवश्यभावी विकल्प के रूप में निवेश एवं उपभोग की स्थापक धारणा तथा आवश्यक परिपूरक के रूप में केन्स के निवेश एवं उपभोग के विचार के बीच समझौता कराने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि, अतिरिक्त पूँजी के कोप के बगैर अतिरिक्त श्रम के बड़े कोप वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था स्थापकों के पूर्णतः नियुक्त साधनों, जिनका अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं के कम तथा पूँजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादन पर लगाया जाता है तथा केन्स के विरद्योगीय साधनों, जिनका प्रयोग दोनों पूँजीगत तथा उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने में किया जा सकता है, के बीच पाई जाती है। यह 'तटस्थ' स्थिति सुखदायक विचार है, किन्तु अधिक विचार-विमर्श करने पर यह भ्रामक जान पड़ सकती है। यहाँ न्यूनाधिक मात्रा में प्रचलित व्यावहारिक आक्षेप² को दुहराने के बजाय हम लोग निवेश एवं उपभोग के सम्बन्ध में स्थापक एवं केन्सीय विचारों के बीच नस्कॉ के इस समझौते के पक्ष में दिये जाने वाले विभिन्न तर्कों में सन्निहित कुछ कठिनाइयों को बतला सकते हैं।

* यह लेखक के पूर्व-उद्धृत 'टेकनीक्स फॉर मैक्सिमम ग्रोथ ऐंड एम्पलायमेंट' का अंग है।

1. देखें नस्कॉ का 'प्रोब्लेम्स ऑफ़ केपिटल फॉरमेशन इन अन्डरडेवलपड कंट्रीज़' साथ ही, देखें बुचानन एवं एलिस का एप्रोचेज टु इकॉनामिक डेवलपमेंट 13 अक्टूबर, 1956 के इकॉनामिक वीकली (इण्डिया) में थो एम० निवासन का कॉमन सेंस मेड डिफिकल्ट; ए० के० दास गुप्ता का पूर्व उद्धृत 'डिसगाइड्ड अन-एम्पलायमेंट एण्ड इकॉनामिक डेवलपमेंट'।
2. मेरे सहयोगी प्रोफ़ेसर रॉबर्ट अलेग्जेन्डर ने मेरा ध्यान लेटिन अमेरिका में बड़े पैमाने पर दृष्टिगोचर इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया कि वहाँ कृषि में छिपे हुए बेरोजगार औद्योगिक अनुशासन से इतने अनभिज्ञ हैं कि जब वे कारखानों में उत्पादक तरीके पर नियुक्त होते हैं, तब स्वभावतः अनुपस्थित हो जाते हैं। उन्होंने इस तथ्य का भी जिक्र किया कि लेटिन अमेरिका में छिपे हुए बेरोजगारों का एक बड़ा भाग सशस्त्र सेवाओं में रोजी पाता है। इससे यह स्पष्ट है कि किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में सभी छिपे हुए बेरोजगारों को उत्पादक-श्रेण में नहीं लगाया जा सकता है।

इन तर्कों का सार निम्न प्रकार से है : मान लिया जाय कि सभी छिपे हुए बेरोज़गार उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में नियुक्त हैं (जिसे साधारणतया गुजारा कृषि कहते हैं) । चूँकि, परिभाषा के अनुसार छिपे हुए बेरोज़गार व्यक्ति सीमान्त अथवा अनुत्पादक श्रम हैं, अतएव उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में से इन्हें हटा देने से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । अब छिपे हुए बेरोज़गार को पूँजीगत उद्योगों के क्षेत्र में ले जाया जाय तथा इस प्रकार के परिवर्तन की व्यावहारिक कठिनाइयों पर विचार नहीं किया जाय । चूँकि, मान्यता के अनुसार, पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में श्रम की सीमांत उत्पादकता घनात्मक है, अतएव इस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों में छिपे हुए बेरोज़गारों को सम्मिलित करने से पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी । अतएव, जब कभी छिपे हुए बेरोज़गारों को पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में प्रभावपूर्ण तरीके से लगाया जाता है, तब इसे 'वचत सम्भाव्य' समझा जाता है, जो शुद्ध निवेश (अथवा पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में उपर्युक्त वर्णित वृद्धि के परिणामस्वरूप पूँजी के वर्तमान कोष में वृद्धि) के रूप में फलित होता है । इस प्रकार, इस धारणा का सर्जन होता है कि छिपी हुई बेरोज़गारी अंततः, औद्योगीकरण पर बोझ होने के बजाय छिपा हुआ वरदान है । किन्तु, निम्नलिखित विवेचन इस वहकाने वाली धारणा को हटा सकता है ।

जब उपभोक्ता-वस्तुओं के क्षेत्र से मुक्त होने वाले श्रम की विशिष्टताओं को ध्यान में रखा जाएगा तब स्थायी पूँजी की निपज में, जिसका औद्योगीकरण के लिए निर्णायक महत्त्व होता है, विशेष रूप से वृद्धि नहीं भी हो सकती है । यह मानते हुए कि छिपे हुए बेरोज़गारों को ऐसी निवेश-सम्बन्धी योजनाओं में स्थानान्तरित किया जा सकता है, जिसमें विशेष दक्षता अथवा साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इस प्रकार की श्रम-प्रधान प्रकृति के निवेश की योजनाओं से औद्योगीकरण के लिए शीघ्र एवं पर्याप्त उपयोगी उचित मात्रा एवं गुण वाली स्थायी पूँजी प्राप्त होने की आशा कठिनाई से की जा सकती है । ऐसी श्रम-प्रधान योजनाओं से अधिक-से-अधिक सीमित मात्रा में प्रारम्भिक पूँजी-निर्माण की आशा की जा सकती है (उदाहरण के लिए, कारखानों के स्थान के लिए महापंक वाली भूमि की सफ़ाई, आधुनिक महापथों के निर्माण के लिए मिट्टी की सड़कों का निर्माण तथा यन्त्र-निर्मित उद्योगों के कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किये जाने वाले हस्तशिल्प) । किन्तु, औद्योगीकरण को पर्याप्त मात्रा में गतिमान बनाने के लिए यन्त्र-निर्माण करने वाले यन्त्रों की आवश्यकता पड़ती है और छिपा हुआ बेरोज़गार इस प्रकार के 'यन्त्र-निर्माण करने वाले यन्त्रों' का अप्रभावी प्रतिस्थापन है ।

स्थायी उपभोग की मान्यता का प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि उपभोग्य वस्तुओं के क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम की उत्पादकता शून्य से अधिक है, वरन् इसलिए कि पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में हस्तान्तरित होने से इसकी उपभोग-श्रमता में

सम्भवतः आय के प्रत्येक स्तर पर वृद्धि होती है। यह सम्भावना दो कारणों से सत्य प्रतीयमान होती है। प्रथमतः, पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र से हस्तान्तरण के पूर्व छिपे हुए बेरोजगार उपभोग के इतने निम्न स्तर को अपनाते के लिए बाध्य होने हैं कि वे हस्तान्तरण के बाद निश्चय ही नई सुदृढ़ उपभोग की आदतों को अपनायेंगे। द्वितीयतः, ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ पूँजीगत वस्तुओं के उद्योग मुख्यतः केन्द्रित होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों, जहाँ से छिपे हुए बेरोजगार आते हैं, की अपेक्षा स्पष्टतः उपभोग की सुदृढ़ता क्षमता को बढ़ाने वाले होते हैं। अतएव, यदि पीगू-सम्बन्धी 'प्रभाव को' अनेक छोड़कर, 'आदत-सम्बन्धी प्रभाव' एवं 'रुचि-सम्बन्धी प्रभाव' पर उचित ध्यान दिया जाय, तो पहले अनु-स्थापक किन्तु अब उत्पादक उपभोक्ताओं, यानी छिपे हुए बेरोजगारों के नागरीकरण के परिणाम-स्वरूप सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की उपभोग-क्षमता में निश्चय ही वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में जो साधन अन्यथा पूँजीगत वस्तुओं की निपज को बढ़ाने के लिए प्रयोग में आने वाली उपभोक्ता-वस्तुओं के क्षेत्र में उनके विनिधान के लिए दबाव बढ़ेगा।

फिर भी, यदि, जैसा कि औद्योगीकरण की प्रक्रिया में सम्भावना रहती है, पूँजीगत वस्तुओं का क्षेत्र उत्पादन के श्रम बचाने वाले तकनीक को अपनाता है, तो निपज की प्रति इकाई अपेक्षित श्रम की मात्रा में सन्निहित कमी, इस क्षेत्र द्वारा छिपे हुए बेरोजगारों को पूर्णतः तथा निरन्तर रूप में लगाने की क्षमता को सीमित बना देती है। जैसा कि पहले ही वर्णन किया जा चुका है, इस प्रकार की स्थिति में स्थायी उत्पादकता वाली श्रम-शक्ति को सज्जित करने के लिए बढ़ती हुई उत्पादकता वाली श्रम-शक्ति की अपेक्षा पूँजी में अधिक दर से वृद्धि करनी होगी। इस प्रकार, छिपी हुई बेरोजगारी को 'बचत सम्भाव्य' गानने के सामान्य तर्क में सन्निहित टेक्नोलॉजिकल तटस्थता की मौन मान्यता अमान्य एवं नि सहाय हो जाती है। यदि हम लोग, टेक्नोलॉजिकल प्रगति से उत्पन्न उपयुक्त समस्याओं को छोड़ भी देते हैं, तो भी हम लोग जनसंख्या की वृद्धि के पूँजी-सचय से अधिक हो जाने की मूलभूत समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते। केवल बड़ी ही नहीं, बरन् बढ़ती हुई जनसंख्या उपभोग को कम किये बगैर शुद्ध निवेश को बढ़ाने की कठिनाई को घनीभूत कर देती है, क्योंकि इसका तात्पर्य खाने के लिए अधिक व्यक्ति तथा नियुक्ति के लिए अधिक काम चाहने वाले, दोनों प्रकार के लोगों से होता है। वृद्धिशील जनसंख्या वाली अर्थ-व्यवस्था में उपभोग से अधिक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति में ऐसी वृद्धि, जिसे छिपे हुए बेरोजगारों का पूर्ण उपयोग सम्भव बनाता है, यदि सम्पूर्ण नहीं, तो अधिकांश अनुसंधान में यथार्थतः अनुत्पादक वृद्धि (उदाहरण के लिए, साधारणतया उत्पादकता उम्र, जैसे 15 वर्ष से कम आयु वालों की बढ़ती हुई संख्या) के द्वारा समाप्त हो जाएगी। साथ ही, जन-संख्या में वृद्धि के पूँजी-सचय से अधिक होने की प्रवृत्ति का तात्पर्य यह है कि छिपे बेरोजगारों की सहायता से पूँजी के कोष में हुई वृद्धि से जितने लोगों को उत्पा-

दक तरीके से काम पर लगाया जा सकता है, उससे छिपी हुई बेरोजगारी की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है।

ये विचार पूँजी-संचय के साधन के रूप में छिपी हुई बेरोजगारी की परिकल्पना की उपादेयता पर सन्देह प्रकट करते हैं। ये विचार एवं हम लोगों के औपचारिक विवरण यह संकेत करते हैं कि ये पूँजी-संचय एवं आर्थिक विकास में सहायक होने के बजाय, छिपी हुई बेरोजगारी की क्षमता को बढ़ाने वाली प्रकृति की जगह उत्पन्न करने वाली अस्पष्ट योजनाओं को सहायता एवं आराम देकर, इनमें बाधा उत्पन्न करते हैं।

अध्याय 7

आर्थिक विकास में पुनर्वितरणात्मक-भूमिका

विकसित अर्थ-व्यवस्था में आय के वितरण के सम्बन्ध में दीर्घकालीन विवेचन मुख्यतः इस प्रश्न पर केन्द्रित है कि आर्थिक विकास का आय के दीर्घकालीन वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है ?¹ जहाँ तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, यह प्रश्न गौण महत्त्व का हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाएँ ऐसी स्थिति में नहीं होती कि विकास को दिया हुआ भानकर आय के वितरण पर इसके सभावित प्रभावों पर विचार किया जाये अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से सम्बद्ध प्रश्न वस्तुतः यह जान पड़ता है : सांस्थानिक, राजनीतिक एवं नैतिक कारणों से आय के वितरण में कुछ परिवर्तनों के दिया हुआ रहने पर, निपज एवं पूँजी की वृद्धि पर इस प्रकार के परिवर्तनों के क्या प्रभाव होंगे ? वर्तमान अध्याय में अंशतः इसी अन्तिम प्रश्न की व्याख्या की जायगी ।

दूसरा प्रमुख प्रश्न, जिसका यहाँ विचार किया जायगा, आर्थिक विकास के सदर्भ में साधनों का पुनर्विनिधान है। क्योंकि, दीर्घकालिक विचार से दिये हुये साधनों का पुनर्विनिधान एवं दी हुई आय का उत्पादक तरीके से पुनर्वितरण ठीक उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना कि उत्पादक साधनों तथा राष्ट्रीय आय के आकार को शीघ्रतापूर्वक बढ़ाना। चूँकि किसी अर्थ-व्यवस्था के विकास की दर में वचत-अनुपात के आनुपातिक तथा पूँजी-निपज अनुपात के प्रतिलोमी दर में परिवर्तन होने

1. देखें सी० क्लार्क, दि कन्डीशन ऑफ इकॉनामिक प्रोग्रेस; एस० कुजनेट्स 'इकॉनामिक प्रोग्रेस एंड इनकम इनइक्वेलिटी', पूर्व उद्धृत; पोस्ट केन्सीयन इकॉनामिक में एम० थ्रोनेफेल्डनेर का 'समनेगलेक्टेड इम्प्लिकेशन्स ऑफ सेकुलर इन्फ्लेशन'। चूँकि हमने अन्तिम परिसंवाद में विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के सदर्भ में निवेश की माँग पर पुनर्वितरण-प्रभाव का वर्णन किया था, अतएव अब हम अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के सदर्भ में पूर्ति एवं पूँजी की क्षमता पर ध्यान देंगे ।

की प्रवृत्ति पाई जाती है, अतएव हम लोग स्पष्टतः निम्नलिखित विषयों का वर्णन करेंगे : (क) वचत-अनुपात पर आय के पुनर्वितरण का प्रभाव, तथा (ख) पूँजी-निपज अनुपात या इसके व्युत्क्रम पूँजी की उत्पादकता पर साधनों के पुनर्विनिधान का प्रभाव ।

तो भी, आय के पुनर्वितरण एवं साधनों के पुनर्विनिधान की विशेष प्रक्रियाएँ¹ जिनमें एक अर्थ-व्यवस्था से दूसरी अर्थ-व्यवस्था में अन्तर पाया जाता है, वितरण के प्राचलों में दिये हुए परिवर्तन में अन्तर्निहित होगी । तथापि, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिकांश परिस्थितियों में आय का पुनर्वितरण एवं साधनों का पुनर्विनिधान मूल्य की गति, प्राथमिकता विनिधान, वित्तीय नीति, एकाधिकार-विरोधी अधिनियम एवं सामूहिक सोदे के द्वारा किया जाता है ।

वचत-अनुपात पर पुनर्वितरणका प्रभाव

संस्थापक अर्थशास्त्रियों से प्रारम्भ कर आज तक यह स्पष्ट रूप से अनुभव किया जाता रहा है कि आय (एवं सम्पत्ति) का वितरण राष्ट्रीय पूँजी के संचय की पृष्ठ-भूमि में प्रमुख एवं आग्रह-युक्त कारण के रूप में वर्तमान रहा है । किन्तु, आर्थिक प्रगति पर वितरण-सम्बन्धी प्रभाव की मात्रा प्रारम्भ से अब तक विवाद का विषय रही है । मैण्डेविले के 'मधुमक्खियों की कल्पित कथा'² से प्रारम्भ कर केन्स के 'मितव्यय के विरोधाभास' तक न्यून उपभोग के समर्थकों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है । जहाँ तक अल्पकाल में विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, केन्स ने इस बात को दिखलाकर कि पूर्ण रोजगार से निम्न बिन्दु पर मितव्यय में वृद्धि से वास्तविक पूँजी में वृद्धि के वजाय कमी होती है, शुम्पीटर³ के वाक्यांशों में, 'बूर्जुआ तर्क के अन्तिम स्तम्भ को भी निस्सन्देह चकनाचूर कर

1. आगे के अध्यायों में कुछ पुनर्वितरणात्मक प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया जायगा ।
2. पूर्व-संस्थापक युग में बर्नार्ड मैण्डेविले (Bernard Mandeville) का यह तत्कालीन विधर्मी विचार था कि समृद्धि वचत से नहीं, बरन् व्यय करने से बढ़ती है । आदम स्मिथ ने गलत कहकर इस विचार का परित्याग कर दिया था, किन्तु केन्स ने इसे स्वीकारात्मक रूप में उद्धृत दिया है । (देखें केन्स की जेनरल थियरी, विशेषतः 'मरकेण्टिलिज्म पर टिप्पणियाँ') आर्थिक विचारधारा के इतिहास में न्यून उपभोग के अन्य समर्थकों लौडरडेल, माल्टस, सिस्मोंडी, मार्क्स एवं हॉबसन हैं ।) देखें नोरटन, एन० बाई०, 1951 द्वारा प्रकाशित ए० एच० हैनसेन की बिजिनेस साइकिल्स एण्ड नेशनल इन्कम, अध्याय 14; किन्तु, हैनसेन ने सिस्मोंडी एवं मार्क्स को छोड़ दिया है ।)
3. जे० शुम्पीटर, "जोन मेनर्ड केन्स 1883-1946" पूर्व उद्धृत ।

दिया।' जहाँ तक दीर्घकाल में अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि व्यय न करने की क्षमता के अनुमित न्यून न हो सकने योग्य दोष के विरुद्ध, केन्स का तर्क पूर्णतः प्रबल तथा मितव्यय के अनुमानित शुद्ध गुण के पक्ष में संस्थापक तर्कों के प्रति विलकुल अप्राप्त है। निम्नांकित विवेचन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के विशेष संदर्भ में इस संस्थापक-भूत केन्सीय विवाद पर कुछ प्रकाश डालता है —

आय की विपमता एवं वचत-अनुपात

मान लिया कि दी हुई राष्ट्रीय आय (Y) मजदूरी-सम्बन्धी आय (Y_w) तथा गैर-मजदूरी-सम्बन्धी आय (Y_π) में समाप्त हो जाती है, जिससे कि

$$Y = Y_w + Y_\pi, \quad (1)$$

जिसमें कि Y_w में वेतन (सफेद कालर वाले मजदूरों का) तथा Y_π में मुनाफा, लाभांश, लगान, ब्याज एवं स्वत्व-शुल्क सम्मिलित हैं यद्यपि वास्तविक विश्व में कुछ अति-व्यापकता हो सकती है, फिर भी प्रत्येक परिवार अथवा व्यक्तिगत आय प्राप्त करने वाले की आय का प्रधान साधन ही इस बात का निर्धारण करता है कि वह किस वर्ग के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार यदि किसी परिवार की आय मुख्यतः मजदूरी तथा अथवा लाभांश (उदाहरण के लिए, इसके कुल स्टॉक पर) जो प्राप्त होती है, तो उसके परिवार को मजदूरी से प्राप्त आय वाले वर्ग के अन्तर्गत समझना चाहिए। इस प्रकार के विचार से सीमान्त साधनों से प्राप्त पारिवारिक आय एक-दूसरे को समाप्त कर देती है, जिससे मुख्य साधन ही शुद्ध रूप में रह जाता है।

1. संस्थापक तर्क इस विश्वास पर आधारित है कि पूँजी का संचय वचत की व्यक्तिगत क्षमता की प्रबलता पर निर्भर करता है। इस पूँजी-संचय के एक बहुत बड़े भाग के लिए सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था 'धनिकों के उपभोग-स्थगन' पर निर्भर करती है। इस तर्क के साथ यह आशय भी जुड़ा हुआ है कि आय की विपमता आर्थिक प्रगति की एक आवश्यक शर्त है। इसके विपरीत सैद्धान्तिक प्रमाणों के अतिरिक्त, वचत को प्रोत्साहित करने में आय की विपमता का क्षेत्र इस तथ्य से भी अत्यधिक कम हो जाता है कि अधिकांश अल्प-विकसित अर्थ व्यवस्थाएँ अपनी विकासात्मक पूँजी के एक बहुत बड़े भाग के लिए सरकारी वचत पर निर्भर रहती हैं। 'अन्योन्याश्रित उपभोक्ता की प्राथमिकता' जो, जैसा कि ऊपर मूल ग्रंथ में वर्णित किया जायगा, पूँजी के विकास की आवश्यक शर्त के रूप में आय की विपमता के व्यावहारिक महत्त्व को और भी कम कर देती है; इस पूर्व-कल्पित शर्त में पूँजी-विकास के तथ्य को और भी बल मिलता है।

समीकरण (1) से निम्नांकित मजदूरी एवं गैर-मजदूरी प्राचल प्राप्त होता है :

$$\frac{Y_w}{Y} = \eta, \quad \frac{Y_\pi}{Y} = 1 - \eta, \quad (2)$$

जो सम्पत्ति एवं उत्तराधिकार के सांस्थानिक कारणों द्वारा पूर्वनिश्चित होते हैं तथा जो साधनों के मूल्य एवं पुनर्वितरण-सम्बन्धी नीति से संशोधित होते हैं। इस विवेचन के सन्दर्भ में मजदूरी-वितरण अनुपात η में किसी भी प्रकार की कमी को आय की विपमता में वृद्धि तथा इसमें किसी प्रकार की वृद्धि को आय की विपमता में कमी के रूप में समझा जायगा। आय की विपमता का यह विचार इस मान्यता पर आधारित है कि औसत राष्ट्रीय आय से कम आय प्राप्त करने वालों में मजदूरी तथा वेतन पर काम करने वालों की अत्यन्त प्रबल प्रधानता रहती है, जबकि गैर-मजदूरी पर काम कराने वाले औसत आय से अधिक आय वाले अल्प-संख्या में होते हैं। इससे अधिक, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के विशेष सन्दर्भ में एक अतिरिक्त धारणा बनाई जा सकती है कि मध्यम वर्ग, जिसकी आय औसत आय से कुछ अधिक है, अपेक्षाकृत कम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धनी एवं निर्धन के बीच आय की विपमता चरम-सीमा पर है। आय के वितरण की यह अत्यधिक विपमता, आधारभूत रूप में, आय-उत्पादन सम्पत्ति के अत्यधिक केन्द्रीकरण का सूचक है।

अब दी हुई राष्ट्रीय आय में से कुल वचत (S) भी दो भागों में विभक्त की जाती हैं—प्रथम वह, जो मजदूरी-सम्बन्धी आय (S_w) से तथा द्वितीय वह, जो गैर-मजदूरी-सम्बन्धी (S_π) आय से प्राप्त होती है। जिससे

$$S = S_w + S_\pi, \quad (3)$$

जिस समीकरण का दाहिना पक्ष दीर्घकालीन प्रवृत्ति के पृथक् वचत-फलन के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है (वचत की औसत एवं सीमान्त क्षमता को सूचित करते हुए) :

$$S_w = s_w Y_w s_{10} \eta Y, \quad (4)$$

और

$$S_\pi = s_\pi Y_\pi = s_\pi (1 - \eta) Y, \quad (5)$$

यहाँ s_w मजदूरी-सम्बन्धी तथा s_π गैर-मजदूरी-सम्बन्धी आय में से वचत की औसत एवं सीमान्त प्रवृत्ति हैं। यह देखा जा सकता है कि $s_w \eta$ राष्ट्रीय आय में से वेतन-भोगी मजदूर-वर्ग के वचाने की औसत तथा सीमान्त क्षमता का एवं $s_\pi (1 - \eta)$ राष्ट्रीय आय में से वेतन न पाने वाले मजदूर वर्ग के वचाने की औसत तथा सीमान्त क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि व्यावहारिक है, यह मान लिया कि

मजदूर-वर्ग के बचाने की औसत एवं उसकी सीमान्त दामता वेतन न पाने वाले मजदूर-वर्ग की अपेक्षा कम है, यानी $s_w < s_n$ । यह वही अन्तर है, जो आय के पुनर्वितरण को सार्थक बनाता है।

समीकरण (3) में (4) एवं (5) को प्रतिस्थापित कर एवं नये क्रम में रखने में कुल वचत आय एवं वितरण के फलन के रूप में निम्नांकित प्रकार से प्राप्त होती है :

$$S = [s_w \eta + s_n (I - \eta)] Y, \quad (6)$$

जिससे हमें सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए वचत की औसत प्रवृत्ति (s) प्राप्त होती है :

$$\frac{S}{Y} = s = s_w \eta + s_n (I - \eta) \quad (7)$$

समीकरण (7) यह स्पष्ट करता है कि यदि मजदूरी-वितरण अनुपात η स्थायी रूप से नीचे आ जाता है, तो $s_w < s_n$ होने पर राष्ट्रीय आय में से बचाने की औसत-दामता में वृद्धि होगी। किसी अर्थ-व्यवस्था की विकास-दर के सम्बन्ध में समीकरण (7) के आशय को निम्नांकित प्रकार से दिखलाया जा सकता है :

$$\frac{\Delta}{Y} = G = \frac{s_w \eta + s_n (I - \eta)}{b} \quad (8)$$

जिसमें G निपज (अथवा पूँजी) में वृद्धि की दर तथा b पहले की ही तरह पूँजी-निपज अनुपात है। समीकरण (8) यह बतलाता है कि यदि पूँजी निपज अनुपात स्थायी रहे, तो आय की विषमता में वृद्धि (निम्न η के रूप में व्यक्त) के परिणामस्वरूप निपज में वृद्धि की दर बढ़ने योग्य है। समीकरण (8) विषमता एवं 'धनिकों के उपभोग-स्थगन' के माध्यम से प्रगति की संस्थापक स्थिति की व्याख्या करता है। इस प्रकार, ऐसा जान पड़ता है कि आर्थिक प्रगति के अपरिहार्य पूर्वा-कांक्षित के रूप में आय की विषमता को मौन रूप में न्यायोचित करार करने में संस्थापक अर्थशास्त्री निर्दोष थे। फिर भी, प्रयुक्त विश्लेषण दो आधारभूत बातों में अपूर्ण है : प्रथमतः, यह वचत-अनुपात पर अन्योन्याश्रित उन्मोक्तता के आचरण के सम्भावित विस्थिति प्रभाव की उपेक्षा करता है तथा द्वितीयतः, यह पूँजी-निपज अनुपात पर साधनों के पुनर्वितरण के सम्भावित निम्नगामी प्रभावों की अवहेलना करता है। साथ ही, मजदूरी कमाने वालों से लेकर गैर-मजदूरी कमाने वालों के बीच आय के पुनर्वितरण, विशेषतः वैसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं पर भी जिन्होंने अवसर की समानता के प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त में अपने को समर्पित कर दिया है, सन्देह

प्रकट किया जा सकता है।¹ ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयों को छोड़कर, हम उप-भोक्ताओं के अन्योन्याश्रित अधिमान के वर्तमान विवेचन को ध्यान में रखते हुए आय के पुनर्वितरण तथा वचत अनुपात के सम्बन्ध पर विचार करें।

आय का समीकरण एवं वचत-अनुपात

ड्यूसेनवेरी ने परिहास के रूप में अथवा अन्यथा विपमता के माध्यम से प्रगति-सम्बन्धी चिर-प्रतिष्ठित विचार पर ऐसा सुभाव देते हुए कि उस समाज में, जो अमुक के बराबर होकर रहने की संस्थागत मनोवैज्ञानिक आदत के वश में है, 'विपमता में कमी से वचत की औसत-प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है,'² प्रश्नवाचक चिह्न लगाया है। संभव है कि इस प्रकार का प्रस्ताव 'न्यून उपभोग' के समर्थकों के इस विश्वास को, कि समर्थ माँग की अपर्याप्तता का शिकार बन जाने वाली एक विकसित अर्थ-व्यवस्था में आय का समान वितरण उपभोक्ता की भाँग में वृद्धि कर सकता है, हतोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया गया हो। फिर भी, जहाँ तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है, अधिक समानता एवं पूँजी में वृद्धि की संगतता में केन्सीय विश्वास को दृढ़ बनाने के कार्य पर ड्यूसेनवेरी के उपर्युक्त सुभाव का संभवतः अनभिमत प्रभाव पड़ता है।

निम्नांकित विवेचन के लिए हम लोग यह एक व्यापक मान्यता स्थिर करते हैं कि सम्बद्ध अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था विदेशी वस्तुओं के आयात पर जो अन्तर्राष्ट्रीय महानुभावों के बराबर होकर रहने में सहायक सिद्ध होती है, प्रभावपूर्ण

1. इसके अनुरूप, एक भारतीय अर्थशास्त्री का कहना है कि आर्थिक सिद्धान्त (संस्थापक) से हमें यह पता चलता है कि अर्थ-व्यवस्था में वचत को बढ़ाने का एक तरीका आय को निर्धन व्यक्तियों से लेकर धनिकों के बीच पुनर्वितरण करना है। किन्तु वर्तमान समय में एक प्रजातन्त्र देश में इस प्रकार की नीति राजनीतिक दृष्टि से कितना सम्भव तथा सामाजिक दृष्टि से वांछनीय भी है, यह कहना कठिन है। (देखें, डी० भा 'फिसकल पॉलिसी एन्ड द इकॉनामिक डिबेलपमेन्ट ऑफ अन्डर-डिवेलप्ड कन्ट्रीज', इण्डियन जनरल ऑफ इकॉनामिक्स, जुलाई, 1956।)
2. देखें, जे० एस० ड्यूसेनवेरी, इनकम, सेविंग एण्ड दि थियरी आफ कन्ज्यूमर बिहेवियर, कैम्ब्रिज, 1949, पृ० 44; साथ ही देखें एच० जी० जान्सन : 'दि इफेक्ट्स आफ इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन आन एग्रीगेट कन्जम्पशन विथ इंटरडिपेंडेंस आफ कन्ज्यूमर प्रेफरेन्सिज', इकॉनामिका मई, 1952। इन दोनों लेखकों का सम्बन्ध विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से है, न कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में आर्थिक विकास की समस्या के लिए आय के समीकरण के आशय से।

नियंत्रण (उदाहरण के लिए, चयनात्मक शुल्क दर एवं अनेक विनिमय-दर के रूप में) रखती है।¹ इस प्रकार की मान्यता हमें आंतरिक आय के समीकरण (लौरेंज-वक्र के अर्थ में) एवं उपभोग (अथवा वचत) अनुपात के सम्बन्ध को पृथक् करने के लिए अनुप्रेरित करती है। अन्य सबद्ध मान्यताओं का उल्लेख यथास्थान किया जाएगा।

मान लिया कि दो हुई राष्ट्रीय आय (Y) का एक अंश निम्न आय वाले परिवारों (Y_1) में, दूसरा अंश मध्यम आय वाले परिवारों (Y_2) में तथा शेष भाग उच्च आय वाले परिवारों (Y_3) में समाप्त हो जाता है, जिससे :

$$Y = Y_1 + Y_2 + Y_3 \quad (9)$$

$$\frac{Y_1}{Y} = \mu, \quad \frac{Y_2}{Y} = \epsilon, \quad \frac{Y_3}{Y} = 1 - \mu - \epsilon \quad (10)$$

जिसके वितरण अनुपात है।

पुनः, हम कुल वास्तविक उपभोग व्यय (C) का विभाजन भी इस तरह करते हैं - एक अंश निम्न आय वाले परिवारों (C_1), दूसरा भाग मध्यम आय वाले परिवारों (C_2) तथा शेष भाग उच्च आय वाले परिवारों (C_3) में समाप्त हो जाता है, यानी

$$C = C_1 + C_2 + C_3, \quad (11)$$

यहाँ पुनर्वितरण के अन्योन्याश्रित प्रभाव को देखने के लिए प्रत्येक वर्ग के परिवारों की उपभोग-सम्बन्धी आदतों को स्पष्ट करना अनिवार्य है। यह मान लिया जाएगा कि पहले एवं तीसरे वर्ग का उपभोग केवल उनके परिवार की अपनी-अपनी आय पर निर्भर करता है, जबकि द्वितीय वर्ग का उपभोग इनकी अपनी आय के अतिरिक्त अशत पहले एवं तीसरे वर्ग की आय पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, मध्यम वर्ग के परिवार को इस अर्थ में प्रति-स्पर्धात्मक माना जाता है कि उनका उपभोग स्पष्टतः अन्य दो वर्गों के परिवारों के उपभोग द्वारा प्रभावित होता है। प्रथम एवं तृतीय वर्गों के उपभोग में परिवर्तन का द्वितीय वर्ग के उपभोग पर किसी हद तक प्रभाव पड़ता है, जिसकी अभी व्याख्या करनी है।

1. देखें, आर० नवसें, प्रोव्लेम्स आफ कॅपिटल फॉर्मेशन इन अडर-डिवेलप्ड कंट्रीज पृ० 577-9 अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में अन्तर्राष्ट्रीय धनवान महानुभावों की 'स्पष्ट उपस्थिति' में आंतरिक वचत को बढ़ाने की कठिनाइयों की विवेचना के प्रयासस्वरूप, नवसें ने, ड्यूसेनवेरी के अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के प्रदर्शनात्मक प्रभाव का, जिसका आशय अंतर्राष्ट्रीय समायोकरण एवं विकसित तथा अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के बीच उपभोग-स्तर की विस्तृत खाई को कम करने की इच्छा है—प्रयोग किया है।

अब समीकरण (11) के दाहिने पक्ष को तीन पृथक् उपभोग-फलन के रूप में निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है :

$$C_1 = a_1 Y_1 = a_1 \mu Y, \quad (12)$$

$$C_3 = a_3 Y_3 = a_3 (I - \mu - \varepsilon) Y, \quad (13)$$

और

$$C_2 = \alpha C_1 + \beta C_3 = [\alpha a_1 \mu + \beta a_3 (I - \mu - \varepsilon)] Y, \quad (14)$$

यहाँ a_1 सम्पूर्ण निम्न आय वाले परिवारों की निम्न आय से उपभोग की औसत एवं सीमांत क्षमता है, a_3 सम्पूर्ण आय वाले परिवारों की ऊँची आय से उपभोग की औसत एवं सीमांत क्षमता है, α सम्पूर्ण मध्यम आय वाले परिवारों की निम्न आय वाले परिवारों के उपभोग की प्रतिस्पर्धा करने की एवं β मध्यम आय वाले वर्गों की ऊँची आय वाले वर्गों के उपभोग में प्रतिस्पर्धा करने की औसत तथा सीमांत क्षमता है। यहाँ आय एवं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के बीच प्रतिलोम सह-सम्बन्ध की सामान्य मान्यता के अनुसार $a_1 > a_3$ है। जहाँ तक प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है, ऐसा मान लेना उचित जान पड़ता है कि मध्यम आय वाला वर्ग, निम्न आय वाले वर्ग की अपेक्षा ऊँची आय वाले वर्ग के उपभोग को अधिक महत्त्व प्रदान करता है, यानी $\beta > \alpha$ है। इसका आशय यह है कि मध्यम आय वाला वर्ग निम्न आय वाले वर्ग के उपभोग-परिवर्तन के परिणामस्वरूप अपने उपभोग में जो वृद्धि करता है, उससे अधिक मात्रा में वृद्धि वह ऊँची आय वाले वर्ग के उपभोग में परिवर्तन के परिणामस्वरूप करता है।

समीकरण (12), (13) एवं (14) को मिलाने से समीकरण (11) अब इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है :

$$C = [a_1 \mu + \alpha a_1 \mu + \beta a_3 (I - \mu - \varepsilon) - a_3 (I - \mu - \varepsilon)] Y, \quad (15)$$

जिससे हमें सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था (c), के उपभोग की औसत प्रवृत्ति प्राप्त होती है :

$$\frac{C}{Y} = c = a_1 \mu + \alpha a_1 \mu + \beta a_3 (I - \mu - \varepsilon) + a_3 (I - \mu - \varepsilon), \quad (16)$$

जो यह बतलाता है कि यदि आय का पुनर्वितरण तीसरे वर्ग से पहले वर्ग में किया जाता है (जो ε को स्थायी रखकर उच्च μ एवं निम्न $I - \mu - \varepsilon$ के रूप में व्यक्त होता है), तो इस प्रकार के पुनर्वितरण से उत्पन्न आय-प्रभाव तथा अन्योन्याश्रित प्रभाव से उपभोग की औसत राष्ट्रीय-क्षमता (c) में कमी हो सकती है। स्पष्टतः समीकरण (16) यह सूचित करता है कि पुनर्वितरण का मध्यम आय वाले वर्ग पर इस प्रकार का अन्योन्याश्रित प्रभाव पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय में इसके उपभोग की औसत एवं सीमांत-क्षमता घट जाएगी, $\alpha a_1 \mu + \beta a_3 (I - \mu - \varepsilon)$, उच्च आय वाले वर्ग पर इसका ऐसा आय-प्रभाव पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय में इसके उपभोग की औसत एवं

मीमात-क्षमता घट जायगी, $a_3(I-\mu-\epsilon)$ और निम्न आय वाले वर्ग की आय पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय में इसके उपभोग का औसत सीमात बढ़ जाएगा, $a_1\mu$ । इसका अन्तिम परिणाम यह होता है कि राष्ट्रीय उपभोग अनुपात (c) कम हो जाता है। अतएव, यदि निम्न आय वाले वर्ग की निम्न आय में से उपभोग की औसत एवं सीमात क्षमता उच्च आय वाले वर्ग की उच्च आय की अपेक्षा अधिक है ($a_1 > a_3$) तो आय के समीकरण के परिणामस्वरूप कुल उपभोग में सन्निहित वृद्धि $\beta < 0$ के विपरीत अन्योन्याश्रित प्रभाव के रहते हुए सूचक विस्थिति-विलकुल ह्रास हो जाता है।

चूँकि राष्ट्रीय बचत-अनुपात $s = I - c$ के द्वारा दिया हुआ है, अतएव एक स्थायी पूँजी-निपज अनुपात (b) वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की विकास-दर के लिए समीकरण (16) का आशय निम्नांकित रूप में देखा जा सकता है।

$$G_k = \frac{I - [a_1\mu + \alpha a_1\mu + \beta a_3(I-\mu-\epsilon) + a_3(I-\mu-\epsilon)]}{b} \quad (17)$$

जो यह बतलाता है कि विकास की दर (G_k) में तभी वृद्धि हो सकती है, जबकि समीकरण (9) से (16) द्वारा वर्णित आय समीकरण के अन्योन्याश्रित प्रभाव एवं आय-प्रभाव की परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय बचत अनुपात में वृद्धि होती है।

उपर्युक्त विवेचन यह बतलाता है कि आय की विषमता पर आयुत-घनिकों के उपभोग-स्थगन के सम्बन्ध में सत्यापक मान्यता उतनी ही अनिश्चयक है, जितना कि यह पथ-भ्रष्ट करने वाली है। यह इस बात को भी बतलाता है कि प्रबल समानता एवं कल्याण की भावना वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के बराबर होकर रहने एवं उपभोक्ता के अन्योन्याश्रित अधिमान के सामाजिक मनो-वैज्ञानिक तत्त्व से सार-ग्रहण द्वारा प्राप्त आर्थिक प्रगति की आय की अधिक समानता के साथ अनुमित असंगति के सम्बन्ध में, इतना आशंकित नहीं होना चाहिए।

पूँजी-निपज अनुपात

अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि साधनों के पुनर्विनिधान के परिणाम-

- वर्तमान विश्लेषण एस० कुजनेट्स के सशयवाद का यह कह कर कम-से-कम अंशतः समर्थन किया है : "साधारण उपमाओं में खतरा है, ऐसे तर्क देने में कि चूँकि पहले पश्चिमी यूरोप में आय के विषम वितरण से बचत का सचय हुआ और आधार-भूत पूँजी-निर्माण की वित्तीय आधार प्राप्त हुआ, अतएव इसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में आय की वर्तमान विषमता को बनाये रखना अथवा बढ़ाना आवश्यक है।"—देखें इसकी 'इकोनामिक ग्रोथ एण्ड इनकम इन इन-इनक्वेलिटी', पूर्व उद्धृत।

स्वरूप, चाहे यह किसी भी प्रकार से क्यों न हुआ हो, पूँजी-निपज अनुपात में कमी, अथवा दूसरे शब्दों में, पूँजी की उत्पादकता में वृद्धि होगी अथवा नहीं। इस प्रकार विचार के पूर्व, यह मान लिया जाता है कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों अथवा उद्योगों के बीच आर्थिकसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण में घोर विषमता व्याप्त है तथा दी हुई अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न उत्पादकता निहित है।

पूँजी का पुनर्विनिधान एवं उत्पादकता

मान लिया कि कोई अर्थ-व्यवस्था कृषि एवं उद्योग, दो क्षेत्रों में विभक्त है, तो पूर्ण प्रयुक्त रहने पर पूँजी के कुल वास्तविक कोष (K) को कृषि-संबंधी पूँजी (K_a) तथा औद्योगिक पूँजी (K_i) में विभक्त किया जा सकता है, जिससे कि

$$K = K_a + K_i, \quad (18)$$

जिसका वितरण अनुपात है—

$$\frac{K_a}{K} = \lambda, \quad \frac{K_i}{K} = I - \lambda. \quad (19)$$

मान लिया कि पूर्ण-क्षमता निपज (γ) के दो अंग कृषि-सम्बन्धी निपज (γ_a) तथा औद्योगिक निपज (γ_i) है, जिससे कि

$$Y = Y_a + Y_i \quad (20)$$

तब श्रम को दिया हुआ मानकर निपज को पूँजी एवं वितरण का फलन मानकर स्पष्ट किया जा सकता है :

$$Y_a = \sigma_a K_a = \sigma_a \lambda K. \quad (21)$$

$$Y_i = \sigma_i K_i = \sigma_i (I - \lambda) K. \quad (22)$$

यहाँ इस आधार पर कि औद्योगिक क्षेत्र को कृषि-क्षेत्र की अपेक्षा श्रेष्ठतम टेक्नो-लॉजिकल जानकारी तथा नवाचार-सम्बन्धी पटुता प्राप्त है यह मान लिया जाता है कि औद्योगिक पूँजी (σ_i) की औसत एवं सीमांत क्षमता कृषि-पूँजी (σ_a) से उच्च है।

प्रतिस्थापित एवं नये क्रम से रखने पर हमें संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए पूँजी की औसत उत्पादकता प्राप्त होती है।

$$\frac{Y}{K} = \sigma = \sigma_a \lambda + \sigma_i (I - \lambda), \quad (23)$$

जो यह बतलाता है कि $\sigma_i > \sigma_a$ होने पर पूँजी-वितरण अनुपात में $(1 - \lambda)$ वृद्धि के

परिणामस्वरूप सामान्य रूप से पूँजी की औसत क्षमता (σ) में वृद्धि हो सकती है। दूसरे शब्दों में, उच्च औसत एवं सीमात उत्पादकता वाले औद्योगिक क्षेत्र के पक्ष में वास्तविक पूँजी के पुनर्विनिधान से सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए पूँजी-निपज अनुपात कम हो जाएगा। अर्थ-व्यवस्था को विकास-दर के लिए पूँजी-निपज अनुपात में इस प्रकार के विनिधान-प्रेरित परिवर्तन का आशय रूपान्तरित विकास समीकरण के रूप में देखा जा सकता है

$$Gk = \frac{s}{b} = s \frac{I}{b} = s\sigma = s[\sigma\lambda + \sigma_1(1-\lambda)], \quad (24)$$

जहाँ पहले की ही तरह s वचत-अनुपात तथा b पूँजी-निपज अनुपात है। समीकरण (24) यह स्पष्ट करता है कि यदि वचत-अनुपात स्थायी रहता है, तो भी जब तक $\sigma_1 > \sigma\lambda$ होगी, तब तक कृषि-क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में वास्तविक पूँजी-पुनर्विनिधान के परिणामस्वरूप निपज की वृद्धि की दर में वृद्धि हो सकती है।

यही विश्लेषण एवं तर्क उम अर्थ-व्यवस्था के साथ भी लागू होता है, जिसे विभिन्न उत्पादकता वाले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। किन्तु, ऐसी स्थिति में पूँजी के पुनर्विनिधान में अधिक राजनीतिक एवं दार्शनिक कठिनाइयाँ होंगी। फिर भी, विभिन्न उत्पादकता वाले भारी तथा हल्के उद्योगों अथवा निर्यात-सम्बन्धी अथवा घरेलू उद्योगों के बीच पूँजी के पुनर्विनिधान में कम ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। समीकरण (18) से (24) तक वर्णित हमारे मॉडल में, इस प्रकार अन्तर-उद्योग पुनर्विनिधानों के अनुरूप वताने के लिए आसानी से संशोधन किया जा सकता है।

श्रम का पुनर्विनिधान एवं उत्पादकता

पूँजी एवं टेक्नोलॉजी को दिया हुआ मानकर, अब हम अर्थ-व्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, श्रम के पुनर्विनिधान के सम्भावित प्रभावों पर भिन्न-भिन्न उत्पादकता वाले विभिन्न प्रकार के श्रम की उपस्थिति की मान्यता के आधार पर, विचार करें। पुनः हम उत्पादन के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पूर्ण-नियुक्त श्रम-संख्या के पुनर्विनिधान के विशेष तकनीक से निष्कर्ष निकालेंगे।

एक दी हुई पूर्ण-नियुक्त श्रम-संख्या (N) को अकुशल, श्रम (Nu) एवं कुशल श्रम (Ns) में अलग किया जाय, जिससे

$$N = Nu + Ns, \quad (25)$$

जिसका वितरण अनुपात है।

$$\frac{Nu}{N} = r, \quad \frac{Ns}{N} = 1 - r \quad (26)$$

जहाँ तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, यहाँ मान्यता यह है कि श्रम-वितरण अनुपात r बहुत बड़ा है। इसका आशय यह है कि टेक्नोलॉजी के निम्न स्तर, विस्तृत तकनीकी शिक्षा के अभाव, गहन उपस्करों के अभाव एवं विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने (उदाहरण के लिए देशी विद्यार्थियों को विदेशी तकनीकी विद्यालयों में भेजना) अथवा विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं के अपेक्षाकृत उच्च व्यय के परिणामस्वरूप, कुशल श्रम पूँजी की ही तरह दुर्लभ है।

पुनः यह मान लो कि कुल निपज अकुशल श्रम के उत्पादन (Y_u) तथा कुशल श्रम के उत्पादन (Y_s) के बीच विभक्त की जा सकती है, जिससे,

$$Y = Y_u + Y_s, \quad (27)$$

जिसके दाहिने पक्ष को इस प्रकार से उल्लिखित किया जा सकता है :

$$Y_u = pu Nu = purN, \quad (28)$$

$$Y_s = psNs = ps (1-r) N \quad (29)$$

यहाँ pu एवं ps क्रमशः अकुशल एवं कुशल श्रम की उत्पादकता हैं (दोनों परिस्थितियों में स्थायी प्रतिफल के आधार पर औसत एवं सीमान्त उत्पादकता समान हैं)। यहाँ भी यह मान्यता है कि अकुशल श्रम की अपेक्षा कुशल श्रम की सीमान्त उत्पादकता ऊँची है, $pu > ps$, तथा अकुशल श्रम अपने को कुशल क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के योग्य हैं। इन मान्यताओं के आधार पर, Y_s क्षेत्र में पूर्ण नियुक्त श्रम का पुनर्वितरण सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए श्रम की औसत उत्पादकता में निम्न प्रकार से वृद्धि करेगा :

$$\frac{Y}{N} = p = pur + ps (1-r) \quad (30)$$

समीकरण (30), यद्यपि कुशल श्रम के वितरण अनुपात $(1-r)$ में वृद्धि के द्वारा औसत उत्पादकता को बढ़ाने की सम्भावना को स्पष्ट करता है, फिर भी, अच्छे प्रशिक्षण, उन्नत अमिरुचि, अथवा उपाजित कुशलता के चलते अकुशल श्रम की क्षेत्रीय क्षमता (उच्च pu) में वृद्धि के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए श्रम की औसत उत्पादकता में वृद्धि की सम्भावनाओं को पृथक् नहीं करता।

समीकरण (30) को ध्यान में रखकर तथा Y/N को पूँजी-निपज अनुपात को प्रभावित करने वाली स्वतन्त्र इकाई के रूप में समझ कर हम वाद वाले अनुपात को संशोधित रूप में निम्नांकित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं :

$$\frac{K}{Y} = b = \frac{K/N}{Y/N} = \frac{K/N}{pur + ps (1-r)} \quad (31)$$

पूँजी-श्रम अनुपात को 0 के द्वारा निर्देशित करते हुए हम स्थायी वचत-

अनुपात (s) वाली अर्थ-व्यवस्था की विकास-दर के लिए समीकरण (30) एवं (31) के आशय को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं :

$$Gk = \frac{s}{0/[pur + ps(I-r)]}, \quad (32)$$

जो बचत अनुपात (s) एवं पूँजी की गहनता के गुणक (0) के स्थायी रहने पर कुशल श्रम के वितरण अनुपात ($I-r$) में वृद्धि के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण विकास दर (Gk) में वृद्धि की सैद्धान्तिक सम्भावनाओं को व्यक्त करता है।

अतएव, औद्योगीकरण-सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण नियुक्ति की स्थिति में दी हुई श्रम-सदया के उन क्षेत्रों तथा उपयोगों में, जिनमें प्रमाण के रूप एवं पूँजी की उत्पादकता ऊँची हो, पुनर्विनिधान की योजना सम्मिलित कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार का विश्लेषण विभिन्न उत्पादकता वाले प्राकृतिक साधनों (भूमि) के पुनर्विनिधान के लाभदायक प्रभाव के सम्बन्ध में भी किया जा सकता है। किन्तु, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि पूर्ण नियुक्त साधनों के पुनर्विनिधान को निर्बाध मूल्य-यन्त्र की मरजी पर छोड़ दिया जा सकता है। इसका कारण यह है कि निर्बाधों नीति की स्थिति में आर्थिक साधनों के दीर्घकालीन तथा खतरनाक कार्यक्रम से हटाकर शीघ्र लाभ प्रदान करने वाले, किन्तु सदा उत्पादक नहीं, कार्यक्रम में लगाने की सम्भावना पाई जाती है। श्रम-शक्ति लाभबन्दी के लिए सार्वजनिक श्रम-नियोजना-लयों के साथ-साथ योग्यता-प्राप्त, निपुण शिल्पियों तथा विशेषज्ञों के राष्ट्रीय रॉस्टरों से उत्पादक पुनर्विनिधान में बहुत अधिक मुविधा होगी। साथ ही, प्रशिक्षित व्यक्तियों के अभाव वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को विदेशी शिल्पियों तथा विशेषज्ञों के उत्प्रवासन की प्रोत्साहन देने वाली राष्ट्रीय नीति से भी बहुत अधिक सहायता प्राप्त होगी।

अध्याय 8

आर्थिक विकास में मौद्रिक भूमिका

विकास-सम्बन्धी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मौद्रिक विचारधारा की वर्तमान स्थिति बहुधा इस शिकायत में प्रतिबिम्बित होती है कि अर्थशास्त्री एवं मौद्रिक अधिकारी अब भी उत्तम बैंकिंग-सम्बन्धी सुविधा शैर-राजनीतिक केन्द्रीय बैंकिंग-सम्बन्धी नीति एवं लोचपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था की वांछनीयता के सम्बन्ध में विहित सामान्य वार्त्ता ही प्रस्तुत करते हैं।¹ फिर भी, कम-से-कम दो आधुनिक अर्थशास्त्रियों—केन्स एवं शुम्पीटर ने दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व एवं विकास के सम्बन्ध में मौद्रिक भूमिका (कुछ अर्थ में) के कारणात्मक महत्त्व पर जोर दिया है। केन्स सार्वजनिक साख (यानी राजकीय प्रतिकारी उधार एवं व्यय तथा विश्व-बैंक के उधार देने की क्रियाएँ) को आन्तरिक स्थायी विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास दोनों की एक आवश्यक शर्त मानता था। साथ ही, दीर्घकाल में प्रवल निवेश के सहायक प्रोत्साहक के रूप में वह सस्ती मुद्रानीति के पक्ष में था। दूसरी ओर, शुम्पीटर निजी साख को आर्थिक विकास का एक प्रमुख परिवर्ती तथा साहसोद्यम एवं नवीन क्रिया का एक अपरिहार्य

-
1. उदाहरण के लिए देखें सी० आर० ह्विटलेसी, रिलेशन ऑफ मनी टू इकॉनामिक ग्रोथ, 'अमेरिकन इकॉनामिक रिव्यू, मई, 1956। साथ ही, देखें जे० जी० कर्ले एवं ई० एस० शा, फाइनान्शियल एस्पेक्ट्स आफ इकॉनामिक डिवेलपमेन्ट', पूर्व उद्धृत, सितम्बर, 1955; आर० एफ० हैरोड की पुस्तक डायनेमिक इकॉनामिक्स (लेक्चर 5) में 'इज़ इन्टरेस्ट ओवर्सलीट' ? जोन रोविन्सन के 'दि रेट ऑफ इन्टरेस्ट ऐटसेटा', में 'दि रेट ऑफ इन्टरेस्ट' (अध्याय 1 से 6); एस० पाल, 'सम एस्पेक्ट्स ऑफ मोनीटरी एन्ड फिसकल पॉलिसीस फॉर इकॉनामिक ग्रोथ इन अन्डर-डिवेलप्ड कन्ट्रीज' 'इन्डियन जनरल ऑफ इकॉनामिक्स, जुलाई, 1956। केवल अन्तिम लेखक का ही सम्बन्ध विशिष्ट रूप से अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से है, यद्यपि इसका विश्लेषण मुख्यतः ऐतिहासिक और सांस्थानिक है।

सहायक समझता था। केन्स एव शूम्पीटर की हम मौद्रिक अन्तर्दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए, इस अध्याय में आर्थिक विकास की वित्तीय भूमिका (जिस पर पृथक् रूप से अगले अध्याय में विचार किया जायगा) से भिन्न, मौद्रिक भूमिका की गणना की जाएगी।

वर्तमान अध्याय में स्पष्ट रूप से निम्नांकित विषयों का विवेचन किया जायगा : (क) साख, ब्याज एव विकास के बीच फलनीय सम्बन्ध, तथा (ख) स्फीति एव विकास-विषयक सम्बन्ध। विवेचन के उद्देश्य से हम यह सांस्थानिक मान्यता स्थिर करेंगे कि सम्बद्ध अल्पविकसित अर्थ-व्यवस्था का एक केन्द्रीय बैंक है, इसके अनिश्चित अन्य व्यावसायिक बैंक हैं, जो केन्द्रीय बैंक के नियन्त्रण (कानून अथवा रिवाज के अनुसार) में हैं, जिसका एक मौद्रिक अधिकारी है, जो जनहित में मुद्रा की उपलब्धि एव मूल्य को निर्धारित अथवा प्रभावित करता है।

साख, ब्याज एवं विकास

यह दिखलाया जा सकता है कि निर्विष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत साख की उपलब्धि एव ब्याज की दर निपज में वृद्धि की दर को प्रभावित कर सकती हैं। पहले हम ब्याज की दर को दिया हुआ मानकर साख एव विकास के सम्बन्ध पर पृथक् रूप से विचार करेंगे।

'संवृत' मॉडल

संवृत व्यवस्था समझी जाने वाली अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय में वृद्धि पर मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन के प्रभावों को दिखलाने के लिए केन्स के तरलता-अधिमान सिद्धान्त में निम्न प्रकार का सशोधन लाभदायक होगा। प्रथमतः, हम पूँति की गई एव धारण के लिए माँगी गई मुद्रा के कुल परिमाण के केवल उसी भाग पर विचार करेंगे, जो आय पर निर्भर करती है तथा जिसे केन्स 'लेन-देन' तथा 'एहतिषाती' प्रवृत्तियों का परिणाम बतलाते हैं। इसे उस भाग से पृथक् किया जायगा, जो ब्याज की दर एवं सन्निहित परिकल्पना की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है।¹ यह सशो-

1. केन्स मौद्रिक साम्य के रूप में लिखते हैं कि $M = M_1 + M_2 = L_1(Y) + (L_2(r))$ जिसमें M पूँति की गई मुद्रा का परिमाण है, M_1 'लेन-देन' तथा 'एहतिषाती उद्देश्य' में पूँत की गई मुद्रा का परिमाण, M_2 'परिकल्पना उद्देश्य' से पूँत की गई मुद्रा का परिमाण, $L_1(Y)$ लेन-देन तथा 'परिकल्पना के उद्देश्य' से मुद्रा की माँग का परिमाण है, जो मौद्रिक राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है तथा $L_2(r)$ 'परिकल्पना के उद्देश्य' से माँगी गई मुद्रा का परिमाण है, जो ब्याज की दर पर निर्भर करता है। (देमो, जेनरल थियरी पृ० 190) यहाँ पर हमारा सम्बन्ध मुख्यतः M_1 एवं $L_1(Y)$ के प्रकारान्तर से है।

धन हमें केवल मुद्रा एवं वस्तुओं के बीच चयन (मुद्रा एवं प्रतिभूतियों को छोड़) के अध्ययन तथा मुद्रा एवं आय के बीच के प्रत्यक्ष सम्बन्ध (इनके बीच निवेश की माँग पर व्याज की दर में परिवर्तन के द्वारा परोक्ष सम्बन्ध को छोड़) के विश्लेषण में सहायक होता है। द्वितीयतः, उपभोक्ता वस्तुओं की उपेक्षा कर हम अपने आपको लेन-देन को पूँजीगत वस्तुओं तक सीमित रखेंगे। यह अधिक सामान्य स्थिति की विशिष्ट स्थिति (जैसा कि केन्स के सिद्धान्त में) है, तथा जिसमें व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत लेन-देन दोनों सन्निहित हैं। यह दूसरा संशोधन हमें लेन-देन से सम्बद्ध मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन से उपभोग एवं वचत को अप्रभावित छोड़कर मुद्रा एवं निवेश के सम्बन्ध पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता प्रदान करता है।

इस संशोधित मान्यताओं के आधार पर हम वचत-निवेश के साम्य की स्थिति को निम्नांकित रूप में व्यक्त कर सकते हैं :

$$I = S + \Delta M_1 - \Delta L_1, \quad (1)$$

जिसमें I शुद्ध निवेश है, S वचत है, ΔM_1 , लेन-देन की मुद्रा के परिमाण में वृद्धि है, जिसकी पूर्ति बैंकिंग-व्यवस्था द्वारा की जाती है तथा ΔL_1 व्यापारी-समुदाय द्वारा माँग की जाने वाली लेन-देन की मुद्रा के परिमाण में वृद्धि है।

समीकरण (1) में लेन-देन के लिए माँगी गई अतिरिक्त मुद्रा से अधिक लेन-देन के लिए अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति, $\Delta M_1 - L_1$ की मात्रा के बराबर वचत से निवेश के अधिक होने, $i > S$, की सम्भावना को व्यक्त करता है। I एवं S के बीच विसंगति की यह सम्भावित स्थिति रावर्ट्सन के आज के निवेश-योग्य कोष की माँग के कल की आय में से आज की वचत से असंग्रह (वचानेवाले अपनी वचत से अधिक ऋण देते हैं) की मात्रा के बराबर अधिक होने की स्थिति के अनुरूप है।¹

अब हम समीकरण (1) के परिवर्तियों को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं :

$$I = b \Delta Y, \quad (2)$$

$$S = sY, \quad (3)$$

$$\Delta M_1 = mY, \quad (4)$$

$$\Delta L_1 = \lambda Y. \quad (5)$$

यहाँ Y शुद्ध राष्ट्रीय आय है, b पूँजी-निपज अनुपात, s वचत-अनुपात, m लेन-देन के लिए अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति तथा आय का अनुपात, और λ लेन-देन के लिए अतिरिक्त माँगी गई मुद्रा एवं आय का अनुपात है। यहाँ m को मौद्रिक-नीति-प्राचल समझा जा सकता है, जिसे व्यावसायिक समुदाय की परिवर्तनीय आवश्यक-

1. देखें, डी० एच० रावर्ट्सन, 'सेविंग एण्ड हेडिंग,' इकॉनामिक जनरल, सितम्बर, 1933।

ताओं के अनुरूप तथा व्यापक मौद्रिक उद्देश्यों के अनुसार धैर्य-व्यवस्था घटा-बढ़ा सकती है। जहाँ तक λ का सम्बन्ध है, इसे किसी दिए हुए राष्ट्रीय व्यय-स्तर (Y के रूप में व्यक्त) को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक समुदाय की लेन-देन के लिए कितना अधिक अथवा कम मुद्रा-धारण करने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हुए समझा जा सकता है।

(1) से (6) तक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, समीकरण (1) को इस प्रकार से पुनः लिखा जा सकता है

$$b \Delta Y = sY + mY - \lambda Y = (s + m - \lambda) Y, \quad (6)$$

जिससे मौद्रिक प्राचलों को अन्तर्गन्त करते हुए विकास की निम्नांकित दर प्राप्त होती है।

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s + m - \lambda}{b}, \quad (7)$$

जो यह व्यक्त करता है कि यदि s एवं b को स्थायी रखा जाय, तो $m - \lambda$ वृद्धि से विकास की दर में वृद्धि होगी तथा $m - \lambda$ के स्थायी रहने अथवा ह्रास होने पर यह भी तमश स्थायी अथवा कम होंगी।

निम्न s एवं उच्च b वाला अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए समीकरण (7) के नीति-सम्बन्धी आशय को समझना कोई कठिन नहीं है। क्योंकि समीकरण (7) के अनुसार इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था को लेन-देन के लिए मुद्रा-अनुपात की दी हुई माँग (λ) को तुलना में लेन-देन के लिए मुद्रा-अनुपात की पूर्ति (m) को बढ़ाना होगा अथवा व्यावसायिक समुदाय को लेन-देन के लिए मुद्रा की दी हुई पूर्ति (m) की तुलना में लेन-देन के लिए मुद्रा की माँग (λ) को घटाने के लिए समझना होगा। इस प्रकार, जैसा कि समीकरण (1) से प्रकट होता है, यदि एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था की निवेश के लिए कोष की माँग सदा बचन एवं नव-निर्मित साधन के द्वारा पूर्ण हो जाती है, तो हमने मौद्रिक परिमाण नीति के लिए दोन है।

‘विवृत’ मॉडल

अब विदेशी आर्थिक सम्बन्ध वाली ‘विवृत’ व्यवस्था समझी जाने वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को ध्यान देने से, आर्थिक विकास के लिए शुद्ध विदेशी उधार के प्राचलीय महस्व को बचन करना सम्भव है। इसके लिए हम सन्तुलित व्यापार की सहज मान्यता करेंगे, जिससे राष्ट्रों के बीच पूँजी की गति को विशुद्धतः स्वतः प्रेरित अथवा गैर-स्वातिपूरक समझा जा सके। यह मान्यता हमें ‘पुनर्भुगतान’ की अटिल गौण समस्या के पृथक्करण में भी सहायता देती है; क्योंकि विदेशी निवेश की आय एवं भुगतान (समुद्र-पार पूर्व-निवेश पर प्राप्त या दिया गया शुद्ध व्याज भभाश आदि) बाह्य भुगतान सन्तुलन के चाल खाते में सम्मिलित होते हैं।

जहाँ तक उधार लेने वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, 'पुनर्भुगतान' की यह पिछली समस्या विदेशी पूँजी की सहायता से उत्पादन क्षमता बढ़ाने की प्रधान समस्या से गौण समझी जाती है। साथ ही, यह भी माना जा सकता है कि अधिकांश अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ स्वतन्त्र रूप से (यानी चालू व्यापार—संतुलन का विचार किये बगैर) वह भी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से विशेषतः, पुनर्निर्माण एवं विकासार्थ उधार लेती है।

साम्य की स्थिति में, एक अल्प-विकसित विवृत अर्थ-व्यवस्था का कुल निवेश इसकी कुल वचत के विशेष रूप से बराबर होता है।

$$I_h + L_f S_h = B_f \quad (9)$$

जहाँ पर I_h शुद्ध घरेलू निवेश, L_f विदेशी उधार-दान, S_h घरेलू वचत तथा B_f विदेशी ऋण है। पहले की ही तरह, यहाँ पर भी सभी परिवर्तियों को वास्तविक रूप में दिखलाया गया है। समीकरण (9) का बायाँ पक्ष विवृत अर्थ-व्यवस्था के कुल 'निवेश' एवं दायाँ पक्ष इसकी कुल 'वचत' का प्रतिनिधित्व करता है। यह मान लेना अधिक उचित है कि स्पष्ट कारणों से अधिकांश अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं L_f शून्य, अथवा बहुत कम है; यद्यपि निर्यात आधिक्य वाली कुछ अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में, कम-से-कम समय के लिए क्षतिपूर्क विदेशी उधार-दान (हम लोगों की मान्यता के अनुसार जिसे L_f सम्मिलित नहीं किया है) धनात्मक या अधिक भी हो सकता है।

समीकरण (9) से हमें निम्नांकित रूप में घरेलू निवेश प्राप्त होता है :

$$I_h = S_h + B_f - L_f \quad (10)$$

जो यह बतलाता है कि विदेशी उधारदान से विदेशी ऋण के आधिक्य, $B_f - L_f$ की मात्रा के बराबर से घरेलू निवेश घरेलू वचत $I_h > S_h$ से अधिक हो सकता है।

पुनः हम समीकरण (10) के दोनों पक्षों को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं :

$$I_h = \frac{\Delta Y}{\sigma} \quad (11)$$

$$S_h = sY, \quad (12)$$

$$B_f = yY, \quad (13)$$

और

$$L_f = \delta Y, \quad (14)$$

यहाँ σ पहले की ही तरह शुद्ध निवेश की औसत एवं सीमान्त उत्पादकता है, s घरेलू वचत का अनुपात है, y विदेशों से उधार लेने की औसत एवं सीमांत क्षमता

है, तथा δ विदेशों में उधार देने की औसत एवं सीमांत क्षमता है। यह मान लेना उचित है, कि एक विवृत अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में सामान्य रूप से निम्न σ , निम्न s उच्च y एवं निम्न δ रहता है।

(11) से (14) तक के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए समीकरण (10) को इस प्रकार से पुनः लिखा जा सकता है :

$$\frac{\Delta Y}{\sigma} = sY + yY - \delta Y = (s + y - \delta) Y, \quad (15)$$

जिससे हमें अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्राचल से युक्त निपज में वृद्धि की निम्नांकित दर प्राप्त होती है :

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \sigma (s + y - \delta), \quad (16)$$

जहाँ पर y एवं δ दोनों नीति में हेर-फेर की शर्त पर मौद्रिक प्राचल हैं। समीकरण (16), निरन्तर निम्न s एवं निरन्तर निम्न σ के रहने पर, एक अल्प-विकसित विवृत अर्थ-व्यवस्था की दर पर विदेशों से उधार लेने की औसत क्षमता (y) में वृद्धि अथवा विदेशों को उधार देने की सीमांत क्षमता (δ) में ह्रास के परिणाम-स्वरूप वृद्धि की सैद्धान्तिक सम्भावनाओं को प्रस्तावित करता है।

(9) से (16) समीकरण द्वारा चित्रित 'विवृत' माडल 'कम विकसित देशों' के साधनों एवं उत्पादन-क्षमता को विकसित करते एवं 'सर्वत्र जीवन-स्तर श्रम की दशाओं में सुधार के लिए' विश्व बैंक के बढ़ते हुए महत्वपूर्ण उधारदान-सम्बन्धी क्रियाओं पर केम्स के आशावादी जोर को न्यायोचित ठहराता है।¹ किन्तु, फिर भी यह महसूस किया जाता है कि यद्यपि विश्व बैंक से उधार लेना सामान्यतः आर्थिक दृष्टि से अधिक वाञ्छित तथा राजनीतिक दृष्टि से कम अनुचित समझा जाता है, तथापि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की पूँजी-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सम्भवतः निजी विदेशी निवेश, अन्तर-राज्य निवेश तथा विदेशी अनुदान की भी आवश्यकता पड़ेगी।²

1. पुनर्निर्माण एवं विकासार्थ विश्व बैंक पर द्वितीय आयोग की प्रथम बैठक में 3 जुलाई 1944 वाला इनका प्रारम्भिक विचार देखें।
2. ज्ञात कारणों से अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था विदेशी पूँजी के इन अतिरिक्त साधनों पर कम-से-कम विश्वास करती है। उदाहरण के लिए, एक लेखक ने निजी विदेशी निवेश के महत्त्व को इस आधार पर न्यूनतम घतलाया है कि 'लाभ की प्रवृत्ति,' 'जातीय एवं राजनीतिक सम्बन्ध,' एवं 'उधार देने वाले देशों की भौगोलिक स्थिति' से अत्यधिक प्रभावित होता है। (देखें डी० फ्रा, फिस्कल पॉलिसी ऐंड दि इकॉनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफ अन्डर-डिवेलप्ड कंट्रीज़, पूर्व उद्धृत) जे०

व्याज, पूंजी एवं विकास

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए व्याज की दर का दीर्घकालीन महत्त्व है, जो कि मौद्रिक नीति का एक अन्य मुख्य शस्त्र है—उसकी आधारभूत व्याख्या इन बातों पर निर्भर करती है (क) बाह्य वित्त की प्रधानता (पूर्व अवितरित लाभ के रूप में जमा की गई व्यावसायिक वचत को प्रयोग करने के बजाय बैंकिंग व्यवस्था अथवा पूंजी बाजार से उधार लेना) और (ख) दीर्घ नियोजन क्षितिज वाले नये टिकाऊ संयंत्रों एवं उपकरणों की तीव्र आवश्यकता, भविष्य में जिनके प्रतिफल को मुद्रा के रूप में बढ़ा दिया जा सके। अब यह देखा जाय कि व्याज की दर किस प्रकार से चक्रदार निवेश-विपयक निर्णयों एवं इसके द्वारा आर्थिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती हैं।

हम व्याज की दर को निम्नांकित रूप से दिया हुआ मानकर प्रारम्भ करते हैं :

$$r = L(pY, \bar{M}), \quad (17)$$

जिसमें r मुद्रा एवं ऋण पर दिया गया व्याज है, L माँगी गई मुद्रा की मात्रा है, Y वास्तविक आय, \bar{M} बैंकिंग व्यवस्था द्वारा स्वतंत्र रूप से पूर्ति की गई मुद्रा की मात्रा और p निपज का औसत मूल्य है (अतएव pY मौद्रिक राष्ट्रीय आय है)। समीकरण (17) वास्तव में केन्स का खास तरलता अधिमान फलन है।

समीकरण (17) द्वारा दी गई व्याज की दर शुद्ध लाभ की दर की गणना में निम्नांकित के माध्यम से प्रवेश करती है :

$$\pi = \frac{pY - wN}{qK} - r, \quad (18)$$

जिसमें Y शुद्ध राष्ट्रीय निपज है, N श्रम-निवेश है, K पूँजीवल, π शुद्ध लाभ की दर है, p राष्ट्रीय निपज की प्रति इकाई कीमत, w श्रम-निवेश की प्रति इकाई कीमत अथवा मौद्रिक मजदूरी की दर है, एवं q पूँजी-निवेश की प्रति इकाई कीमत है। समीकरण (18) यह

बाइनर प्रत्यक्षतः विकसित उधार देने वाले देशों के दृष्टिकोण से लिखते हुए निजी विदेशी महत्त्व के सम्बन्ध में निराशवादी विचार व्यक्त करते हैं.....“युद्ध की क्षतियों, भारी कर तथा समाजीकरण से उधार देने योग्य विदेशी निवेश के लिए उपलब्ध सम्भावित पूँजी के कोप में कम-से-कम कुछ देशों में, जो पहले पूँजी के प्रधान निर्यातक थे, बहुत कमी आ गई है।” (देखें, इनकी पुस्तक ‘इन्टरनेशनल ट्रेड एवं इकाँनामिक डिवेलपमेंट, पृ 109) जहाँ तक अन्तर-राज्य उधार देने तथा लेने का सम्बन्ध है। अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ, इनके साथ के राजनीतिक बन्धन से साधारणतया भय खाती हैं। सहायक अनुदान भी इसी प्रकार राजनीतिक प्रभावों से युक्त रहते हैं, अतएव व्यावसायिक सिद्धान्तों पर दिये जाने वाले ऋण की तरह ये उत्पादक नहीं हो सकते।

बतलाता है कि मुद्रा एव ऋण पर दी गई ब्याज की दर जितनी ही निम्न होगी, लाभ की दर उतनी ही ऊँची होगी। यह मान लिया जाता है कि चेतनशील उत्पादक, निम्नांकित उत्पत्ति-फलन की शर्त पर समीकरण (18) द्वारा दी गई शुद्ध लाभ की दर को अधिकतम बनाने है :

$$\frac{Y}{N} = f\left(\frac{K}{N}\right), \quad (19)$$

यहाँ पहले की ही तरह यह मान लिया जाना है कि चक्रदार की मात्रा को व्यक्त करने वाले पूँजी की गहनता के गुणक (K/N) में वृद्धि से श्रम की उत्पादकता (Y/N) में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। $p = Y/N$ एवं $0 = K/N$ मानकर, हम इस मान्यता को निम्नांकित रूप में व्यक्त कर सकते हैं

$$\frac{dp}{d\theta} > 1, \quad (20)$$

वर्तमान में ही हम जिस मान्यता को महत्त्वपूर्ण पायेंगे।

केन्स के पूँजी के सिद्धांत के अनुरूप ही कुल लाभ की दर, यानी शुद्ध लाभ की शुद्ध जमा ब्याज की दर को, उचित बट्टे की दर के रूप में विचार करना है, जो पूँजी के भविष्य के प्रतिफल के वर्तमान बट्टाकृत मूल्य को उस पूँजी के निर्मित करने अथवा प्राप्त करने वाले वर्तमान व्यय के बराबर बनाता है।

$$qK = \frac{pY - wN}{\pi + r}, \quad (21)$$

जिसका दाहिना पक्ष नये पूँजीगत उपकरणों के, जैसा कि केन्स ने कहा था, 'प्रत्याशित प्राप्ति' के वर्तमान बट्टाकृत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है तथा जिसका बायाँ पक्ष, जिसे उसने उस उपकरण का, 'प्रतिस्थापन व्यय' कहा था, का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम K को टिकाऊ मानने हैं और $pY - wN$ के सन्दर्भ में q_k का अवकलन करते हैं, तो हम लोगों की बट्टा-दर $\pi + r$ केन्स की 'पूँजी की सीमांत क्षमता' का संकेतक हो जाता है। इस बात की ध्यान में रखना है कि हम लोगों की प्रत्याशित प्राप्ति अपेक्षित शुद्ध मौद्रिक आय (pY) घटाव अपेक्षित मौद्रिक मजदूरी (wN) का प्रतिफलन है, जबकि हम लोगों की बट्टा-दर में दो तत्वों का समावेश है—शुद्ध लाभ की दर (π) , जो जोखिम एवं अनिश्चितता की मात्रा को मापता है तथा ब्याज की दर (r) , जो सरलता अधिमान की मात्रा को मापता है।

समीकरण (21) से हमें पूँजी की आय (पूँजी-निवेश के व्यक्तिगत उपभोक्ता के दृष्टिकोण से व्यय) प्राप्त होती है जो शुद्ध मौद्रिक राष्ट्रीय आय, घटाव मजदूरी-सम्बन्धी आय (श्रम-निवेश के व्यक्तिगत उपभोक्ता के दृष्टिकोण से व्यय) के बराबर होती है :

$$(\pi + r) q_k = pY - wN \quad (22)$$

जिसके दोनों पक्षों को N से भाग देने तथा नये क्रम रखने से हमें निम्नांकित प्राप्त होता है :

$$\frac{K}{N} = \theta = \frac{P \frac{Y}{N} - w}{(\pi + r)q} = \frac{Pp - w}{(\pi + r)q} \quad (23)$$

समीकरण (23) यह बतलाता है कि पूँजी की गहनता का गुणक θ पूँजी की प्रति इकाई शुद्ध प्रत्याशित प्राप्ति $Pp-w$ से प्रत्यक्ष-रूप में तथा पूँजी की प्रति इकाई व्यय $(\pi + r)q$ से उलटी तरह से परिवर्तित होता है। यहाँ प्रासंगिक बात यह है कि यदि P , p , w एवं q स्थायी हों, तो व्याज की दर r में ह्रास के परिणामस्वरूप θ में वृद्धि हो सकती है। क्योंकि, सम्बद्ध प्रणाली में r ही एक ऐसा है, जिसे मौद्रिक अधिकारी प्रत्यक्ष-रूप से प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी, जैसा कि जोन रॉबिन्सन¹ ने बतलाया है, उत्पादन की किसी प्रक्रिया में श्रम की प्रति इकाई प्रयुक्त पूँजी की मात्रा पर निम्न व्याज की दर का उत्तेजक प्रभाव भी निपज की प्रति इकाई मूल्य में ह्रास, श्रम की उत्पादकता में ह्रास या मजदूरी की दर में वृद्धि (समी θ के अंश के रूप में आते हैं) तथा शुद्ध लाभ की दर में वृद्धि π या पूँजी-निवेश की प्रति इकाई कीमत q (दोनों r के साथ-साथ θ के प्रत्येक रूप में आते हैं) से विस्थित हो सकता है। फिर भी, हमें इस सम्भावना को अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी में स्वतन्त्र परिवर्तन विस्थिति-मूलक प्रवृत्ति के हो सकते हैं।

20-वीं मान्यता को ध्यान में रखते हुए, स्थायी वचन-अनुपात (s) वाली अर्थ-व्यवस्था के विकास की दर $(\Delta Y/Y)$ के लिए 'सस्ती मुद्रा'-नीति के अनुकूल आशय को, यदि हय उपयुक्त विस्थिति परिवर्तनों से प्रतिलोलित नहीं हो जाता है, पूँजी की गहनता के गुणक को पूँजी-निपज अनुपात से सम्बद्ध करते हुए, बतलाना सम्भव है :

$$\frac{K}{Y} = b = \frac{K/N}{Y/N} = \frac{pp - w/(\pi + r)q}{P} \quad (24)$$

और इसलिए

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{b} = \frac{s}{[pp - w/(\pi + r)q]/P} \quad (25)$$

1. देखें, इनकी पुस्तक 'दि रेट ऑफ़ इंटरेस्ट, एट्सेट्रा,' से विशेषतः पृ० 65।
2. यह विशेष रूप से उन उत्पादकों के लिए सत्य है, जिन्हें दूसरों से पूँजीगत वस्तुओं का क्रय करना पड़ता है; क्योंकि शुद्ध लाभ की दर में वृद्धि से पूँजीगत वस्तुओं के क्रय-मूल्य (q) में मजदूरी की दर (w) की अपेक्षा वृद्धि हो जाती है, जिससे कि उत्पादकों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूँजी के बदले श्रम के प्रति-स्थापन के लिए प्रेरणा मिलती है।

समीकरण (25) यह बतलाता है कि अन्य बातों के समान रहने पर निम्न व्याज की दर, पूँजी की गहनता के गुणक (चक्रदार) पर बढ़ते हुए प्रभाव तथा श्रम की उत्पादकता पर इस वादवाले के प्रभाव के द्वारा श्रम-निपज अनुपात b को कम कर देगा और इसलिए जब वचत-अनुपात s स्थायी रहता है, तब विकास की दर $(\Delta Y/Y)$ को ऐंसे ही बढ़ा देगा। ऐसे अन्य प्राचलीय परिवर्तनों तथा विस्थितिमूलक प्रकृति वाले स्वतन्त्र टेक्नालॉजिकल परिवर्तन, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, को छोड़कर, विकास कार्यक्रम तैयार करने के अस्त्र के रूप में 'सस्ती मुद्रा'-नीति के लिए, विशेषतः इन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में जो स्थायी पूँजीगत उपकरणों के भविष्य में अपेक्षित लाभदायक जीवन के ऊपर लाभ में परम वृद्धि के सिद्धान्त का अनुकरण करती हैं,¹ कुछ धेन है, ऐसा जान पड़ता है।

स्फीति एवं विकास*

तीसा में कुछ अर्थशास्त्रियों ने केन्स के पूर्ण रोजगार के सिद्धान्त को स्फीति-विरोधी कहकर इसका विरोध किया था। आज भी हम देखते हैं कि कुछ अर्थ-शास्त्री, स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप में, स्फीति के भय में विकास-सम्बन्धी नीति का विरोध करते हैं। 'स्फीति-जनक' वित्त के द्वारा पूर्ण रोजगार एवं आर्थिक विकास दोनों के विरोध से यह सन्देह होता है कि इसमें निहित आर्थिक तर्क-नियमनवादियों, समाजवादियों, साम्यवादियों, राष्ट्रवादियों, संरक्षणवादियों, नीकरशाही के समर्थकों तथा इन सभी के सम्बन्धियों पर² एक हल्का, छिपा हुआ सैद्धांतिक आक्रमण है। इस

1. ग्रैर-बाज़ारवाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में भी चक्रदार निवेश के सम्बन्ध में, निर्णय में, सम्भवतः व्यय के ऊपर अपेक्षित प्रतिफल की अधिकता को मापने के लिए कुछ बढ़ा दरें सन्निहित रहती हैं।

*यह परिच्छेद प्रारम्भ में 'ए नोट ऑन इन्फ्लेशन एंड डिवेलपमेंट' नामक शीपंक के अन्तर्गत रिरॉन किजैमकु (इटाँनामिक स्टडीज क्वाटर्ली), जापान, जून, 1957 में प्रकाशित हुआ था।

2. यह उद्धरण एफ० मैचल्प के 'दि फाइनाल्स फॉर डिवेलपमेंट इन यूएर कंट्रीज : फॉरेन कैपिटल एवं डोमेस्टिक इन्फ्लेणन' रिरॉन किजैमकु अप्रैल, 1956 से है। नियमनवादियों, समाजवादियों एवं अन्यो को स्फीति के समर्थकों की श्रेणी में शामिल करने की वैधता पर आपत्ति उठाई जा सकती है। मैं स्वयं केन्स के इस विचार से गहमत होने की इच्छा करता हूँ कि सामूहिक बेरोजगारी (और अल्प-रोजगारी) के त्रातिकारी खतरे प्रजातन्त्रात्मक आस्थाओं के लिए स्फीति के सहगामी नियंत्रणों की अपेक्षा अपरिमित रूप में अधिक हानिकारक हैं। जे०

वात का थोड़ा भय है कि स्फीति-विरोधी अड़ंगा लगानेवाले अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को, आर्थिक विकास के ऊपर, मूल्य-स्थायित्व को प्राथमिकता देने के लिए, झुलावा देंगे। किन्तु, यहाँ निर्णायक सैद्धान्तिक प्रश्न यह है कि क्या स्फीति के द्वारा विकास, जैसा कि अल्प-विकसित देशों के अर्थशास्त्री आशापूर्ण ढंग से दावा करते हैं, पूँजी-संचय में सहायक होता है, अथवा, जैसा कि विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के अर्थशास्त्री भयपूर्ण तर्क देते हैं, इसके प्रतिकूल होता है। इस टिप्पणी का उद्देश्य इसी विवादास्पद प्रश्न पर कुछ प्रकाश देना है।

सच्ची स्फीति के प्रमाण

प्रारम्भ में, जिसे केन्स ने विकसित अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्ध तथा अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था से सम्बद्ध 'सच्ची स्फीति' कहा है, के बीच विभेद करना महत्त्वपूर्ण है। जैसा कि सर्व-ज्ञात है, वृद्धिशील समर्थ माँग की तुलना में पूर्ण रोजगार निपज की लोच का अभाव ही, केन्स के अर्थ में, सच्ची स्फीति के अभाव का कार्य करती है, यद्यपि केन्स ने पूर्ण रोजगार-स्तर के पूर्व ही असामान्य कठिनाइयों के परिणामस्वरूप उत्पन्न कुछ स्फीति की सम्भावनाओं की चर्चा की है¹। फिर भी,

ए० शुम्पीटर ने भी अपनी मृत्यु के पूर्व अन्तिम व्याख्यान में नाटकीय ढंग से इस पर बहुत अधिक जोर दिया था।

केन्स के कथन की तुलना कीजिए : 'अतएव जबकि उपभोग की क्षमता एवं निवेश की प्रेरणा की एक-दूसरे के साथ समायोजित करने के कार्य में सन्निहित सरकार के कार्यों में वृद्धि उन्नीसवीं शताब्दी के किसी लोक-प्रचारक अथवा अमेरिका के किसी समकालीन वित्तदाता को व्यष्टिवाद का तीव्र अतिक्रमण जान पड़ेगा। किन्तु, ठीक इसके विपरीत, वर्तमान आर्थिक ढाँचे को सम्पूर्ण विनाश से बचाने तथा व्यक्तिगत प्रेरणा के सफल कार्यान्वयन की शर्त के रूप में एकमात्र व्यावहारिक साधन समझ कर मैं इसका समर्थन करता हूँ।' (जेनरल थियरी, पृ० 380)। जे० ए० शुम्पीटर का कथन : 'चिरस्थायी स्फीति-जनक दबाव नौकरशाही द्वारा निजी कार्यक्रम की प्रथा पर अन्तिम रूप से विजय प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न संघर्ष एवं गत्यवरोध के लिए निजी उपक्रम को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है तथा उन्हें और अधिक नियंत्रण एवं नियमन के पक्ष में तर्क के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। (देखें, इनका मरणोपरान्त प्रकाशित लेख 'दि मार्च इनटू सोशलिज़्म', अमेरिकन इकॉनामिक रिव्यू, मई, 1950)।

1. जेनरल थियरी, पृ० 296-302, निम्नांकित पर विशेष रूप से ध्यान दें : 'यदि हम स्वयं उपकरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए अधिक मध्यान्तर की मान्यता करते हैं, तो अन्ततः पूर्ति की लोच निश्चय ही बहुत अधिक होगी। इस

जहाँ तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, सच्ची स्फीति का उचित प्रमाण पूर्ण क्षमता निपज की लोच के अभाव में पाया जाता है। क्योंकि, इन अर्थ-व्यवस्थाओं में, धर्म का नहीं, वरन् वास्तविक पूँजी का अभाव ही 'मौद्रिक' प्रसार की तुलना में 'वास्तविक' प्रसार के मार्ग में अन्तिम कठिनाई है।

दीर्घकालिक विश्लेषण के रूप में (उदाहरण के लिए, पाँच वर्षों के कार्यक्रम तैयार करने की अल्पकालीन अवधि से अधिक) इसका तात्पर्य यह है कि इस बात का पता लगाना अनिवार्य है कि क्या दीर्घकालिक स्फीति के लिए जो तत्त्व उत्तरदायी हैं, वे ही मूल्य-स्थायित्व के भी तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अथवा नहीं। अधिक स्पष्ट होने के लिए, इस बात की जाँच करनी चाहिए कि क्या तथाकथित स्फीति-जनक वित्त से प्राप्त निवेश का दीर्घकाल में आय-उत्पन्न करने वाले प्रभाव की तुलना में क्षमता-बढ़ानेवाला प्रभाव अधिक होगा, अथवा नहीं। यहाँ पर डोमर के निवेश की दुहरी प्रकृति प्रासंगिक है; क्योंकि यह इस सभावना की ओर संकेत करता है कि $\Delta 1/1$ की दर से विनियोग करनेवाली कोई अर्थ व्यवस्था, यद्यपि गुणक प्रभाव के माध्यम से मौद्रिक प्रसार का अनुभव करती है, फिर भी 'सिमगा प्रभाव' के माध्यम से अधिक वास्तविक प्रसार का अनुभव कर सकती है। डोमर इसी सभावना से इस तथ्य को कि "शान्ति काल में..... स्फीति इतनी विरल होती है" ¹ सम्बद्ध करता है। कई-एक कारणों से हम किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए भी इस प्रकार की सभावना का परित्याग नहीं कर सकते। अब हम इसके कुछ स्वीकार कारणों की एक स्परेखा तैयार करें कि क्यों निवेश में वृद्धि की दी हुई दर उत्पादन-क्षमता में इतना पर्याप्त विस्तार कर सकती है, जिससे कि दीर्घकालिक स्फीति की अनिवार्यता को अल्प करने वाले तज्जनित स्फीति-मूलक प्रभाव को यह निष्फल कर सके।

1. यदि कोई अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था, जो शुद्ध निवेश में $\Delta 1/1$ की दर से वृद्धि का आयोजन करती है, अपने निवेश कार्यक्रम को मुख्यतः टिकाऊ उत्पादक उपकरणों के निर्माण की ओर सयोजित करती है, तो दीर्घकाल में यह 'सिमगा प्रभाव'

प्रकार दूर-दूर तक विस्तृत बेरोजगारी के अन्तर्गत उत्पन्न समर्थ माँग में साधारण परिवर्तन से मूल्य-स्तर में बहुत कम वृद्धि होकर मुख्यतः रोजगार में वृद्धि होती है, जबकि इसमें बड़ा परिवर्तन, जो अप्रत्याशित होने के कारण कुछ अस्थायी कठिनाइयों को उत्पन्न करता है, बाद की अपेक्षा पहले रोजगार के बदले मूल्यों में ही वृद्धि उत्पन्न करता है।' पूर्व-उद्धृत पृ० 300-301)।

1. इ०डी० डोमर, "एक्सपैन्शन एण्ड एम्प्लायमेंट" अमेरिकन इकॉनामिक रिव्यू, मार्च, 1947।

को पूर्ण अवसर प्रदान करेगी और इसलिए सन्निहित, 'गुणक प्रभाव' को, यदि पूर्ण रूप से नहीं, तो कुछ मात्रा में निष्फल बना देगी। व्यवहार में इसका यह अर्थ हो सकता है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था पिरामिड-निर्माण अथवा शस्त्रीकरण की तरह की निवेश की योजनाओं में जान-बूझकर विनियोग नहीं करती है। ये योजनाएँ उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के बगैर ही माँग का सर्जन करती है। यहाँ पर हमारा संबंध निरपेक्ष शुद्ध निवेश¹ की तुलना में शुद्ध निवेश में कुछ वृद्धि ($\Delta 1$) के अवयव गुण्यों की उत्पादकता से है। अतएव, एक मिश्रित विवृत अर्थ-व्यवस्था में $\Delta 1/1$ का $\Delta 1p/1p, \Delta 1g/1g$ और $\Delta F/F$ में अलग-अलग करना पड़ेगा। यहाँ $1P$ शुद्ध निजी निवेश को बतलाता है, $1g$ शुद्ध राजकीय निवेश को बतलाता है और F शुद्ध विदेशी संतुलन को बतलाता है। यदि कोई अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था दीर्घकालिक स्फीति के भय का अल्पीकरण चाहती है, तो उसे शुद्ध निवेश में वृद्धि की दर के उन विशेष अवयवों पर अधिक जोर देना होगा, जिसकी उत्पादकता की संभावना सर्वाधिक हो। यह मान लिया जा सकता है कि शुद्ध निवेश में वृद्धि की राजकीय दर ($\Delta 1g/1g$) को इस संबंध में जान-बूझकर अत्यंत तत्परता के साथ चुना जा सकता है।

2. चूँकि पूँजी-संचय एवं तकनीकी प्रगति दोनों सहगामी होते हैं, अतएव यह तर्क दिया जा सकता है कि शुद्ध निवेश में वृद्धि की दर ($\Delta 1/1$) जितनी ही ऊँची होगी, शुद्ध निवेश के किसी भी स्तर के लिए, निवेश की उत्पादकता में वृद्धि (डोमर की अंकन-पद्धति में σ) की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यदि ऐसा है, तो $\sigma 1$ की दर से बढ़ती हुई उत्पादन-क्षमता अनुमानक $\Delta 1 \propto$ दर से बढ़ती हुई समर्थ माँग से अधिक हो सकती है (जहाँ डोमर की अंकन-पद्धति में σ वचन की सीमांत क्षमता को व्यक्त करता है)। इसी आशय का जोन रॉबिन्सन का यह सुझाव है कि जितना ही अधिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उद्योग के यंत्र-निर्माण करनेवाले क्षेत्र में उत्पादन के तरीकों में सुधार के अवसर उतने ही अधिक होते हैं।¹ जैसा कि जोन रॉबिन्सन का संकेत है पूँजी के गुण में सुधार पूँजी की मात्रा का परिणाम हो सकता है। यदि यह सत्य है, तो तकनीकी प्राचलों σ के मूल्य में वृद्धि का एक तरीका पूँजी की मात्रा में वृद्धि है, या वर्तमान संदर्भ में उचित मौद्रिक एवं वित्तीय नीतियों के द्वारा $\Delta 1/1$ में वृद्धि करना है। विचार करने की यही पद्धति ही हावेल्मो के विचार के पीछे कार्य करती हुई जान पड़ती है :..... "साधारणतया तकनीकी प्राचल रासायनिक सूत्रों एवं यंत्रशास्त्र के नियमों की अपेक्षा मानवीय चुनाव एवं मानवीय आचरण से अधिक सम्बद्ध हैं।² साथ ही, यह मान लेना

1. देखें इनका "नोट्स ऑन दि इकॉनामिक्स ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस", द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट्सेट्टा, मेकमिलन, लंदन, 1952, पृ० 63।
2. देखें इनकी पुस्तक "ए स्टडी इन दि थियरी ऑफ इकॉनामिक इवोल्यूशन, नॉर्थ हालैंड पब्लिशिंग कम्पनी, अमस्टरडम, 1954, पृ० 49।

अधिक सुरक्षित होगा कि निजी उपक्रम की प्रधानता-वाली अर्थ-व्यवस्थाओं में विस्फीति-जनक मंदी की अपेक्षा स्फीति-जनक तेजी, नवीन क्रिया के लिए अधिक सहायक होती है। इस संबंध में, जे०ए० शुम्पीटर की तरह कोई भी व्यक्ति उत्पादकता को अधिकाधिक करने अथवा लागत के अल्पीकरण के उद्देश्य से नवीन क्रिया को प्रोत्साहित करने अथवा वित्त-प्रदान में सरकार के बढ़ते हुए महत्त्व की अपेक्षा नहीं कर सकता। (उदाहरण के लिए, प्रमाणस्वरूप अमेरिका के विश्वविद्यालयों में सरकारी अनुदान के अंतर्गत 'एकघातीय कार्यक्रम' से संबंधित अनुसंधान के कार्यों को देखें।)

3. इस प्रकार, यदि निवेश की उत्पादकता (σ) घट जाती है, तो संभव है कि संपत्ति से प्राप्त आय (विशेषतः मुनाफा एवं लाभान्) से बचाने की सीमात क्षमता एवं इसके साथ ही बचने की संपूर्ण सीमात-क्षमता (α) में भी वृद्धि हो जाय। यदि ऐसा हो, तो अतिरिक्त¹ शुद्ध निवेश के लिए गुणक प्रभाव में ह्रास होगा, जिससे कि $\sigma > 1$ की दर से बढ़नेवाली दी हुई उत्पादन-क्षमता की तुलना में समर्थ मार्ग में $\Delta 1/\sigma$ की निम्न दर से वृद्धि हो सकेगी। σ वृद्धि के इस गैर-म्फीतिक सघटन के अतिरिक्त वचत की उच्च औसत क्षमता की ओर प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है, जिसका उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के लिए लाभदायक प्रभाव होता है। इसके बदले, यदि वचत की सीमात-क्षमता (α) में वृद्धि स्वतंत्र मितव्यय-अभियान के परिणाम-स्वरूप होती है, तो इसका दीर्घकालीन प्रतिरूप (वचत की औसत क्षमता) में वृद्धि हो सकती है, जो उत्पादन-क्षमता के लिए 'सम्भवतः' लाभदायक होती है। उन-अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में जिनमें उपभोग का स्तर निम्न होता है, $\Delta 1/1$ की दर से बढ़ता हुआ साख द्वारा व्यवस्थित शुद्ध निवेश, वैयक्तिक आय पर अपने वृद्धिशील प्रभावों के द्वारा, उपभोक्ता इकाइयों में वचत की आदत को प्रारंभ करने का एक-मात्र व्यवहारिक तरीका है। यदि वास्तविक निवेश में वृद्धि की धनात्मक दर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, ऋण-पत्रों अथवा स्कधों के रूप में निवेश (वित्तीय) की व्यवस्था सौ वर्षों से अधिक तक कार्य करती है, जिससे कि बचाना तथा विनियोग करना एक बड़े वर्ग का हर्षजनक कार्य हो जाता है, तो जैसा कि केन्स ने कहा है¹—आधुनिक अल्प-विकसित, अर्थ-व्यवस्था, वचत की आदत डालने के प्रारंभिक उपाय के रूप में $\Delta 1/1$ की दर से वृद्धि पर विचार कर सकती है।

इन कारणों से बैंक साख अथवा राजकीय घाटे के द्वारा स्थायी धनात्मक दर $\Delta 1/1$ से विनियोग करनेवाली अर्थ-व्यवस्था में 'सच्ची स्फीति' को टाला जा सकता है। निवेश के उत्पादकता-प्रभाव की अपेक्षा अथवा न्यून-आकलन करने पर ही मौद्रिक

¹ देखें-जे०एम० केन्स, एसेज इन परसुएशन, पृ० 84।

राष्ट्रीय आय के आचरण पर इसके गुणक प्रभाव से कोई अत्यधिक भयभीत हो सकता है। डोमर के निवेश की दुहरी प्रकृति इस बात के अनुस्मारक का कार्य करती है कि निवेश के केवल एक पक्ष आय-उत्पादक पहलू पर विचार कर तथा इसके क्षमता-वर्द्धक पहलू की उपेक्षा कर सामान्य मूल्य के अस्थायित्व को कभी बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहना चाहिए। विश्लेषण के इस अंश को समाप्त करने के पूर्व इस बात पर ध्यान देना रुचिकर है कि समर्थ माँग की अपर्याप्तवाली विकसित अर्थ-व्यवस्था में दीर्घकालिक विकास एवं मूल्य-स्थायित्व के लिए आनन्ददायक शक्ति के रूप में माना जाता है।

पूँजी की वृद्धि पर स्फीति का विशिष्ट प्रभाव

हम उन कारणों को सिद्ध कर चुके हैं, जिनके परिणामस्वरूप किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में सच्ची स्फीति घटित अथवा बनी नहीं रह सकती है। फिर भी, तर्क के दृष्टिकोण से, हम यह मान लेंगे कि स्थायी धनात्मक दर $\Delta 1/1$ पर साख से प्राप्त निवेश से कुछ स्फीति उत्पन्न होनी है। अब प्रश्न यह है कि पूँजी की वृद्धि पर स्फीति का संभावित प्रभाव क्या होता है। यह निर्णायक प्रश्न है; क्योंकि औद्योगीकरण-सम्बन्धी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में पूँजी की वृद्धि कुंजी समझी जाती है। इस प्रश्न का जवाब कई तरीकों से दिया जा सकता है।

1. कोई भी व्यक्ति इस बात से शीघ्र सहमत हो सकता है कि अति-स्फीति की चरम स्थिति निजी मितव्यय के विरुद्ध काम करती है। केन्स ने भी इस संबंध में चेतावनी दी थी कि इस प्रकार की स्फीति के अनुभव से बचाने एवं विनियोग करने के आचरण के सम्बन्ध में समाज की मनोवृत्ति में निश्चित रूप से संशोधन होना आवश्यक है।¹ इस प्रकार की अति-स्फीति के अतिरिक्त भी जहाँ तक बचाने एवं विनियोग करने के आचरण पर स्फीति के संघट्टन का सम्बन्ध है, दो बातों की चर्चा अनिवार्य है। प्रथमतः, हमारे समक्ष यह टिप्पणी है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि उस देश में, जहाँ मौद्रिक रूप में व्यक्त परिसम्पत्ति-ऋण-पत्र, बीमा-पॉलिसी और वचत-जमा का परिमाण अपेक्षाकृत कम है, वहाँ स्फीति का प्रभाव कम गम्भीर होता है।² वास्तव में, यह बात अधिकांश अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं, जिनमें मध्यम वर्ग के बचाने वालों की संख्या अपर्याप्त होती है, में लागू होती है।³ दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है

1. परसुएशन, पृ० 91।

2. देखें एच० सी० वालिच का 'मनी, टूडे एण्ड इकॉनामिक ग्रोथ' (जे० एच० विलियम्स के उपलक्ष्य में) 'अंडर-डिप्लेड कंट्रीज एण्ड दि इंटरनेशनल मानिट्री मेकनिज्म', मैकमिलन, न्यूयार्क, 1951।

3. देखें एस० कुजनेट्स, 'इकॉनामिक ग्रोथ एंड इनकम इनइक्वेलिटी, अमेरिकन इकॉनामिक रिव्यू, मार्च, 1955।

कि ऋण एवं इक्विटी वित्त, बाह्य एवं आंतरिक वित्त, तथा निजी एवं सार्वजनिक बचतों के सापेक्षिक महत्त्व के सम्बन्ध में ठोस सूचना अथवा प्रक्षेपण होना चाहिए। क्योंकि, स्फीति का इक्विटी-लाभांश, निगम एवं व्यापार के लाभ तथा कर से प्राप्त राजकीय आय पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। विकासात्मक वित्त की समग्र योजना में इक्विटी-पूंजी, अवितरित लाभ तथा वजट की बचतों इतना अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती है कि निजी बचत पर स्फीति के हानिकारक प्रभाव के सम्बन्ध में सभी आशकाएँ व्यर्थ हो जाएँ।

2 साधारण प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि स्फीति वास्तविक सम्पत्ति, स्कंधों आभूषण एवं स्थायी विदेशी मुद्राओं जैसे स्फीति-जनक बाड़ों में अप-संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। यह दो हुई बचत की प्रकृति को अनुचित रूप में महत्त्व देना है, जबकि सन्निहित वास्तविक प्रश्न का सम्बन्ध बचत के कुल आकार से है। जहाँ तक दो हुई बचत के विनिधान का प्रश्न है, इसकी अधिक उपयुक्त आलोचना दो हुई बचत के लाभदायक, किन्तु दीर्घकालीन दृष्टिकोण से अनुत्पादक कार्यक्रमों में लगाने के खतरे को बतलाना होगा। किन्तु, जैसा कुछ लेखक सोचते हैं, यह मुनाफा-स्फीति नहीं, बरन् स्वयं लाभ की व्यवस्था है, जो दो हुई बचत के अनुचित विनिधान के लिए मूल रूप से उत्तरदायी है। इस प्रकार, ब्रिटेन के मनोरंजन (उदाहरण के लिए, कुत्तों का रेस-पय) तथा जापान के पाचिन्को (पिनबाल) को युद्धोत्तरकालीन पुनर्निर्माण के युग में दुर्लभ पूंजी के अनुचित उपयोग के उदाहरण के रूप में दिया जाता है। यह सब केन्स के इस तर्क कि 'राज्य, जो दीर्घकालीन विचारों तथा सामान्य सामाजिक लाभ के आधार पर पूंजीगत मालों की सीमान्त क्षमता (वर्तमान सन्दर्भ में इसे उत्पादकता सम्पर्क) का पता लगाने की स्थिति में है, निवेश की व्यवस्था में सदा अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करे,' के पक्ष को प्रबल बनाता है। यहाँ एक मुख्य बात पर जोर देना है कि जहाँ एक पूंजी-विपन्न अर्थ-व्यवस्था को सीमित बचत के उत्पादक विनिधान पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, वहाँ इसे बचत के आकार को और अधिक बढ़ाने की आवश्यक समस्या पर सम अधिक ध्यान देना चाहिए। वैयक्तिक संपत्ति-धारकों के द्वारा आत्म-रक्षा के लिए स्फीति-जनक बाड़ों में दो हुई बातों के इस प्रकार के अप-संचय का कोई बहुत गम्भीर परिणाम नहीं होगा।

1. वजट की बचतों के उत्पादक महत्त्व के लिए देखें मेरा 'थोथ मॉडल्स एवं फिस्कल पॉलिसी पैरामीटर्स', फाइनान्स पब्लिक (नीदर लैंड्स) नं० 2/1956।

2. जनरल थियरी, पृ० 164। इसके अतिरिक्त यदि और जब कभी बचत की निजी क्षमता-पूंजी में अपेक्षित वृद्धि के लिए अपर्याप्त सिद्ध होती है, तो केन्स राज्य द्वारा 'सामुदायिक बचत' का भार ग्रहण करने की वाञ्छनीयता पर विचार करते हैं। (देखें, पूर्व उद्धृत, पृ० 376)।

3. इसका एक अन्य सम्भावित जवाब यह भी है कि स्थायी आय वाले वर्ग के विरुद्ध एवं अस्थिर आय वाले वर्ग के पक्ष में वास्तविक आय के स्फीति-प्रेरित पुनर्वितरण से अस्थिर आय वाले वर्ग की वचत की आदतों में होनेवाली कमी से अधिक वृद्धि होगी। इसका तात्पर्य यह है कि स्फीति-प्रेरित पुनर्वितरण के परिणाम-स्वरूप अस्थिर आय से वचाने की सीमान्त-क्षमता स्थिर आय से वचाने की सीमान्त-क्षमता से अधिक हो जाती है। इस प्रकार, वचाने की अवकल सीमान्त-क्षमता के दिया हुआ होने पर, यह सुगमतापूर्वक दिखलाया जा सकता है कि वास्तविक आय के प्रत्येक स्फीति-प्रेरित पुनर्वितरण से संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए वचाने की औसत क्षमता में वृद्धि होगी। इस प्रकार, यदि सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए वचाने की औसत क्षमता में वृद्धि हो जाती है, तो प्रकल्पना यह है कि चाहे हम हेरोड के विकास मॉडल का अनुकरण करे अथवा डोमर के विकास मॉडल का¹, उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की दर में वृद्धि होगी। किन्तु, यह मान लेना अधिक सुरक्षित है कि मुनाफ़ा प्राप्त करने वाले तथा लाभान्वित मिलने वाले पहली श्रेणी के अन्तर्गत के महत्त्वपूर्ण वर्ग हैं तथा व्याज या/और लगान प्राप्त करने वाले दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत के प्रधान वर्ग हैं। मजदूरी से प्राप्त आय को अस्थिर माना जाय अथवा स्थिर, यह किसी ठोस अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत संगठित श्रम के विषय में सौदा करने की सापेक्ष शक्ति पर निर्भर करता है। यदि स्फीति, जैसा कि केन्स ने कहा है, लगान-उपजीवी की सुख मृत्यु को त्वरायित करता है,² तो यह साहसी एवं इसी प्रकार के अन्य वर्गों के उत्साह के लिए और भी ठीक है। दूसरे शब्दों में, यदि स्फीति का प्रभाव वास्तविक आय को व्याज प्राप्त करनेवालों से मुनाफ़ा प्राप्त करने वालों के पक्ष में विवर्तन करना है, तो स्कन्वों एवं ऋण-पत्रों में वित्तीय निवेश की तुलना में पूँजीगत उपकरणों में वास्तविक निवेश अधिक होगा। यह पूँजी-संचय एवं आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन लाभ की चीज होगी।

4. इसका एक दूसरा उत्तर इस संभावना में पाया जा सकता है कि उपभोग

1. देखें आर० एफ० हेरोड, टुवार्ड्स ए डायनमिक इकॉनामिक्स, मैकमिलन, लंदन, 1948, डोमर, पूर्व उद्धृत।
2. जेनरल थियरी, पृ० 376। केन्स निम्नांकित प्रकार के निवेश-मांग समीकरण $1=f(y, p, r)$ तथा मुनाफ़ा को अधिकतम बनाने की स्थिति $e(1)=r$ मानते हैं, जिनमें 1 वास्तविक निवेश है, y अतिरिक्त पूँजी-सम्पत्ति का प्रतिफल है, p पुनस्थापित व्यय है तथा y व्याज की दर, e पूँजी की सीमान्त क्षमता ($e=Y/p$) है।

करने वाले मोग दीर्घकालिक स्फीति की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप, भविष्य में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में और वृद्धि की प्रत्याशा से वर्तमान समय में अधिक व्यय करने की अल्पकालीन क्षमता को रोक कर, अपने उपभोग-व्यय को धीरे-धीरे निम्न स्तर पर समायोजित करेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि ए० सी० पीगू¹ की तरह हम यह मान लेते हैं कि वचत-मूल्य तल से प्रत्यक्ष रूप में और इसलिए वास्तविक नकद जमा के आकार (उदाहरण के लिए वचत खाते, सरकारी प्रतिभूतियों एवं अन्य तरल साधनों—संक्षेप में उपभोक्ताओं में संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने वाले) से प्रतिलोमत सम्बन्ध है, जो बढ़ने हुए मूल्यों का—‘पीगू-प्रभाव’ के ठीक विपरीत वास्तविक आय में से उपभोग को हटानेवाला और वास्तविक की प्रोत्साहित करने का प्रभाव पड़ेगा। पीगू यह मान लेते हैं कि परिसंपत्ति के परिमाण को स्थायी रखा जाता है $A=A$, मया निजी वचत की मात्रा परिसंपत्ति के वास्तविक मूल्य का घटता हुआ फलन है, $dS/d(A/P) < 0$, जिसमें S वचत है तथा P मूल्य-सूचकांक है। इन मान्यताओं के आधार पर, यदि सामान्य मूल्यों से परिसंपत्ति के वास्तविक मूल्य में ह्रास हो, जिससे कि संचय को प्रोत्साहित करने वाले बड़े आधार की इच्छा में वृद्धि हों (‘सुख-सुविधा’ के लिए नहीं, जैसा कि विकसित अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में पीगू तर्क देते हैं किन्तु वर्तमान संदर्भ में सुरक्षा के लिए) तो किसी दी हुई वास्तविक आय एवं व्याज के लिए कुल वचत में अनुमानित वृद्धि होगी।

5. अतः, केवल वचत पर ही जोर देना, मानो यह पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता एवं वर्तमान उपभोग से वंचित रहने की क्षमता दोनों का प्रतिनिधित्व करती हो, अनुचित होगा। क्योंकि, मितव्यय के प्रति समाज की अभिवृत्ति के बावजूद यदि किसी विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था का औद्योगीकरण अधिक समजातीय निपज एवं अधिक लोचपूर्ण औद्योगिक संगठन को प्रोत्साहित करता है, तो पूँजीगत वस्तुओं को उत्पादन करने की इसकी क्षमता में वृद्धि हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि अन्यथा निपज की विपन्न-जातीय वनावट से सबन्ध उपकरणों एवं श्रम की विशिष्टता कम हो जाती है, जिससे की उपभोग नहीं होने के कारण मुक्त माधनों को चाहे किसी कठिनाई के पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सके। इस का तात्पर्य यह भी है कि उद्योग के संगठन का चित्रण इस प्रकार की जटिलता

1. देखें इनका ‘इकॉनामिक प्रोग्रेस इन ए स्टेबल इनवायरन्मेंट’, इकॉनामिका 14/1947। इसमें सन्निहित आर्थिक व्यष्टिभाव-सम्बन्धी युक्ति यह है कि बढ़ते हुए मूल्यों के परिणामस्वरूप मौद्रिक वचत के वास्तविक मूल्य में कमी का प्रभाव व्यक्तिगत उपभोक्ता के लिए अतिरिक्त वचत की सीमान्त उपयोगिता में वृद्धि होती है।

एवं कुसंमंजन की अपेक्षा साधनों की अगतिशीलता, साधनों के अकशल संयोजन, तथा विशिष्ट योग्यता एवं पदार्थों की दुर्लभता से अधिक होता है। एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की कठिनाई यह हो सकती है कि इसकी पूँजीगत वस्तुओं को उत्पन्न करने की क्षमता, न कि बनाने की क्षमता, विकास के अपेक्षित लक्ष्य की दर से बहुत निम्न हो। यदि ऐसा हो, तो इसके लिए स्फीति नहीं, वरन् संरचनात्मक असंमंजन को दोष देना चाहिए। क्या यह मान लेना उचित नहीं है कि बढ़ते हुए मूल्य का वातावरण संरचनात्मक सुधार के लिए सहायक होता है।

उपर्युक्त विवेचन इन दोनों बातों को सूचित करता है। प्रथमतः, पूँजी-संचय की क्षमता-वर्द्धक प्रकृति स्वयं एक विस्फीतिक शक्ति है और द्वितीयतः, अति-स्फीति से कम वृद्धिशील मूल्य, द्रुतगति के औद्योगीकरण के लिए आवश्यक पूँजी-संचय में, बाधा डालने के बजाय इसे प्रोत्साहित करते हैं। यह इस बात को भी बतलाता है कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को, स्फीति के भय के वगैर, यानी इस प्रकार के अनुचित भय के वगैर कि इससे मूल्य-स्थायित्व समाप्त हो जायगा,¹ अपने उत्पादक साधनों

-
1. कुछ विशिष्ट अर्थ-व्यवस्थाओं में 'स्फीति के द्वारा विकास' की निम्नांकित सीमाओं की चर्चा की जा सकती है : (1) गुप्त बेरोजगारी अनुपस्थित अथवा शांत हो सकती है, जिससे कि यह मौद्रिक मजदूरी की दर पर थोड़ा अथवा बिल्कुल निम्नगामी दबाव नहीं दे सकती और मूल्य-मजदूरी की चक्राकार समस्या को उत्तेजित कर सकती है। (2) मुद्रा के घटते हुए वास्तविक मूल्य से हानि की संभावना विक्रय-मूल्य एवं लागत-व्यय के बीच अप्रत्याशित अंतर से लाभ प्राप्त करने की आशा से अधिक हो सकती है, जिससे उत्पादन की अभिप्रेरणा क्षीण हो जायगी। (3) स्फीति के चलते बलात्-वचत में वर्धनशील मुद्रा की क्रम-शक्ति के स्थायित्व में विश्वास की कमी के चलते ऐच्छिक वचत में ह्रास से बिल्कुल समाप्त हो सकती है। (4) अपनी स्थायी आय पर बढ़ते हुए मूल्यों के विपरीत प्रभाव से ऋणदाता इतने अधिक हतोत्साहित हो सकते हैं कि वे अन्य सरकारी ऋण-पत्रों अथवा विकास की योजनाओं के लिए वित्त प्राप्त करने के उद्देश्य से जारी किये गये नये निजी ऋण-पत्रों को न खरीदें। (5) मौद्रिक भ्रम का स्थान वास्तविक प्रयोजन ले सकता है, जिससे कि मजदूरी, व्याज, लगान तथा लाभांश सभी को जीवन-मान के साथ समायोजित करना एक सामान्य नियम बन जाय और इस प्रकार नियमों की वचत एवं निवेश के मूल्य पर उपभोक्ता की माँग को प्रोत्साहित किया जाय। (6) स्फीतिक उधारकर्ता देशों में बढ़े हुए कर, विनिधान की प्राथमिकता विदेशी विनिमय-संबन्धी नियंत्रण, तथा सार्वजनिक नीति के अन्य स्फीति-विरोधी उपाय पूँजी-सम्पन्न राष्ट्रों द्वारा प्रत्यक्ष एवं

अध्याय 9

आर्थिक विकास में वित्तीय भूमिका

राजकोषीय सिद्धांत एवं नीति के महत्त्व में राजस्व से कल्याण की ओर तथा बिल्कुल हाल में, चक्रीय स्थिरीकरण से दीर्घकालिक विकास की ओर ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। इस अध्याय का संबंध दीर्घकालिक विकास में वित्तीय भूमिका से है। विशिष्टतः, हम लोग निम्नांकित का पृथक् रूप से विवेचन करेंगे— (क) अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के अधिकतम विकास में वित्तीय भूमिका-तथा (ख) विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के स्थायी विकास में वित्तीय भूमिका।

अधिकतम विकास के लिए वित्तीय क्रिया*

आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राजकोषीय तरीकों का सचेत प्रयोग हाल में ही विकसित हुआ है। इसका विकास संभवतः युद्ध के पूर्व के विशुद्ध रूप से राजकोषीय नीति के प्रतिचक्रीय पहलू पर केन्स द्वारा दिये गये जोर की प्रति-

* यह परिच्छेद मुख्य रूप से हमारे 'दि फिस्कल रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकॉनामिक डिवेलपमेंट, इण्डिया जरनल ऑफ इकॉनामिक्स, जुलाई, 1956 पर आवृत हैं। पाठकों का ध्यान इसी पत्रिका के इसी अंक में प्रकाशित निम्नांकित निबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है : ओ० प्रकाश, "टेक्सेशन पॉलिसी इन ए ट्रेनजीशनल इकॉनामी;" डी० भ्मा, 'फिस्कल पॉलिसी ऐंड दि इकॉनामिक डिवेलपमेंट ऑफ अंडरडिवेलपड कंट्रीज,' एम० एस० भाटिया, 'दी रोल ऑफ पब्लिक बजटिंग इन एन अंडरडिवेलपड इकॉनामी,' एस० पाल, 'सम एस्पेक्ट्स ऑफ मॉनीटरी ऐंड फिस्कल पॉलिसीज़ फॉर इकॉनामिक ग्रोथ इन अंडरडिवेलपड कंट्रीज।'।

क्रिया तथा हेरोड एव डोमर की तरह का केन्सीयोत्तर विकास-संबंधी विश्लेषण, जो संभवतः नीति को व्यावहारिक रूप देने में सहायक होता है, के परिणाम-स्वरूप हुआ है। हेरोड-डोमर के विकास-संबंधी मॉडल विशुद्धतः अवध-नीति से संबद्ध हैं तथा राजकोपीय तटस्थता की मान्यता पर आधृत हैं। इनका रूपांकन विकसित अर्थ-व्यवस्था के प्रगतिशील साम्य की स्थिति को सूचित करने के लिये किया गया है। अतएव, इनका नीति-मंत्रधो आशय अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की स्थिति के ठीक विपरीत है। फिर भी, हेरोड-डोमर मॉडल केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ये केन्स के स्थायी अल्पकालीन वृत्त-विनियोग सिद्धांत की गतिशील एव दीर्घकालिक बनाने के उत्तेजक प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं, वरन् इसलिए भी कि अल्प-विकसित देश के आर्थिक विकास में स्पष्ट परिवर्तों के रूप में राजकोपीय-नीति प्राचलो के प्रयोग के लिए इनमें सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार के सुधार इस विवेचन के क्रम में किये जायेंगे। इस परिच्छेद में हम लोग अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की उत्पादन-क्षमता के विकास में सरकार के राजकोपीय कार्यों का (क) विनियोक्ता, (ख) बचानेवाला, तथा (ग) आय के पुनर्वितरक के रूप में विश्लेषण करेंगे।

विनियोक्ता के रूप में सरकार

विनियोक्ता के रूप में सरकार के राजकोपीय कार्यों को दिखलाने के लिए वास्तविक सरकारी व्यय (G) को सरकारी निवेश (I_g) तथा सरकारी उपभोग (C_g) में विभक्त करना अनिवार्य है, यानी

$$G = I_g + C_g, \quad (1)$$

जिसमें वर्तमान सदर्भ में I_g को ऐसे उत्पादक कार्यों एवं उपकरणों—जैसे राजपथ, बन्दरगाहों, पुलों, विद्यालयों, अस्पतालों तथा यातायात एवं संचहन-संबंधी सुविधाओं पर राजकीय व्यय का प्रतिनिधित्व करते हुए तथा C_g को अनुत्पादक मदों, जैसे उपभोक्ता वस्तुएँ, सामाजिक सेवाएँ, अस्त्र-शस्त्र एवं पिरामिड पर राजकीय व्यय का प्रतिनिधित्व करते हुए, समझा जा सकता है। इन दोनों प्रकार के सरकारी व्यय के बीच चुनाव करना वैधानिक रुकावट पर निर्भर करता है।

पुनः, हम यह मान लेंगे कि विनियोक्ता के रूप में सरकार के कार्यों को बचाने वाले के रूप में कार्यों से पृथक् करने के लिए राष्ट्रीय बजट को संतुलित बनाया जाता है, यानी—

$$G = T, \quad (2)$$

जिसमें T वास्तविक रूप में करों की मात्रा है। हम लोग करों का शुद्ध वास्तविक राष्ट्रीय आय (Y) के फलन के रूप में उल्लिखित करेंगे :

$$T = z Y; z = \frac{T}{Y}, \quad (3)$$

जहाँ z सरकार के कर लगान की औसत (= सीमांत) क्षमता अथवा वैधानिक नियन्त्रण को ध्यान में रखते हुए केवल कर की दर है।

निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की अन्तःक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए उपभोग एवं निवेश फंक्शन को निम्नांकित रूप में उल्लिखित करना लाभदायक है :

$$C = C_p + C_g = a_p(Y - T) + a_g Y = a_p(1 - z)Y + a_g Y, \quad (4)$$

जिसमें C वास्तविक रूप में कुल उपयोग व्यय, C_p निजी उपभोग, a_p खर्च करने योग्य आय $(Y - T)$ में से उपभोग की निजी औसत (= सीमांत) प्रवृत्ति, a_g राष्ट्रीय एवं सरकारी उपभोग व्यय का परिवर्तनीय औसत अनुपात है तथा शेष पहले की तरह परिभाषित रूप में ही है।

$$I = I_p + I_g = \Delta K_p + \Delta K_g = \frac{\Delta Y}{\sigma}, \quad (5)$$

जिसमें I कुल वास्तविक शुद्ध निवेश, तथा I_p निजी निवेश है। यहाँ चूँकि शुद्ध निवेश-पूर्जी में वृद्धि के बराबर है, $I = \Delta K$ अतएव, जैसा कि डोमर के समीकरण में उपलक्षित है, हम निजी शुद्ध निवेश (ΔK_p) एवं सरकारी शुद्ध निवेश (ΔK_g) दोनों की निपज में वृद्धि (ΔY) के साथ प्रत्यक्ष रूप में तथा निवेश की औसत (= सीमांत) उत्पादकता (σ) के साथ विपरीत रूप में परिवर्तित होते हुए मान सकते हैं। (यानी $\Delta Y = \sigma \Delta K$, $\sigma = \Delta Y / \Delta K$ तथा $\Delta K = \Delta Y / \sigma$ समान हैं)।

हम जानते हैं कि साम्यावस्था में कुल निवेश बराबर होता है कुल आय घटाव कुल उपभोग के, जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं :

$$I = I_p + I_g = Y - C_p - C_g. \quad (6)$$

समीकरण (5) एवं (6) से हमें निम्नांकित रूप में उत्पादन क्षमता में वृद्धि प्राप्त होती है :

$$\Delta Y = \sigma (I_p + I_g) = \sigma (Y - C_p - C_g), \quad (7)$$

समीकरण (1) से (4) तक ध्यान में रखते हुए एवं समीकरण (7) के दोनों पक्षों को Y से विभाजित करने पर हमें निपज की पूर्ण क्षमता वृद्धि की दर (G_k) प्राप्त होती है :

$$\frac{\Delta Y}{Y} = G_k = \sigma [1 - a_p(1 - z) - a_g] \quad (8)$$

इस समीकरण में तीन स्पष्ट राजकोपीय—नीति प्राचल σ , z और as हैं जो उचित क्रियाओं के द्वारा सबन्ध विकास की दरों में वृद्धि के योग्य हैं। अब हम समीकरण (8) के परिचालन—महत्त्व को स्पष्ट करें।

सर्वप्रथम, समीकरण (8) यह बतलाता है कि यदि वर्धनशील सरकारी निवेश (I_g) को यथामाध्य विशुद्ध उत्पादक स्रोतों में लगाने से निवेश की औसत क्षमता (σ) में वृद्धि होती है, तो अन्य बातों के समान रहने पर, पूर्ण क्षमता वाली वृद्धि की दर में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार, केन्स के अल्पकालीन गुणक सिद्धान्त की तरह जब किसी विकास-सम्बन्धी विश्लेषण में, निवेश की क्षमता-सर्जन पहलू को इसके आध-उत्पादक पहलू से अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है, तो I_g में से पिरामिड निर्माण की तरह के व्यय को निकाल देना अनिवार्य है। जिस हद तक सरकारी निवेश उत्पादक कार्यों तक सीमित है (यद्यपि सार्वजनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य-जैसे कम विस्पष्ट मामलों में इसे मापना सुगम नहीं है) उसी हद तक, जैसा कि समीकरण (8) से स्पष्ट है, निवेश की औसत क्षमता (σ) में वृद्धि होगी और इसीलिए जैसा कि समीकरण (8) बतलाता है, पूर्ण क्षमता विकास की दर (G_k) में भी वृद्धि होगी। यहाँ पर थोड़ा खतरा इस बात का है कि σ पर उत्पादक सरकारी निवेश का बुद्धिमान प्रभाव σ पर अनुत्पादक, किन्तु लाभदायक, निजी निवेश (जैसे सराय, रंगशाला, श्रीडा-मच तथा आमोद-प्रमोद-केन्द्र) के ह्रास-मान प्रभाव से बिस्थित हो जाय। यहाँ उद्धार के लिए प्रत्यक्ष नियन्त्रण (जैसे विनिधान की प्राथमिकता) का सहारा लेना पड़ सकता है।

दूसरी ओर, औसत कर की दर (z) में वृद्धि के द्वारा भी पूर्ण क्षमता-विकास दर में वृद्धि की जा सकती है। क्योंकि, जैसा कि समीकरण (4) से स्पष्ट है, z में वृद्धि से व्यय की जाने वाली आय में से निजी उपभोग व्यय में कमी होती है और इसलिए समीकरण (6) के अनुसार वास्तविक आय का वह भाग, जो सरकारी निवेश के लिए उपलब्ध है, बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में, z में वृद्धि का तात्पर्य Y के दिये हुए स्तर पर कुल करों (T) में वृद्धि है और इसलिए समीकरण (2) के अनुसार कुल सरकारी व्यय में वृद्धि है। यदि स्थायी σ के साथ-साथ सरकार के उपभोग की औसत क्षमता (as) स्थायी रहे, तो समीकरण (1) के अनुसार T में वृद्धि के साथ-साथ G में वृद्धि का तात्पर्य निश्चित रूप से सरकारी निवेश की अधिक मात्रा से है। दूसरी क्रिया केन्स के इस सुझाव के अनुरूप, यद्यपि कि विपरीत दिशा में है कि राज्य को अपनी करों की योजना के द्वारा उपभोग की क्षमता पर निर्देशक प्रभाव डालना चाहिए। (एक विकसित अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में केन्स अनुमानतः उपभोग की क्षमता में वृद्धि करना चाहेंगे)।

अन्ततः, स्थायी z एवं σ दिया हुआ रहने पर, सरकार के उपभोग की औसत

क्षमता (a_g) में कमी के द्वारा पूर्ण क्षमता-विकास दर में वृद्धि की जा सकती है। a_g में कमी का प्रभाव सरकारी उपभोग (C_g) में कमी और इसलिए समीकरण (4) एवं (6) के अनुसार सरकारी निवेश में वृद्धि होगी। यहाँ यह बात स्वीकार की जाती है कि Y के किसी भी स्तर के लिए a_g को घटाने के प्रयास में उपभोक्ता उपदान, सामाजिक सेवाएँ, प्रतिरक्षा-सम्बन्धी व्यय एवं स्पष्ट रूप से अन्य अनुत्पादक, किन्तु सामाजिक दृष्टि से लाभदायक राजकीय व्यय को कम करने की व्यावहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से जब अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था कल्याण के प्रति सचेत एवं प्रतिरक्षा के प्रति सचेत राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हो।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि विनियोक्ता के रूप में सरकार पूर्ण-क्षमता विकास की दर में एक सन्तुलित बजट के ढाँचे में, (क) निवेश की औसत उत्पादकता σ में वृद्धि, (ख) कर लगाने की औसत क्षमता z में वृद्धि, तथा (ग) सरकार के उपभोग की औसत क्षमता a_g में कमी के द्वारा वृद्धि कर सकती है।

वचानेवाले के रूप में सरकार

अब सरकार के वचाने वाले के रूप में राजकोपीय कार्य पर ध्यान देने से, हम लोग अपना विश्लेषण सन्तुलित बजट की मान्यता को समाप्त कर प्रारम्भ करेंगे। यह आवश्यक है; क्योंकि जैसा कि नीचे दिखलाया जायगा, सरकारी वचत बजट के आधिक्य की मान्यता पर आधृत है।

मान लिया जाय कि वास्तविक शुद्ध आय एवं कर, अन्तरणरूप अदायगी एवं सरकारी व्यय के बीच कुछ निश्चित सम्बन्ध है :

$$\frac{T}{Y} = z, \quad \frac{R}{Y} = r, \quad \frac{G}{Y} = g, \quad (9)$$

जिसमें R अन्तरण-रूप अदायगी (जिसमें सामाजिक बीमा-सम्बन्धी लाभ, सहायता, उपदान एवं सार्वजनिक ऋण पर व्याज भी सम्मिलित है) के लिए है, r सरकार के अन्तरण-रूप की औसत (= सीमांत) क्षमता है, g सरकार के व्यय करने की औसत (=सीमांत) क्षमता है तथा शेष पहले की ही तरह हैं। यहाँ वैधानिक नियन्त्रण की शर्त पर z , r एवं g राजकोपीय नीति प्राचल हैं। समीकरण (9) के सम्बन्ध में दो बातों पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए : प्रथमतः सरकारी व्यय (G) को निवेश (I_g) एवं उपभोग (C_g) में विभक्त करने, जैसा कि हम ने सरकार के नियोक्ता के रूप में कार्य के अन्तर्गत किया था, के बजाय यहाँ हम लोग सम्पूर्ण सरकारी व्यय पर विचार करते हैं। द्वितीयतः, अन्तरण-रूप अदायगी का प्रयोग यहाँ = 'शुद्ध वापसी' ($T-R$) के अन्तर्गत करने के बजाय स्पष्ट रूप से आय के पुनर्वितरण के तरीके के रूप में किया गया है।

वजट-सम्बन्धी उपलक्षक स्थितियों को निम्न-रूप में व्यक्त किया जा सकता है ।

- (क) $(Z-r) = g$: वजट-सम्बन्धी सन्तुलन,
 (ख) $(Z-r) > g$: वजट-सम्बन्धी आधिक्य,
 (ग) $(Z-r) < g$: वजट-सम्बन्धी घाटा ।

यहाँ वजट-सम्बन्धी सन्तुलन (क) को शून्य सरकारी बचत, वजट-सम्बन्धी आधिक्य (ख) को घनात्मक सरकारी बचत तथा वजट-सम्बन्धी घाटे (ग) ऋणात्मक सरकारी बचत समझना चाहिए । दीर्घकालीन गतिशील राजकोपीय नीति में वजट-सम्बन्धी इन उपलक्षक स्थितियों में उचित परिवर्तन पाये जाते हैं । जहाँ तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, यह अन्तःप्रज्ञात्मक रूप से स्पष्ट है कि वजट-सम्बन्धी आधिक्य ही सम्बद्ध स्थिति है, जिसे प्राप्त करना तथा बनाये रखना चाहिए । क्योंकि, बचाने वाले के रूप में सरकार के राजकोपीय कार्य को अपूर्ण निजी बचत के पूरक के रूप में ही समझना चाहिए ।

समीकरण (9) को ध्यान में रखते हुए, सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए वचत-निवेश सम्बन्ध को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है :

$$b\Delta Y = sY + zY - rY - gY = (s + z - r - g)Y, \quad (10)$$

जिसमें $s = S/Y$ या निजी बचत अनुपात (औसत = सीमात) एवं b पूँजी-निपज अनुपात (औसत = सीमात) है । समीकरण (10) का दायीं पक्ष निजी एवं सरकारी कुल बचत तथा बायाँ पक्ष निजी प्रेरित निवेश का प्रतिनिधित्व करता है ।

समीकरण (10) में हम पूर्ण-क्षमता विकास की दर प्राप्त होती है, जो निजी एवं सरकारी बचत अनुपात तथा पूँजी-निपज अनुपात के तकनीकी सम्बन्ध पर निर्भर करती है :

$$\frac{\Delta Y}{Y} = G_k = \frac{s + z - r - g}{b} = \sigma (s + z - r - g), \quad (11)$$

जो यह स्पष्ट करता है कि अन्य सभी स्वतन्त्र परिवर्तितियों के स्थायी रहने पर, पूर्ण-क्षमता विकास दर में घनात्मक सरकारी बचत अनुपात, $(z-r) > g$ के परिणाम स्वरूप वृद्धि होगी । फिर भी, जैसा कि समीकरण (11) सूचित करता है, यदि निजी बचत-अनुपात सामाजिक आदर्शतम विकास की दर g_m (तृतीय अध्याय में वर्णित) के लिए अपेक्षित दर की तुलना में बहुत कम है, तो सरकारी बचत-अनुपात को बढ़ाने के लिए वास्तव में z , r एवं g पर वैकल्पिक राजकोपीय क्रियाएँ हैं । अतएव, $G_k = G_m$ के समग्र उद्देश्य को वँसी विशिष्ट राजकोपीय अधिकारियों के सर्वोत्तम निर्णय के अनुरूप ही, पूर्ण किया जा सकता है और यह अवश्य करना चाहिए ।

पूर्ण-क्षमता विकास की दर से सामाजिक आदर्शतम विकास की दर की अधिकता $G_m > G_k$ के दिया हुआ रहने पर $G_k = G_m$ करने के लिए विकासात्मक राजकोपीय नीति का उद्देश्य G_k में वृद्धि करना होना चाहिए। ऐसा निरन्तर वजट-सम्बन्धी आधिक्य को निम्नांकित उपाय द्वारा बनाये रख कर किया जा सकता है :— (क) सरकार के बचाने की औसत क्षमता g में कमी करके, (ख) कर लगाने की औसत क्षमता z में वृद्धि के द्वारा, अथवा (ग) अन्तरण-रूप अदायगी के लिए सरकार की औसत क्षमता में कमी के द्वारा। किन्तु इनमें से किसी एक क्रिया पर दबाव को कम करने के लिए शायद तीनों क्रियाओं का सम्मिश्रण उचित होगा।

किन्तु, इस बात को ध्यान में रखना होगा कि किसी भी प्रकार से प्राप्त निरन्तर वजट-सम्बन्धी आधिक्य, सरकार के विनियोक्ता एवं बचानेवालों के रूप में राजकोपीय कार्य के अनुरूप है; क्योंकि राजकोपीय अधिकारी को कुल सरकारी व्यय $gY = G$ के उस भाग को कम करने की? जो उपभोक्ता वस्तुओं (C_g) के क्रय पर व्यय किया जाता है और इस प्रकार जैसा कि समीकरण (1) से स्पष्ट है, सरकारी निवेश में वृद्धि ($I_g = G - C_g$) करने की छूट है। साथ ही, इस बात पर भी ध्यान देना है कि बचाने वाले के रूप में सरकार की राजकोपीय भूमिका केन्स के इस सुझाव के अनुरूप है कि यदि और जब कभी 'उपभोग की वैयक्तिक क्षमता, इतनी अधिक है कि शुद्ध बचत बहुत कम होती है और इसलिए पूँजी की पूर्ति भी कम होती है, तो भी 'राज्य के माध्यम से सामुदायिक बचत का स्तर पर बनाये रखना सम्भव है, जिस पर पूँजी में वृद्धि सम्भव हो सकेगी...'।¹ वजट के लिए आधिक्य के द्वारा प्राप्त की जाने वाली इस प्रकार की सामुदायिक बचत की मात्रा सामाजिक आदर्शतम विकास की दर (G_m) के सम्बन्ध में वास्तविक निजी बचत अनुपात (s) एवं पूँजी-निपज अनुपात (b) के अनुमित मूल्य पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि $G_m = .03$, $s = .05$, एवं $b = 5$, 'सामुदायिक बचत' ($s^* - s$) y होगी, जिसमें $s^* = bG_m = .15$ (आदर्शतम विकास की दर के लिए अपेक्षित बचत अनुपात), यानी राष्ट्रीय आय के किसी भी स्तर का 10 प्रतिशत ($= .15 - .05$)। इस प्रकार की 'सामुदायिक बचत' की अनुपस्थिति में अर्थ-व्यवस्था $s_r/b = .03$ की जगह $s/b = .01$ की दर से विकसित होगी। 'विवृत' व्यवस्था में पूँजी के आयात के द्वारा सामुदायिक बचत पर इस प्रकार के दबाव को बहुत अधिक कम किया जा सकता है।¹

1. जनरल थियरी, पृ० 376।
2. देखें मेरा 'ग्रेथ एनेलिसिस एन्ड दि प्रोब्लेम्स ऑफ़ केपिटल एकुमुलेशन इन अंडर-डिवेलपड कंट्रीज', पूर्व उद्धृत।

आय के पुनर्वितरक के रूप में सरकार

उपयुक्त विवेचन में हम कर की दर एवं अंतरणरूप दर की बनावट से पृथक् रहे, किन्तु यह दिखलाना आवश्यक है कि निम्न-भिन्न आय-वर्गों पर लगाये गये विभिन्न प्रकार के करों की दरों तथा अंतरणरूप दरों से निजी वचत अनुपात में परिवर्तन होता है और इसलिए पूर्ण-क्षमता से विकास की दर प्रभावित होती है। तदनुसार, अब हम लोग विकास-कार्यक्रम की सामान्य योजना के अन्तर्गत आय के पुनर्वितरक के रूप में सरकार के राजकोषीय कार्यों पर विचार करेंगे।

वितरित की जानेवाली वास्तविक राष्ट्रीय आय को दो भागों में विभक्त किया जाय—पहली वह, जो निम्न आय वाले वर्ग को प्राप्त होती है (Y_1) और दूसरा वह, जो उच्च आय वालों (Y_2) को प्राप्त होती है, यानी—

$$Y = Y_1 + Y_2, \quad (12)$$

जिसका वितरण अनुपात निम्नांकित है :

$$\frac{Y_1}{Y} = d, \quad \frac{Y_2}{Y} = 1 - d. \quad (13)$$

और आगे बढ़ने के पूर्व यह मान लिया जाय कि दो पृथक्-पृथक् आय-वर्ग हैं, जिनके बीच किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं पाई जाती है तथा जिनके बीच करों, अंतरणरूप अदायगियों तथा वचत की क्षमता के सबंध में पूर्ण विभेद पाया जाता है। इन वर्गों से बाहर सभी आय-उपाजित करने वालों को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की सहज मान्यता निम्नांकित विश्लेषण में सन्निहित आय एवं करों, अंतरणरूप अदायगियों तथा वचतों के स्यासी, किन्तु विभिन्न अनुपातों को न्यायोचित करार करने के लिए की गई है।

कुल करों को दो वर्गों में विभक्त किया जाय—एक वे, जो निम्न आयवर्गों पर लगाये जाते हैं (T_1), तथा दूसरे वे जो उच्च आय वर्गों पर लगाये जाते हैं (T_2)। भुगतान की योग्यता सिद्धांत के अनुसार यह मान लिया जाता है, कि पहले वर्ग पर कर की दर दूसरे वर्ग से निम्न है :

$$T = T_1 + T_2 = z_1 Y_1 + z_2 Y_2 \quad (14)$$

जिसमें z_1 निम्न आय वर्ग पर एवं z_2 उच्च आय वर्ग पर औसत (=सीमांत) कर की दर है।

इसी प्रकार, अंतरणरूप अदायगियों को भी दो वर्गों में विभक्त किया जाता है जो निम्न आय वाले वर्गों को जाती है (R_1), तथा वह जो उच्च आय वाले

वर्गों को जाती हैं (R_2)। अंतरणरूप दर, मुख्य रूप के प्रति कल्याण से सचेत अर्थ-व्यवस्थाओं में पहले वर्ग में दूसरे की अपेक्षा साधारणतया अधिक है :

$$R = R_1 + R_2 = r_1 Y_1 + r_2 Y_2, \quad (15)$$

जिस में r_1 निम्न आय वाले वर्ग के लिए तथा r_2 ऊँची आय वाले वर्गों के लिए औसत (=सीमांत) अंतरणरूप दर हैं। $r_1 > r_2$, यह Y_1 एवं Y_2 वर्गों के लिए उपदान को दिये जाने वाले महत्त्व पर निर्भर करता है।

करों एवं अंतरणरूप अदायगियों के पश्चात् निम्न आय वाले वर्गों की निजी वचत निम्नांकित है :

$$S_1 = s_1 (Y - T_1 + R_1) = s_1 (i - z_1 + r_1) Y_1, \quad (16)$$

जिसमें s_1 व्यय की जाने वाली आय में से निम्न आय वाले वर्ग के वचाने की औसत (=सीमांत) क्षमता है। इसी प्रकार, ऊँची आय वाले वर्ग की वचत इस प्रकार है :

$$S_2 = s_2 (Y_2 - T_2 + R_2) = s_2 (i - z_2 + r_2) Y_2, \quad (17)$$

जिसमें s_2 व्यय की जाने वाली आय में से ऊँची आय वाले वर्ग के वचाने की औसत (=सीमांत) क्षमता है। यह मान लेना सत्य प्रतीत होता है कि निम्न आय वाले वर्ग की तुलना में ऊँची आय वाले वर्ग की वचाने की सीमांत क्षमता अधिक है, अथवा $s_2 > s_1$ ।

(12) से (17) समीकरणों से हमें पूर्ण-क्षमता विकास की दर प्राप्त होती है, जिसमें निजी वचत-अनुपात पर राजकोपीय पुनर्वितरण के प्रभाव का समावेश है।

$$G = \frac{[s_1 (i - z_1 + r_1) d + s_2 (i - z_2 + r_2) (i - d)] + z - r}{b} \quad (18)$$

जिसमें $s_1 (i - z_1 + r_1) d$ तथा $s_2 (i - z_2 + r_2) (i - d)$ राष्ट्रीय आय में से क्रमशः निम्न आय एवं ऊँची आय वाले वर्गों की वचाने की औसत (=सीमांत) क्षमता है।

समीकरण (18) यह बतलाता है कि यदि व्यय-योग्य आय में से (s_1, s_2) दोनों आयवाले वर्गों की वचाने की औसत क्षमता स्थिर रहती है, तो सरकारी बजट संतुलित हो अथवा असंतुलित, $(z - r)g$ इससे स्वतंत्र रूप में, सापेक्ष कर की दरों (z_1, z_2), सापेक्ष अंतरण-दरों (r_1, r_2) तथा वितरण अनुपात (d और इसलिए $i - d$) में परिवर्तन से राष्ट्रीय आय में से वचाने की कुल औसत क्षमता और इसलिए पूर्ण क्षमता-विकास दर (G_k) में परिवर्तन हो सकता है। और स्पष्ट बनाने के लिए, $G_k = G_m$ करने के लिए पूर्ण क्षमता विकास की दर में वृद्धि के प्रयास के लिए—(क) z_2 , में कमी, (ख) r_2 में वृद्धि, (ग) z_1 में वृद्धि, तथा (घ) r_1 में कमी अथवा थोड़े में एक कम प्रगतिशील कर एवं अंतरणरूप रचना की आवश्यकता होगी। साथ ही, इसी प्रकार के प्रयास के लिए कम प्रगतिशील उत्तराधिकार अथवा मृत्यु-करों एवं अन्य तरीकों से वितरण अनुपात d में कमी की आवश्यकता होगी।

यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की जाती है कि अधिक निजी बचत के उद्देश्य से निम्न से उच्च वर्गों में आय के पुनर्वितरण की ये राजकीय क्रियाएँ किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में प्रचलित समानता के उद्देश्य के विरुद्ध जा सकती हैं। साथ ही, यह भी स्वीकार किया जाता है कि निम्न आय वाले वर्गों से ऊँची आयवाले वर्गों में आय के राजकोपीय पुनर्वितरण से, प्रतिस्पर्धात्मक कारणों के परिणामस्वरूप, समुदाय की उपभोग की इच्छा में वृद्धि हो सकती है और इसलिए कुल निजी बचत में भी कमी होगी, जो पूँजी-सचय तथा निपज में वृद्धि के लिए अहितकर सिद्ध होगी। क्योंकि, यह विचारणीय बात है कि मजदूरी उपार्जित करनेवाले परिवारों अथवा व्यक्तियों को, जो लाभ उपार्जित करने वालों की तुलना में बहुत ही कम आय प्राप्त करते हैं, 'जोन्सों की धरावरी करने' का प्रयत्न प्रलोभन हो और जो स्वयं दूसरे को 'स्मिथों से आगे बढ़ने' के लिए प्रेरित कर सकता है। यदि ऐसा है, तो दोनों निजी बचत अनुपात (s_1, s_2) में ह्रास होगा, जिससे उपर्युक्त राजकीय क्रियाओं का समग्र निजी बचत-अनुपात पर जो वृद्धिशील प्रभाव पड़ेगा, वह विस्थित हो जायगा। इस प्रकार, अतः इस समाजशास्त्रीय सघटन (तथाकथित 'प्रदर्शन-प्रभाव') को छोड़ कर तथा अतः पूर्ण रोजगार की मान्यता पर ही कोई व्यक्ति अधिक विकास के लिए आय की विषमता की अनिवार्यता-सम्बन्धी संस्थापकों की तर्क-संगति को स्वीकार कर सकता है।¹

स्थायी विकास के लिए राजकीय क्रियाएँ*

हम लोग देख चुके हैं कि किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में दीर्घकालीन राजकोपीय कार्यों का आशय मुख्य रूप से उत्पादन-क्षमता के विकास की दर को अधिकाधिक बनाना होता है। इसके विपरीत एक विकसित बाजारी अर्थ-व्यवस्था में दीर्घकालीन राजकोपीय क्रियाओं का निरूपण इस प्रकार की दर को स्थायी बनाने के लिए किया जाता है। अब हम एक दूसरे प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता प्रदान करने वाले के रूप में सरकार की राजकोपीय क्रियाओं पर विचार करेंगे।¹

1. इसके लिए पाठक का ध्यान अध्याय 7 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

* यह अंश मुख्यतः हमारे 'प्रोय मॉडल्स एंड फिस्कल पॉलिसी पैरामीटर्स' फाइनान्सेज पब्लिक (नियरलैंड) सं० 2/1956 पर आधारित है।

2. ए० एच० हैनसेन पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने विशुद्धतः चक्रीयविरोधी क्रियाओं के अतिरिक्त दीर्घकालीन राजकोपीय नीति की आवश्यकता पर जोर दिया। (देखें, इनकी फिस्कल पॉलिसी एंड बिजिनेस साइकिल, तोरटन, न्यूयार्क, 1941)। हेरोड, डोमर, केलेकी तथा हबलामो के तटस्थ विकास-मॉडलों में सन्निहित राजकोपीय तटस्थता की मान्यता ने बाजारी अर्थ-व्यवस्थाओं के विशुद्ध

गतिशील साम्यावस्था का अस्थायित्व

विशिष्ट प्राचलीय क्रियाओं को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हम लोग विशुद्ध अवैध-नीति की परिस्थितियों में गतिशील साम्यावस्था (परिवर्तन की घनात्मक स्थायी दर के साथ) में अन्तर्निहित अस्थायित्व के विश्लेषणों से प्रारम्भ करेंगे। एक विकसित बाजार अर्थ-व्यवस्था मूलतः निरन्तर प्रगति के पथ से दीर्घकालिक रूप में इसलिए विचलित होती है कि निजी वचन एवं निवेश से संगत विकास की दर जनसंख्या की वृद्धि एवं तकनीकी प्रगति से संगत विकास की दर के कदाचित् ही अनुरूप होती है। इस विवेचन के उद्देश्य से हम वगैर उच्चावचन के निरन्तर प्रगति की साम्यावस्था की दर को निपज में वृद्धि (वास्तविक शुद्ध) की उस दर से निर्दिष्ट करेंगे, जो श्रम को बढ़ती हुई उत्पादकतावाली वृद्धिशील श्रम-संख्या को पूर्ण नियुक्ति की स्थिति में रखने के लिए अपेक्षित होती है। किसी भी समाज में प्राप्त करने योग्य विकास की यह सम्भावित अधिकतम दर है। हम इस प्रकार की दर का निम्नांकित तरीके से सन्निकट अनुमान कर सकते हैं :

औसत वास्तविक मजदूरी की दर को दिया हुआ तथा निपज एवं श्रम के

विकास की मौलिक अंतर्दृष्टि के प्रति प्रबल अनुतोष लानेवाले के रूप में कार्य किया है। हेरोड नीति के सम्बन्ध में अत्यधिक सचेत हैं, किन्तु रॉबिन्सन ने इनकी नीति-सम्बन्धी विवेचना को, इनके नये योगदानों पर बहुत कम निर्भर बतलाते हुए आलोचना की है।' (देखें इनका 'मि० हेरोड्स डायनामिक्स', पूर्व-उद्धृत)।

स्पष्ट राजकोपीय नीति-सम्बन्धी प्राचलवाले विकास मॉडल बहुत ही कम हैं। इस सम्बन्ध में जे० बी० गुल्ले का 'फिस्कल पॉलिसी इन ए ग्राईंग इकॉनामी 'जरनल ऑफ पोलिटिकल इकॉनामी', दिसम्बर, 1953 ई०, एक अपवाद है। गुल्ले ने यद्यपि कि अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा उपेक्षित विकास अर्थशास्त्र के महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया है, तथापि इसकी आलोचना इन बातों को लेकर की जाती है—गतिशील साम्यावस्था की अस्थिरता-सम्बन्धी स्थिति के अपारदर्शकत्व के लिए जिसे सम्भवतः राजकोपीय नीति दूर कर सकती है; दीर्घकालिक विकास पर दीर्घकालीन राजकोपीय क्रियाओं के पुनर्वितरणात्मक प्रभावों की उपेक्षा के लिए; और विकासशील अर्थ-व्यवस्था के दीर्घकालिक अस्थायित्व के बदले चक्रीय अस्थायित्व पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए (यानी हेरोड के विभेद के अनुसार, 'अपेक्षित' दर एवं 'प्राकृतिक' दर में अन्तर से उत्पन्न अस्थायित्व की जगह 'वास्तविक' विकास की दर एवं 'अपेक्षित' विकास की दर में अन्तर से उत्पन्न अस्थायित्व पर)।

अनुपात को तकनीक की दृष्टि से स्थायी मानकर, हमे निम्नांकित सम्बन्ध प्राप्त होते है :

$$\frac{N}{Y} = v, \quad N = vY, \quad Y = \frac{N}{v}, \quad (19)$$

जिनमे N पूर्ण नियुक्त रहने पर श्रम की मात्रा है, Y वास्तविक शुद्ध राष्ट्रीय निपज और v औसत (=सीमांत) श्रम-निपज अनुपात है।

समीकरण (19) से और चूँकि श्रम की औसत उत्पादकता श्रम-निपज अनुपात का व्युत्क्रम है, निपज एवं श्रम के सम्बन्ध को निम्नांकित रूप में व्यक्त किया जा सकता है :

$$Y = pN, \quad \left(p = \frac{1}{v} = \frac{Y}{N} \right), \quad (20)$$

जिसमे p श्रम की औसत उत्पादकता को मापनेवाला गुणाक है। यहाँ $\Delta Y = p \Delta N$ अन्तर्निहित है।

समीकरण (19) एवं (20) से तथा अतिरिक्त श्रम एवं निपज के अनुपात ($\Delta N/Y$) को n से सूचित करने पर हमे निपज में वृद्धि की पूर्ण रोजगार-सम्बन्धी दर (G_n) प्राप्त होती है :

$$G = \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta N}{Y} \cdot p = np \quad (21)$$

जो दर 'तटस्थ तकनीकी प्रगति' की सहज मान्यता, एवं इसलिए स्थायी पूँजी-निपज अनुपात के अनुरूप स्थायी श्रम-निपज पर आघृत हैरोड के विकास की 'प्राकृतिक' दर के तुल्य है। केवल इसी मान्यता के चलते, नहीं तो पिछले अध्याय की 'सामाजिक आदर्शतम' विकास की दर इसके लिए अच्छा सन्निकटतम मान होती। चूँकि, हैरोड विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए 'प्राकृतिक' एवं 'अपेक्षित' विकास की दरों को पास-पास रखते है, अतएव अधिक जटिल सामाजिक आदर्शतम विकास की दर की तुलना में समीकरण (21) द्वारा दी गई पूर्ण रोजगार-सम्बन्धी विकास की दर प्रयोग करने के लिए अधिक उचित धारणा जान पड़ती है। इस प्रकार, पूर्ण रोजगार-सम्बन्धी विकास की दर को प्राप्त करने तथा बनाए रखने के लिए पूँजी-संचय की एक निश्चित दर की आवश्यकता होती है। इस अनुकूल मान्यता पर कि तकनीकी परिस्थितियों एवं साधनों के सापेक्ष मूल्य इस प्रकार हैं कि वास्तविक पूँजी एवं वृद्धिशील श्रम-संख्या में शीघ्रतापूर्वक समायोजन स्थापित हो जाता है, यह कहा जा सकता है कि G_n ही पूर्ण रोजगार को बनावे रखने की गारन्टी प्रधान करता है। किन्तु, G_n आवश्यक रूप में पूँजी के प्रयोग की गारन्टी नहीं देता। यही पर हमें पूर्ण क्षमता विकास की दर, अथवा हैरोड की शब्दावली में 'अपेक्षित दर' की ओर ध्यान देना चाहिए।

हम जानते हैं कि पूर्ण क्षमता-दर निर्माकित द्वारा दी जाती है :

$$G_k = \frac{s}{b} = s\sigma; \left(\sigma = \frac{1}{b} = \frac{Y}{K} \right), \quad (22)$$

जो वृद्धिशील पूँजी के कोष के साथ श्रम-संख्या के उचित समायोजन की पूर्व कल्पना करता है। श्रम की पूर्ति को सदा लोचदार मानकर यह कहा जा सकता है कि G_k पूँजी के वर्तमान कोष के पूर्ण प्रयोग की गारन्टी प्रदान करता है। किन्तु, चूँकि वास्तव में जनसंख्या की वृद्धि एवं तकनीकी प्रगति सदा इस प्रकार की नहीं होती, जिससे कि पूँजी के साथ मिलाई जानेवाली श्रम की माँग के अनुरूप श्रम की लोचदार पूर्ति की व्यवस्था कर सके, अतएव G_k आवश्यक रूप से श्रम की पूर्ण नियुक्ति की गारन्टी नहीं प्रदान करता।

मान लिया जाय कि अर्थ-व्यवस्था वास्तव में G_n , यानी पूर्ण नियुक्ति की दर से बढ़ रही है अब कोई कारण नहीं है कि सिवाय संयोग अथवा निश्चित प्रायोजन के, पूर्ण-क्षमता विकास की दर G_k पूर्ण नियुक्ति-संबंधी विकास दर के सदा अनुरूप हो। किन्तु तर्क के लिए यह मान लिया जाय कि अर्थ-व्यवस्था प्रारंभ में जैसा कि जोन राँबिन्सन ने कहा है, स्वर्णयुग में है, जिसमें पूँजी-संचय की दर जनसंख्या में वृद्धि की दर में ठीक अनुरूप है, जिससे पूँजी एवं श्रम दोनों की पूर्ण नियुक्ति है। ऐसा होने पर, स्वर्णयुग को बनाये रखने के लिए आवश्यक शर्त इस प्रकार से है :

$$G_k = G_n; \frac{s}{b} = np. \quad (23)$$

समीकरण (23) के तुल्यांक दीर्घकालिक विषमरूपता के वगैर स्थायी विकास को बनाये रखने के लिए आवश्यक शर्तों को दिखलाते हैं। मानलिया कि प्रारम्भिक काल के कुछ समय बाद किसी समय वचत-अनुपात s में स्थायी रूप से ह्रास हो जाता है, जिससे समीकरण (22) के अनुसार पूर्ण क्षमता-विकास की दर G_k पूर्ण नियुक्ति-संबंधी विकास की दर G_n से निम्न हो जाती है। $G_k < G_n$ के रूप में अंतर्जनित आघात से दीर्घकालीन स्फीति की एक पृथक् प्रवृत्ति की शुरुआत होती है; क्योंकि अब पूर्ण क्षमता विकास-दर के अनुरूप वचत-अनुपात जनसंख्या एवं तकनीक की वास्तविक प्रवृत्ति से अभिप्रेरित निवेश की दर से कम है, यानी— $bG_k = s < bG_n$; $dY_m/dt = f(I_m - S_m)$ की तरह से यंत्र के अनुसार दीर्घकालिक स्फीति की वास्तविक अपसारी हानि मौद्रिक राष्ट्रीय आय की वृद्धिशील प्रवृत्ति से विशेषित होगी। इसमें Y, I एवं s क्रमशः आय, निवेश एवं वचत हैं तथा नीचे का लेख m मुद्रा के रूप में मापे गये परिवर्तियों को सूचित करता है।

इसके विपरीत, यह मान लिया जाय कि किसी खास समय में वचत-अनु

स्थायी रूप से वृद्धि हो जाती है। तो पूर्ण-क्षमता-विकास-दर पूर्ण-नियुक्ति-संबंधी विकास-दर से निश्चय ही बढ़ जायेगी $G_k > G_n$ । G_n से G_k का यह आधिक्य दीर्घकालिक स्थिरता की एक विपरीत पृथक् प्रवृत्ति को जन्म देता है; क्योंकि इस बार पूर्ण-क्षमता-विकास-दर के अनुरूप बचत-अनुपात जनसंख्या एवं तकनीक में वास्तविक वृद्धि से अभिप्रेरित निवेश की दर से अधिक है, यानी $bG_k = s > bG_n$ । अब $dY/dt = F(S - i)$ की तरह के यत्र के अनुसार, दीर्घकालिक स्थायित्व की अपसारी गति वास्तविक आय की घटती हुई प्रवृत्ति में विशिष्ट होगी। प्रति सन्तुलन-नीति के अभाव में बचत-अनुपात में स्थायी परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप प्रारम्भिक बाधाएँ (अथवा इसके लिए, पूँजी-निपज-अनुपात में जिसे अभी हम लोग स्थायी मानते हैं, G_k तथा G_n के बीच सदा बढ़ते धाले विकास-संबंधी अंतर का सज्जन करेगी। इसमें सन्निहित दीर्घकालिक अस्थायित्व की स्फीति-जनक अथवा स्थायित्व की प्रकृति $G_k > < G_n$ पर निर्भर करेगी। अतएव, हम गतिशील साम्यावस्था के अस्थायित्व की स्थिति को बढ़ते हुए विकास-संबंधी अंतर के रूप में समझ सकते हैं, यानी

$$\Delta (G_n - G_k) = \psi (G_n - G_k) \quad (24)$$

जहाँ फंक्शन ψ की विशेषताएँ $\psi(0) = 0$ और $\alpha' > 0$ है (जिसमें $\psi' = dX/di$; $X = G_n - G_k$)।

संक्षेप में एक विशुद्ध अव्यवस्था विकासशील अर्थ-व्यवस्था में सन्निहित दीर्घकालिक अस्थायित्व की इस तरह की ही अतर्निहित प्रकृति है।

स्थायित्व प्रदान करने वाले के रूप में सरकार

स्थायी विकास के लिए गतिशील राजकोपीय नीति के सामान्य उद्देश्यों को बतलाने के लिए उपयुक्त विवेचन पर्याप्त है। क्योंकि, $G_k < G_n$ के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न दीर्घकालिक स्फीति की सम्भावित स्थिति में राजकोपीय नीति का आशय यह है कि कर एवं व्यय-संबंधी क्रियाओं के द्वारा बचत-अनुपात में इस प्रकार वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे की $bG_k = s = bG_n$ हो जाय। दूसरी ओर, यदि $G_k < G_n$ के परिणाम-स्वरूप अर्थ-व्यवस्था में दीर्घकालिक स्थायित्व की प्रवृत्ति की आशंका है, तो बचत-अनुपात में कमी की जानी चाहिए। किन्तु अब हमें विशिष्ट प्राचलीय क्रियाओं के विचार पर ध्यान देना चाहिए।

समीकरण (22) के अनुसार किसी समय $t > 0$ निजी बचत अनुपात s में स्थायी ह्रास के परिणाम-स्वरूप मान लिया जाय कि पूर्ण क्षमता-विकास की दर पूर्ण नियुक्ति-संबंधी विकास-दर से घट जाती है, $G_k = G_n$ । यदि $G_k = G_n$ करना है, तो आवश्यक दीर्घकालीन प्रतिकरात्मक राजकोपीय नीति घनात्मक सरकारी बचत-अनुपात को प्राप्त करने तथा बनाये रखने की होनी चाहिए। इसके विपरीत, यदि अनुपात में स्थायी वृद्धि के परिणाम-स्वरूप $G_k > G_n$ के हो, तो राज-

कोषीय नीति को ऋणात्मक सरकारी वचत-अनुपात (यानी वजट-संबंधी घाटा रखने) को प्राप्त करने एवं बनाये रखने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि, निरंतर वजट-संबंधी आधिक्य के परिणाम-स्वरूप पूर्ण-क्षमता-विकास की दर के अनुरूप वचत में इतनी मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे यह जनसंख्या एवं तकनीकी वास्तविक प्रवृत्तियों से अभिप्रेरित विकास की दर के बराबर हो जाय। इसके विपरीत निरंतर वजट-संबंधी घाटे के परिणामस्वरूप पूर्ण क्षमता-विकास की दर के अनुरूप वचत की मात्रा में इतनी कमी हो जाती है। समीकरण (11) को ध्यान रखते हुए हम समीकरण (23) को निम्नांकित प्रकार से पुनः लिख सकते हैं :

$$\frac{s+z-r-g}{b} = np, \quad (25)$$

जो गतिशील साम्यावस्था की एक नई स्थिति, जिसे राजकोषीय क्रियाओं द्वारा पूरा किया जाता है, को व्यक्त किया करता है। समीकरण (25) यह बतलाता है कि यदि $G_k < G_n$ के परिणाम-स्वरूप दीर्घकालिक स्फीति का भय है, तो इसे निरंतर वजट-संबंधी आधिक्य $(z-r) > g$ के द्वारा दूर किया जा सकता है। और इसी प्रकार यदि $G_k > G_n$ के परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक स्थायित्व की आशंका है, तो इसे निरंतर वजट-संबंधी घाटे $(z-r) < g$ के द्वारा दूर किया जा सकता है।

साथ ही, समीकरण (25) यह प्रस्तावित करता है कि अपूर्ण अथवा अत्यधिक निजी वचत को पूरा करने के लिए वजट-सम्बन्धी आधिक्य अथवा घाटे को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय अधिकारी द्वारा राजकोषीय नीति-प्राचलों— Z , r एवं g के लिए वैकल्पित क्रियाएँ की जा सकती हैं। यदि निजी वचत के अनुरूप पूर्ण-क्षमता-विकास की दर पूर्ण रोजगार-सम्बन्धी विकास-दर से सामान्यतः ऊँची है, तो जंसा कि हेरोड का प्रस्ताव है, $G_k = G_n$ करने के उद्देश्य से निम्नांकित की आवश्यकता होगी—(क) सरकार के व्यय करने की औसत क्षमता g में वृद्धि, (ख) कर लगाने की औसत क्षमता z में कमी, तथा (ग) अन्तरण-रूप की औसत क्षमता r में वृद्धि—संक्षेप में लगातार वजट-सम्बन्धी घाटे के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। इस प्रकार, विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की तरह यदि निजी पूँजी-संचय की दर की प्रवृत्ति जनसंख्या में वृद्धि एवं तकनीकी प्रगति की दर का अतिक्रमण करने की होती है, तो वजट-सम्बन्धी घाटे को बनाये रखने का प्रयास, अनैतिक होने के बजाय, दीर्घकालिक स्थायित्व के वगैर, श्रम एवं पूँजी दोनों की पूर्ण नियुक्ति से युक्त स्थायी विकास को प्रोत्साहित करने के सामान्य उद्देश्य के पूर्णतया अनुरूप है। यदि करों में कमी, सरकारी व्यय तथा अन्तरण-रूप अदायगी के उचित सम्मिश्रण के द्वारा लगातार उत्प्लावन अर्थ-व्यवस्था को बनाये रखा जा सकता है, तो वजट-सम्बन्धी घाटा-विषयक सामान्य आक्षेप बहुत हृद तक तथ्यहीन हो जायेंगे।

समीकरण (12) से लेकर (18) तक से हम यह जानते हैं कि निजी

वचत दर को प्रभावित करने और इसलिए दो हुई पूर्ण रोजगार-सम्बन्धी विकास-दर की तुलना में पूर्ण-क्षमता-विकास-दर को स्थायी बनाने के लिए राजकोपीय अधिकारी कर एवं अन्तरण-रूप की दरों में परिवर्तन कर सकते हैं। इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, हम लोग गतिशील साम्यावस्था की मौलिक शर्तों को विस्तृत रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं।

$$\frac{[s_1(I-z_1+r_1)d+s_2(I-z_2+r_2)(I-d)]+z-r-g}{b} = np, (26)$$

जो यह बतलाता है कि यदि $G_h < G_n$ के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न दीर्घकालिक स्फीति को टालना है, तो z_2 एवं r_1 में कमी तथा r_2 एवं z_1 में वृद्धि-यानी कम प्रगतिशील कर एवं अन्तरण-रूप संरचना के द्वारा समग्र निजी वचत अनुपात में वृद्धि की जा सकती है। ठीक इसके विपरीत यह बतलाता है कि यदि $G_h > G_n$ के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न दीर्घकालिक अस्थायित्व को रोकना है, तो z_2 एवं r_1 में वृद्धि तथा r_2 एवं z_1 में कमी, यानी अधिक प्रगतिशील कर एवं अन्तरण-रूप संरचना के द्वारा समग्र निजी वचत-अनुपात में कमी की जा सकती है। पहले की ही तरह, पुथक् की जाने योग्य प्रकृति की ये प्राचलीय क्रियाएँ $s_2 > s_1$ की पूर्ण कल्पना करती हैं।

हमारी इस सम्भावना पर भी स्वीकृति देनी चाहिए कि उन व्यक्तिगत फर्मों अथवा उद्योगों, जो सम्भवतः 'पूँजी प्रयोग करने वाले' अथवा 'पूँजी-बचाने वाले' तकनीकों को अपना सकते हैं, को चयनात्मक उपादान (अन्तरण-रूप दर r में अन्तर्निहित) की नीति के द्वारा, r के समग्र आकार को प्रभावित किये बिना, पूँजी-निपज अनुपात b में जान-बूझ कर परिवर्तन किया जा सके। इस प्रकार की चयनात्मक उपादान की नीति को 'पूँजी-प्रयोग' अथवा 'पूँजी बचाने' के आधार पर औद्योगिक विकास के पक्ष में करों की छूट, यानी करों की दर z की संरचना में परिवर्तन, से सम्बद्ध किया जा सकता है। अन्ततः, एक अधिक विस्तृत दीर्घकालीन राजकोपीय नीति के अन्तर्गत जनसंख्या की वृद्धि की दर¹ को प्रभावित करने और इसलिए

1. इस सम्बन्ध में एन० कालडोर का कहना है कि उसने (हेरोड) ने जो स्वीकार नहीं किया था, वह यह है कि विकास की प्राकृतिक दर को निर्धारित करने वाली 'मौलिक शर्त' आकाश के द्वारा निर्धारित नहीं होती। ये अनाम्य (विस्तृत सीमाओं के अन्दर) हैं और आर्थिक व्यवस्था की अन्तर्जनित शक्तियों से बाहर ढकेली जा सकती हैं या अन्दर लाई जा सकती हैं। (देखें इनका 'दि रिलेशन ऑफ इकॉनामिक ग्रोथ ऐंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशन्स', इकॉनामिक जनरल, मार्च 1954)। इसी प्रकार का विचार हैब्लेनो के 'ए स्टडी इन दि थियरी ऑफ इकॉनामिक इवोल्यूशन' में व्यक्त किया गया है किन्तु, इनमें से किसी ने भी।

केवल G_h से सम्बद्ध क्रियाओं पर ध्यान केन्द्रित करने की वजाय पूर्ण-रोजगार-सम्बन्धी विकास दर G_n को परिवर्तन करने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। स्थायी विकास के लिए एक अधिक विस्तृत दीर्घकालीन राजकोपीय नीति की उपलब्धि केवल और अधिक सैद्धान्तिक विश्लेषण पर ही निर्भर नहीं करती, वरन् इस बात पर भी निर्भर करती है कि राजकोपीय नीति की आर्थिक सम्भावनाओं को इसकी राजनीतिक सीमाओं के साथ कहाँ तक समन्वित किया जा सकता है।¹

इस प्रकार का सुभाव नहीं दिया है कि जनसंख्या की वृद्धि अथवा श्रम-निपज-अनुपात पर राजकोपीय नीति के उद्देश्य के रूप में विचार करना चाहिए। इस प्रकार के सुभाव की ओर जनाधिक्य वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं तथा जनाभाव वाली विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं—दोनों का ध्यान आकृष्ट था।

1. राजकोपीय क्रियाओं में सन्निहित कुछ राजनीतिक एवं सांस्थानिक कठिनाइयों के लिए पोस्ट केन्सीयन इकॉनामिक में देखें एच० आर० बोवेन एण्ड जी० एम० मापर 'इन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी'।

विदेशी व्यापार एवं आर्थिक विकास*

विश्लेषण की गहनता के लिए सवृत मॉडल जिस प्रकार अनिवार्य है, उसी प्रकार विश्लेषण की व्यापकता के लिए विवृत मॉडल लाभदायक है। वर्तमान अध्याय में विदेशी व्यापार एवं घरेलू विकास के बीच प्राविधिक सम्बन्ध के स्पष्टीकरण के लिए हम आर्थिक विकास के विवृत मॉडल का निर्माण करेंगे। इस अध्याय में एक विवृत अर्थ-व्यवस्था, के सदर्भ में जिसमें माँग में, क्षमता से अधिक वृद्धि की प्रवृत्ति के परिणाम-स्वरूप निरन्तर स्फीति तथा असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, विशिष्ट रूप से निम्नलिखित की व्याख्या की जायगी—(क) विदेशी व्यापार एवं माँग की वृद्धि में सम्बन्ध, (ख) विदेशी व्यापार एवं क्षमता की वृद्धि में सम्बन्ध, तथा (ग) सन्तुलन विक्रम के लिए प्राचल क्रिया।¹

इस समस्या का यह विशिष्ट उपचार वर्तमान व्याख्या को घरेलू विकास एवं

*यह अप्रैल, 1958 के मेट्रोकोनोमिका (Metroeconomica) के 10-वें वोल्यूम में प्रकाशित मेरे 'इकॉनामिक डिवेलपमेंट ऐंड दि बैलेस आफ पेमेट्स' का बहुत कुछ उपातरित रूप है।

1. डॉलर-क्षेत्र के बाहर अधिकांश अर्थ-व्यवस्थाओं को घरेलू स्फीति एवं विदेश भुगतान-सम्बन्धी कठिनाइयों के बीच चिर-कालिक विकास की युद्धोत्तरकालीन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए—देखें 'यू० एन० इकॉनामिक कमिशन फॉर लेटिन अमेरिका', इकॉनामिक सर्वे ऑफ लेटिन अमेरिका, 1954, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1955, तथा नवम्बर, 1955 ई० के रिव्यू ऑफ इकॉनामिक स्टेटिस्टिक्स में प्रकाशित मेरा लेख 'जापान ट्रेड पोजिशन इन ए चैजिंग वर्ल्ड मार्केट'।

भुगतान सन्तुलन के सम्बन्ध में केन्सोत्तर विवाद से सम्बद्ध करने के लिए चुना गया है।¹ इस सम्बन्ध में दो भिन्न विचार-धाराएँ दृष्टिगोचर हैं। इनमें से एक विचार-धारा भुगतान-सन्तुलन पर इसकी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखे बिना घरेलू उन्नति पर जोर देती है। दूसरी विचार-धारा भुगतान को साम्यावस्था पर जोर देती है, चाहे वह बाह्य सन्तुलन आंतरिक विकास में सहायक हो अथवा नहीं। पेशेवर मत में यह अन्तर विदेशी व्यापार के आय-उत्पादन पहलू (माँग-पद) अथवा क्षमता सर्जनात्मक पहलू (पूर्ति-पक्ष) के सम्बन्ध में एक पक्षीय पूर्वधारणा का परिणाम जान पड़ता है।

आंतरिक स्फीति एवं बाह्य असन्तुलन के वगैर सन्तुलित विकास के लिए आवश्यक शर्तों को स्पष्ट बनाने के लिए यहाँ विदेशी व्यापार के इन दोनों क्षेत्रों के समायोजन का प्रयत्न किया जायगा। इस प्रकार का प्रयत्न अधिक मुक्त व्यापार एवं चतुर्दिक् उच्च जीवन-स्तर के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय उपायों पर भी कुछ प्रकाश डाल सकता है।

विदेशी व्यापार एवं माँग में वृद्धि

पूर्ति की दशाओं को दिया हुआ मानकर, विदेशी व्यापार एवं माँग में वृद्धि के प्राविधिक सम्बन्ध के विश्लेषण से प्रारम्भ किया जाय। समर्थ माँग की वृद्धि पर विदेशी व्यापार-सम्बन्धी क्रियाओं के प्रभाव को दिखाने के लिए केन्स के गुणक सिद्धान्त को निम्न प्रकार से गति प्रदान करना तथा लौकिक कार्य में लगाना अनिवार्य है :—

$$\Delta Y^a = \frac{I}{s' + m' - b'} (\Delta I + \Delta G + \Delta E), \quad (1)$$

जिसमें Y^a समर्थ माँग द्वारा निर्धारित वास्तविक शुद्ध राष्ट्रीय आय अथवा केवल समर्थ माँग है, I स्वतः प्रेरित शुद्ध निजी निवेश है, G सरकारी व्यय, E स्वतः प्रेरित निर्यात (जिसमें अदृश्य उधार मदे भी शामिल हैं), s' वचत की सीमांत

1. तुलना करें—फरवरी 1955 के 'बुलेटिन ऑफ ऑक्सफोर्ड इन्स्टीच्यूट ऑफ स्टेटिस्टिक्स' में प्रकाशित "ग्रोथ ऐंड दि वेल्लेस ऑफ पेमेंट्स : सिम्पोजियम", मई 1956 के रिव्यू ऑफ इकॉनामिक स्टेटिस्टिक्स में प्रकाशित आर० नक्से का लेख 'दि रिलेशन बिटवीन होम इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल वेल्लेस इन दि लाईट ऑफ ब्रिटिश इक्सपीरियेंस 1954-55, अप्रैल 1956 के इकॉनामिक स्टडीज क्वाटर्ली (जापान) में प्रकाशित एफ० मैथ्युलुप का 'दि फाइनांस ऑफ डिवेलपमेंट इन दि यूएर कन्ट्रीज : फारेन कैपिटल एंड होमेस्टिक इन्प्लेशन।'।

प्रवृत्ति, m' आयात की सीमांत प्रवृत्ति तथा b' विनियोग की सीमांत प्रवृत्ति हैं। यहाँ पर ΔI , ΔG तथा ΔE गुण बहिर्जनित प्राचल, तथा बचत करने, आयात करने एवं निवेश की सीमांत प्रवृत्तियाँ s' , m' , b' अन्तर्जनित प्राचल हैं। ΔI , ΔG एवं ΔE का सापेक्षिक महत्त्व विचार की जाने वाली अर्थ-व्यवस्था की प्रकृति पर निर्भर करता है। अवलोकन से ऐसा स्पष्ट होता है कि निर्यात गुण्य ΔE विकसित अर्थ-व्यवस्था की अपेक्षा अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में परिमाणात्मक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण है।¹ कहने की आवश्यकता नहीं है कि ΔI एवं ΔG का सापेक्षिक महत्त्व मुख्यतः अवन्ध नीति की परम्परा से प्रस्थान की मात्रा पर निर्भर करता है। बचत, आयात एवं विनियोग की सीमांत प्रवृत्तियाँ अनिवार्यतः अपने औसत प्रतिरूप की ही तरह नहीं हैं और न इनका राष्ट्रीय आय से सम्बन्ध ही है। साथ ही, s' , m' एवं b' में विकसित तथा अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में स्पष्ट रूप से अन्तर होता है। यहाँ पर b' को शामिल करने से स्वतः प्रेरित निवेश के साथ-साथ प्रेरित निवेश की सम्भावित उपस्थिति भी स्पष्ट होती है।

समीकरण (1) के दोनों पक्षों को Y^d में भाग देने एवं नये क्रम में रखने से, हम समर्थ माँग (G^d) में वृद्धि की दर पाते हैं:

$$G^d = \frac{\Delta Y^d}{Y^d} = \frac{\alpha + \beta + \gamma}{s' + m' - b'} \quad (2)$$

जिसमें $\alpha = \Delta I/Y^d$, $\beta = \Delta G/Y^d$ और $\gamma = \Delta E/Y^d$ के हैं। समीकरण (2) से यह स्पष्ट होता है कि समर्थ माँग-सम्बन्धी वृद्धि की दर राष्ट्रीय आय की तुलना में स्वतः प्रेरित निवेश, सरकारी व्यय एवं निर्यात से प्राप्त आय में परिवर्तन के साथ प्रत्यक्ष रूप में तथा बचत, आयात एवं विनियोग की सीमांत उत्पादन-क्षमता के प्रतिस्तीही दिशा में परिवर्तन होने में सक्षम है। यह वृद्धिशील विवृत अर्थ-व्यवस्था के माँग-पक्ष को बतलाता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अन्य बातों के समान रहने पर, राष्ट्रीय आय (y) की तुलना में निर्यात में वृद्धि या आयात की सीमांत प्रवृत्ति (m') में कमी होने से समर्थ माँग में वृद्धि की दर में और वृद्धि होगी। फिर भी, समर्थ माँग में अधिक उच्च दर से वृद्धि प्राप्त करना तथा बनाये रखना है अथवा निम्न दर से, इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की दर, जिसे अभी तक हम स्थिर मानते हैं, के उल्लेख के बिना नहीं किया जा सकता है। इस बात पर हम लोग आगे चलकर विचार करेंगे। इसी बीच

1. देखें, 1951 ई० में मैकमिलन (न्यू० या०) द्वारा प्रकाशित एच० सी० यालिच की पुस्तक 'मनि, ट्रेड एंड इकोनामिक प्रोप' में 'अन्डरडिवेलपड कन्ट्रीज एंड डिइन्टरनेशनल मोनेटरी मेकेनिज्म'।

एक विवृत अर्थ-व्यवस्था के भुगतान-सन्तुलन की स्थिति के लिए दूसरे समीकरण का क्या आशय है, इस पर विचार करना अधिक रोचक होगा।

$\Delta i = 0$, $\Delta G = 0$ तथा $\Delta E = i$ मानकर हम लोग प्रेरित आयात से इस निर्यात-सम्बन्धी परिवर्तन की तुलना के लिए निर्यात में परिवर्तन होने के गुणक प्रभाव पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे। क्योंकि, हम जानते हैं कि घरेलू आय में निर्यात-जनित वृद्धि के परिणाम-स्वरूप अतिरिक्त आयात निम्नांकित प्रकार से प्रेरित होती है—

$$\Delta M = m' \Delta Y^d = m' \frac{i}{s' + m' - b'} \Delta E = \frac{m'}{s' + m' - b'} \Delta E \quad (3)$$

भुगतान-सन्तुलन की साम्यावस्था के मूल स्थान $E - M = \Delta R = 0$ (जिसमें M विकलन के अदृश्य मदों को शामिल करते हुए वास्तविक आयात एवं ΔR विदेशी विनिमय-कोष में कमी या वृद्धि है) से प्रारम्भ करने पर अनुकूल अथवा प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन उद्गमन तीसरे समीकरण के निम्नलिखित निर्देशनों से स्पष्ट होता है—

यदि $0 < s' > b' = 0$, तो $\Delta M < \Delta E$ (अपूर्ण हानिपूर्ति की स्थिति)।
यदि $0 < s' < b' > 0$, तो $\Delta M > \Delta E$ (अधिक हानिपूर्ति की स्थिति)।
यदि $0 < s' = b' > 0$, तो $\Delta M = \Delta E$ (समान हानिपूर्ति की स्थिति)।

इनमें से पहली स्थिति केन्स द्वारा दी गई है तथा जो अधिक क्षमता का मान्यता पर आधारित है, जो प्रेरित विनियोग को कम या निष्फल बनाती है। इसके परिणामस्वरूप प्रेरित आयात सदा निर्यात में किसी भी मौलिक वृद्धि से कम होता है तथा विदेशी विनिमय कोष में निम्नलिखित रकम के बराबर संचयन होता है—

$$\Delta R_n = (\Delta E_{n-1} + E_0) - (\Delta M_{n-1} + M_0).$$

दूसरी स्थिति एक अस्थायी व्यवस्था की ओर संकेत करती है, जिसमें विनियोग की सीमांत प्रवृत्ति वचत की सीमांत प्रवृत्ति से अधिक होने की ओर प्रवृत्त होती है। जिस तरह, युद्ध-विनष्ट अथवा अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में, जिनमें पूँजी का आम-तौर पर अभाव पाया जाता है अथवा व्यापार-चक्र की बढ़ती हुई स्थिति, जिसमें निष्कार्य संयंत्र एवं उपकरण समाप्तप्राय होते हैं, पाई जाती हैं। अधिक हानि पूर्ति की स्थिति में विदेशी कोष में असंचयन निम्न प्रकार से होता है—

$$-\Delta R_n = (\Delta M_{n-1} + M_0) - (\Delta E_{n-1} + E_0).$$

अन्तिम, यानी समान हानि पूर्ति की स्थिति वचत की सीमांत प्रवृत्ति के विनियोग की सीमांत प्रवृत्ति के बराबर होने से उत्पन्न होती है, जिससे विनिमय-कोष में न कोई संचयन होता है और न असंचयन ही, जिसमें $\Delta R = 0$ । इस अन्तिम स्थिति

को विशुद्ध घरेलू दृष्टिकोण से अपेक्षित नहीं माना जा सकता ; क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि स्वतः प्रेरित निर्यात में वृद्धि किसी-न-किसी समय आयात में समान वृद्धि से समाप्त हो जाती है। साथ ही, बिकामशील पूँजी के सम्भावित साधन के रूप में विदेशी विनियम के कोप में भी कोई वृद्धि नहीं होती है। फिर भी, यदि कोई एक अर्थ-व्यवस्था असन्तुलित भुगतान के मूल स्थान से प्रारम्भ होती हो, तो उसके लिए इसे अपेक्षित समझा जा सकता है।

विदेशी व्यापार एवं माँग में वृद्धि में इसी प्रकार का पारस्परिक एवं अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध है। माँग के साधन के रूप में निर्यात में वृद्धि से चिन्ता केवल इसी-लिए उचित है कि पूर्ति की दी हुई स्थिति में राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि माँग के ही द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार की चिन्ता बिल्कुल केन्स की परम्परा पर आधारित है, जो इस स्थापकीय धारणा, कि पूर्ति स्वयं अपने माँग का सर्जन करती है, को अस्वीकार करती है। फिर भी, इस प्रकार की चिन्ता बिल्कुल एकपक्षीय है; क्योंकि विदेशी व्यापारिक सम्बन्ध एक वृद्धिशील अर्थ-व्यवस्था के पूर्ति-पक्ष को भी प्रभावित कर सकता है। यही पर हमें केन्स की समर्थ माँग की पूर्ण धारणा का परित्याग कर पुनः एक बार, से के नियम (Say's Law) के बगैर पूर्ति एवं उत्पादकता पर स्थापकों की दृढ़ तीव्रता की ओर उन्मुख होना चाहिए।

विदेशी व्यापार एवं क्षमता में वृद्धि

अब माँग की परिस्थितियों को दिया हुआ मानकर, हम विदेशी व्यापार एवं क्षमता में वृद्धि के अन्य सम्बन्ध का विश्लेषण कर सकते हैं। प्राकृतिक साधनों के आकार एवं श्रम की सख्या दी हुई होने पर, किसी अर्थ-व्यवस्था की कुल पूर्ति अथवा उत्पादन-क्षमता मुख्यतः वास्तविक पूँजी की मात्रा एवं गुण पर निर्भर करती है। कुल उपलब्ध पूँजी के पूर्ण उपयोग के परिणामस्वरूप उत्पादन-क्षमता में वृद्धि को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—

$$\Delta Y^* = \sigma \Delta K = \sigma I, \quad (4)$$

जिसमें Y^* उत्पादन-क्षमता द्वारा निर्धारित शुद्ध राष्ट्रीय निपज अथवा केवल उत्पादन क्षमता है, K पूर्ण उपयोग की स्थिति में पूँजी की मात्रा, I शुद्ध निवेश ($I_t = K_t - K_{t-1}$) एवं σ प्राविधिक रूप में दी गई पूँजी की सीमान्त (औसत) उत्पादकता।

किन्तु सामान्यावस्था में, एक विवृत अर्थ-व्यवस्था का शुद्ध विनियोग असाधारण अर्थ में वचत के बराबर होता है, यानी

$$i = S + M - E; \quad i + E = S + M, \quad (5)$$

जहाँ S घरेलू वचत है और अन्य परिवर्तों पहले की ही तरह है।

पाँच को चार से प्रतिस्थापित करने पर आयात एवं निर्यात से युक्त उत्पादन क्षमता में वृद्धि प्राप्त होती है—

$$\Delta Y^s = \sigma (S + M - E). \quad (6)$$

पुनः हम S , M एवं E को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं $S = sY^s$, $M = mY^s$, एवं $E = eY^s$ जिसमें s वचत अनुपात, m आयात अनुपात एवं e निर्यात अनुपात हैं, (यानी औसत वचत एवं आयात की प्रवृत्ति तथा दिये हुए आन्तरिक उत्पादन एवं स्वतःप्रेरित निर्यात का अनुपात) उपर्युक्त परिभाषाओं को ध्यानमें रखते हुए पुनर्व्यवस्थित करने पर, उत्पादन-क्षमता (G^s) में वृद्धि की निम्नलिखित दर प्राप्त होती है—

$$G^s = \frac{\Delta Y^s}{Y^s} = \sigma (s + m - e), \quad (7)$$

जो एक विवृत अर्थ-व्यवस्था के पूर्ति-पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। समीकरण (7) यह बतलाता है कि जैसे-जैसे पूँजी की उत्पादकता (σ) बदलती है और आन्तरिक वचत के अनुपात जोड़ व्यापार-संतुलन के अनुपात ($s + m - e$) बदलते हैं, वैसे-वैसे उपलब्ध पूँजी के पूर्ण प्रयोग से प्राप्त उत्पादन-क्षमता की वृद्धि की दर प्रत्यक्ष अनुपात में परिवर्त्ती होने के लिए सक्षम है। समीकरण (7) का परिचालन-सम्बन्धी महत्त्व निम्नलिखित लोकप्रिय संख्यात्मक उदाहरणों² से स्पष्ट होता है—

1. σ के मूल्य का अनुमान विकसित एवं अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के औसत पूँजी-निपज अनुपात से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, देखें डब्ल्यू० फेलर का पूर्व-उद्धृत 'दि कैपिटल आउटपुट रेशियो इन डाइनामिक इकॉनामिक्स'; आई० यामडा का जुलाई, 1956 के इकानामिक रिव्यू में 'दि फाइव ईयर इकॉनामिक प्लान इन जापान ऐंड दि एनालिसिस ऑफ पोस्ट वार जेपेनीज इकॉनामी'; वाई० ओजेकी का मार्च, 1957 के इकॉनामी स्टडीज क्वार्टरली में 'ऑन दि कैपिटल-कोएफिसियण्ट इन अंडर-डिवेलपड इकॉनामीज'। विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में पूँजी निपज अनुपात साधारणतया कम होता है, जिससे श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पर आधृत पूँजी गुणक की अधिक क्षमता का आभास होता है। तुलनात्मक वचत-अनुपात के लिए देखें 'एस० कुज़नेट्स का पूर्व-उद्धृत इकॉनामिक ग्रोथ ऐंड इनकम इनइक्वेलिटी'। जहाँ तक कि निर्यात एवं आयात-अनुपात का सम्बन्ध है, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की निम्न उत्पादन एवं निर्यात-क्षमता इनके निर्यात-अनुपात के आयात-अनुपात के निरन्तर अधिक होने की एक आवश्यक प्रकल्पना है। निरपेक्ष रूप में तुलनात्मक निर्यात-आयात-अंकों³ एच० वालिच का पूर्व उद्धृत लेख देखें।

यदि $\sigma = .5$, $s = .10$, $m = .05$, $e = .07$, तो $G' = .04$
(विकसित अर्थ-व्यवस्था)

यदि $\sigma = 2$, $s = .05$, $m = .015$, $e = .10$, तो $G' = .02$
(अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था)

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि उच्च पूँजी-उत्पादकता गुणक एक उच्च बचत अनुपातवाली विकसित अर्थ-व्यवस्था धनात्मक विदेशी सतुलन-अनुपात ($e - m > 0$) द्वारा उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की उच्च दर प्राप्त कर सकती है। इसके विपरीत निम्न उत्पादकता एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था ऋणात्मक विदेशी सतुलन-अनुपात ($e - m < 0$) के परिणामस्वरूप उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की निम्न दर ही प्राप्त कर पाती है। ये इस बात को भी सक्षित करते हैं कि यदि एक विकसित अर्थ-व्यवस्था में उसकी माँग से अधिक वृद्धि होती है, तो इससे उसके धनात्मक विदेशी सतुलन अनुपात में अवश्य वृद्धि होगी और यदि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की क्षमता में उसकी माँग की तुलना में धीरे-धीरे वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती हो, तो इससे उसके ऋणात्मक विदेशी सतुलन-अनुपात में अवश्य वृद्धि होगी।

इस प्रकार, प्रकल्पना है कि एक विकसित अर्थ-व्यवस्था में साधारणतया अनुकूल भुगतान-संतुलन होता है, जो $eY' - mY' = \Delta R > 0$ से स्पष्ट होता है जब कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में व्यवहारतः प्रतिकूल भुगतान-संतुलन होता है, जो $eY' - mY' = \Delta R < 0$ से ज्ञात होता है। किन्तु, इसका तात्पर्य यह नहीं कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को संतुलित भुगतान-संतुलन को ध्यान में रखे बगैर अपनी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि का प्रयास नहीं करना चाहिए; क्योंकि आगे का विश्लेषण इसके ठीक विपरीत बतलाता है। अब स्फोति एवं असंतुलन के बगैर संतुलित विकास की प्राचलीय क्रिया पर विचार किया जाय।

संतुलित विकास के लिए प्राचलीय क्रियाएँ

संतुलित विकास आगे बढ़ने की आदर्श नीति है, जो पूर्ण होने पर ऐसी बढ़ती हुई वास्तविक आय की गारन्टी प्रदान करता है, जो न बढ़ते हुए मूल्य से कम होती है, न भुगतान के संतुलन की दीर्घकालिक कठिनाइयों से ही समाप्त होती है। पूर्ववर्ती विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि संतुलित विकास की स्थिति को प्राप्त करने तथा बनाये रखने के लिए निम्नलिखित आधारभूत शर्त की पूर्ति अनिवार्य है।

$$\frac{\alpha + \beta + \gamma}{s' + m' - b'} = \sigma (s + m - e) \text{ या } G^d = G^s \quad (8)$$

समीकरण (8) यह बतलाता है कि यदि $G^d = G^s$ के, तो मौद्रिक राष्ट्रीय आय ($Y^d m$) में निम्नलिखित घातीय रूप में वृद्धि होगी—

$$Y^d = Y^d = P(t) \quad Y^s = Y^d (1 + g_m)^t,$$

$m \qquad \qquad \qquad mo$

जिसमें P समय में मूल्यसूक्ष्म हैं, Ymo^d मौद्रिक आय का प्रारम्भिक मूल्य है, और gm मौद्रिक आय में वृद्धि की दर ($\Delta Ym^d/Ym^d$) है। यदि अर्थ-व्यवस्था $G^d = G^s$ संतुलन की प्रारम्भिक स्थिति से बढ़ी हो, तो $t > 0$ समय में, $G^d > G^s$ के रूप में एक आकस्मिक आघात पूर्ण क्षमता-विकास के अपरिवर्त्ती पथ से स्फीति-जनक अन्तर की सृष्टि करेगा। जैसा कि दूसरे समीकरण से स्पष्ट है $G^d > G^s$ के रूप में प्रारम्भिक आघात α, β, γ या B' में साधारणतया स्थायी वृद्धि अथवा विकल्पतः s' एवं m' में इसी प्रकार की कमी के परिणामस्वरूप हो सकता है। $G^d > G^s$ की स्थिति केवल स्फीति की ओर की निरन्तर प्रवृत्ति का ही नहीं, वरन् भुगतान-संतुलन की दीर्घकालिक कठिनाई का भी सूचक है। क्योंकि, उच्च G^d से बड़े पैमाने पर प्रेरित आयात तथा निम्न G^s से छोटे पैमाने पर किये गये निर्यात की सम्भावना का बोध होता है।

इससे प्रश्न यह होता है कि $G^d > G^s$ के रूप में विषमता से युक्त एक विवृत अर्थ-व्यवस्था इस विषमता में निहित आंतरिक स्फीति एवं बाह्य असंतुलन को किस प्रकार से दूर कर सकती है? इसका सामान्य उत्तर यह है कि यदि $G^d = G^s$ के रूप करना है, तो G^s में साथ-ही-साथ कमी किये वगैर G^d में कमी, या G^d में वृद्धि के वगैर G^s में वृद्धि की जाय। यह वास्तव में एक बड़ी बात है, किन्तु फिर भी समीकरण (8) द्वारा व्यक्त शर्तों की पूर्ति के लिए दूसरे तथा सातवें समीकरणों के प्राचल के साथ संभावित क्रियाओं का पता लगाया जाय।

समर्थ माँग का नियंत्रण

G^d को कम करने की परिचालन-सम्बन्धी सम्भावना, विदेशी भुगतान-शेष के संतुलन को भंग किये वगैर आंतरिक आर्थिक उन्नति को पोषित करने के मूल उद्देश्य से आवश्यक रूप में सीमित है। इस सीमा को ध्यान में रखते हुए, अन्तर्जनित प्राचल s', m' एवं b' को दिया हुआ मानकर, पहले बहिर्जनित प्राचल α, β एवं γ में कमी की सम्भावना पर विचार किया जाय।

किसी दिये हुए राष्ट्रीय आय के स्तर पर, स्वतः प्रेरित निवेश की कितनी मात्रा से सरकारी व्यय या निर्यात-संबन्धी आय में कमी होगी, यह गुणक तत्रा सम्बद्ध समर्थ माँग में वांछित कमी पर निर्भर करता है; क्योंकि पहले समीकरण से हम यह जानते हैं कि इनमें से किसी भी गुण में इच्छित कमी निम्नलिखित रूप से स्पष्ट

होती है : $\Delta I = \Delta Yd/k$, $\Delta G = \Delta Yd/k$, अथवा $\Delta E = \Delta Yd/k$ जिसमें, $k = i/(s^1 + m^1 - b^1)$ । उदाहरण के लिए, मान लिया जाय कि $s^1 = .05$, $m^1 = .3$, $b^1 = .1$, $\Delta Yd = 1$ है, तो $\Delta I = Yd/k$ के अनुसार माँग के सम्बन्ध साधन के रूप में स्वतः प्रेरित निवेश में $1/4 = .25$ से कमी होगी । अन्य किसी भी गुण्य के लिए यही सत्य होता है ।

इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण यह है कि माँग के किसी विशेष साधन में कमी के लिए चुनाव-भुगतान शेष तथा उत्पादन-क्षमता के दीर्घकालिक विकास के सम्भावित प्रतिपात से प्रभावित होना चाहिए । जहाँ तक भुगतान-शेष का सम्बन्ध है, अन्य बातों के समान रहने पर, माँग के किसी दिये हुए स्तर (y) से सम्बन्ध निर्यात में स्वतः प्रेरित कमी बाह्य असंतुलन को उत्तेजित किये बगैर Gd में कमी करेगी । किन्तु, ऐसा तभी होगा, जबकि साय-ही साय b' से सम्बद्ध s' में भी वृद्धि हो । किन्तु, चूँकि Y में परिवर्तन का s' पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता, अतएव Y में कमी अधिक माँग को अवमदित करने के लिए भुगतान शेष को संतुलित करने के उद्देश्य के अनुरूप समझकर छोड़ देना चाहिए । इसके अतिरिक्त, चूँकि किसी एक अर्थ-व्यवस्था के निर्यात की माँग मुख्यतः दूसरे देशों की आय के स्तर पर निर्भर करती है, इसलिए कोई भी एक अर्थ-व्यवस्था y में अपने इच्छानुसार हेर-फेर नहीं कर सकती है । (केवल समुक्त-राज्य के सम्भावित अपवाद को छोड़कर, जो अपने निर्यात की विदेशी माँग को ऋण एवं अनुदान के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है, जैसा कि मार्शल प्लान ने स्पष्ट कर दिया था) । जहाँ तक उत्पादन-क्षमता में दीर्घकालिक वृद्धि का सम्बन्ध है, α अथवा β में कमी, यदि यह स्वतः प्रेरित निजी निवेश के अनुत्पादक अग अथवा राजकीय व्यय (जैसे पिरामिड का निर्माण अथवा शस्त्रीकरण) में कमी के द्वारा की जाती है, से पूँजी की उत्पादन-क्षमता में (σ) कमी नहीं होनी चाहिए । यदि α अथवा β में कमी महँगी मुद्रा-नीति के द्वारा हुई हो, तो यह उत्पादन के चक्रदार तरीके को हतोत्साहित कर सकती है और इस प्रकार दीर्घकाल में पूँजी की उत्पादकता में कमी कर सकती है । (यह अंतिम प्रभाव ध्रम की उत्पादन-क्षमता पर संभवतः पूँजी एवं ध्रम के निम्न अनुपात के माध्यम से पड़ता है, जैसा कि $Y/K = (Y/N)/(K/N)$ से स्पष्ट है ।

अब α , β एवं Y को दिया हुआ मानकर तथा भुगतान शेष एवं उत्पादन-क्षमता में दीर्घकालिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, हम समर्थ माँग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही s' , m' एवं b' की सम्भावित क्रियाओं का अध्ययन करेंगे ।

s' में वृद्धि के द्वारा भुगतान-शेष के संतुलन को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन-क्षमता में विस्तार के उद्देश्यों को समाप्त किये बगैर Gd में कमी की जा सकती है । क्योंकि, जैसा कि पूर्व विश्लेषण से स्पष्ट है, एक ओर $s' \leq b'$ से

$\Delta M \leq \Delta E$ होता है तथा दूसरी ओर s' में समान वृद्धि से दीर्घकाल में s एवं σ में वृद्धि होती है और इस प्रकार $m > e$ के अनुपात में बढ़े बाह्य घाटे पर अत्यधिक निर्भरता के बगैर G_s में वृद्धि होती है। इस सम्बन्ध में यहाँ एक आवश्यक आरक्षण यह है कि s' में वृद्धि के उपाय, उपभोग में मितव्ययिता को आवश्यकता से अधिक बतलाने के कारण, अनुचित सिद्ध हो सकते हैं।

बचत की सीमांत प्रवृत्ति के निवेश की सीमांत प्रवृत्ति के बराबर अथवा अधिक होने की स्थिति में आयात की सीमांत प्रवृत्ति m' में वृद्धि भी अपेक्षित हो सकती है। क्योंकि, जैसा कि पूर्ववर्णित है, $s' \leq b'$ से $\Delta M \geq \Delta E$ होता है। m' वृद्धि से G_d में कमी के अतिरिक्त दीर्घकाल में m में वृद्धि होती है, जिससे G_s की वृद्धि में भी सहायता मिलती है। पुनः यदि उच्च m' का, आय विपाक में किसी क्षतिपूर्ति के परिणामस्वरूप, प्रविस्थापन विपाक उत्पादित उपभोक्ता की वस्तुओं की माँग में ह्रास होता है, तो इससे उस स्तर तक s' एवं s में वृद्धि होगी, जिससे G_d में कमी तथा G_s में और अधिक वृद्धि होगी।

निवेश की सीमांत प्रवृत्ति, b' में कमी पर भी एक वैकल्पिक परिचालन-सम्बन्ध सम्भावना के रूप में विचार किया जा सकता है। b' में ह्रास भुगतान-शेष की स्थिति को और खराब किये बगैर G_d' में कमी उत्पन्न करता है; क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि शून्य या लघु b' से केन्स के अपूर्ण क्षति-पूर्ति के सिद्धांत की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। साथ ही, चूँकि b' में ह्रास ऐसे उपायों द्वारा किया जाता है, जिनका उद्देश्य नवीन क्रिया-निवेश के क्षेत्र में वृद्धि तथा प्रेरित निवेश में अत्यधिक निर्भरता में कमी (त्वरण-सिद्धांत की तरह) होता है, अतएव इससे दीर्घकाल में σ में वृद्धि होती है और इसलिए G_s में भी वृद्धि होती है।

इस प्रकार, $G_d > G_s$ से उत्पन्न स्फीतिजनक परिस्थितियों में, भुगतान-शेष के असंतुलन को प्रोत्साहित तथा उत्पादन-क्षमता में दीर्घकालिक विकास में बाधा उत्पन्न किये बगैर माँग में वृद्धि को निम्नलिखित उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है—(1) s' में वृद्धि, (2) m' में वृद्धि, (3) b' में ह्रास, (4) α में ह्रास, (5) β में ह्रास तथा/या (6) ϵ में ह्रास। उत्पादन-क्षमता में नियंत्रण का अभी वर्णन करना बाकी है।

उत्पादन-क्षमता का नियंत्रण

उत्पादन-क्षमता के विकास की दर में वृद्धि निश्चय ही समर्थ माँग में विकास की दर में कमी की तुलना में अधिक कठिन है। यह कठिनाई प्राचलीय क्रिया पर इस निरोध पर कि G_s में इस प्रकार से वृद्धि नहीं करनी चाहिए, जिससे G_d में वृद्धि हो तथा $\Delta R < 0$ हो जाय, के परिणामस्वरूप और भी बढ़ जाती है। इस प्रतिबंध

को ध्यान में रखते हुए समीकरण (7) की सम्भावित प्राचलीय क्रिया की खोज की जाय।

पूँजी की कार्य-क्षमता (σ) में वृद्धि का लाभ माँग में वृद्धि के आत्माघाती सहायक तथा बाह्य श्रेय की स्थिति को और अधिक खराब किये बगैर G_s की स्थिति को बढ़ाना होता है। वयोजि, यह एक दी गयी पूँजी के कोष के अधिक योग्य उपयोग, न कि पूँजी में वृद्धि, जिससे अनपेक्षित माँग का सृजन हो अथवा अनपेक्षित आयत की आवश्यकता हो, के द्वारा अधिक उत्पादन एवं निर्यात-सम्बन्धी क्षमता को सूचित करता है। हम इसे निम्नांकित प्रकार से देख सकते हैं।

मान लिया कि पूँजी का संपूर्ण कोष (K) दो भागों में विभक्त है—एक वह, जो स्वदेश-प्रधान उद्योगों, यानी जो केवल घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, के द्वारा स्वीकृत तथा प्रयोग किया जाता है (K_h), तथा दूसरा वह, जो निर्यात-प्रधान उद्योगों, यानी जो केवल विदेशी बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, के द्वारा स्वीकृत तथा प्रयोग किया जाता है (K_e) है। अतएव—

$$K = K_h + K_e \quad (9)$$

जिसके वितरण का अनुपात है—

$$\frac{K_h}{K} = \eta, \quad \frac{K_e}{K} = 1 - \eta \quad (10)$$

पुनः हम उत्पादन-क्षमता (Y^s) को स्वदेश प्रधान-विपज (Y_h^s) तथा निर्यात-प्रधान विपज (Y_e^s) के योग के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिससे—

$$Y^s = Y_h^s + Y_e^s \quad (11)$$

इस समीकरण के दाहिने पक्ष को विशेष रूप से इस प्रकार कहा जा सकता है—

$$Y_h^s = \sigma_h K_h \quad (12)$$

$$Y_e^s = \sigma_e K_e \quad (13)$$

जिसमें σ_h समस्त स्वदेश-प्रधान उद्योगों की पूँजी की औसत एवं सीमांत उत्पादकता तथा σ_e निर्यात-प्रधान उद्योगों में पूँजी की औसत तथा सीमांत उत्पादकता है।

यहाँ हम इस स्वीकार्य आधार पर कि ह्रास-मान लागत (वर्द्धमान-प्रतिफल) वाले उद्योगों को स्वदेशी बाजार के साथ-साथ साधारणतया वृद्धि-शील निर्यात-बाजार (विशेषतः वृद्धिशील स्वदेशी सीमा तथा बाजार के अभाव में) की आवश्यकता होती, $\sigma_e > \sigma_h$ मानते हैं। यह मान्यता वितरण के अनुपात, $1 - \eta$ में वृद्धि के पक्ष में वर्तमान तर्क प्रस्तुत करने एवं संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए पूँजी की

उत्पादकता तथा निर्यात-प्रधान उद्योगों की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के लिए निर्णायक महत्त्व का है।

अब 10वें, 12वें तथा 13वें समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, हम 11वें समीकरण को पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं—

$$Y^s = \sigma_h K_h + \sigma_e K_e = \sigma_h \eta K + \sigma_e (i - \eta) K. \quad (14)$$

14वें समीकरण से संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए पूँजी की औसत उत्पादकता प्राप्त होती है—

$$\frac{Y^s}{K} = \sigma = \sigma_h \eta + \sigma_e (i - \eta), \quad (15)$$

जिससे यह स्पष्ट होता है कि $\sigma_e > \sigma_h$ होने पर, संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए पूँजी की औसत उत्पादकता वितरण के अनुपात $(i - \eta)$ में वृद्धि के परिणामस्वरूप वृद्धि के सक्षम है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वितरण के अनुपात $(i - \eta)$ में इस वृद्धि से निर्यात-प्रदान-निपज में भी $Y^s = \sigma_e (i - \eta) K$ के द्वारा वृद्धि होती है।¹ साथ ही, पूँजी-उत्पादकता गुणक (σ) में वृद्धि का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि स्वदेशी वचत अनुपात (S) को संपूरित करने के लिए छोटे आयात-अनुपात (m) की आवश्यकता पड़ती है।

वचत-अनुपात (s) में वृद्धि से m यदि इससे m में भी वृद्धि का प्रतिनिधित्व होता है, G_s में वृद्धि हो जिससे समर्थ-माँग में वृद्धि की दर कम हो जाय, तो यह G_s में साथ-ही-साथ वृद्धि के बगैर G_s में वृद्धि कर सकता है। साथ ही, सातवें समीकरण के अनुसार, उच्च पूँजी उत्पादकता की ही तरह, उच्च स्वदेशी वचत-अनुपात स्वदेशी वास्तविक पूँजी के संपूरक के रूप में आयात पर निर्भरता में कमी करता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उच्च वचत-अनुपात उच्च

1. किन्तु, निर्यात-संवंधी वस्तुओं की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि से निर्यात की माँग में आवश्यक रूप से वृद्धि नहीं होती; क्योंकि निर्यात विदेशी आय, सापेक्षिक मूल्य विनियम-दर एवं संभवतः शैर-आर्थिक वैदेशिक नीति पर निर्भर करता है। आर० नम्बर्स ब्रिटेन के निर्यात उद्योगों में इस प्रकार की वृद्धि की सिफारिश करते हैं, यह अधिक-से-अधिक उस विशेष परिस्थिति का परिचायक है, जिसमें यू० के० (U.K.) से निर्यात की विदेशी माँग ठीक उसके अनुरूप होगी जिसकी ब्रिटेन पूर्ति कर सकता है। किन्तु अधिकांश व्यापारी राष्ट्रों (जैसे जापान) के साथ प्रधान कठिनाई निर्यात की क्षमता का अभाव न होकर विदेशी बाजार (माँग) का अभाव है। अतएव, निर्यात-प्रधान उद्योगों की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि, संपूर्ण एवं विकास के क्षेत्र में योगदान करते हुए भी वृद्धिशील विदेशी बाजार के अभाव में निराशजनक सिद्ध हो सकती है।

बचतवाले आय-वर्गों के पक्ष में स्वायत्त आय के पुनर्वितरण या लगातार बजट-आधिक्य का परिणाम होता है।

यदि आयात-अनुपात (m) में वृद्धि m' में वृद्धि का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो इससे G_d में वृद्धि के बगैर G_s में वृद्धि हो सकती है¹। किन्तु दीर्घ-कालीन भुगतान-शेष के सतुलन के दृष्टि-कोण में उपभोक्ता वस्तुओं के आयात की औसत प्रवृत्ति (mc) को स्थायी रखकर पूँजीगत वस्तुओं के आयात की औसत प्रवृत्ति (mi) में वृद्धि को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि, आयात-अनुपात वास्तव में इन्हीं प्रवृत्तियों का योग है, यानी $m = mc + mi$ । इसका तात्पर्य यह है कि यदि m स्थायी है, तो mi में वृद्धि mc में कमी के द्वारा ही होगी। और यदि $m = mc$ के स्थायी है तो m में वृद्धि mi में वृद्धि का सूचक है। यदि m में वृद्धि की जगह mc की जगह mi में वृद्धि का परिणाम है, तो यह स्वदेशी पूँजीगत वस्तुओं के उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देगा।¹ व्यापारिक नीति के संदर्भ में इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि शुल्क-दर तथा अन्य प्रकार के आयात-नियंत्रण की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि उपभोक्ता वस्तुओं के आयात की सीमात प्रवृत्ति में किसी प्रकार की वृद्धि न हो।

अतः एक दिये हुए m की तुलना में e में ह्रास में, G_d में वृद्धि के अन्य उद्देश्यों का विरोध किये बगैर, G_s में वृद्धि होगी; क्योंकि अति अल्पकाल में e में ह्रास y में ह्रास का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। फिर भी, e में इस ह्रास का भुगतान-शेष के सतुलन पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। कोई एक अर्थ-व्यवस्था अपने दीर्घकालीन भुगतान सतुलन की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए अधिक-से-अधिक Y में वृद्धि के e पर वृद्धिशील प्रभावों पर आश्रित रह सकती है। इससे G_s में वृद्धि के लिए, अन्यथा बड़े घाटे के अनुपात $e - m < 0$ को टाला जा सकता है। इससे अधिक एक अकेला निर्यातक देश केवल यह आशा कर सकता है कि दिये हुए सापेक्षिक मूल्य एवं विनिमय-दर पर शेष विश्व अपनी आय अथवा अपनी आयात की औसत प्रवृत्ति में वृद्धि करेगा। एक दिये हुए m की तुलना में e में किस मात्रा तक कमी होनी चाहिए, यह σ एवं s के प्रचलित मूल्यों पर निर्भर करता है; क्योंकि जब कोई अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था अधिक उत्पादक एवं मितव्ययी हो

1. इसका तात्पर्य यह नहीं कि आयात की गई उपभोक्ता-वस्तुएँ अनुत्पादक होती हैं, क्योंकि ये जैसे उत्पादक साधनों को, जो अन्यथा उपभोक्ता-वस्तुओं के उद्योग में लगे होते हैं, मुक्त कर स्वदेशी पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों को परोक्ष रूप में योगदान देती है। किन्तु साधनों की सापेक्ष निश्चलता एवं अपर्याप्त विनिमय-कोषवाली अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए पूँजीगत वस्तुओं के आयात पर ध्यान केंद्रित करना ही अधिक व्यावहारिक और महत्व की बात है।

जाती है, तो यह अपनी उत्पादन क्षमता को अपने निर्यात से अधिक विदेशी वस्तुओं एवं पूँजी के आयात के बगैर ही विकसित कर सकती है।

अंतिम टिप्पणी

एक विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था के केवल माँग-पक्ष पर जोर देने का तात्पर्य विदेशी व्यापार के क्षमता-सर्जनात्मक पहलू, जिसकी चर्चा आदमस्मिथ के 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' से अब तक के संस्थापक सिद्धांतों में मिलती है, की अपेक्षा करना होगा। इसी प्रकार केवल पूर्ति-पक्ष पर जोर देने का तात्पर्य विदेशी व्यापार के आय-सर्जनात्मक पहलू की, जिसे केन्स के सिद्धांतों ने बताया है, अपेक्षा करना तथा संस्थापकों की 'पूर्ति' स्वयं अपनी माँग का सर्जन करती हैं—“इस बात की मान्यता-संबंधी भूल को दोहराना है। तदनुकूल पूर्ण रोजगारी (श्रम एवं पूँजी दोनों की) के साथ, किन्तु आंतरिक स्फीति एवं बाह्य असंतुलन के बगैर संतुलन विकास की प्राप्ति एवं उसे बनाये रखने के लिए समर्थ माँग एवं उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की दरों को एक-दूसरे के समरूप बनाना अनिवार्य है। $G^d > G^s$ से उत्पन्न स्फीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने माँग में वृद्धि-संबंधी समीकरण एवं क्षमता में वृद्धि-संबंधी समीकरण की संभावित प्राचलीय संक्रियाओं का पता लगाया है, जिससे $Gd = Gs$ होता है, यानी उन उपायों एवं साधनों का पता लगाया है, जिससे कि Gs में कमी किये बगैर Gd में कमी तथा Gd में साथ-ही-साथ वृद्धि के बगैर Gs में वृद्धि की जा सकती है।

यदि स्वदेशी विकास एवं भुगतान-शेष संतुलन के बीच निश्चित रूप में चुनाव करना हो तो अधिकांश अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ पिछले की तुलना में पहले को ही अधिमान देगी। इसके कारण भी स्पष्ट हैं। क्षमता में वृद्धि धीरे-धीरे उन्नतिशील भुगतान-संतुलन की एक प्रकल्पना है, किन्तु भुगतान-शेष की समस्याओं में अत्यधिक पूर्वग्राह्यता से संपूर्ण उद्योगीकरण की जगह विनिमय उपार्जन-संबंधी उद्योगों के एक पक्षीय विकास को प्रोत्साहन मिलता है। उपनिवेशी इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं।

अपूर्ण रोजगार की ही तरह, अल्प विकास की मुक्त श्रम-भेदमूलक व्यापार के विरुद्ध एक प्रबल प्रकल्पना है। क्योंकि, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ सदा स्वदेशी उद्योगों को, विदेशी वस्तुओं की वास्तविक या संभावित प्रतियोगिता से सुरक्षित रखने का प्रयास करती हैं और ऐसा करना साधारणतया उनके लिए उचित भी होता है। फ्रेडरिक लिस्ट के संक्षरण के द्वारा उद्योगीकरण के सिद्धांत¹ में सत्य की यही प्रधान मात्रा है जिसे हावेलमो (*Haavelmo*) के वाक्यांश² “अंतर्राष्ट्रीय सम-

1. देखें इनकी पुस्तक 'दस नेशनल सिस्टम देर पोलिटिशन ओकनोमी'।

2. टी. हावेलमो, 'ए स्टडी इन दि थियरी ऑफ इकोनामिक इवोल्यूशन'।

स्थितिकरण के उद्देश्य की पूर्ति के सदर्थ में मुक्त व्यापार के समर्थकों के अतिरिक्त सभी स्वीकार करते हैं। विश्व के अल्प-विकसित क्षेत्रों को विकसित किये बगैर बहु-पक्षीय व्यापार की आशा करना उतना ही निष्फल है, जितना कि सर्वव्यापी पूर्ण रोजगारी को प्रोत्साहित किये बगैर मुक्त व्यापार की चर्चा करना निरर्थक है। इस अंतिम तथ्य का हम लोगो ने अभी केन्स के सिद्धांत में अध्ययन किया है। इस अवध में यह स्मरण करना शिक्षाप्रद होगा कि केन्स के निश्चित रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्ण रोजगार की नीति से सम्बद्ध किया था। साथ ही, उसने विश्व बैंक के एक प्रधान रूप में, विश्व के साधनों को संपूर्ण मानवता के लिए और अच्छी तरह से उपलब्ध बनाना तथा इस उद्देश्य से अपनी क्रियाओं को इस प्रकार संपादित करना माना था, जिससे सभी सदस्य-राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान-शेष के संतुलन में वृद्धि हो सके।¹ अब हमारा विश्लेषण यह सूचित करना है कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की भुगतान-शेष के असंतुलन के अनुचित मय के बगैर, उद्योगीकरण के कार्यक्रम को चलाना चाहिए।²

1. देखें, 23 मई, 1944 को हाऊस ऑफ लांड्स के समक्ष केन्स का व्याख्यान तथा 3 जुलाई, 1944 ई० को ब्रुड-वैंक पर द्वितीय आयोज की प्रथम बैठक में उसकी प्रारंभिक चर्चा।
2. उद्योगीकरण के सभावित विरोध के अवध में हम निम्नलिखित विशेष टिप्पणी कर सकते हैं। (1) उद्योगीकरण के परिणाम-स्वरूप निर्मित वस्तुओं का अधिक उत्पादन तथा निर्यात से आयात (या उद्योगीकरण अर्थ-व्यवस्था के निर्यात) के लिए विदेशी माँग के आय का लचीलापन इकाई से भी बहुत अधिक बढ़ जायगा $(\Delta M_w/M_w)/(\Delta Y_w/Y_w) > 1$, जिसमें M_w शेष विश्व का आयात तथा Y_w इनकी सम्मिलित राष्ट्रीय आय है। ऐसी स्थिति में निर्यात करने वाली अर्थ-व्यवस्था अपने विदेशी संतुलन में सम्भवतः अत्यधिक अस्थायित्व और विशेषतः संपूर्ण विश्व की राष्ट्रीय आय में कमी आने पर अपने निर्यात में अत्यधिक हानि का अनुभव करेगी। (2) यदि उद्योगीकरण की ओर उन्मुख अर्थ-व्यवस्था के आयात में पूँजीगत मालों की प्रधानता है, तो आयात को आय में परिवर्तन की दर पर आश्रित माना जा सकता है, यानी $M_L = \beta \Delta Y$, जिसमें M_L पूँजीगत वस्तुओं का आयात तथा β सम्बद्ध पूँजी-निपज का अनुपात (आयातित पूँजीगत मालों की उत्पादकता का उल्टा) है। इस आयात-संबंधी समीकरण के दोनों पक्षों को Y से भाग देने पर निम्नलिखित आयात अनुपात मिलता है : $M_L/Y = \beta (\Delta Y/Y)$ । इससे स्पष्ट है कि स्वदेशी आय वृद्धि की दर से बढ़ने से आयात-अनुपात में एक दिये हुए निर्यात-अनुपात (E/Y) से अधिक वृद्धि हो सकती है, जब तक कि पूँजी-निपज अनुपात (β) में आयातित पूँजीगत मालों की बढ़ती हुई उत्पादकता से

कमी न हो जाय। (3) श्रम की बढ़ी हुए उत्पादकता के परिणाम-स्वरूप मौद्रिक मजदूरी की उच्च दर से औसत आयात-मूल्य (P_m) की तुलना में औसत निर्यात-मूल्य P_e में वृद्धि हो सकती है, जिससे निर्यात में कमी तथा आयात में वृद्धि होगी। यह अंतिम प्रभाव $\Delta m = m \Delta Y = m k t \Delta E$, के माध्यम से होता है, जिसमें k' विदेशी व्यापार गुणक, $t = P_e / P_m$ या व्यापार की शर्तों का सूचनांक तथा E निर्यात हैं। किन्तु t में इस प्रकार की वृद्धि साधारणतया निर्यातकों को सरकारी उपदान, अथवा निर्यातकों के बीच निर्यात मूल्य नहीं बढ़ने के एकाधिकार-संवंधी समझौते के द्वारा समाप्त कर दी जाती है। (4) पूर्ण रोजगार-के बिन्दु तक निर्यात-प्रधान उद्योगों के विस्तार से सामान्य मूल्य (निर्यात मूल्य-सहित) में वृद्धि होती है, जो निर्यात-व्यापार के लिए हानिकारक होता है। किन्तु इन्हीं के पूर्ण रोजगार के बिन्दु से कम विस्तार से स्वदेशी वास्तविक आय एवं प्रेरित आय में वृद्धि होती है और आयात के लिए विदेशी माँग की कीमत-लोच जितनी अधिक तथा आयात की स्वदेशी सीमांत-प्रवृत्ति जितनी ही उच्च होगी, विदेशी संतुलन पर इसका शुद्ध प्रभाव उतना ही प्रतिकूल होगा।

अध्याय 11

केन्सीयोत्तर विकास-सिद्धान्तों पर उपसंहार

इस अध्याय में हम पूर्वगामी अध्यायों में विकसित सिद्धान्त की अन्य केन्सी-योत्तर विकास के सिद्धान्तों से तुलना कर, इसे समाप्त करेंगे। यह तुलना इस बात को स्पष्ट करने के उद्देश्य से की जायगी कि इनमें प्रमुख अन्तर कहाँ से पाये जाते हैं तथा ये अन्तर, कहाँ तक अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास से सम्बन्ध रखते हैं। यह तुलना दो शीर्षकों के अन्तर्गत की जायगी : (क) राज्य के विकासात्मक कार्य, तथा (ख) सन्तुलित विकास की प्रकृति एवं यत्र।

राज्य के विकासात्मक कार्य

हमारे विचार में, सबसे पहिले अल्प-विकसित देशों के विशेष सन्दर्भ में, केन्स के नाम से सम्बद्ध राज्य के स्थायित्व प्रदान करने के कार्य को, इससे विकासात्मक कार्य से, पहिले की अपेक्षा और अधिक पैमाने पर, मिलाना चाहिए। हैरोड, डोमर एवं रॉबिन्सन के अवध-विकास-सम्बन्धी माडलो में इस बात को स्पष्ट करने का निपेधात्मक गुण पाया जाता है कि किसी अर्थ-व्यवस्था के दीर्घकालिक विकास को, निजी वचन एवं निवेश की मरजी, लाभ से प्रेरित आविष्कार एवं नवीन क्रियाओं के संयोग तथा बाजार की अनियन्त्रित शक्तियों की कार्यवाही पर छोड़ना, कितना अनिश्चित एवं निष्फल है। इन सभी विकास माडलो से अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को यह सकारात्मक शिक्षा मिलती है कि मात्र की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्थाओं ने अवध नीति के वातावरण में जिस गति से विकास किया था, उससे यदि इन अर्थ-व्यवस्थाओं का अधिक प्रभाव-पूर्ण एवं द्रुतगति से उद्योगीकरण करना है, तो राज्य को केवल स्थायित्व प्रदान करने वाले कार्यों के रूप में ही नहीं, बरन् विकासात्मक कार्य करने चाहिए।

अधिक स्पष्टतः, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को हैरोड के स्वतःप्रेरित निवेश-अनुपात (k) पर उससे अधिक गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा, जितना कि वह स्वयं एक विकसित अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में करता है। क्योंकि, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में, जैसा कि हैरोड स्वेच्छा से मान लेता है, स्वतःप्रेरित निवेश अनिवार्यतः केवल एक आय-उत्पादक, वचत को समाप्त करने वाला शस्त्रीकरण-सम्बन्धी व्यय ही नहीं, बल्कि सम्भवतः क्षमता-वर्द्धक सार्वजनिक निवेश-सम्बन्धी व्यय है। स्वतःप्रेरित निवेश के निर्णायक महत्त्व को कम आंकने से ही हैरोड के निजी निवेश को अभिप्रेरित करने के लिए आय में वृद्धि की अपेक्षित दर को महत्त्व दिया है। अल्प-विकसित परिस्थितियों में, जहाँ किसी प्रकार भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादक निवेश लाने के लिए निजी अभिप्रेरणा एवं जोखिम वहन करने की बहुत न्यूनता होती है, वहाँ, स्वतःप्रेरित निजी निवेश का प्रेरित निवेश पर समावेश, अन्यथा असह्य बोझ को बहुत कम कर देता है। यह दिखलाया जा चुका है कि स्वतःप्रेरित निवेश को हटा देने के परिणाम-स्वरूप, हैरोड के अवस्फीति झुकाव को विकास-समीकरणों में स्पष्ट सार्वजनिक नीति-सम्बन्धी प्राचल के रूप में स्वतःप्रेरित निवेश को अपनाने से दीर्घकालिक विकास के प्रारम्भ करने वाले आधार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सरकारी निवेश के रूप में निर्दिष्ट किया हुआ रहने पर स्वतःप्रेरित निवेश उन बाह्य मितव्ययिताओं के सर्जन का कारण होता है, जो निजी उपक्रम को प्रोत्साहित करने तथा सामान्य उत्पादकता को बढ़ाने में बहुत अधिक सहायक होती हैं। निजी प्रकृति के स्वतःप्रेरित निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक प्रकृति के निजी निवेशों को बहुत अधिक स्थायी होने का अतिरिक्त लाभ होता है।

डोमर द्वारा जोर दी गई निवेश की दुहरी प्रकृति ऐसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में, जो राज्य को केन्सीयन तरीके से वचत एवं निवेश को नियंत्रित करने का कार्य सौंप देती है, एक नया अर्थ-ग्रहण कर लेती है। क्योंकि, केवल अवधि वचत एवं निवेश की मान्यता पर ही निवेश के क्षमता-सूचक सर्जनात्मक पहलू को अधिकाधिक उत्पादकता एवं मूल्य-स्थायित्व के लिए एक शक्ति के रूप में अभिनन्दन करने की वजाय, निवेश की लाभदायकता को और अधिक कम करने के लिए निन्दा की जा सकती है। एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था, जो केन्स के कुछ अंशों में निवेश के समाजीकरण और राज्य के माध्यम से समुदायिक वचत के प्रस्ताव को गम्भीरता पूर्वक मानती है,¹ समर्थ माँग के उत्पादन-क्षमता से अधिक अथवा कम होने के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न स्फीति अथवा अवस्फीति की आशंका के स्थायी भय से मुक्त हो जायगी। हम ने आर्थिक विकास में राज्य के मौद्रिक एवं राजकोपीय महत्त्व की विवेचना में केन्स के उन सुझावों का प्रयोग किया है।

निवेश की माँग एवं वृद्धिशील बाजार के महत्त्व पर आर० नस्कॉ द्वारा दिया गया जोर केवल अवध नीति के अन्तर्गत ही कुछ अर्थ रखता है। आर्थिक विकास में सरकार के कार्य के निरोध से ही नस्कॉ के एक ओर घरेलू निवेश के सम्बन्ध में अत्यधिक निराशा-वादी तथा दूसरी ओर 'वचत सम्भाव्य' के सम्बन्ध में अत्यधिक आशा-वादी विचार को प्रोत्साहन मिला है। क्योंकि 'प्रदर्शन-प्रभाव,' जिसे नस्कॉ अल्प-विकसित विवृत अर्थ-व्यवस्था के घरेलू निवेश के लिए सम्भावित रुकावट मानता है, वास्तव में, यदि इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में प्रभाव-पूर्ण आयात-नियन्त्रण हो, तो शास्त्रीय है। इसी तरह सम्बद्ध अर्थ-व्यवस्था में 'वचत सम्भाव्य' के रूप में छिपे हुए देशीजगारों की लाभवन्दी भी, प्रभावपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रम अथवा लोकश्रम-नियोजनालयों के अभाव में पूर्णतः शास्त्रीय है। इस प्रकार, उपभोग में कमी के द्वारा वचत एवं निवेश में वृद्धि की सत्यापक सीमा (पूर्ण रोजगार की मान्यता पर) एवं उपभोग तथा निवेश दोनों में साथ-साथ वृद्धि (पूर्ण रोजगार से कम की मान्यता पर) केन्द्रीय सीमा के बीच मध्यम मार्ग के अवलम्बन करने का नस्कॉ का प्रयास, केवल अवध नीति के परित्याग, यानी राज्य द्वारा बाह्य रूप से 'प्रदर्शन-प्रभाव' के नियन्त्रण तथा आंतरिक रूप में सार्वजनिक कार्यक्रम अथवा श्रम के विनिधान की सार्वजनिक प्रणाली में सुधार के अधिक सक्रिय कार्यक्रम अपनाने से ही सम्भव हो सकता है।

किन्तु, एच० एच० हैनसेन, जोन रॉबिन्सन, तथा डब्ल्यू० ए० लीविस¹ के विकास-सम्बन्धी विवेचन इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण अपवाद हैं। आर्थिक विकास में अन्य लेखकों की अपेक्षा लीविस सरकार के महत्त्व पर अधिक जोर देता है, यद्यपि वह सरकार के कार्य को उत्पादन के साधनों के नियन्त्रण की केन्द्रीय नीति, न कि इन साधनों को अपने स्वामित्व में लाने की मावर्सीयन नीति के द्वारा अमल में लाना चाहता है। अन्यत्र लीविस इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कोई अपूर्ण रोजगारी वाले श्रम की अधिकता वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था, स्फीति-जनक दबाव में वृद्धि के बगैर अपेक्षाकृत श्रम प्रयोग करने वाले एवं शीघ्र फल देने वाले विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए वित्त-प्रवन्ध के उद्देश्य से साख का विस्तार कर सकती

1. देखें इनका 'प्रोब्लेम्स ऑफ कैपिटल फारमेशन, एटसेट्रा'।
2. देखें हैनसेन, 'दि अमेरिकन इकॉनामी, मॅकग्रीज़-हिल, न्यूयार्क, 1957'; रॉबिन्सन, 'दि एकुमुलेशन ऑफ कैपिटल,' इरविन होमबुड, 1956; लीविस, 'विथियरी ऑफ इकॉनामिक ग्रोथ,' एलेन एड अनवीन, सन्दन, 1955; हैनसेन की पुस्तक एवं लीविस की पुस्तक के सम्बन्ध में क्रमशः करेंट इकॉनामिक कमेंट (1957 नवम्बर,) तथा इकोनोमेट्रिक (जनवरी, 1957); में हमारी समीक्षाओं की तुलना करें।

है।¹ पूंजी-वृद्धि के सम्बन्ध में जोन रॉबिन्सन की विवेचना का अति सूक्ष्म प्रभाव यह पड़ता है कि इससे आर्थिक विकास जैसी महत्त्वपूर्ण समस्या को 'खेल के पूंजीवादी नियमों',² पर छोड़ देने का सम्पूर्ण विचार अविश्वसनीय सिद्ध हो जाता है। क्योंकि, अवंध नीति-सम्बन्धी इनका विकास-मॉडल, हैरोड एवं डोमर के मॉडलों से भी अधिक निश्चयता पूर्वक, इस बात को दिखलाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं तथा उन्नतिशील तकनीक की संभावनाओं के अनुरूप किसी अर्थ-व्यवस्था के स्थायी विकास जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य को निजी मुनाफ़ा प्राप्त करने वालों को सौंपना कितना संदिग्ध, अयोग्य एवं अनिश्चित है। अतएव यह बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है कि जोन रॉबिन्सन ने अन्यत्र यह सुभाव दिया है कि अपने उद्योगीकरण-सम्बन्धी कार्य-क्रम के निर्धारण में अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को समाजवादी राज्य का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा।³ इनके इस वयान पर विचार कर कि "प्रजातन्त्र के पारम्परिक तरीकों को नियन्त्रण की आवश्यक मात्रा के साथ मिलाना वर्तमान समय

1. डब्ल्यू० ए० लीविस, 'इकॉनामिक डिवेलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर', दि माच्चेस्टर स्कूल ऑफ इकॉनामिक एंड सोशल स्टडीज, मई 1954।
2. देखें इनकी पुस्तक 'दि एकुशुलेशन ऑफ कैपिटल।'
3. हितोत्सुबासी यूनिवर्सिटी (जापान) के समक्ष इनका व्याख्यान, जैसा कि 30 मई, 1955 के हितोत्सुबासी सीनवन द्वारा सूचित किया गया था; इस सम्बन्ध में एवं भारतीय अर्थ-शास्त्री के वयान के रूप में अत्यधिक रोचक जान पड़ता है। व्याख्यान का एक अंश इस प्रकार है—“जापान के आर्थिक विकास के इतिहास से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है। हम लोग पाते हैं कि 1868 से 1879 के बीच जापान की सरकार ने उद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था में मार्ग-दर्शन का कार्य किया था। इन्होंने पोत-प्रांगणों, लोह-ढलाई घरों, पश्चिमी यन्त्रों से सुसज्जित आदर्श कारखानों, रेलवे-लाइनों तथा टेलीग्राफ्स आदि का निर्माण किया तथा नई तकनीकी के सम्बन्ध में शिक्षा-प्रदान करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया। जापान की सरकार द्वारा प्रदान किया गया यह प्रोत्साहन जापान के आर्थिक विकास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था तथा इसने उद्योगीकरण के लिए आवश्यक समय में कई दशाब्दियों की कमी कर दी। आज भारत भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिनसे जापान उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में अपने द्रुतगति से विकास की प्रेरणा में से गुजर रहा था। अतएव, सरकार को मार्ग-प्रदर्शन का कार्य करना है तथा देश में आर्थिक विकास के लिए संवेग का सर्जन करना है। (डी० भा० 'फिस्कल पालिसी एंड दि इकॉनामिक डिवेलपमेंट ऑफ अंडरडिवेलप्ड कंट्रीज', इंडियन जनरल ऑफ इकॉनामिक्स, जुलाई, 1956.)

की प्रधान राजनीतिक समस्या है" 12 कोई केवल यह सन्देह व्यक्त कर सकता है कि अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्था के उद्योगीकरण के लिए तैयार की गई समाजवादी राज्य की जोन रोबिन्सन की धारणा अनिवार्यतः उत्पादक सुविधाओं के केन्द्रीय नियन्त्रण पर आधृत तथा विकसित अर्थ-व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अनुशसित केन्म के 'राज्य समाजवाद की व्यवस्था' की ही तरह है ।

यद्यपि हैनसेन स्पष्ट रूप से विकसित अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में व्याख्या करता है, तथापि वह बहुत सी ऐसी बातें बतलाता है, जो अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए बहुत ही शिक्षा-प्रद है ।¹³ 'प्रजातन्त्राय कल्याणकारी राज्य' के साथ-साथ 'मिश्रित सार्वजनिक-सह-निजी-अर्थ-व्यवस्था', को जिसका हैनसेन अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था के स्थायी विकास के लिए समर्थन करता है, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के अधिकतम विकास के लिए और प्रबल रूप में प्रभावित किया जा सकता है । क्योंकि, जैसा कि हैनसेन मानते हैं, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का प्रधान अस्त्र राज-कोषीय एवं मौद्रिक नीति है, जिसे पूँजी-सचय एवं तकनीकी प्रगति को तीव्र बनाने तथा समर्थ माँग को स्थायी बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है । इसी प्रकार प्रजातन्त्रात्मक कल्याणकारी राज्य को केवल 'तैयार स्थायित्व प्रदान करने वाले साधनों' (जैसे सामाजिक बीमा-सम्बन्धी भुगतान, कृषि को समर्थन देने के कार्यक्रम, सार्वजनिक इमारतों, सामुहिक शिक्षा, एवं अन्य, जिनका समर्थन उसने विकसित अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में किया है) की व्यवस्था करने वाले के रूप में ही नहीं, बल्कि सामान्य उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अनिवार्य 'सामाजिक पूँजी' (जैसे विद्यालयों, अस्पताल, सार्वजनिक मनोरंजन केन्द्रों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक कल्याण-

1. देखें इनका क्लेक्टेड इकॉनामिक पेपर्स, पृ० 113. ।
2. देखें जेनरल थियरी, पृ० 378. वहाँ केन्स; जैसा कि कभी-कभी कहा जाता है, केन्द्रीय समाजवाद एवं पारम्परिक समाजवाद में सावधानी पूर्वक निम्नांकित तरीके से विभेद करते हैं : "राज्य के लिए उत्पादन के साधनों के स्वामित्व को प्राप्त करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है । यदि राज्य उपकरणों को बढ़ाने में लगाये जाने वाले साधनों की कुल मात्रा तथा इनके स्वामित्व के लिए आधारभूत पारिश्रमिक की दरें निर्धारित करने में सफल हो जाता है, तो यह सभी अपेक्षित चीजों को प्राप्त कर लेता है । साथ ही, समाजीकरण के लिए आवश्यक उपायों को क्रमशः तथा समाज की सामान्य परम्पराओं को भंग किये बिना अपनाया जा सकता है ।"
3. हैनसेन की मिश्रित 'अर्थ-व्यवस्था एवं कल्याणकारी राज्य' की योजना की विस्तृत विवेचना के लिए देखें मेरा निबन्ध 'प्रोफेसर हैनसेन ऑन अमेरिका इकॉनामिक-रिवोल्यूशन,' इकॉनामिक जनरल, सितम्बर, 1958. ।

विभाग एवं राज्य द्वारा नियन्त्रित जीवन की अन्य सुविधाओं) प्रदान करने वाले के रूप में समझा जा सकता है। अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में, हैनसेन की 'मिश्रित अर्थ-व्यवस्था एवं कल्याणकारी राज्य' की धारणा के अन्तर्गत सम्भवतः प्रत्यक्ष नियन्त्रण (जैसे विनिधान की प्राथमिकता की नीति, मूल्य-नियन्त्रण एवं आयात-नियन्त्रण) तथा परोक्ष राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों का भी समावेश करना पड़ेगा। साथ ही, अल्प-विकसित देशों के द्रुतगति से उद्योगीकरण के लिए सम्भवतः हैनसेन की मिश्रित अर्थ-व्यवस्था एवं कल्याणकारी राज्य की योजना तथा केन्स के 'राज्य-समाजवाद' की कुछ अधिक विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे इनके अन्तर्गत कुछ ऐसे उद्योगों एवं उद्यमों, जिनका जन-कल्याण एवं निजी उपक्रम के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है (उदाहरण के लिए, जनोपयोगी सेवाएँ तथा बैंकिंग की सुविधाएँ) का सरकारी स्वामित्व एवं संचालन के अन्तर्गत समावेश किया जा सके।

हैनसेन एवं हमारे बीच प्रधान अन्तर यह है कि वह अधिक परम्परा-निष्ठ केन्सीय तरीके से राज्य को मुख्यतः त्रुटि-पूरक संस्था मानता है, जबकि हम उत्पादन-क्षमता को अधिकाधिक बनाने के अतिरिक्त कार्य को राज्य के जिम्मे सुपुर्द करते हैं। क्योंकि, अल्प-विकसित देशों में राज्य का निर्णायक कार्य समर्थ माँग के स्थायित्व को प्रोत्साहित करना नहीं है। वरन्, ऐसे देशों में राज्य का प्रधान आर्थिक कार्य समर्थ माँग में वृद्धि के दिये हुए स्तर अथवा दी हुई दर की तुलना में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इसकी उत्पादन-क्षमता को विकसित करना है। इस उपर्युक्त कार्य को पूरा करने के लिए केन्द्रीय नियन्त्रण एवं केन्द्रीय स्वामित्व को कार्य के अनुसार उचित अनुपात में तथा सम्बद्ध अल्प-विकसित देश के सामाजिक दर्शन के अनुरूप मिश्रित करना अनिवार्य है। अनन्य नियन्त्रण के सिद्धान्त एवं अनन्य स्वामित्व के सिद्धान्त के बीच अव्यावहारिक बिलगाव कम-से-कम ऐसे समाज के लिए जिसमें केन्द्रीय अधिकारी की बुराइयों के विरुद्ध प्रजातन्त्रात्मक वचाव उपलब्ध है, बिल्कुल अर्थहीन है। किन्तु यह एक ऐसा कार्य है, जिसमें तकनीकी अर्थ-शास्त्रियों को राजनीति-शास्त्र के विद्वानों, दार्शनिकों, समाज-शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों का सह-योग मिलना चाहिए, यदि हमें मानव-मूल्यों के रूप में अर्थपूर्ण एवं लाभदायक तकनीकी सलाह देते हैं।

संतुलित विकास की प्रकृति एवं यंत्र

आर्थिक विकास के लेखकों में संतुलित विकास शब्द के जिक्र करने का रिवाज-सा हो गया है। किन्तु, अधिकांश लेखक इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि किस वस्तु को संतुलित किया जाता है तथा इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जहाँ तक अवधि-नीति संबंधी अर्थ-व्यवस्था का संबंध है, संतुलित विकास, यदि पद के

रूप में नहीं, तो सार रूप में, परस्पर-विरोधी है। इसी प्रकार वे लोग उस निश्चित विधि को भी स्पष्ट नहीं करते, जिसके द्वारा 'संतुलित विकास' (कुछ परिभाषाओं के आधार पर) को प्राप्त किया जा सकता तथा बनाये रखा जा सकता है। अतएव, 'संतुलित विकास' की विभिन्न धारणाओं तथा इनमें सन्निहित विकास-संबंधी विधियों की आलोचनात्मक समीक्षा लाभदायक जान पड़ती है।

आधुनिक विकास-संबंधी अर्थशास्त्र दोर्धकालीन विकास की 'विशुद्ध प्रकृति' एवं अल्पकालीन साम्यावस्था की अस्थायी प्रकृति, यानी पूँजीवाद के चक्रीय विकास में केन्स एवं शुम्पीटर की अंतःप्रज्ञा व अंतर्दृष्टि को परिष्कारण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बनाने की व्याख्या के प्रयास से प्रारंभ होता है। मुख्य रूप से अवध-नीति की स्थिति में एक विकसित अर्थ-व्यवस्था के अस्थायी विकास के लिए निवेश की दोहरी प्रकृति पर ध्यान देने के संबंध में हैरोड एवं डोमर ने नया मार्ग तैयार किया। केन्स के समर्थ माँग के अल्प-कालीन सिद्धांत की तरह, बचत एवं निवेश की समानता को साम्यावस्था की पर्याप्त शर्त तभी समझा जा सकता है, जब कि पूँजी के कोप को स्थायी मान लिया जाता है। किन्तु, यदि पूँजी के कोप में वृद्धि होने दी जाय, जैसा कि दोर्धकाल में अवश्य ही होगा, तो क्षमता में परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप निवेश के धनात्मक अथवा ऋणात्मक होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे निवेश एवं बचत की अस्थायी समानता भंग हो जाती है। इस प्रकार वृद्धिशील पूँजी के कोप वाली विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में बचत एवं निवेश को किस प्रकार संतुलित किया जाय, यही प्रधान समस्या है, जिसके समाधान का हैरोड तथा डोमर ने औपचारिक रूप से प्रयास किया था।

हैरोड तथा डोमर में उभयनिष्ठ संतुलित विकास का सार यह है कि यदि किसी अर्थ-व्यवस्था को ब्रेकर क्षमता अथवा अतिरिक्त श्रम के बगैर निपज में निरंतर वृद्धि को बनाये रखना है, तो समर्थ माँग एवं उत्पादन-क्षमता को किसी भी प्रकार संतुलित बनाये रखना अनिवार्य है। हैरोड के विकास-संबंधी सिद्धांत में, स्थायी विकास की एक आधारभूत शर्त यह है कि यदि बचत-अनुपात (s) एवं पूँजी-निपज-अनुपात (b) दिये हुए हैं, तो शुद्ध राष्ट्रीय वास्तविक आय (Y) में उत्पादन-क्षमता के बराबर ही वृद्धि होनी चाहिए।

$$\Delta Y = \frac{s}{b} Y,$$

जिसका दायीं पक्ष उत्पादन-क्षमता तथा बायाँ पक्ष समर्थ माँग में वृद्धि है। इसी समीकरण से आय में वृद्धि की निम्नांकित अपेक्षित दर (हैरोड की शब्दावली में—प्रमाणित दर) प्राप्त होती है :

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{b},$$

जो यह बतलाता है कि यदि अधिक अथवा कम क्षमता के वंश उत्पादन-क्षमता की पूर्ण रूप से प्रयोग करना है तो आय में निश्चित रूप से s/b की स्थायी दर से वृद्धि होनी चाहिए। क्योंकि, उपर्युक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि यदि $\Delta Y/Y < s/b$, जो कि नियमित रूप से समग्र विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में प्रचलित प्रवृत्ति मालूम पड़ती है, तो समर्थ माँग के उत्पादन-क्षमता से अधिक धीरे-धीरे बढ़ने के कारण, यानी $\Delta Y < s/bY$ के परिणामस्वरूप दीर्घकालीन अस्थायित्व की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है।

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में प्रयोग करने पर माँग से धीरे-धीरे क्षमता में वृद्धि $\Delta Y/Y > s/b$ की विपरीत प्रवृत्ति में स्फीतिजनक भुकाव ही अंतर्निहित है, जो दीर्घकाल में सम्मिलित होने वाले अल्पकालों में $\Delta Y > (s/b)Y$ को सूचित करता है। यदि स्फीतिजनक प्रवृत्ति को छोटे-से-छोटा बनाना है, तो एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को समर्थ माँग के विस्तार (ΔY) को मंद बनाना या उत्पादन क्षमता में वृद्धि ($(s/b)Y$) को तीव्र बनाना या दोनों कार्यों को करने के लिए उचित उपायों को अपनाना होगा। फिर भी, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के स्फीति-जनक दबाव को कम करने की अपेक्षा वास्तविक पूँजी के संचय एवं दीर्घकालिक अपूर्ण रोजगारी को दूर करने के लिए उपर्युक्त समीकरण की पूर्ति अथवा क्षमता-पक्ष पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। दूसरे शब्दों में, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को केवल समर्थ माँग में वृद्धि की दर तथा स्थायी विकास के लिए उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की दर को ही समान नहीं बनाना चाहिए, वरन् उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की दर एवं जनसंख्या में वृद्धि की दर को भी बढ़ती हुई उत्पादकता के साथ बराबर करना चाहिए, यानी—

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{b} = n + h,$$

जिसमें n श्रम-संख्या में वृद्धि की दर, h श्रम की उत्पादकता में वृद्धि की दर है, और अतएव $n + h$ 'विकास की अधिकतम सामाजिक दर' है, जिसकी व्याख्या इस पुस्तक में पहले की जा चुकी है। वहाँ पर यह दिखलाया गया है कि हैरोड की 'प्राकृतिक' दर श्रम की परिवर्तनशील उत्पादकता (अथवा परिवर्तनशील श्रम-निपज अनुपात) से युक्त सामान्य स्थिति की एक विशेष स्थिति है; क्योंकि इनकी 'प्राकृतिक' दर के अनुरूप इनकी 'प्रमाणित' दर पूर्ण रोजगार की व्यवस्था तभी कर सकती है, जबकि श्रम-निपज-अनुपात में इसी प्रकार कमी नहीं होती (अथवा श्रम की उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती), जिससे कि निपज की प्रति इकाई को कम श्रम की आवश्यकता पड़े। दूसरे शब्दों में, जैसा कि स्थायी श्रम-निपज अनुपात की मान्यता पर होता

है, यदि उत्पादन-क्षमता में उसी दर से वृद्धि-विषयक श्रम-संख्या में वृद्धि होती है, तो एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था दोनों पूँजी के अभाव से दीर्घकालिक अपूर्ण रोजगारी तथा वृद्धिशील उत्पादकता के कारण स्थायी जीवन-मान का अनुभव करेगी। अतएव, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए हम लोगों की सतुलित विकास की धारणा में समर्थ माँग, उत्पादन क्षमता एवं श्रम, जिसकी उत्पादकता समय के क्रम से बढ़ रही हो, के विकास की दरें (हैरोड की प्राकृतिक दर की विवेचना की तरह स्थायी रहने के बजाय) सन्निहित हैं।

जहाँ तक डोमर के 'सतुलित विकास' की धारणा का संबंध है, एक वृद्धिशील अर्थ-व्यवस्था के माँग-पक्ष की ओर हैरोड की अपेक्षा यह अधिक स्पष्ट है; क्योंकि डोमर ने माँग-पक्ष के गुणक पहलू की विवेचना की है, जबकि हैरोड ने ऐसा नहीं किया है। पूर्ति पक्ष की ओर, डोमर एव हैरोड के पूँजी-निपज अनुपात के व्युत्क्रम के प्रयोग यानी निवेश की उत्पादकता के प्रयोग को लेकर हैं; इस प्रकार, निःसंदेह समर्थ माँग के स्तर के रूप में $Y = I/\alpha$ तथा उत्पादन-क्षमता के स्तर के रूप में $Y' = \sigma K$ और इसलिए $Y = Y'$ अथवा $I/\alpha = \sigma K$ को स्थायी साम्यावस्था की शर्त के रूप में प्रारम्भ करते हुए (जिसमें Y समर्थ माँग, Y' उत्पादन-क्षमता है। शुद्ध निवेश, K पूँजी का कोष, α बचाने की सीमात (=स्वीकृत औसत) क्षमता एवं σ निवेश की सीमात (=स्वीकृत औसत) क्षमता हैं), डोमर स्पष्ट रूप से गत्यात्मक साम्यावस्था शर्त की ओर आगे बढ़ता है।

$$\frac{\Delta 1}{1} = \alpha \sigma$$

जो माँग-पक्ष की ओर से $\Delta Y = \Delta 1/\alpha$ तथा पूर्ति-पक्ष की ओर से $\Delta Y' = \sigma \Delta K = \sigma 1$ और अतएव $\Delta Y = \Delta Y'$ या $\Delta 1/\alpha = \sigma 1$ का अनुकरण करता है।

डोमर का विकास-सम्बन्धी समीकरण $\Delta 1/1 = \alpha \sigma$ हैरोड के विकास की 'प्रमाणित' दर की ही तरह है; क्योंकि डोमर के $Y = I/\alpha$ से हमें निम्नांकित प्राप्त होता है :

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta 1/\alpha}{Y} = \frac{\Delta 1/\alpha}{1/\alpha} = \frac{\Delta 1}{1} = \alpha \sigma = \frac{s}{b} \cdot (\alpha = s, \sigma = 1/b)$$

इस प्रकार, डोमर के सतुलित विकास की धारणा समर्थ माँग एवं उत्पादन क्षमता को सतुलित रखने की है, जिससे कि कोई अर्थ-व्यवस्था अतिरिक्त अथवा न्यून क्षमता के उत्पन्न हुए बगैर, सतत रूप में विकास कर सके। हैरोड की तुलना में डोमर द्वारा सूत्र के रूप में इसे वर्णित करने का लाभ यह जान पड़ता है कि सार्व-जनिक निवेश के रूप में इसकी व्यवस्था को सम्भव बनाने के लिए डोमर ने माँग-पक्ष की ओर स्पष्ट रूप से स्वतःप्रेरित गुण्य ($\Delta 1$) को शामिल किया है। इसके विप-

रीत इसका दोष हैरोड की तरह की 'प्राकृतिक' दर की व्याख्या का अभाव जान पड़ता है, जो पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण क्षमता की व्याख्या कर सके। साथ ही, डोमर के 'संतुलित विकास' के विरुद्ध भी वे ही आलोचनाएँ दी जा सकती हैं, जो हैरोड के स्थायी तकनीकी गुणांकों (उदाहरण के लिए, स्थायी पूँजी-निपज अनुपात, स्थायी पूँजी-श्रम अनुपात तथा स्थायी श्रम-निपज) की मान्यता के विरुद्ध दी जाती है। अंशतः, इसी प्रकार की आलोचनाओं को सन्तुष्ट करने के लिए हमने गत्यात्मक तकनीकी प्राचलों की व्याख्या से सम्बद्ध एक अध्याय (इस पुस्तक का पाँचवाँ अध्याय) को सम्मिलित किया है। फिर भी, तकनीकी प्राचलों को इच्छित दिशा में परिवर्तनीय बनाने में बाज़ार की शक्तियों तथा साधनों के सापेक्ष मूल्य को परिवर्तनों की विश्वस्तता के प्रति हम ने पर्याप्त मात्रा में संशय व्यक्त किया है। इसके विपरीत इस बात पर हमने कुछ आशा व्यक्त की है कि सार्वजनिक नीति विचारपूर्वक उन तथ्यों को प्रभावित कर सकती है, जो बाज़ार की शक्तों से स्वतन्त्र रूप में तथा अन्य प्रचलित विकास-सम्बन्धी परिवर्तियों के सन्दर्भ में तकनीकी गुणांकों को प्रभावित करते हैं।

हैरोड तथा डोमर ने विकास के संयंत्रों की अनिवार्य प्रकृति को परिचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाया है; क्योंकि लोग विकास की अपेक्षित दर की जाँच तथा सम्भवतः हेर-फेर के लिए वचत-अनुपात एवं पूँजी-निपज-अनुपात (या इसके व्युत्क्रम) पर मापनीय महत्वपूर्ण परिवर्तियों के रूप में जोर दिया है। इन महत्वपूर्ण परिवर्तियों की व्यापक प्रकृति के चलते हैरोड तथा डोमर द्वारा वर्णित विकास संयंत्र सभी अर्थ-व्यवस्थाओं में, यद्यपि कुछ सुधार के साथ, लागू होता है। इसके विपरीत, जोन राँविन्सन का विकास-सम्बन्धी संयंत्र है। जिसमें विशेष रूप से पूँजीवादी प्रकृति के मूल्य एवं वितरण-सम्बन्धी प्राचल सन्निहित हैं। यद्यपि जोन राँविन्सन का विकास-सम्बन्धी संयंत्र पूँजीवादी व्यवस्था के ऐतिहासिक विकार को अधिक यथार्थवादी तरीके से व्यक्त करता है, तथापि इसमें कम अनुकूलता है, अतएव इसमें व्यापक आकर्षण का अभाव है। हम ने यह अनुमान लगाया है कि जोन राँविन्सन का उद्देश्य यह दिखलाना हो सकता है कि आज की किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को उत्पादन के अन्य साधनों की तुलना में श्रम के लिए अधिक प्रतिकूल विकास की पद्धति को अपनाना कितना व्यर्थ एवं असह्य होगा। जोन राँविन्सन के पूँजी-संचय-सिद्धान्त का आशय यह जान पड़ता है कि आर्थिक विकास की ऐसी पद्धति के लिए, जो पूर्ण रोजगारी एवं भजदूरी कमानेवाले वर्गों के उपभोग की ऊँची आकांक्षाओं के लिए कम-से-कम हानिकारक सिद्ध हो सकती है, 'खेल के पूँजीवादी नियमों' को सार्वजनिक नीति से प्रतिस्थापित करना चाहिए। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि जोन राँविन्सन 'श्रमवाद'-सम्बन्धी केन्सीय रूपान्तर से सहमत हैं।

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से अधिक प्रत्यक्ष रूप में सम्बद्ध आर० नस्कॉ

का पूँजी-निर्माण का सिद्धान्त एव 'संतुलित विकास है'।¹ नस्कों की संतुलित विकास धारणा इस प्रकार जान पड़ती है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को मुख्यतः, स्वतन्त्र समाज के ढाँचे के अन्तर्गत आंतरिक नीतियों एवं विदेशी व्यापार-सम्बन्धी नीतियों के सम्मिश्रण के द्वारा निवेश की माँग एवं पूँजी की पूर्ति के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए। पूँजी-सचय के माँग-पक्ष पर इनका जोर संस्थापकों की इस धारणा कि 'पूर्ति स्वयं अपनी माँग का सर्जन करती है' के विरुद्ध केन्स की प्रतिक्रिया को प्रतिबिम्बित करता है। अल्प-विकसित अर्थ व्यवस्था के आर्थिक विकास के स्पष्ट उद्देश्य में निवेश की माँग के विस्तार के लिए इनकी पिता अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के बाजार अथवा कच्चे माल के साधन के रूप में समझने की परम्परावादी प्रवृत्ति से एक प्रकार का मुखद अपसरण है। किन्तु निवेश की माँग के लिए इनकी उस चिन्ता के परिणाम-स्वरूप बचत की पूर्ति के लिए इनकी दूसरी चिन्ता, जो किसी भी दीर्घकालीन विश्लेषण-संस्थापक अथवा केन्सीयन के लिए अधिक सारभूत है, शक्तिहीन हो जाती है। साथ ही, नस्कों की निवेश-माँग विप-यक धारणा की एक प्रधान कमी 'प्रेरित' एवं 'स्वतन्त्र' निवेश के बीच विभेद का अभाव है, जिससे वह विकासात्मक कार्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से निवेश-सम्बन्धी कार्यक्रमों के सगठन में सरकार के स्पष्ट महत्व को छोड़ देता है। वह विवादास्पद ही रह जाता है कि क्या एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था निवेश-सम्बन्धी निर्णयों को मुख्यतः निजी उपक्रमियों के हाथ में छोड़कर उत्पादक कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में निजी निवेश को प्रेरित करने की बाजार-सम्बन्धी प्रारम्भिक कठिनाइयों को दूर कर सकती है, अथवा नहीं। जहाँ तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, 'संतुलित विकास' (आय का), जैसा कि नस्कों मानता है, की इच्छा निजी निवेश को प्रेरित करने के लिए नहीं, वरन् स्वयं इसी के लिए की जाती है। क्योंकि, स्वतन्त्र निवेश की उपेक्षा कर प्रेरित निवेश पर हैरोड द्वारा अत्यधिक जोर देने के विरुद्ध आलोचना में बतलाया जा चुका है कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के सकुचित बाजारों एवं निम्न वास्तविक आय के चलते निवेश की प्रेरणा के मार्ग में अवरोध के विरुद्ध नस्कों की शिकायत बिल्कुल अनावश्यक हो जायगी, यदि क्षमता-वर्द्धक एवं आय-उत्पादक प्रकृति के स्वतन्त्र सार्वजनिक निवेश को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जायगा।

पूँजी-सचय के पूर्ति-पक्ष की ओर नस्कों, छिपी हुई बेरोजगारी से मिले हुए 'प्रदर्शन-प्रभाव' को 'बचत सम्भाव्य' मानता है। हम इन विषयों की व्याख्या पहिले ही कर चुके हैं, अतएव यहाँ पुनः इस पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी, यहाँ कुछ अतिरिक्त विचार व्यक्त किया जा सकता है। प्रथमतः, जनसंख्या की वृद्धि तथा पूँजी के विकास के फलनीय सम्बन्ध के विश्लेषण, जैसा कि हम ने विकास की सामाजिक श्रेष्ठ दर तथा दीर्घकालिक अपूर्ण रोजगारी की विवेचना में तथा हैरोड

¹ देखें इनकी पुस्तक 'प्रोत्सेस ऑफ़ कैपिटल फॉरमेशन इन अंडर डिवेलपड कंट्रीज'।

एवं जोन रॉबिन्सन ने अपने 'प्रगतिशील साम्यावस्था' तथा 'स्वर्णयुगीय साम्यावस्था' की विवेचना में किया था, के वगैर नस्कों द्वारा जनसंख्या की व्याख्या छिपी हुई बेरोज़गारी को 'वचत सम्भाव्य' मान लेने तक सीमित है। द्वितीयतः, नस्कों के 'संतुलित विकास' की विवेचना में तकनीकी प्रगति के महत्त्व की बिल्कुल उपेक्षा की गई है। इसी तकनीकी महत्त्व की उपेक्षा के कारण नस्कों ने पूँजी-संचय की आवश्यकता पर अत्यधिक जोर दिया था, जबकि तकनीक में शुम्पीटर की तरह थोड़ी और दिल-चस्पी से उसे यह पता लग सकता था कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था किसी दी हुई वचत अनुपात की तुलना में पूँजी-निपज अनुपात को घटाकर विकास की दर में वृद्धि कर सकती है। तृतीयतः, नस्कों राजकोपीय नीति के कार्यक्षेत्र को अतिरिक्त 'वचानेवाले', 'विनियोग करनेवाले', 'नवीन क्रिया के संचालनवाले' तथा 'पुनर्वितरक' के रूप में, विभिन्न प्रकार के कार्यों को सौंपने के वजाय, इसे केवल वर्तमान वचतों को गतिमान करने तक ही सीमित रखता है। हम ने उन अल्प-विकसित देशों के लिए, जिनमें निजी उपक्रम, निजी स्वेच्छिक वचत तथा निजी नवीन क्रिया का प्रभाव पाया जाता है, राजकोपीय नीति के इन वादवाले कार्यों के महत्त्व की व्याख्या की है। अंततः, यद्यपि नस्कों पूँजी के आयात को विकासात्मक पूँजी का एक अतिरिक्त साधन मानता है, तथापि 'प्रदर्शन-प्रभाव' के सम्बन्ध में उसका संशययुक्त विवरण तथा 'वचत सम्भाव्य' के रूप में उसकी छिपी हुई बेरोज़गारी के आशापूर्ण विवेचन का सम्भवतः ऐसा अनभिप्रेरित प्रभाव पड़ता हुआ दीखता है कि पूँजी के विदेशी साधनों पर निर्भरता महत्त्वहीन हो जाती हैं। हम ने केन्स के 'अन्तर्राष्ट्रीय समस्थितिकरण' की भावना के अनुरूप सम्भवतः राष्ट्र के अभिकरणों के द्वारा विदेशी उधारकरण के अति विस्तृत क्षेत्र का निर्देशन किया है। किन्तु इन सीमाओं के चावजूद, नस्कों के आर्थिक विकास का सिद्धान्त इस अर्थ में महत्त्वपूर्ण है कि इसने वास्तविक पूँजी को, जो विकास का एक-मात्र वृद्धि करने योग्य साधन है, अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया है।

यदि समग्र मानव-समुदाय के कल्याण के लिए अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है, तो हैरोड, डोमर, हैनसेन, जोन रॉबिन्सन, नस्कों, लीविस एवं अन्य केन्सीय-उत्तर लेखकों के विकास-सम्बन्धी विश्लेषण में प्रकाशित सम्भावनाओं पर और अधिक अनुसंधान, अध्ययन तथा खोज करनी चाहिए। यदि वर्तमान पुस्तक इस प्रकार के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए कुछ अतिरिक्त प्रेरणा प्रदान करती है, तो लेखक का परिश्रम व्यर्थ नहीं कहा जा सकता।

परिशिष्ट

संयुक्त राष्ट्र एवं आर्थिक विकास*

अपने पूर्ण रोजगार के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय उपायों के परिणाम-स्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास के तरीकों पर एक विवरण प्रकाशित किया है, जो ए० बी० कोज (चिली), डी० आर० गैडगिल (भारत), जी० हकीम (लेबनन), डब्ल्यू० ए० लीविस (इंग्लैंड) तथा टी० डब्ल्यू० सरज (यू० एस०)¹ द्वारा तैयार किया गया था। इस विवरण के अध्ययन से शीघ्र ही बहुत बड़ी सद्भावना, कल्पना पूर्ण परिज्ञान एवं विस्तृत सूक्ष्म प्रकट होती है। किन्तु प्रतिवेदन के इन प्रशंसनीय पहलुओं के बावजूद, इस बात की आशंका की जाती है कि तकनीकी पाठक इसमें प्रस्तावित विभिन्न उपायों के सैद्धान्तिक आधार से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं हो सकते। शायद विशेषज्ञ उन लोगों के विरुद्ध, जिन्होंने पूर्ण रोजगार के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तैयार किया था, दी गई इस आलोचना कि वे अपने समक्ष समस्याओं को बहुत कुछ इस प्रकार समझते थे, मानो वे गणितीय समस्याएँ हों, से बहुत अधिक सचेत थे।² वे इतना अधिक सचेत थे कि परिचालन की दृष्टि से

*यह हमारा समीक्षा-सम्बन्धी निबन्ध है, जो प्रारम्भ में 'इंडियन इकॉनामिक जनरल' अप्रैल, 1954 में प्रकाशित हुआ था।

- 1 संयुक्त राष्ट्र, आर्थिक मामलों का विभाग, न्यूयार्क, मई, 1951 :
- 2 देखें संयुक्त राष्ट्र के इकॉनामिक एंड सोशल कौंसिल ऑफिसियल रेकर्ड्स, 10-वाँ सत्र, 358-वी बैठक, 21 फरवरी, 1950, पृ० 98। विश्लेषणात्मक, न कि रीति-विधानसम्बन्धी समालोचना के लिए—देखें मेरा निबन्ध 'दि यूनाइटेड नेशन्स एंड फुल एम्प्लायमेंट' जनरल ऑफ पोलिटिकल इकॉनामी, अगस्त, 1950।

सम्बद्ध महत्वपूर्ण फलनीय सम्बन्धों की उपेक्षा में बहुत हद तक वे आगे जा सकते थे। ऐसा निस्संदेह अंशतः आर्थिक विश्लेषण के प्रयोजन के लिए आर्थिक विकास की समस्या की जटिलता एवं कठिनाई के परिणाम-स्वरूप है। फिर भी, चूँकि प्रतिवेदन का अभिप्राय अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास की व्याख्या करना है, अतः मैं मुख्यतः आर्थिक दृष्टिकोण से इसकी समालोचना करना तथा शायद इसे कार्यान्वित करना उचित समझता हूँ। ऐसा करने में मैं प्रतिवेदन के नीति-सम्बन्धी विचार को छोड़कर इसके विश्लेषणात्मक पहलू पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूँ।

प्रथमतः प्रतिवेदन में निम्न 'प्रति-व्यक्ति वास्तविक आय' (जिसका संयुक्त राज्य एवं कैनाडा-जैसे 'धनवान' देशों को 'निर्धन देशों' से पृथक् करने का कार्य अपना ही महत्व रखता है), के रूप में अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की एक सक्रिय परिभाषा दी गई है। तब अल्प-विकसित स्थिति को (1) आर्थिक संगठन एवं नियोजन, (2) टेक्नोलॉजी, (3) जनसंख्या की वृद्धि, तथा (4) आंतरिक एवं बाह्य पूँजी से सम्बद्ध किया गया है। प्रतिवेदन इन परिवर्तितियों पर, पृथक् रूप में तथा एक-दूसरे के सम्बन्ध में सदा व्यावहारिक नीति-सम्बन्धी सिफारिशों के निर्माण के उद्देश्य से विवेचना करता है।

विशेषज्ञ सम्भवतः अल्प-विकास की स्थिति के हानिकारक सहायक के रूप में जोर देने के कार्य की व्याख्या, बेरोजगारी, विशेषतः उस प्रकार की बेरोजगारी, जो मुख्य रूप से पूँजीगत साधनों तथा अन्य औद्योगिक सुविधाओं के अभाव के कारण उत्पन्न होती है, यानी 'संरचनात्मक बेरोजगारी' से प्रारम्भ करते हैं। अतएव, वे 'उद्योगीकरण' को, इस प्रकार की बेरोजगारी का अत्यधिक तार्किक उपचार बतलाते हैं। इसके विपरीत इसे स्वीकार किया जाता है कि विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में सबसे जटिल प्रकार की बेरोजगारी समर्थ माँग के अभाव की प्रचलित धारणा के कारण उत्पन्न होती है। जैसा कि श्रीमती जोन रॉबिन्सन ने बतलाया है, तथा-कथित 'संरचनात्मक बेरोजगारी' जनसंख्या में पूँजी-संचय से अधिक बढ़ने की स्पष्ट प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न मार्क्स के प्रकार की बेरोजगारी की एक-मात्र दूसरी आकृति है¹ यह प्रवृत्ति पूँजीवाद के प्रारम्भिक विकास की प्रमुख विशेषता थी और जो आज औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राष्ट्रों में पाई जाती है। किन्तु, प्रतिवेदन में ऐसी सीमांत स्थिति की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया गया है, जिसमें कोई देश मार्क्सियन बेरोजगारी के दानव तथा केन्सीयन बेरोजगारी के अथाह सागर के बीच हो। जापान इसका उदाहरण है; क्योंकि इसका द्रुतगति से उद्योगीकरण कृषि पर आश्रित जनसंख्या की तुलना में कृषि के अपूर्णजीकरण, यानी अस्थायित्व एवं समर्थ माँग में कमी के परिणाम-स्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के बढ़ते हुए खतरे पर ही सम्भव हुआ है। अतएव फिर भी, अपूर्व रोजगार के मुख्य उपचार के रूप में आर्थिक विकास पर

1. देखें इनका निबन्ध 'मि. हैरोल्ड डायनैमिक्स', इकॉनामिक जनरल, मार्च, 1949।

उचित रूप से जोर देने के पूर्व केन्स के इस आरक्षण का प्रयोग करना चाहिए कि जब कोई देश द्रुतगति से संपत्तिवान् बन रहा है, तो निवन्ध-नीति की स्थिति में नवीन निवेश की प्रेरणाओं की अपर्याप्तता के प्रलोभन से, इस सुखद स्थिति में, आने वाली प्रगति में, सम्भवतः, कोई अवरोध हो सकता है।¹ निवन्ध-नीति की व्यावहारिक प्रवृत्ति तथा पूँजी के ह्रासमान फलन के रूप में निवेश की संद्धान्तिक लुप्ति—इन दोनों के विरुद्ध इसे चेतावनी के रूप में समझना चाहिए।

‘मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक शर्तों की प्रगति-विपयक पूर्वदशाओं’ की दूसरी विवेचना प्रायः सामान्य जान पड़ती है। निश्चय ही अल्प-विकसित देशों को यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि द्रुतगति से आर्थिक प्रगति तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि जनता में प्रगति की इच्छाओं के साथ-साथ देश के हर-एक स्तर के नेता-गण—राजनीतिज्ञ, शिक्षक, इंजीनियर, व्यावसायिक नेता, मजदूर-संघों के नेता, पुजारी तथा पत्रकार—देश की आर्थिक प्रगति की इच्छा नहीं करेंगे (पृ० 16)। सदियों की निर्धनता, बेरोजगारी, तथा सामाजिक मुविधाओं के सामान्य अभाव ने सभी पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्थाओं को इनके औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रति इतना अधिक संवेदनशील बना दिया है कि निष्कपट तरीके से प्रयोग करने तथा भाव-रहित तरीके से बोलने पर भी ‘पिछड़े हुए’ शब्द से ये लोग अप्रतिष्ठाजनक अर्थ लगाने लगते हैं। वान यह है कि विश्व के अधिकांश अल्प-विकसित क्षेत्रों में दीर्घकाल तक ‘उपनिवेशवाद’ के परिणाम-स्वरूप, उद्योगीकरण, विशेषतः तीव्र राष्ट्रीयवादी एशियाई देशों के साथ एक घरेलू शब्द तथा लुभानेवाला राजनीतिक नारा हो गया है। आकस्मिक प्रेक्षकों को जो-कुछ सहज राष्ट्रीय विभिन्न विचार जैसा दीख पड़ता है, उसके पीछे उनकी सर्व-प्रथम आर्थिक एवं सर्वोपरि लक्ष्य की ओर बढ़ने वाली दृढ़ता, सकल्प एवं इच्छा-शक्ति अवस्थित है। आर्थिक दृष्टि से ‘आगे बढ़ने की यह इच्छा’, राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति करने अथवा बनाये रखने के अप्रतिहत आग्रह से और भी बलवती हो जाती है। इन सभी राष्ट्रीयवादी भावनाओं में अल्प-विकसित देशों की अमेरिका के उद्योगीकरण तथा स्वतन्त्रता, जापान की अद्भुत औद्योगिक प्रगति तथा, अच्छा समझा जाय अथवा दुरा, रूस के साहसी आर्थिक प्रयोगों के ऐतिहासिक उदाहरणों से निरन्तर प्रोत्साहन मिलता रहता है। विशेषज्ञ शायद क्रम को पलट देना चाहते हैं, अब वे यह तर्क देते हैं कि द्रुतगति से आर्थिक प्रगति के पूर्व प्राचीन दर्शनों को खंडित करना पड़ेगा, प्राचीन सामाजिक संस्थाओं को समाप्त करना पड़ेगा, एवं जाति, मत, प्रजाति आदि को तोड़ना पड़ेगा। इस बात की सम्भावना अधिक है कि

1. जेनरन थियरी, पृ० 355. 1

2. उदाहरण के लिए देखें हमारी पुस्तक ‘लेबर इन दि फिलिपाइन इकॉनामी’ स्टेनफोर्ड यनिव० प्रेस०, 1945. 1

यह 'दुःखदायी पुनःसमंजन' द्रुतगति से आर्थिक प्रगति के परिणाम-स्वरूप होगा, न कि इसकी एक महत्त्वपूर्ण 'पूर्व शर्त' के रूप में। इन तथा-कथित अवरोधों पर अधिक जोर देने से केवल इस कृत्रिम धारणा को बल मिलेगा कि अल्प-विकसित देशों को केवल इसलिए पिछड़ा रहना पड़ेगा कि उनके रहन-सहन की प्रणाली पिछड़ी है। यदि, जैसा कि जान पड़ता है, आर्थिक प्रगति में इन सब सामाजिक बाधाओं को समाप्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं द्वारा 'निर्धारकों के निर्धारक' को दिया हुआ मानकर अतिक्रमण करने तथा प्राचलीय दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण निर्धारकों की ओर प्रत्यक्ष-रूप में जाने को न्यायोचित सिद्ध किया जा सकता है। फिर भी, किसी को इस बात पर हठ करने की आवश्यकता नहीं है।

'आर्थिक संगठन' एवं 'विकास-सम्बन्धी नियोजन' की विवेचना से मुझे यह बात खटकती है कि जहाँ एकत्रीकरण की समस्या विचार प्रधान-वस्तु है, वहाँ हम अ-संग्रहण के विलास-भोग में फँसे हुए हैं और जहाँ निपज का आधार ही अत्यधिक आग्रही समस्या है, वहाँ दो हुई निपज की बनावट पर गलत ढंग से जोर दे रहे हैं। हमें ऐसी धारणा हो जाती है कि जहाँ स्थिति का तकाजा है कि 'आर्थिक संगठन एवं नियोजन' आर्थिक समष्टिभाव की नीति के अनुसार हो, वहाँ विशेषज्ञ लोग संस्था-पकों के विनिधान-सिद्धान्त को वस्तुतः यंत्रवत् प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार, उन लोगों ने साधनों के अयोग्य विनिधान के खतरे पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया है, मानो अधिकतम निपज एवं पूर्ण रोजगार की समस्या का पूर्व ही समाधान हो चुका है। यहाँ दो बातें विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं : (1) विकास के सन्दर्भ में विदेशी व्यापार की व्याख्या तथा (2) अनुकरणीय विकासात्मक नियोजन के माडल के रूप में जापान का चुनाव।

जहाँ तक पहले का सम्बन्ध है, प्रतिवेदन इस बात को स्वीकार करता है कि 'अपूर्ण रोजगारी वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त का सीमित प्रयोग होता है। इस प्रकार वे देसी शिशु-उद्योगों के संरक्षण के उपायों को न्यायोचित बतलाते हैं। साथ ही, विदेशी व्यापार पर अत्यधिक निर्भरता एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को केवल चक्रीय दृष्टि से ही अस्थायी नहीं बना देती, वरन् अनेकता एवं उद्योगीकरण की उपेक्षा कर कुछ लाभदायक व्यावसायिक फसलों की खेती पर स्थायी रूप से तत्पर कर देती है। पुनः भुगतान सन्तुलन-सम्बन्धी कठिनाइयाँ देश के आर्थिक विकास को जटिल एवं बाधा-पूर्ण बना देती हैं। इस तरह, अनुमानतः 'विदेशी विनिमय उपार्जन' एवं 'विदेशी विनिमय बचाने वाले' उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कुछ 'प्राथमिकता' निर्धारण को दृढ़ बनाती हैं। किन्तु, आर्थिक विकास में 'बड़े पैमाने पर क्रय' तथा 'राजकीय व्यापार' के महत्त्व की विवेचना नहीं हुई—यह बिल्कुल स्पष्ट है।

जहाँ तक दूसरे का सम्बन्ध है, विशेषज्ञ पिछली आधी शताब्दी में जापान के विकास को 'व्यापक तथा समाकलित' विकासात्मक नियोजन के सन्दर्भ में 'अत्यधिक शिक्षाप्रद' मानते हैं (पृ० 60) । यहाँ उन लोगो ने जिस धात की उपेक्षा की, वह है सामंतवादी पितृत्व की भावना; यह एक ऐसी 'प्राचीन सामाजिक सस्था' है, जिसे वे विकास के लिए रुकावट मानते थे, तथा 'उत्पादन का एकाधिकारी सगठन', जिसे वे विकासात्मक प्रेरणा के प्रतिकूल मानते थे; ये दो ऐसे तत्त्व हैं, जिन्होंने बाधा उत्पन्न करने के बजाय जापान के द्रुतगति से उद्योगीकरण में सहायता की । दूसरे शब्दों में, जहाँ तक जापान का सम्बन्ध है, 'व्यापक तथा समाकलित' नियोजन की प्रकृति के सम्बन्ध में अधिक स्पष्ट होने की आवश्यकता है ; क्योंकि वहाँ नियोजन बहुत सारे 'आधार-भूत' उद्योगों (उदाहरण के लिए इस्पात का निर्माण तथा वस्त्र का निर्यात) को सरकार द्वारा पितृवत् प्रोत्साहन, आधार-भूत यातायात सेवाओं (उदाहरण के लिए रेलवे) पर सरकारी एकाधिकार तथा निजी एकाधिकारों को सरकार द्वारा प्रारम्भिक अनुदान (उदाहरण के लिए 'जैबासु', यद्यपि यह प्रायः सैनिक कारणों से है) पर आधृत था । अतएव, जे० ए० शुम्पेटर की इस विरोधाभासी उक्ति की, कि एकाधिकार, न कि प्रतियोगिता से, उद्योगीकरण की प्रगति प्रोत्साहित होती है, जापान में सीमित परीक्षा हुई । साथ ही, यह सदिग्ध है कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का भविष्य में विकास समाकलित 'घरेलू एवं कारखाना-उद्योग' के आधार पर लाभदायक तरीके से किया जा सकता है । क्योंकि, यह किसी प्रकार भी स्पष्ट नहीं कि जापान की द्रुतगति से औद्योगिक प्रगति सरकार द्वारा प्रेरित कारखाना-उद्योग के 'युक्तीकरण' से हुई अथवा 'घरेलू एवं कारखाना-उद्योगों' के समाकलन से । मैं स्वयं इनमें से पहले की अधिक महत्त्व देने के लिए तैयार हूँ ।

तकनीकी तत्त्व की ओर ध्यान देने पर, विशेषज्ञ अल्प-विकसित देशों में 'तकनीक के निम्न स्तर' पर उतनी ही चिंता व्यक्त करते हैं, जितना कि वे विकास के लिए तकनीकी प्रगति की आकस्मिक संभावनाओं की खोज पर जोर देते हैं । यह कहा गया है कि अल्प-विकसित देशों में तकनीक की सामान्य प्रगति में सर्व-प्रथम बाधा एक शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सगठन का अभाव है, जिसके द्वारा उत्पादक नई टेक्नोलॉजी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । (पृ० 29) साधारणतः, अधिक जोर के साथ यह तर्क दिया जा सकता है कि सस्ती एवं प्रचुर मात्रा में श्रम की उपलब्धि सामान्य रूप से औद्योगिक प्रगति-एवं विशेष रूप से औद्योगिक युक्तीकरण के मार्ग में बड़ी बाधा सिद्ध हो सकती है; क्योंकि उत्पादकों में आधुनिक आधार पर नवीन क्रिया अपनाने की प्रेरणा का तब तक अभाव पाया जाता है, जब तक कि वे, सही अथवा गलत, यह विश्वास करते हैं कि श्रम की प्रचुरता के चलते निम्न-मजदूरी-उत्पादन के ऐसे कम चकदार तरीके, जिसमें पूँजी की अपेक्षा श्रम की अधिकता पाई

जाती है, की उत्पादक अकुशलता को विस्थित कर देती है। कृषि की सीमाकारी स्थिति में 'सहज एवं सस्ती तकनीकी प्रगति' (उदाहरण के लिए, रासायनिक खाद का प्रयोग एवं फसलों के उत्तम हेर-फेर) को बढ़ावा देना, प्रतिवेदन करना जैसा है, और मानो अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की उत्पादन-कुशलता एवं उच्च जीवन-स्तर के लिए उद्योगों में अपेक्षाकृत जटिल एवं खर्चीले तकनीकी प्रयोगों पर अधिकाधिक मात्रा में निर्भर रहना, एक प्रकार का धोखा जान पड़ता है।

हमें यह बतलाया जाता है कि 'कुछ-एक अल्प-विकसित देशों में जहाँ पर श्रम की अत्यधिक प्रचुरता रहती है, मुख्य समस्या पूँजी वचाने वाले नये लाभदायक तकनीकों का पता लगाना है' (पृ० 31)। ऐसा संभवतः इसलिए होता है कि प्रचुर श्रम के परिणाम-स्वरूप निम्न मजदूरी की दर 'श्रम वचाने वाले' उपायों को वेकार तथा दुर्लभ एवं मूल्यवान पूँजी के प्रयोग में मितव्ययिता को आवश्यक बना देती हैं। फिर भी, ऐसा कहना उचित होगा कि जहाँ जनसंख्या की अत्यधिक प्रचुरता है, वहाँ पर वचत अनुपात के दिया हुआ होने पर, निपज में वृद्धि की दर में अपेक्षित वृद्धि उच्च पूँजी-निपज अनुपात की अपेक्षा निम्न पूँजी-निपज अनुपात से अधिक संभव है, चूँकि 'पूँजी प्रयोग करने वाले' औद्योगिक आधार (जैसे रेलवे) के निर्माण में अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को अपनी वचाने की सीमित शक्ति की तुलना में बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऐसा तर्क दिया जा सकता है कि इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था को 'पूँजी वचाने के' तरीकों के आधार पर तकनीकी प्रगति में रुचि रखनी चाहिए। प्रतिवेदन में अल्प-विकसित क्षेत्रों को अधिक तकनीकी सहायता की प्रबल आवश्यकता पर उचित रूप में जोर दिया गया है, किन्तु इसने तकनीकी सहायता के समग्र प्रश्न को फलनीय तरीके से या तो वचत-अनुपात या पूँजी-निपज-अनुपात और इसलिए प्रगति की तकनीक की दृष्टि से संभव दर से सम्बद्ध न करने की भूल के परिणाम-स्वरूप इसे आवश्यकता से कम ही महत्त्व दिया है। संक्षेप में, जब तक जनसंख्या में वृद्धि की दी हुई दर की तुलना में निपज में वृद्धि की दर के निर्धारक के रूप में तकनीक के प्रश्न को आकस्मिक रूप से महत्त्वपूर्ण प्रदर्शित नहीं किया जाता, तब तक 'पूँजी वचाने के' उद्योगों के पक्ष में तर्क निर्णयात्मक नहीं हो सकता।

जनसंख्या के संबंध में, प्रतिवेदन जनसंख्या में उत्पादन से अधिक होने की प्रवृत्ति की पारंपरिक निराशावृत्ति को अस्वीकार करता है। इसके विपरीत यह इस मान्यता को स्वीकृति प्रदान करता है कि उत्पादन में जनसंख्या से अधिक तीव्र गति से वृद्धि की जा सकती है। यह बिना संशय के मान लिया जाता है कि जीवन-स्तर प्रति व्यक्ति निपज की वृद्धि का फलन, यानी निपज की वृद्धि की दर में जनसंख्या की वृद्धि की दर के भाग के बराबर है। अतएव, जहाँ तक निपज में वृद्धि की दर वचत-अनुपात पर फलनीय तरीके से आश्रित है, जीवन-स्तर को उठाने का एक

निश्चित तरीका जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ पूँजी-संचय की दर में वृद्धि करना है। जहाँ जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में पूँजी बहुत अधिक दुर्लभ है, वहाँ प्रतिवेदन में जनसंख्या में वृद्धि से अधिक उत्पादन बढ़ाने की घनात्मक नीति के साथ-साथ प्रसव-दर में कमी की ऋणात्मक नीति का अनुमोदन किया गया है (पृ० 48)। विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के समर्थ माँग के सभावित प्रोत्साहन की तरह अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में जनसंख्या की वृद्धि के सबध में जैसा कि हैरोड मानते हैं,¹ वैसा कोई भ्रम नहीं है। बाद में प्रतिवेदन इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि यदि संयुक्त राज्य की तरह, जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में बचत-अनुपात बहुत उच्च हो तो उन्हें विशेषतः जनाधिक्यवादी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को, जिन्हें इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाना चाहिए (देखें पृ० 77)।

‘घरेलू पूँजी-निर्माण’-सबधी अध्याय पूँजी के अभाव तथा उद्योग की प्रगति के विरोध पर स्थापकीय जोर के साथ-साथ पूर्ण रोजगार में बहुत अधिक पूँजी की सभावित बाधा पर केन्स जितना जोर देता है, ठीक उसके विपरीत है। यह एक प्रकार से तर्क-संयुक्त विरोधाभास है, क्योंकि पहिला अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के अनुरूप है, जबकि दूसरा विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए है। अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक प्रगति को नवीन पूँजी-निर्माण की दर का फलन मानते हुए, प्रतिवेदन पूँजी-संचय के मार्ग की उन सीमाओं तथा कठिनाइयों की चर्चा करता है; जैसे—बचाने एवं विनियोग करने की अपेक्षा गुप्त संचय की प्रवृत्ति, प्रति व्यक्ति निम्न आय, बचत-सबधी संस्थाओं का अपूर्ण विकास, मध्यम एवं उच्च आयवाले वर्गों में प्रदर्शन उपभोग की प्रवृत्ति। फिर भी इसमें पूँजी-निर्माण के मार्ग की कुछ प्रमुख कठिनाइयों की चर्चा नहीं की गई है; जैसे—भित्तब्यता को हतोत्साहित करने में राजनीतिक अस्थायित्व, टिकाऊ वस्तुओं से रुचि हटाने के लिए उत्तरदायी युद्धोत्तरकालीन अनिश्चयता, उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों से पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों में साधनों की सापेक्ष अगतिशीलता तथा समानता के प्रति सामाजिक एवं नैतिक प्रवृत्ति (विशुद्ध-वादी दृष्टिवाद की तुलना में जिसे मैक्स वेबर के पाठक पूँजी-निर्माण के आधार पर आर्थिक विषमता को ऐतिहासिक औचित्य के रूप में जानते हैं)। ये बाधाएँ कठिनाइयाँ अंशतः उद्योग की संरचना एवं समग्र माँग की बनावट तथा अंशतः सहकारी जीवन की गहरी सामंतवादी परंपराओं के परिणाम-स्वरूप हैं। जब इन बाधाओं को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है, तो पूँजी-संचय की दर में वृद्धि का कार्य प्रतिवेदन में वर्णित तरीके से भी अधिक कठिन हो जाता है। सिद्धांततः, यह स्पष्ट है कि निपज में वृद्धि की दर को सभवतः बचत के अनुपात का नहीं, बल्कि उसी

1. देखें, आर० एफ० हैरोड, ‘ट्वार्ड्स ए डायनेमिक इकॉनामिक्स,’ मैकमिलन, लंदन, पृ० 106-115।

परिवर्त्ती के, जो पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता को व्यक्त करता है तथा जो समुदाय की वचने की इच्छा से अधिक उद्योग आदि की संरचना के द्वारा निर्धारित होता है, फलन बनाने की आवश्यकता होगी। तब यह समझने में सुविधा होगी कि क्यों, उदाहरण के लिए, युद्धोत्तर काल में जापान वचने की अपेक्षाकृत ऊँची औसत क्षमता के बावजूद अपनी युद्धोत्तर-कालीन पूँजी की आवश्यकताओं के अनुरूप पूँजी-संचय की दर को प्राप्त करने में असफल रहा है¹

प्रतिवेदन में उन अल्प-विकसित देशों के विकासात्मक कार्यों के लिए 'वलात् वचत' के निर्णायक महत्त्व पर उचित रूप में जोर दिया गया है, जहाँ संस्थानिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से स्वेच्छिक वचत इतनी कम है कि सरकार को कर मुद्रा-स्फीति, साधनों के विनिधान की प्राथमिकता तथा विनिमय-नियन्त्रण (मुख्यतः पूँजी के बाहर जाने के विरुद्ध) आदि के द्वारा विकासात्मक पूँजी प्राप्त करनी पड़ती है। यह अनिच्छापूर्वक इस बात को स्वीकार करता है कि स्फीति के वगैर द्रुतगति से आर्थिक विकास सम्भव नहीं है (पृ० 42)। ऐसा अंशतः इसलिए है कि जहाँ पहिले से ही जीवन-स्तर बहुत निम्न है, वहाँ उपभोग में राजकोपीय तरीकों के द्वारा अनिवार्य कमी का विकल्प असह्य है और मुख्यतः इसलिए कि मूल्य-स्फीति के परिणाम-स्वरूप 'मौद्रिक भ्रम का प्रभाव' यह पड़ता है कि कागजी मुनाफाखोरों तथा कागजी मजदूरी उपाजित करनेवाले की अपनी वास्तविक आय तथा वांछित समृद्ध स्थिति के सम्बन्ध में भ्रम दूर होने के पूर्व पूँजीगत वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाती है। पूँजी-संचय पर स्फीति के उत्तेजक प्रभावों के विरुद्ध निम्न तथा मध्यम आयवाले वर्गों का स्वेच्छिक वचत पर हतोत्साहित करने वाला संघात प्रारम्भ हो जाता है। फिर भी, यह संदिग्ध है। प्रथमतः, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में निम्न तथा मध्यम आयवाले वर्गों की वचत इतनी अधिक नहीं होगी कि उन्हें उच्च मूल्यों के परिणाम-स्वरूप इनके वास्तविक मूल्य में कमी के लिए चिन्ता करनी पड़े। दूसरी बात यह है कि सभी स्थायी आयवाले वर्गों में लगान-उपजीवी की वचत ही सर्वाधिक प्रभावित होगी तथा जिनकी वचने की सीमान्त क्षमता किसी भी प्रकार साहसियों से कम होगी। इस स्थिति में विकासात्मक स्फीतिजनक वित्तीयकरण के परिणामस्वरूप उच्च मूल्यों के वितरणात्मक प्रभाव से स्वेच्छिक वचत में महत्त्वपूर्ण कमी नहीं होगी।

उपभोग में कमी के वगैर पूँजी-संचय में वृद्धि की सम्भावना विशेषतः उन देशों में स्वीकार की गई है, जिनमें अपेक्षाधिक कृषि-मजदूर होते हैं और जिनके पूँजीगत उद्योगों में स्थानांतरण से उपभोक्ता वस्तुओं की निपज में कमी की सामान्य रूप से कोई आशा नहीं की जाती है; किन्तु, 'अपूर्ण रोजगारवालों' की गतिशील

1. तुलना कीजिए के० ओकावा का 'दि ग्रेथ रेट ऑफ जापानीज इकॉनामी, हायरन, फरवरी, 1952।

वनाने में सन्निहित सम्भावित अवरोधों—जैसे श्रम की अगतिशीलता (यदि पारिवारिक सम्बन्धों के कारण नहीं तो अपर्याप्त परिवहन-सम्बन्धी कठिनाइयों के परिणाम-स्वरूप) तथा 'कम-मजदूरी वालों' को पर्याप्त काम दिलाने में 'किसी कारण-विशेष' के अभाव की कोई चर्चा नहीं की गई है।

घरेलू पूँजी के अभाव को पूरा करने के लिए पूँजी के आयात के पक्ष में अपने तर्कों में विशेषज्ञों ने उन तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कठिनाइयों को, जो रास्ते में रुकावटें उपस्थित करती हैं, उचित मान्यता दी है। इस प्रकार वे अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को 'वर्तमान राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में इनके जोखिमपूर्ण अनुमान' तथा 'अल्प-सांख्यिकीय' गूँचना के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं। किन्तु वे उन प्रत्यायात्मक कठिनाइयों के महत्त्व पर, जो वचत की समग्र धारणा में सन्निहित हैं, जोर नहीं देते। उदाहरण के लिए, कॉलिक ब्लाँक की आलोचना जापान के उस वचत-अनुपात के अत्यन्त कम के लिए की गई है, जिसके अन्तर्गत कितनी ही उपभोक्ता-सम्बन्धी पूँजी की मदें (उदाहरण के लिए, अर्द्ध-टिकाऊवस्त्र सम्मिलित हैं), जिन्हें साधारणतया अलग रखा जाता है। वास्तविक राष्ट्रीय सम्पत्ति आँकड़ों पर आधारित वचत की इतनी विस्तृत धारणा के प्रयोग से सांख्यिकी के ऊर्ध्व विस्तार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे सम्बद्ध देश को भूल से पूँजी आयात करने वाले के बजाय 'अतिरिक्त' वचत को निर्यात करने योग्य समझा जाने लगता है। दूसरी ओर, चूंकि देश को भ्रमवश समुदाय की वचत की क्षमता के अनुरूप पूँजीगत वस्तुओं को उत्पन्न करने योग्य समझा जाता है, इसलिए उपर्युक्त उद्योग की संरचना के प्रभाव तथा समग्र माँग की रचना की उपेक्षा से अधोमुख सांख्यिकी के झुकाव की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय और एव व्युत्पन्न घरेलू वचत-अनुपात के सम्बन्ध में 'जोखिमपूर्ण' अनुमान भी लगाने के पूर्व ही इन प्रत्यायात्मक समस्याओं को ठीक कर लेना चाहिए। एक दूसरे अर्थ में भी प्रतिवेदन कमजोर जान पड़ता है, अर्थात् अल्प-विकसित देशों की पूँजीगत आवश्यकताओं और विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के अत्यधिक पूँजी की इतिहास-प्रसिद्ध ह्रासमान सीमात-क्षमता से परिसीमित वर्तमान निवेश-सम्बन्धी अवसरों के अनुपात में अधिक बचाने की प्रवृत्ति से उत्पन्न स्थायित्व-जनित खतरे के बीच सम्बन्ध जोड़ने की सम्भवतः इच्छित असफलता ही वह कमजोरी है। यह भूल उन लोगों के द्वारा, जो केन्स एव हैन्सेन के स्थायित्व-सम्बन्धी परिकल्पना का दृढ़तापूर्वक विरोध करते हैं, दुर्बलता की बजाय कदाचित् दृढ़ता समझी जायगी। मेरा विचार केवल यह है कि जब प्रतिवेदन विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से अविकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में पूँजी के निर्यात की मिफारिश, उन विकसित देशों के लिए जिनकी प्रवृत्ति हैरोड के पूर्ण रोजगार के साथ 'प्रगतिशील साम्यावस्था' के मार्ग से विचलित होने की है, इस प्रकार के निर्यात के लाभों (उदाहरण के लिए सम्भावित अत्यधिक घरेलू वचत के लिए अतिरिक्त विकास तथा निर्यात गुण्य के रूप में कार्य करनेवाले

लाभांश एवं व्याज का अन्तिम अंतःप्रवाह) का वर्णन किये बगैर, करता है, तो यह कम विश्वासजनक है।

ऐतिहासिक एवं राजनीतिक तथा कुछ हद तक आर्थिक कारणों से प्रतिवेदन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए पूंजी-निर्यात में बहुत कम लाभ देखता है। इसके विपरीत, यह अन्तर-सरकारी उधारदान तथा बहुराष्ट्रीय विकासात्मक वित्त की वांछनीयता एवं सम्भावना पर अधिक विश्वास रखता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अन्तर-सरकारी उधारदान पर जोर देने के कारण, 'हस्तांतरण-समस्या', जो विशेषज्ञों के अनुसार सफल विकास के क्रम में पूर्णरूप से सदा के लिए समाप्त हो जायगी, वे उसकी परम्परागत चिन्ता से प्रभावित होने के लिए तैयार नहीं होते। विश्व-बैंक की आलोचना इसकी वर्तमान उधारदान नीति की विकास-सम्बन्धी आवश्यकताओं पर आधारित न होकर विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के अनुमान पर आधारित होने के लिए की जाती है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की उपलक्षित आलोचना समझा जा सकता है; क्योंकि कोष का उद्देश्य विदेशी विनिमय-सम्बन्धी कठिनाइयों का समाधान करना है, जिससे बैंक अपना ध्यान दृढ़तापूर्वक केवल विकासात्मक उधारदान पर केन्द्रित कर सके, किन्तु केन्स द्वारा जोर दिये गये विशुद्धतः तकनीकी एवं गैर-राजनीतिक आधार पर उधारदान के अभाव से दूर हटने के खतरे के विरुद्ध, विशेषतः आज के अन्तर्राष्ट्रीय तनाव एवं संघर्ष के विक्षुब्ध युग में, चेतावनी न देने के लिए प्रतिवेदन की आलोचना की जा सकती है।

ऊपर जो बातें कही गई हैं, उनमें किसी का भी ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए, जिससे संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा समस्या के सामान्यतः सुन्दर विश्लेषण पर सन्देह प्रकट किया जा सके। सामान्य अधिमत के तौर पर यह कहना अनुचित न होगा कि समीक्षा से सम्बद्ध प्रतिवेदन आने वाले कई वर्षों के लिए आर्थिक विकास की अत्यावश्यक प्रवेशिका के रूप में कार्य करता रहेगा। किन्तु, इसकी नीति-सम्बन्धी सिफारिशें गतिशील विश्व की अर्थ-व्यवस्था के लिए कम स्थायी महत्त्व की हैं। परन्तु सम्पूर्ण प्रतिवेदन में सबसे बड़ी बात आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की नई भावना है, जो अर्थशास्त्रियों की संकुचित तकनीकी दृष्टि से बहुत दूर तथा युद्ध के पूर्व राष्ट्रीयतावादियों के 'साम्राज्यवादी' क्षितिज से बहुत ऊपर है।